Fourth Series Vol. IV - No. 12

Wednesday, June 7, 1967
Jyaistha 17, 1889 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Second Session)

(Vol. IV contains Nos. 11 - 20)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price : Rs. 1.00

CONTENTS

No. 12.—*Wednesday, June 7, 1967/Jyaistha 17, 1889 (Saka)*

	COLUMNS
Member Sworn :	3337
Oral Answers to Questions—	
*Starred Questions Nos. 331 and 334 to 337	3337—71
Short Notice Question No. 8 . . .	3371—84
Written Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 332, 333 and 338 to 360 . . .	3385—3400
Unstarred Questions Nos. 1640 to 1669, 1671 to 1750, 1752 to 1788 and 1790 to 1792	3400—3512
Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices (*Query*)	3513—14
Question of Privilege against the *Hindustan Times*	3514—25
Re. Calling Attention Notices (*Query*)	3526—30
Papers Laid on the Table	3525—26, 3530—32
Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
Third Report .	3532
Elections to Committees—	
(i) Central Advisory Board of Education; and	3532—33
(ii) Council of the Institute of Science, Bangalore .	3535
General Budget—General Discussion	3533—3624
Shri Hanumanthaiya . .	3534—39
Dr. Ram Manohar Lohia	3539—64
Shrimati Tarkeshwari Sinha . . .	3564—82
Shri Surendranath Dwivedy	3582—98
Shri Ram Kishan	3598—3611
Shri Amiyanath Bose.	3611—18
Shri Randhir Singh	3618—24
Half-an-hour Discussion *re.* National Food Budget	3624—40
Shri Madhu Limaye	3624—29
Shri S. S. Kothari	3630—31
Shri E. K. Nayanar . . .	3632
Shri Sequeira	3633
Shri Annasahib Shinde	3633—40

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PARLIAMENT LIBRARY
DIGITIZED

LOK SABHA

Wednesday, June 7, 1889/Jyaistha 17, 1889 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MEMBER SWORN

Shri Vikram Chand (Chamba).

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

शिक्षा संस्थाओं के साम्प्रदायिक नाम

*331. **श्री ओ० प्र० त्यागी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की धर्म निरपेक्षता की नीति की दृष्टि से उनके मंत्रालय का विचार यह बात सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करने का है कि जब तक शिक्षा संस्थाएं अपना साम्प्रदायिक नाम नहीं बदलती तब तक उन्हें सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलेगा; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों को आदेश जारी करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) और (ख). जी, नहीं। केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा इस विषय में निर्धारित की जाने वाली कोई नीति संविधान के संगत अनुच्छेद के अनुकूल होगी।

श्री ओ० प्र० त्यागी : मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि जातीयता, प्रान्तीयता

और साम्प्रदायिकता की भावना देश की प्रगति में बाधक है तथा सरकार बार बार इस बात की घोषणा भी करती है, परन्तु आचरण इस के सर्वथा विपरीत है। उत्तर प्रदेश ने इस संबंध में पग उठाये हैं। तो जो संस्थाये हमारे केन्द्र के अधीन हैं या जो क्षेत्र केन्द्र के अधीन हैं उन में हमारी सरकार इस प्रकार की संस्थाओं के ऊपर जो कि साम्प्रदायिकता या जातिवाद का प्रचार करती हैं किसी भी रूप में, उन के ऊपर प्रतिबंध लगाने को क्यों तैयार नहीं है कि जब तक उन को अनुदान नहीं दिया जायेगा जब तक वह जातिवाचक नाम रक्खेंगी ? हमारी प्रान्तीय सरकारें तो आचरण कर रही हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार क्यों नहीं आचरण करती ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं माननीय सदस्य का ध्यान संविधान के अनुच्छद 25 और 30 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली बात अनुच्छेद 25 में है कि "सब व्यक्तिओं को, अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक्क होगा।" दूसरी बात अनुच्छेद 30 में है कि "धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुची की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।" हम ने प्रयत्न किया लेकिन विधि की राय यह है कि हमारे संविधान में इन धाराओं के रहते हुए हम यह संशोधन नहीं कर सकते हैं।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था संबंधी आपत्ति है। यह मंत्री महोदय

सदन को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने जो संविधान की धारायें बतलाई हैं उन का इससे कोई संबंध नहीं है। सम्प्रदाय के नाम रखने वाली संस्थाओं के ऊपर कानून से रोक लगाई जाय, यह सवाल यहां पर नहीं है। सवाल यह है कि जब हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है तब किसी भी सम्प्रदाय या धर्म के नाम पर जो संस्थायें चलती हैं उन को सरकार अनुदान क्यों दे रही है। यहां पर इन धाराओं का कोई संबंध नहीं है। इस लिये इस प्रश्न का जवाब आना चाहिये।

Mr. Speaker: Let him put his second question; he will himself ask that.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिये। माननीय सदस्य का प्रश्न अनुदान देने के संबंध में है। हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है अब आप बतलाइये कि संविधान की कौन सी धारा है जिस में इस प्रकार की रोक है। कोई रोक नहीं है। इस लिये वह गलतबयानी न करें। अगर वह करना नहीं चाहते हैं तो कहें कि हमारी हिम्मत नहीं है और हम करना नहीं चाहते, लेकिन सदन को गुमराह क्यों करते हैं?

श्री भागवत झा आजाद : गुमराह करना और गलतबयानी करना इन माननीय सदस्य का काम हो गया है, मेरा नहीं।

श्री मधु लिमये : आप का काम है। बनारस विश्वविद्यालय के विधेयक तक में किया गया था।

श्री भागवत झा आजाद : हिम्मत माननीय सदस्य की नहीं है। गुमराह वह कर रहे हैं, मैं नहीं करता हूं। इस लिये गुमराह करने की बात वह न करें। अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 30 में यह लिखा गया है कि :

> "शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।"

श्री मधु लिमये : मामला बिल्कुल साफ हो गया। यह संस्थाओं में विभेद करने के बारे में लिखा हुआ है...

श्री भागवत झा आजाद : हम किसी विश्वविद्यालय के नाम के सामने जो कुछ लिखा हुआ है उस को तब तक नहीं हटा सकते हैं, चाहे वह हिन्दू के नाम पर हो या मुसलिम के नाम पर अथवा क्रिश्चियन के नाम पर, जब तक संविधान की यह धारा माजूद है। क्योंकि आप को याद होगा कि इसी संसद् में हिन्दू यूनिवर्सिटी बिल के संबंध में जो संशोधन आया था उस को न इस सदन ने माना था और न उस सदन ने। इस लिये मैं इस बात पर पुनः जोर देता हूं कि संविधान की धारा इसके रास्ते में आ जाती है।

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं, अध्यक्ष महोदय, आप से व्यवस्था चाहता हूं। व्यवस्था का जवाब मंत्री नहीं देंगे, आप देंगे। उन्होंने जो धारा पढ़ी वह विभेद के बारे में है। मान लीजिये कि हिन्दू संस्था को दिया जाता है और मुसलिम संस्था को इस की इजाजत नहीं दी जाती तो यह संविधान के खिलाफ है। माननीय सदस्य का सवाल था कि जिन के नाम में कोई सम्प्रदायवाचक शब्द है क्या आप उन संस्थाओं को अनुदान देना बन्द कर देंगे, उन्होंने विभेद अथवा डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कही। इस लिये या तो मंत्री महोदय कानून मंत्री से सलाह मशवरा कर के बतलायें नहीं तो चुप बैठें। आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दीजिये।

Mr. Speaker: What is the 'vyavastha' here? If the questioner is not satisfied with the answer, let him say to which aspect of the answer he wants clarification.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा आने दीजिये कि संविधान बाधक है या नहीं । इस का निर्णय प्रश्नोत्तर काल में नहीं हो सकता । यहां इस पर चर्चा होनी चाहिये ।

Mr. Speaker: He can ask for it. Let the question go on. He can ask the second question now.

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय अपनी बात कह सकते हैं । संविधान कोई बाधा नहीं डाल रहा है ।

श्री ओ० प्र० त्यागी : जो हमारे फंडामेंटल सिद्धांत हैं उन की अवहेलना कोई भी भारतीय नागरिक नहीं कर सकता, और न सरकार ही इस बात को प्रोत्साहन दे सकती है । अभी माननीय मंत्री जी ने इशारा किया इन अनुच्छेदों की तरफ कि भारत सरकार इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा सकती है स्कूलों के ऊपर कि किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी क्योंकि सरकार का दृष्टिकोण है कि इससे साम्प्रदायिकता आयेगी अथवा विशेष धर्म का प्रचार होगा । जब सरकार इस प्रकार का आचरण कर सकती है तो जो साम्प्रदायिक नाम है उन पर वह प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा सकती ?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा और इस को दुबारा फिर कहता हूं हम इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं कि संविधान की धारायें हमारे रास्ते में आती हैं और माननीय सदस्य की राय है कि ऐसा नहीं है । हम ने इस संबंध में विधि विभाग से राय ली है । वह कहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं । इस के बाद हम क्या करें ? जो ला मिनिस्ट्री की राय के अनुसार ठीक हैं वह मानें या जो माननीय सदस्य कहते हैं वह मानें ?

श्री मधु लिमये : ला मिनिस्ट्री की राय क्या है ?

श्री भागवत झा आजाद : उन की राय है कि हम नहीं हटा सकते हैं ।

श्री रामसेवक यादव : राज्य सरकार ने भी राय ले कर ही यह निर्णय किया होगा । वह आप से ज्यादा अकलमन्द है ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं केन्द्रीय सरकार की बात कर रहा हूं ।

Mr. Speaker: No, no. I will request the Minister not to answer that type of question.

Shri Anbazhagan: With due regard to the safeguard of minorities, both religious minorities as well as linguistic minorities, whenever other communal considerations are there in any institution or whenever the institutions are named after certain communities which do not come under the purview of religious or linguistic minorities, will the Government consider a proposal to discourage such institutions and discourage Government's benefit and grants to such institutions?

Shri Bhagwat Jha Azad: It is a hypothetical question. All that I can say is that in respect of such institutions where there are names starting with Hindu or Muslim or Christian or something of this type, we have been advised that we cannot stop grants to such institutions because Article 30(2) says that we cannot discriminate against any educational institution in giving grants to these institutions. We have already got the opinion of the Law Ministry. That is why we cannot do it.

Shri Anbazhagan: That is not my question. My question is this. With due regard to religious and linguistic minorities, will the Government come forward to discourage or prevent the other type of communal institutions or institutions named after communities?

Shri Bhagwat Jha Azad: I think it is the same question as before.

Shri Anbazhagan: I was referring to cases other than those of linguistic minorities. I do not know whether Government have taken a decision on such cases.

Shri Bhagwat Jha Azad: I am sorry I have not followed the import of the question. I thought that it was the same question as before.

Mr. Speaker: Could the hon. Member repeat his question?

Shri Anbazhagan: The principle expounded by Government is that Government may give grants to institutions of minorities, with religious or linguistic names. But about the other types of institutions which are named after communities or castes or sects, may I know whether Government will think of a programme to stop grants for such institutions?

Shri Sezhiyan: Shall I explain the position?

Mr. Speaker: I think the Leader of his Party has explained it sufficiently now.

Shri Bhagwat Jha Azad: It will depend upon the institutions which the hon. Member has in mind. All that I can say is that on the basis of names, we cannot discriminate. As regards the institutions to which the hon. Member has referred, we can examine each individual case and find out what can be done.

Shri S. S. Kothari: I think we should go over to the next question. There are other more important questions.

Mr. Speaker: But those who have sponsored this question think that it is important. So, I must allow at least four or five supplementary questions.

Shri S. S. Kothari: What is in a name?

Mr. Speaker: At least four or five supplementary questions must be allowed. Only two have been asked till now.

Shri Bedabrata Barua: Changing the name of a particular educational institution by the deletion of the word 'Hindu', 'Muslim' or 'Christian' is itself not an ideal, but the more important question is whether such attempts in the past had led to the reduction of the communal feelings or an increase of such feelings. May I also know whether such attempts, when they were made, were opposed or supported by the political parties, as, for instance, when the question came up in regard to the Aligarh and Banaras Universities?

Shri Bhagwat Jha Azad: As I have said already, there was such an attempt, and we had brought forward a Bill in this House as well as in the other House. The Bill was referred to a Joint Committee. When the Bill as reported by the Joint Committee was discussed in the Rajya Sabha, Rajya Sabha changed the name to Kashi Vishwavidyalaya. But even that was not accepted by the Lok Sabha. That is one instance where it was not agreed to. The second instance where it was not agreed to was in the case of the draft Delhi Secondary Education Bill, 1964. In the Bill as introduced before this House, we had said that we should not name a school after a sect or a caste. The Joint Committee on the Bill, however, accepted an official amendment to drop this provision as it was not considered constitutional These are two instances where things have been considered already by the House and not agreed to.

Shrimati Lakshmikanthamma: A distinction has been made between religious and communal institutions. In all the educational institutions, students are not supposed to mention the name of the community such as Khamma, Reddy etc. Similarly, what prevents the hon. Minister from abolishing or not recognising the names of institutions which are named in such manner as Khamma hostel, Red-

dy hostel and so on, and from stopping grants to such institutions?

Shri Tenneti Viswanatham: The hon. Minister was saying that he had obtained legal opinion. Could he place a copy of the same in the Table of the House?

Shri Bhagwat Jha Azad: Yes, we can.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी माननीय मंत्री जी ने संविधान की जिस धारा का उल्लेख किया है उसमें स्पष्ट रूप से भाषा और धर्म ये दो शब्द हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो निर्णय किया है वह किसी धर्म विशेष के आधार पर नहीं बल्कि जाति और उपजातियों के आधार पर जिन शिक्षण संस्थाओं के नाम हैं, किया है । मैं समझता हूं कि उस आधार पर शायद संविधान मार्ग में बाधक नहीं होता है । अगर बाधक होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकार का निर्णय नहीं करती । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो इस प्रकार के विद्यालय हैं, जिन के साथ जाति और उपजाति वाचक नाम हैं, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने का आप विचार करेंगे ?

श्री भागवत झा आजाद : अभी एक प्रश्न के जवाब में मैंने यह कहा है कि सिद्धान्ततः हमने जो सरकार का विचार है उसको प्रकट कर दिया है । लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज हो और सिद्धान्तों के अनुकूल हो तो उस पर निश्चय ही विचार किया जा सकता है ।

श्रीमती सावित्री श्याम: पिछले आम चुनावों में इन शिक्षण संस्थाओं ने काफी सक्रिय भाग लिया था और इस कारण से बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं लेकिन छोटे पैमाने पर कम्युनल डिसहार्मनी पैदा हुई थी, फैली थी अभी वहां गया है कि संविधान हमारे रास्ते में बाधक है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने विचार किया है कि संविधान में संशोधन किया जाये और नहीं किया है तो क्या सरकार विचार करेगी ताकि इस तरह के नामों को, इस तरह के नामक्लेचर्ज को समाप्त किया जा सके ?

श्री भागवत झा आजाद : यह एक सुझाव है जो माननीय सदस्या दे रही हैं ?

श्री राम सेवक यादव : अपने यहां जब कोई मरता है तो कहा जाता है "राम नाम सत्य है" । मैं समझता हूं कि इस देश में जातियां ही सत्य हैं, जातपात ही सत्य है । मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न सम्प्रदायों और जातियों के नाम पर जो शिक्षा संस्थायें चल रही हैं उसके कारण क्या यह सही नहीं है कि जातियों में आपस में घृणा, द्वेष और जातीयता का वातावरण पनपा है, यदि हां तो क्या इसका लेखा जोखा किया गया है कि वह किस हद तक बढ़ा है ? यदि हां तो धर्म निरपेक्षता को जो हमने स्वीकार किया है और संविधान की मंशा के मुताबिक सरकार इन नामों को खत्म करने पर क्या विचार कर रही है ?

श्री भागवत झा आजाद : मैंने इसका जवाब दे दिया है । उसी प्रश्न को माननीय सदस्य दूसरी भाषा में रख रहे हैं । अभी हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं, उनका मैं उल्लेख कर चुका हूं । इस सदन में और राज्य सभा में जो बिल आये माननीय सदस्यों ने उनको स्वीकार नहीं किया । अब इस बारे में पबलिक ओपिनियन को तैयार करना होगा और वह हम सब को करना होगा ।

Naga Activities in Tirap Division

\+

*324. **Shri Bal Raj Madhok:**
Shri A. B. Vajpayee:
Shri R. S. Vidyarthi:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the hostile Nagas are busy meeting tribesmen in Tirap Division of N.E.F.A. for armed rebellion against Government; and

(b) if so, the steps Government have taken to prevent such an outbreak in that strategic region?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) We are aware of attempts to bring tribals of Tirap under the influence of Naga hostiles.

(b) Suitable measurers to check the attempts of Naga hostiles to infiltrate into Tirap have been taken.

Shri Bal Raj Madhok: In view of the fact that the Tirap sub-division of NEFA falls in the tri-junction of India, Burma and Tibet and also considering the fact that there has been a systematic propaganda by the Chinese among the tribesmen there that because their facial expression is more akin to that of Mongolians they are nearer to the Chinese than to Indians, and also taking into account the fact that no Indian from the plains is allowed to go there—it is kept as a sanctuary—are these not contributory factors enabling the Nagas and the Chinese to play havoc with the loyalty of the people in that area? If so, what steps are Government taking to prevent this kind of thing happening?

Shri Vidya Charan Shukla: It is not a fact that Nagas and Chinese have played havoc with the loyalty of the people there. They have been trying to extend their influence there, but we have taken various measures to check this and we have been quite successful in this respect.

Shri Bal Raj Madhok: It is known that the Chinese did come into that area, stayed there and then went back. What have the security forces and other Home Ministry officials been doing there? We have an administration there with a high-sounding name. Could they not find out whether the Chinese came, stayed there so long and went back?

Shri Vidya Charan Shukla: No Chinese came there.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई थी और प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ने इसको प्रसारित किया था कि कुछ चीनी तीरप डिविजन के क्षेत्र में आये और कुछ दिन वहां रुके और फिर वापिस चले गये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्रालय ने प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया से पता लगाने की कोशिश की है कि यह समाचार उनको कहां से मिला ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम लोगों को इसके बारे में पता लगा है स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन से और इस बात को हम कह सकते हैं कि जो यह खबर निकली यह बिल्कुल गलत थी और खबर किस तरह से निकली, क्यों निकली, इसके बारे में जांच पड़ताल अवश्य कर लेंगे ।

Shri R. Barua: From the answer given, it seems that Nagas are operating in that area. Are Nagas as such operating there or are they engaging some people of the locality for their purpose?

Shri Vidya Charan Shukla: Some Nagas come from the adjoining area of Nagaland. But we have tried to check them and now we have been able to do so. We do not allow them to come there and subvert the loyalty of the people there.

Shri Hem Barua: These Naga hostiles are not only contacting the tribesmen in Tirap Division of NEFA, but it is reported that they are contacting the Karens in Upper Burma also with a view to establishing, with their co-operation, a Christian independent republic of the Nagas living in Upper Burma, the Nagas living in Nagaland, the Nagas living in Manipur and the Nagas living in Assam. And since the External Affairs Ministry which is in over-all control of Nagaland affairs maintains only a superficial contact, and it is the Home Ministry that is responsible for peace

and security in that part of our country, may I know what the Home Minister has particularly done to see that the lawful or peaceful atmosphere in that part of the country is not transgressed by these Naga hostiles?

Shri Vidya Charan Shukla: As I have said in reply to earlier questions, we have taken measures to check them, and we have been able to check them. We are at present dealing with the limited question of Naga hostiles in Tirap Sub-division of NEFA. Here we have been successful in containing their influence which they wanted to extend to the tribals living in this sub-division.

Shri Hem Barua: I wanted to know if they want to establish an independent Christian republic. Do Government know about it, and if they know about it, what steps have Government taken to see that it does not come.

Shri Vidya Charan Shukla: As I said, we are dealing with the limited question of Naga hostiles in Tirap sub-division. If the hon. Member puts a separate question on the larger matter, we shall certainly look into it.

Shrimati Jyotsna Chanda: In view of the statement made just now by the hon. Minister that no Chinese came in that area, I want to know whether the Government is aware of the fact that Chinese women came to the NEFA area just before China's aggression and married tribal men there and settled down?

Shri Vidya Charan Shukla: The hon. Member is referring to something which might have happened before October, 1962. I am not at present aware of any such thing.

Shri Hem Barua: That was admitted on the floor of the House.

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ये नागा लोग जो बर्मा और चीन में जाते हैं, उनको वहां जाने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? क्या सरकार को यह भी मालूम है कि वहां पर कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रहे हैं जिनमें कुछ फारेन मिशनरीज भी हैं, जो यह गड़बड़ करवाते हैं, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक नागालैंड का सवाल है, उसकी सुरक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय देखते हैं । जहां तक तीरप सब-डिविजन का सवाल है, उसको गृह मंत्रालय देखता है । हम ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए हैं, जिस से वे लोग इस सब-डिविजन में से हो कर बर्मा और चीन न जा सकें ।

Shri Kanwar Lal Gupta: What are those steps, I want to know. He is simply repeating the answer that they have taken some steps.

Shri Vidya Charan Shukla: The steps are: we have established more check posts, we have intensified patrolling, and we have taken some other steps which we cannot disclose in the House because it will be taken advantage of by the hostiles. We cannot lay all those things before the public, because that will be taken advatage of by the hostiles.

Shri Kanwar Lal Gupta: What about the Christian missionaries?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): The point is, he asked whether some of these people go into Northern Burma or China. In Northern Burma there are Christian tribes there, among them also some Christian missionaries are there. The writ of that Government running there is certainly a matter on which I cannot express an opinion, but certainly some people from Nagaland and other areas are trying to infiltrate into Northern Burma and trying to establish contact with the Christian community there. I think there are some foreign missionaries functioning on the other side, I cannot say.

Shrimati Sharda Mukerjee: May I refer to the answer of the hon. Minis-

ter of State that as far as his information goes, there are no Chinese in NEFA, and may I ask him as to what is his source of information? Is it only the intelligence of the Home Ministry, or has the Minister taken care also to find out from the military people etc. who operate in that area, because during the NEFA hostilities we found to our cost that our intelligence had failed miserably? May I know if he has taken the trouble to find out as to what is happening there from our military people who are posted there, or is he depending only on Home Ministry's intelligence?

Shri Y. B. Chavan: When we give our assessment here, it is naturally evaluation of information received from both the sources, military sources and intelligence sources and the statement is made on the basis of absolutely reasonable information. One need not normally go back to what happened before 1962. We had learnt the lesson, the very costly lesson from them and they were not wasted on us.

Mr. Speaker: Next question, 335.

Shri Hem Barua: 341 also may be taken.

Mr. Speaker: Only the word 'Mizo' is common to both. 335.

Escape of Mizos

+

*335. **Shri Swell:**
Shri Kikar Singh:
Shri Kolai Birua:
Dr. Karni Singh:
Shri Hem Raj:
Shri Sharda Nand:
Shri J. B. Singh:
Shri Bharat Singh Chauhan:
Shri Ranjit Singh:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Mizos who have entered into East Pakistan during the last six months;

(b) whether Government have brought this to the notice of the Government of Pakistan;

(c) if so, the reaction to or the reply from Pakistan Government in the matter; and

(d) the steps being taken to seal the border to prevent Mizos from going to East Pakistan?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) According to our information, Mizo hostiles have been in contact with Pakistan for sometime, but it is not possible to give the number of rebels who crossed over the Pakistan during the last six months.

(b) and (c). A number of protests were lodged with the Pakistan Government demanding discontinuance by Pakistan of the facilities given by them to Mizo hostiles, but the Pakistan Government have repeatedly denied having provided any assistance whatsoever.

(d) Defence forces have been assisting the civil authorities to check the activities of Mizo hostiles.

Shri Swell: The Mizo rebellion has been there for the last more than one year. From time to time we get statements from the Government saying that the rebellion was breaking up. The latest incident occurred on May the 23rd when an ambush took place on the Silchar-Aijal road, the main line of communication almost for the entire district, in which 16 of our securitymen lost their lives. It would go to indicate that far from the rebellion weakening, it gained further accretion of strength and firepower. May I know whether this is not the sign that the Mizos have been receiving active assistance in arms, ammunition and other ways from neighbouring foreign countries?

Shri Vidya Charan Shukla: There was an ambush in which we lost some lives but that was an isolated incident compared to the progress of our peacekeeping operations. We have made very good progress in that respect. A good many Mizo rebels have surrendered to our security forces and many

of their important people have been captured by us, whereas this is an isolated incident. By and large our progress towards eliminating these Mizo rebels has been satisfactory.

Shri Swell: I am very sorry to hear the reply of the Minister. He says that the incident of May 27th was an isolated incident whereas reports that we get show that this is only the latest in the series of such incidents that have taken place. The complaint of our security forces is that the Government does not give out the correct figures of the casualties that they suffer and the result is that the security forces feel extremely reluctant to go against the hostiles and may I know whether the latest policy of the Government of moving the Mizo villages into 19 centres and leaving out wide areas of the district for the operation of the Mizo hostiles is not working against us?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): I was trying to find out the purpose of the question which the hon. Member was putting. The purpose seems quite obvious. He wants to prove that the grouping system is a failure. As I had occasion to explain this position on the floor of the House, it is certainly one more measure we have taken. So far, on balance, I can say that this grouping system has certainly given us certain advantages. I cannot say at this stage whether it has completely succeeded or not, but it certainly has given one advantage, that these Mizo rebels used to take advantage of the scattered population to terrorise them and to take away their food and other supplies from them, which is being denied too them, and as a result of this, the Mizo rebels have become a little more desperate.

The ambush to which he made reference is one of them. I know that it is also one of the series of incidents that took place, but when there is a rebellion, ambush is certainly a part of it. One has to learn to live with it. Unfortunately in this particular ambush also, one of the aspects is this: as I said last time, an ambush has certainly an element of surprise; a surprise attack is made as a result of which some life is normally lost, but in this particular case, I must say I have got all the sympathy for those people who lost their lives, but tactically they were rather mistaken, and they were rather negligent in their job in this way, that if there is fear of any ambush, the group that makes progress does not move in groups; the group moves slowly; moves on foot and unfortunately, here, the whole lot was travelling in vehicle which was against standing orders as a result of which they lost their lives.

About giving wrong figures, we never try to conceal the figures; wherever it is necessary to give the figures, we have given the figures; here on the floor of the House there cannot be wrong figures, because, we can be held up for giving wrong figures.

Dr. Karni Singh: The hon. Minister just mentioned that the Mizos have denied any help being received from China and Pakistan. I would like to know if the Minister is absolutely certain that no help is received by the Mizos from China and Pakistan, both for arms and ammunition for their military training, and also whether there is hand of any east European country behind this?

Shri Y. B. Chavan: I think you have misunderstood what I said.

Dr. Karni Singh: I mean the Deputy Minister.

Shri Y. B. Chavan: We never denied it; Pakistan is giving aid to them and those people are getting arms, etc., from Pakistan. We have said that many times.

Dr. Karni Singh: The hon. Minister mentioned that the Mizos have denied having received any help.

Shri Vidya Charan Shukla: It is not that the Mizos have denied it. I said Pakistan has denied that they have given any arms to the Mizos. I am sorry.

Dr. Karni Singh: Then the question has not been answered. My question about any east European countries in this matter has not been answered.

Mr. Speaker: It is about any aid being given by east European countries.

Shri Vidya Charan Shukla: No, Sir.

Shri Ranjit Singh: Since 1949 onwards up to the present time, since the time of the cease-fire in Kashmir, the army authorities have been recommending that the only way to stop ingress and egress at the borders, of hostiles was to break the physical contact of villagers from the borders, that is, to create a depopulated zone along the borders. We have throughout heard in this House that the country there is a very difficult country, that Nagaland is a close country, meaning in military terms, that it is overgrown with thick forests. So, what steps has the Government taken to create such a depopulated zone in order to break physical contact of the people there in the border and what considerations has the Government given on this recommendations of the security force?

Shri Vidya Charan Shukla: We are not dealing with Nagaland in this question. We are dealing with Mizo hostiles. As we have already stated, we have undertaken measures to recruit villagers along the Silchar-Aijal road, and that has proved successful.

Shri Ranga: He asked about the depopulated zone and whether any steps have been taken.

Shri Vidya Charan Shukla: We are dealing with the Mizos in this question.

Shri Kanwar Lal Gupta: Once you have allowed the question, he should answer the question.

Shri Vidya Charan Shukla: There was no proposal of that kind.

Shri Hem Barua: May I know if the attention of Government was drawn to a radio broadcast by Peking saying that the Mizo rebels have successfully revolted against the Indian Government, which means an encouragement to the Mizo rebels to rebel against the Government and which shows the diabolical hand of China behind this move? May I know if the Government have any knowledge of that broadcast and what steps Government have taken to see that the Chinese help is not allowed to create another problem for us in Mizoland, as has been created by the Pakistani help at present?

Shri Y. B. Chavan: Chinese are certainly interested in subverting India. We know that any trouble in Indian territory anywhere is an opportunity for them and they propagate about it. So far as this matter is concerned, there is no direct contact of the Chinese in the subversive activities with the Mizos. But the Chinese possibly might reach them through Pakistan. I am not eliminating that possibility. Therefore, what we have to take care is to see that Pakistan does not succeed in contacting the Mizos and helping them.

Shri Hem Barua: It is reported that Mizo hostiles go to Dacca in East Pakistan and there they meet the Chinese diplomats.

Shri H. N. Mukerjee: In view of the Home Minister's repeated statement in the House that problems like that of the Mizos have to be solved by persuasion and mutual understanding, because after all, in spite of their being hostile—many of them—they are our own people, may I know why it is that he is not examining the idea of the regrouping of villages, which, while it may bring us some advantages in the military operations against the hostiles, would alienate completely the sympathy of the local population, because that is what exactly happened in the case of Malaya and South Vietnam where the British and the Americans were trying to operate on that principle? May I know whether the minister will examine this matter and take steps which

would not alienate the sympathies of those Mizos who are not at present hostile?

Shri Y. B. Chavan: Before we give up this regrouping, we want to convince ourselves exactly as to what will happen. He himself said that I am emphasising on the political aspect and winning the cooperation of the local people is the most important factor. I find that although in the initial stages the regrouping of villages was resented and resisted by the local people because of certain inconveniences involved, they are coming round now.

Shri Hem Barua: They have welcomed it.

Shri Y. B. Chavan: I personally feel that this scheme should be given a fair trial. Before it is completed if it is given up, really speaking we are not learning anything. I do not want it for the sake of the scheme. We will work it but for some time and see what are the advantages and disadvantages. We are trying it for the first time with that determination in Mizoland. We started doing it in Nagaland and possibly we gave it up rather too early. I do not want to feel later on that we gave it up too early. If we want to give it up, it is much better we do so after a fair trial.

Shri N. R. Laskar: The Mizo hostiles do not confine themselves to the Mizo district. They have come right up to Cachar and the plains. There are so many incidents. I would like to know if Government have any definite programme so that at least the people in the plain districts may live peacefully on the border.

Shri Y. B. Chavan: Naturally sometimes they do come down to the plains in their violent activities and sometimes they loot some villages. The only thing that can be done is to tighten the protection arrangements in the plains possibly with the help of the local leaders and allowing the people also to organise themselves in a better way.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मिजो पहाड़ियों में जो यह विद्रोही लोग कार्य कर रहे हैं इन को पाकिस्तान से सहायता मिलती है, अभी कुछ दिन पहले बताया गया था कि जो नागा विद्रोही कार्य कर रहे हैं उनको भी पाकिस्तान से सहायता मिलती है, इसी प्रकार आसाम और पश्चिमी बंगाल की सीमाओं पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन को भी वह सहायता देते हैं तो इन सब के प्रतिकार के सम्बन्ध में जब गृह मंत्रालय से पूछा जाता है तो वह यह कहते हैं कि हमने विरोध पत्र भेजा है, इस बार कुछ इसमें थोड़ी सी गति आई है, हमारे गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री ने बताया कि सो मैनी टाइम्स, यानी कई बार भेजा, तो मैं यह जानना चाहता हूं जो यह विरोध पत्र भेजे जा रहे हैं क्या हर बार की घटनाओं का पता लगने पर नये सिरे से विरोध पत्र तैयार किये जाते हैं या कोई साइक्लोस्टाइल कराकर रख रखा है ?

Mr. Speaker: No answer need be given.

Shri Kanwar Lal Gupta: Last serial number may be given.

Shri Samar Guha: May I know whether the hon. Minister is aware that very recently Pakistan has sent 200 Mizos and Kukis after giving them training in a camp situated in Sylhet and another camp situated in Cox Bazar near Chittagong under the leadership of Dem Khosai, and these 200 Mizos and Kukis have taken possession of a hill area called the southern hill area and started plundering there? May I know whether the Government is also aware that in these two training camps that Pakistan has established Chinese guerilla experts are being utilised for giving guerilla war training to the Naga hostiles and Mizo rebels?

Shri Vidya Charan Shukla: Actually, Sir, Pakistan has established more than two training camps for the Mizo hostiles. It is also a fact that recently a group of Mizo hostiles came back from Pakistan.

Mr. Speaker: What about the Chinese? He mentioned about Chinese giving them training.

Shri Vidya Charan Shukla: Some Chinese instructors were noticed in those two camps.

An hon. Member: What was done when they were noticed?

Mr. Speaker: Order, order. Let us go to the next question.

Anti-National Activities on Rajasthan Border

*336. **Dr. Karni Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently some people living in the border District of Barmer in Rajasthan have been indulging in anti-national activities in collusion with Pakistanis across the border; and

(b) if so, the steps taken to check these activities?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Dr. Karni Singh: Sir, I admire the hon. Minister for his brevity. May I know whether it has been brought to the attention of the hon. Minister that during the Indo-Pakistan war a twenty-mile belt of the border along Rajasthan and Pakistan was cleared of the fifth-column activity that was taking place, and whether this belt of area, what we might call as denazified area, still continue in the present form or have the infiltrators and fifth-columnists returned back?

Shri Vidya Charan Shukla: No, Sir. I do not know to whom the hon. Member refers as fifth-columnists, but some people who migrated to Pakistan during the hostilities did come back. They have been arrested and they are being prosecuted under the law by the Government of Rajasthan.

Dr. Karni Singh: Has it been brought to the attention of Government that during the Indo-Pakistan war the fifth-column which I referred to, and which had operated between India and Pakistan on the Rajasthan border were cleared by the Indian army at that time and they were allowed to come back because certain Ministers of Rajasthan whose constituencies were on the border did not allow the Central Government to see that these fifth-columnists were kept out?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): May I say, Sir, that these questions are loaded questions.

Shri Surendranath Dwivedy: You must take the load of the Member also into consideration.

Shri Y. B. Chavan: In order to take it I must say that it is loaded. It is not a fact that the whole area was full of fifth-columnists. To say like that would be a wrong thing. There was no question of the area being cleared. Certainly, as it happens in the border area, sometimes the population migrates to both sides, and it happened here also. Some Muslim population did go to the other side. I am not prepared to accept the position that the entire Muslim population are fifth-columnists.

Dr. Karni Singh: I never insinuated them. Sir, I stand to correction. I only said "certain fifth-columnists". I did not say whether they are Hindus or Muslims.

Shri Y. B. Chavan: I am making my point clear and when I make my point clear the hon. Member does not like it. The hon. Member himself said in a vague manner that everybody who went to the other side were fifth-columnists. It is not true. Certain people did go to the other side,

some of them came back and those who are suspected among them are being proceeded against.

Dr. Karni Singh: The fifth columnists are functioning within the country. They are not going to Pakistan.

Shri S. S. Kothari: May I know whether the Government will deal firmly with traitors and saboteurs who are indulging in anti-national activity in collusion with Pakistan instead of showing a soft, fatherly and vegetarian attitude towards them?

Shri Y. B. Chavan: The Government is a responsible body and it normally takes a firm attitude. But in order to be firm one has to be reasonable also. But I do not see why hon. Members should feel....

Shri S. S. Kothari: I was referring to traitors and saboteurs.

Shri Y. B. Chavan: With that type of people Government has always been and will be firm.

Shri Hem Barua: Sir, the word 'vegetarian' should be expunged because it is an insinuation that vegetarians are weak when in actual fact they are great fighters.

श्री तुलशी दास जाधव : राजस्थान के बार्डर पर या पाकिस्तान के बार्डर पर जो लोग रहते हैं उनकी कई दिक्कतें हैं पानी की दिक्कत है, रास्ते की दिक्कत है, मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हमले के बाद क्या इन दिक्कतों को दूर करने का प्रयत्न किया गया जिससे उन लोगों की तकलीफें दूर हों और उनका दिल जो पाकिस्तान की तरफ रहता है, वह उधर न जाय। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किया है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : उन के लिये उधर जाने के लिये सड़क बना दी है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कोशिश की जा रही है।

Shri E. K. Nayanar: There are newspaper reports that peace corps volunteers working in Rajasthan are giving secret reports to Pakistan. May I know whether this is correct? As it is dangerous to the security of India in the borders of India may I know whether Government have taken any precautions against the peace corps volunteers?

Shri Vidya Charan Shukla: We are not aware of such a report.

श्री पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, जिस समय पाकिस्तान का हमला हुआ था उस समय हमने इस बात की प्रार्थना की थी कि कुछ ऐसे परिवार हैं राजस्थान के बार्डर पर, जो न केवल पाकिस्तान के पिछले हमले के समय, बल्कि रन आफ़ कच्छ के समय भी पाकिस्तान चले जाते रहे हैं तथा बाद में वे वापस आ जाते हैं। हमने मांग की थी कि ऐसे परिवारों को जिनके बारे में सन्देह स्पष्ट हो चुका है, उनको वापस न आने दिया जाय। लेकिन हमने सुना है कि उन में से कुछ फिर वापस आ गये हैं। हम को यह आश्वासन दिया गया था कि इसी प्रकार का कानून बना दिया जायेगा ताकि इस तरह से उनका आना जाना रोक दिया जाय। क्या उनका भविष्य में आना जाना बना रहेगा, या इस सम्बन्ध में कोई रोक थाम की जायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस तरह के परिवार जिनके बारे में शक था, उन को रोकने का प्रयत्न किया गया। लेकिन जो प्रयत्न के बावजूद भी आ गये, उन के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है और कानून के अनुसार उनको सजा दी जायेगी।

श्री अब्दुल गनी डार : क्या वजीर साहब फरमायेंगे कि राजा साहब ने जो सवाल किया कि कुछ लोग फिफ्थ-काल मनिस्ट्स थे, उन को हमारी फौजों ने दूसरी तरफ धकेल दिया था, लेकिन अब वह फिर आ

गई हैं—क्या उनको धकेलने से पहले उनके फिफ्थ-कालमनिस्ट होने के बारे में कोई जांच पड़ताल हुई थी। अगर हुई थी तो उन को उधर धकेलने के बजाय जेलों में में क्यों नहीं धकेला गया ? दूसरा सवाल यह है कि अगर उनका मुसलमान होना जुर्म है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जितने मुसलमान बार्डर पर बैठे हैं—आसाम से लेकर कच्छ बार्डर तक, उन सबको वहां से हटा कर किसी अच्छी जगह पर, जहां ये भाई चाहें उनको आबाद कर दिया जाय, ताकि वे फिफ्थ-कालमनिस्ट न बन सकें ? क्या सरकार ऐसा कोई न्याय मुसलमानों के साथ करेगी ?

[کیا وزیر صاحب فرمائینگے کہ راجہ صاحب نے جو سوال کیا کہ کچھ لوگ ففتھ کالمنسٹ تھے انکو ہماری فوجوں نے دوسری طرف دھکیل دیا تھا لیکن اب وہ پھر آگئی ہیں - کیا ان کو دھکیلنے سے پہلے ان کے ففتھ کالمنسٹ ہونے کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال ہوئی تھی - اگر ہوئی تھی تو ان کو ادھر دھکیلنے کے بجائے جیلوں میں کیوں نہیں دھکیلا گیا - دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اُنکا مسلمان ہونا جرم ہے تو کیا سرکار اس بات پر وچار کریگی کہ جتنے مسلمان بارڈر پر بیٹھے ہیں - آسام سے لیکر کچھ بارڈر تک - ان سب کو وہاں سے ہٹا کر کسی اچھی جگہ پر جہاں یہ بھائی چاہیں ان کو آباد کر دیا جائے تاکہ وے ففتھ کالمنسٹ نہ بن سکیں - کہ کوئی نہائے مسلمانوں کے ساتھ کریگی -]

Shri Y. B. Chavan: I would like to make it clear that nobody has suggested that army pushed out any people. It is not a fact. Army has not pushed out any people from this side or that side. When the conflict started, out of fear, out of a sense of a place of protection they naturally moved. Some people came to this side and some people went to the other side. So, there was no question of Army deciding who were fifth-columnists or who were not fifth-columnists because they had not pushed out any people. Secondly, that is not the suggestion of the hon. Member who put the question or the one who answered the question and I want to make it clear, even though by implication he meant that, there is no question of removing them from the border. (*Interruption*).

Dr. Karni Singh: On a point of clarification . . . (*Interruption*).

Mr. Speaker: He has not answered your question now.

Dr. Karni Singh: I think, he misunderstood it. I rise on a personal explanation.

Mr. Speaker: It does not arise now.

Dr. Karni Singh: The hon. Member there referred to Muslims——(*Interruption*). t had nothing to do with Muslims. The fifth columnist is an expression which is understood.... (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order. I would request both of you to sit down. The whole House has understood it.

Dr. Karni Singh: That has nothing to do with Muslims.....

Shri Abdul Ghani Dar: Mr. Speaker, Sir,....

Mr. Speaker: No please.

Shri Bal Raj Madhok: In view of the fact that Indo-Pakistan border in the west has become alive and in view of the fact that we cannot afford to take risk or chance where country's security is involved and also in view of the lesson of the last war when certain things happened on the border, certain fifth columnists helped the enemy, may I know whether Government is considering the suggestion

made by the Security authorities that a depopulated zone be created on the border to eliminate physical contact between the fifth-columnists here and on the other side so that in future infiltration may not take place and in case of war, Pakistan may not have that facility which she had last time.

Shri Y. B. Chavan: I think, the whole thing is being looked at in a rather wrong perspective. There cannot be a completely depopulated zone all along the border. It is an impossible thing to conceive of. In certain strategic areas, it is in the interest of the population themselves to remove them. Certain suggestions were made but I do not propose to discuss them. (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Order, order. All of you may kindly sit down.

Neither the questioner gave a communal colour nor the Minister gave a communal colour to it. Fifth columnist does not mean Hindu or Muslim or Parsi. Why give a communal colour to it? This is very unfortunate.

श्री अब्दुल गनी डार : आये दिन सवाल होते हैं कि मुसलमान फिफ्थ कौलिमिस्टस हैं और उसका नतीजा यही है कि हजारों मुसलमानों को बिना मुकद्दमा चलाये बेगुनाह कैद में डाल दिया जाता है । अब पकड़े तो मुसलमान ही जाते हैं.....

[آئے دن سوال ہوتے ہیں کہ مسلمان
ففتھ ء کالمسٹس ہیں اور اس کا
نتیجہ یہی ہے کہ ہزاروں مسلمانوں
کو بلا مقدمہ چلائے بیگناہ قید میں
ڈال دیا جاتا ہے - اب پکڑے تو
مسلمان ہی جاتے ہیں . . . .]

Mr. Speaker: Order, order. We go to the next question.

Shri Badrudduja: When the Maharaja Karni Singh referred to fifth columnists did he mean those thousands of Muslims who were put behind the prison bars during the Indo-Pakistan conflict? Did he mean that those were also fifth-columnists? I can appreciate the stand of the hon. Minister; he may not make a distinction between one community and the other. Does the Maharaja refer to those thousands of innocent Muslims, who for no rhyme or reason, who were put behind the prison bars during the Indo-Pakistan conflict? Let them have courage to appear before the court of justice.... (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Order, order.

Dr. Karni Singh: On a point of personal explanation, Sir . . . (*Interruption*). There is no question of any community; it may be any community.

Shri Bal Raj Madhok: Why is this communal propaganda being carried on? (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Order, order. The Minister has categorically said that there is absolutely no communal colour to it. You have said that; the Minister has said that. I do not know why there is any misunderstanding. (*Interruption*). Let us go to the next question.

Shri Jyotirmoy Basu: 750 Muslims were put behind the bar . . . (*Interruption*).

Mr. Speaker: Again, you are adding fuel to the fire . . . (*Interruption*). Order, order. Shri Ram Sewak Yadav.

श्री राम सेवक यादव : बाड़मेर सीमा पर खास तौर पर तस्करी होती है और उस तस्करी में हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल रहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि युद्ध के समय जो लोग इधर से उधर जाते थे जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल थे खास तौर से वहां की समितियों के अध्यक्ष, प्रधान, पंच और सरपंच जो वहां गये उस समय खबर छपी थी कि उन्हें वापिस आने दिया गया है तो दरअसल हकीकत क्या है ? क्या यह वहीं पर रह रहे हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल: मैं ने इस के बारे में कहा कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में चले गये थे उन को इधर फिर लौटने से रोका गया है लेकिन जो लोग इस पर भी इधर आ गये हैं उन पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है।

श्री प० ला० बारूपाल: मैं देखता हूं कि सदन में जब भी मुसलमानों का सवाल आता है, इधर, उधर के सब लोग एक हो जाते हैं और हिन्दुओं की नीयत में शक करते हैं और उन पर तरह तरह के इलजाम लगाये जाते हैं लेकिन उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए और इस सरकार पर उन्हें विश्वास होना चाहिए जिसमें देश का राष्ट्रपति मुसलमान है और इस तरीके से श्री अब्दुल ग़नी दार और श्री बदरुद्दुजा ने जो यह कहा है .... (व्यवधान)

Mr. Speaker: No, no. Order, order. Next Question.

Pak. Infiltration

\+

*337. **Shri D. N. Patodia:**
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Ram Singh Ayarwal:
Shri Kanwar Lal Gupta:
Shrimati Tarkeshwari Sinha:
Shri Sharda Nand:
Shri Bharat Singh Chauhan:
Shri Ranjit Singh:
Shri R. S. Vidyarthi:
Shri S. C. Samanta:
Shri A. K. Kisku:
Shri S. N. Maiti:
Shri Tridib Kumar Chaudhuri:
Shri Yashpal Singh:
Shri R. Barua:
Shri Chintamani Panigrahi:
Shri G. S. Mishra:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the infiltration of Pakistani nationals in the border States continues unabated;

(b) whether Government have made any assessment of the Pakistani infiltrators across the borders during the last three months; and

(c) if so, the number of infiltrators and the steps taken to prevent further infiltration?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir. The infiltration is now on the decrease.

(b) and (c). The number of infiltrators was 998 during the three months ending April, 1967. Border patrolling has been intensified and greater vigilance is maintained by the border outpost staff.

Shri D. N. Patodia: In a statement issued by Mr. Chaliha, Chief Minister of Assam, on 1st April 1967, he has mentioned....

Mr. Speaker: Order, order. There is so much of noise. We have gone to the next question. That controversy cannot continue like this. The other members also must have a chance of putting questions and getting answers. We cannot have discussions like this. It is not proper.

Mr. Patodia.

Shri D. N. Patodia: The Chief Minister of Assam stated on 1st April 1967 that there were still 75,000 infiltrators in the State of Assam alone. Over the past several years we have been taking several steps, we have been giving various assurances that something effective will be done, but it appears that the Government is not capable of taking any effective steps. These persons, in the shape of infiltrators, are coming to our borders, they spy all over the country, try to brainwash the people on the borders and, in fact, they create panic in the country. What effective steps does the hon. Minister propose to take now in view of the fact that the steps taken in the past were ineffective?

Shri Vidya Charan Shukla: It is not correct to say that effective steps have

not been taken. As I have given the figure, the infiltration has been checked and it is on the decrease. We are continuously watching the situation and if any additional measures are necessary, we shall definitely take them to further put a stop to it.

Shri D. N. Patodia: Even today the total number of infiltrators is near about 75,000 in the State of Assam alone. These infiltrators cause lot of difficulties in Nagaland and Mizo Hills also.

Shri Vidya Charan Shukla: A certain number of infiltrators are still there, but we are making every attempt to send them back to Pakistan.

Shri D. N. Patodia: What is the number?

Shri Vidya Charan Shukla: I will require notice for it.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या असम के अतिरिक्त भी राजस्थान और पश्चिमी बंगाल की सीमाओं पर इस प्रकार की कुछ घटनाएं भारत सरकार को पता लगी हैं। यदि पता लगा है तो उनकी अपनी संख्या कितनी है और इसको रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि माननीय सदस्य इसके बारे में अलग से सूचना दें तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह तो सारी सीमाओं के लिये है किसी प्रदेश विशेष के लिये यह प्रश्न नहीं है।

Mr. Speaker: He has no information.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : भारत पाक युद्ध के समय में लगभग 50,000 लोग पूंछ राजोरी सीमा के क्षेत्र से पाकिस्तान चले गये थे केन्द्रीय सरकार ने यह विश्वास दिलाया था कि इनको वापिस नहीं लिया जायेगा इतना कहने के बाद भी वह जब फिर इधर वापिस आगये और इस ओर ध्यान भी आकृष्ट कराया तब भी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): It is a fact that large number of people who had crossed over to Pakistan are coming back; most of the families are trying to come back to their lands and homes. But it is rather difficult to take any very effective steps to stop those families from coming over; when women and children start coming back in such numbers, it is rather difficult to stop them. But the suspected among them are being proceeded against legally.

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमें अलग से नोटिस दी जाये तो वह बतला सकते हैं। परन्तु जो प्रश्न पूछा गया है उस में ही यह पूछा गया है कि कितने पाकिस्तानी घुसपैठिये भारत में आये हैं पिछले तीन महीनों में यह संख्या हमको बतलाई जाये।

Shri Y. B. Chavan: Particularly in regard to Assam, I require notice, because unfortunately I have not got that information with me just now.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस प्रश्न में साफ कहा गया है कि यह सिर्फ असम के बारे में नहीं है। पूरी सीमा के बारे में है। पूरी सीमा में तीन महीनों में कितने घुसपैठिये आये भारत में। मंत्री महोदय ने प्रश्न देखा नहीं है और उत्तर दे रहे हैं। अगर वह प्रश्न पढ़ें तो उनको मालूम होगा कि उस में क्या लिखा हुआ है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं पढ़कर बतला रहा हूं।

Mr. Speaker: Now, the Question Hour is over. Short Notice Question.

Shri Kanwar Lal Gupta: I want to ask a question....

Mr. Speaker: I am sorry. We have to take up the Short Notice Question now.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, हमको जो प्रश्न साफ पूछा गया है उसका उत्तर तो दिलवाया जाये।

Mr. Speaker: I think the hon. Minister has no reply to it just now.

SHORT NOTICE QUESTIONS

Supply of paddy seeds to Bihar

S.N.Q. 8. Shri Beni Shankar Sharma:
Shri M. L. Sondhi:
Shri N. S. Sharma:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Shri Chand Goel:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Kameshwar Singh:
Shri A. Sreedharan:
Shri Shiva Chandra Jha:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of paddy seeds in tonnes asked for by the Bihar Government from the Central Government;

(b) the quantity of paddy seeds in tonnes supplied to them so far and the quantity which is yet to be supplied; and

(c) whether immediate arrangements are being made to supply them the remaining quantity of paddy seeds?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The Bihar Government had originally asked the Central Government to arrange for the supply of 25,000 tonnes of paddy seeds from outside the State for sowings during Kharif 67. Subsequently, the State Government reviewed the position and raised their minimum requirements of paddy seeds from outside the State to 61,000 tonnes.

(b) The quantities of paddy seeds allocated to Bihar from various States and the quantities moved till 2nd June, 1967 are as under:—

State	Quantity allocated (in tonnes)	Quantity despatched (in tonnes)
1. Andhra Pradesh	31,000	27,179
2. Orissa	20,000	3,261
3. Madras	2,000	458 (upto 31-5-67)
4. Punjab	846	..
5. West Bengal	5,000	900
6. Mysore	2,000	..
TOTAL	60,846	31,798

In addition to above, Bihar Government are also procuring paddy seeds in the bordering districts of Nepal and hope to get about 5,000 tonnes. The National Seeds Corporation is also supplying 3,000 tonnes of Taichung Native-I paddy seeds from its special production programme in Andhra Pradesh.

(c) All possible assistance is being rendered to the Government of Bihar in procurement and movement of paddy seeds from the various States by the Government of India and the State Government concerned. Several teams of technical personnel have been sent by the Bihar Government to different States to ensure the quality of the seed and every effort is being made to speed up despatches, so that the seed reaches in time for sowings.

श्री बेणी शंकर शर्मा : बिहार में जो सूखा पड़ा है और उससे जो सैकड़ों लोग आज मर रहे हैं उसके सम्बन्ध में यहां सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। अब हमारी आशा केवल आगामी फसल पर केन्द्रित है। बिहार सरकार ने आगामी फसल के लिये केन्द्र से 60 हजार टन धान के बीज भेजने की मांग की थी। जो स्टेटमेंट माननीय मंत्री महोदय ने सदन पटल पर रखा है उस से मालूम होता है कि 2 जून तक उन्होंने कुल 31,798 टन धान के बीज के भेजने की व्यवस्था की है। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि यह धान का बीज बिहार पहुंच गया है या नहीं....

Mr. Speaker: The hon. Member should put his question now, because this is a question.

श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि धान के बीज के रोपने का समय रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र में वह बोया जाता है और रोहिणी नक्षत्र बीत रहा है उस से पहले वह बीज पहुंचना चाहिए था। अगर वह जानते हैं तो बाकी बीज कब तक पहुंचेगा?

Shri Annasahib Shinde: As already mentioned in the statement, about 31,798 tonnes of paddy seed have actually been despatched to Bihar. The Bihar Government officials are actually in Orissa and Andhra Pradesh and they are co-ordinating the activities.

Moreover, I must take this opportunity to say that the Andhra Pradesh and Orissa Governments have co-operated with us so well and they have tried their level best to see that Bihar gets adequate supplies of seed; the despatches of seed from Andhra Pradesh have been so quick that it is really a commendable thing that they have done.

As far as Orissa is concerned, some difficulty arose not because the Orissa Government were not prepared to supply it, but because the Bihar Government officers had first checked up the seed and when it was brought to the loading stations, some of the Bihar Government officials had rejected the seed. That is why the difficulty has arisen. Now, the Bihar Government have deputed some senior officials, and the Orissa Government are trying to expedite the movement.

Mr. Speaker: Shri B. S. Sharma.

Shri Thirumala Rao: What is the quantity of seed supplied by the Andhra Pradesh Government to Bihar?

Shri Annasahib Shinde: Say, about 27,000 tonnes.

Mr. Speaker: The hon. Minister should not answer the question across the Table. I have called Shri B. S. Sharma.

श्री बेणी शंकर शर्मा : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह कोई समय निर्धारित करके बतला सकते हैं कि धान के बीज कब तक पहुंचेंगे? आज समय हमारे विरुद्ध चल रहा है। अगर एक हफ्ते के भीतर धान का बीज नहीं मिलता है और खेतों में पानी पड़ जाता है तो धान रोपा नहीं जा सकेगा, और फिर वही अवस्था लोगों के सामने आयेगी जिससे हम त्राहि त्राहि कर रहे हैं। इस लिये क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकेंगे कि वह एक हफ्ते के भीतर धान का बीज बिहार में पहुंचा सकेंगे।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी हां इस संबंध में हम लोग भी समझते हैं कि जितनी जल्दी बीज वहां पहुंच जाये उतना ही अच्छा होगा और इसी लिये कई एक राज्य सरकारों से अनुनय विनय करके उन्हें तैयार किया गया कि व वहां के लिये बीज

दें । और जैसा मंत्री महोदय ने बतलाया है आंध्र गवर्नमेंट और उड़ीसा सरकार ने इस मामले में हमारी बहुत सहायता की है । मैं इस मौके पर उनको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार के इस गाढ़ मौके पर अपनी कठिनाइयों के बावजूद भी इतनी तत्परता से धान का बीज देना स्वीकार किया । कठिनाई इस में यह आई कि जब हम राज्य सरकारों से बात कर लेते हैं तब बिहार सरकार से कहते हैं कि वह जल्दी से जल्दी अपने अफसरों को भज दें कि जा कर वहां से बीज भिजवाने का प्रबन्ध करें ।

यह भी ध्यान रखना चाहिये सदन को कि जो धान मिल रहा है वह बीज के लिये रक्खा हुआ ही धान नहीं था । बहुत से स्थानों पर वह खाने के लिये भी रक्खा हुआ धान भी था । वसे धान से यह आशा करना कि जितना बीज का धान पौध निकालता है उतना ही इस से निकलेगा यह ठीक नहीं है । इस में बिहार सरकार के अफसरों की गलती हो सकती है हो सकता है कि उन को अपने लिये डर लगा हो कि उड़ीसा से जो बीज दिलवाया गया था उस से 80 या 85 फीसदी पौधे न उगते हों जो कि आम तौर से उगने चाहिये उसमें 70 या 75 फीसदी ही उगते हों और इस लिये उन्होंने उस को स्वीकार कर लिया जिससे यह कठिनाई आ गई । वहां से 20 हजार टन मिलना है ; अभी जो नया धान आया है वह 15 जून तक वहां आ जायेगा ।

Mr. Speaker: The hon. Minister has explained the whole policy; I hope supplementaries should be few now.

Shri M. L. Sondhi: I would also preface my question by paying a tribute to the people of Andhra who are providing foodgrains to the rest of the country. You, Sir, also come from Andhra, we all pay a tribute to the people of Andhra.

Mr. Speaker: Thank you.

Shri M. L. Sondhi: I would ask whether the Minister has personal awareness that hundreds of people have lost their lives in Bihar, that Bihar has become a shame for us in the world. In that context, is he seriously considering any proposal to restore confidence in Bihar? As far as I can see, he must come out with some proposal to subsidise the farmers there. Will the Centre be prepared to be generous as far as seeds are concerned? Would he agree to depute people from the Indian Council of Agricultural Research to see whether they can help select quality seeds, special draught-resistant varieties? Can we have an assurance that there is a sense of urgency on the part of the hon. Food Minister?

Shri Jagjivan Ram: I do not think eloquence can bring a sense of urgency. Perhaps the hon. Member is not ware of the many forms of assistance that the cultivators do get. So far as the supply of seeds and fertilisers is concerned, there are arrangements for provision of loans and subsidy to the cultivator. As regards the question of price, it is entirely for the Bihar Government to fix the price they think the cultivator will be in a position to pay or supply them as loan or subsidy. There is no bar to that. All these provisions have been made and if the hon. Member had cared to know about the arrangements made for all these matters, about which reports have been circulated, perhaps he would not have felt the need to ask this question.

श्री ना० स्व० शर्मा : प्रान्ती यसर - कारों ने माननीय मंत्री जी की बात मान ली है यह बहुत प्रशंसा की बात है, परन्तु अब तक केवल ३१ हजार टन, यानी जितना मांगा गया था उससे आधा ही, बीज वहां

पहुंच पाया है । क्या मंत्री जी कोई इस बात का आश्वासन देंगे कि बाकी बीज वहां कब तक पहुंचेगा ?

श्री जगजीवन राम : जो कुछ मैंने अभी कहा है, उसके अतिरिक्त कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Shri Chand Goel: Considering that the sowing season for paddy is on and there is hardly a fortnight left, can we have an assurance from the Food Minister that the rest of the supply of 30,000 tonnes of paddy seeds would actually arrive and Government would facilitate its reaching the areas where it is needed as otherwise it will become useless?

Shri Jagjivan Ram: I do not think we are responsible for reaching seed to the areas which it has to reach. I think if the hon. Member had listened to what I had said in Hindi, he would not have put the question again. As I have said, it is the responsibility of the Bihar Government also to see that once the seed has been located in a particular State and the State Government has offered to supply the seed, the officers of the Bihar State who are there will expedite the testing of the seed and also the despatches. As I have said, there have been delays in despatches of seed from Orissa on account of the lapses of the officers of the Bihar Government, and as I have further assured, we have every expectation that by the 15th of this month the requisite quantity of seed will be available in Bihar.

श्री विभूति मिश्र : इसमें यह लिखा हुआ है कि बिहार सरकार नेपाल के तटवर्ती जिलों से धान के बीज प्राप्त कर रही है और पांच हजार टन इस तरह से प्राप्त हो जायेगा । यह धान चम्पारन हो या मुजफफरपुर हो वहां से खरीदा जा रहा है । इन स्थानों के नाम न लिख कर नेपाल के तटवर्ती जिले लिख दिया गया है । यहां पर दो लाख एकड़ भूमि में धान की खेती होती है । वहां से बिहार सरकार 42 रुपये से लेकर 53 रुपये मन तक के भाव से बीज खरीद रही है । किसी किसान ने अगर एक बीघा भूमि में धान की खेती की है तो उसके पास एक डेढ़ मन से अधिक धान नहीं है, और दूसरा धान उसने अपने खाने के लिये रक्खा हुआ है । सरकार उस को बीज के तौर पर ले रही है । मैं जानना चाहता हूं कि जो आपका टेक्नीकल स्टाफ है, जो सेंटर का टेक्नीकल स्टाफ है या जो स्टाफ पैडी के बारे में रिसर्च करता है, उस को भेजकर इस बात की जांच सरकार करवायेगी कि किसान को जो बीज मिले सही बीज मिले और ऐसा बीज मिले कि जो उसके खेत में जा कर जमे ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का कोई प्रबन्ध सरकार कर रही है । मैं यह भी चाहता हूं कि जिन किसानों को यह बीज दिया जाए अगर उनके खेत में ठीक से यह जमे, तब तो चाहे सबसिडी में दें या लोन पर दें, लेकिन उसके साथ साथ गारंटी इसके बारे में पूरी पूरी करें । यदि वह बीज न जमे तो सरकार उन से पैसा न ले । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार का इस ओर ध्यान खींचा है ? यदि खींचा है तो बिहार सरकार की क्या प्रतिक्रिया इसके सम्बन्ध में है ?

श्री जगजीवन राम : यह बात सही है कि नेपाल से भी पांच हजार टन लेने की बात थी । बिहार सरकार बिहार के भीतर जहां पर धान हुआ है और जहां पर बीज उपलब्ध है वहां से भी बीज ले रही है । उनका अपना ख्याल था कि तीस हजार टन बिहार में भी मिलेगा । जहां जहां से भी बिहार सरकार के लिए बीज उपलब्ध किया गया है

उस बीज की जांच पड़ताल करने के लिए बिहार के कृषि विभाग के पास सही तरह के एक्सपर्ट्स हैं और ऐसी आशा की जाती है कि किसानों को जो बीज बिहार सरकार देगी समझ बूझ कर देगी और इसको देख कर देगी कि उनको उगने लायक बीज दिया जा रहा है। सदस्यों को समझ लेना चाहिये कि हर बात को जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार ले ले यह हमारे लिए सम्भव नहीं है। इस तरह से हमारे लिये काम करना सम्भव नहीं होगा। हर प्रान्त में और हर खेत में जा कर हमारे अफसर देखें कि बीज निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, इसको देखना हमारे लिए सम्भव नहीं है। मैंने कह दिया है कि किसानों को जो बीज दिया जाए वह कुछ को तो दाम ले कर दिया जाए, कुछ को लोन पर और कुछ को मुफ्त में देने की व्यवस्था होनी चाहिये, किसानों की अवस्था को देख कर बीज देने की व्यवस्था होनी चाहिये। यह सब जो काम है यह बिहार सरकार को करना होगा। हम यहां से नहीं कर सकते हैं।

श्री क० ना० तिवारी : मैं समझता हूं कि जो पैडी सीड सप्लाई किया जाएगा वह जहां पर दुर्भिक्ष है, उन इलाकों के किसानों को सप्लाई किया जाएगा। आप तीन हजार मीट्रिक टन ताइचुंग नेटिव 1 धान का बीज सप्लाई करने जा रहे हैं। इस बीज को देते वक्त क्या सरकार इस बात का ख्याल रखेगी कि यह सीड केवल उन्हीं स्थानों के किसानों को दिया जाए जहां पर पानी का अच्छा प्रबन्ध हो क्योंकि इस बीज के लिए पानी का दिया जाना बहुत जरूरी है। जहां पर दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है वहां पर पानी का इंतजाम नहीं है। वहां पर इस बीज को नहीं दिया जाना चाहिये। क्या टैक्नीकल एडवाइस ले कर इस बीज को दिया जाएगा और क्या बिहार सरकार को कह दिया गया है कि जहां पानी का इंतजाम है वहीं पर इस सीड को दिया जाए और कम पानी जिस बीज के लिये आवश्यक होता है उस बीज को इन क्षेत्रों में ला कर दिया जाए? मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए भी आपने क्या कोई व्यवस्था की है?

श्री जगजीवन राम : ऐसी आशा की जाती है कि बिहार सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों को इस तरह की साधारण बातों की जानकारी है और वे इन बातों का ज्ञान रखते हैं। ताइचुंग पैंडो का बीज वे उन्हीं जगहों पर भेजेंगे जहां इसके उगाने का प्रबन्ध हो, ऐसी उनसे आशा की जाती है। इन सारी विस्तार से की जाने वाली बातों की जिम्मेवारी हम लें, यह हमारे लिए सम्भव नहीं है और हम इनको लेना भी नहीं चाहते हैं।

श्री कामेश्वर सिंह : रोज़ कितने टन बीज बिहार को दिया जा रहा है? अभी आपने कहा है कि पंद्रह तारीख तक सब बीज वहां पहुंच जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितना बीज रोजाना बिहार को डिसपैच होता है?

श्री जगजीवन राम : इसकी जानकारी जो बिहार सरकार के वहां अफसर हैं उनको होगी हमारे पास यह जानकारी नहीं है। सूचना मिलने पर हम यह जानकारी आपको दे सकते हैं।

श्री कामेश्वर सिंह : अगर यह वक्त पर नहीं पहुंचा तो इस सब की जिम्मेदारी आप पर होगी. . . (**इंटरप्शंज**)

श्री जगजीवन राम : मैं इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने बता दिया है बिहार सरकार को कि फलां फलां स्टेट्स से बिहार सरकार कृपा करके इतने इतने टन धान जो वे दे रही हैं, अपने अफसरों को भेज कर मंगवा ले और उसकी जांच करवा कर जल्दी से जल्दी बिहार में इस बीज के भिजवाने का प्रबन्ध कर ले।

श्री कामेश्वर सिंह : आप तो अकाल मंत्री हैं.....(इंटरप्शंज)

Shri Hem Barua: May I know if the attention of the Government had been drawn to the fact that the displaced, disinherited and discarded ministers of the last Bihar Government, that is, the defeated Bihar Government, have organised a demand called the "Demand seed day" and if so, may I know whether this is a day against the Union Government for its filure to supply seeds in time to the State of Bihar?

Shri Jagjivan Ram: There had been no failure on the part of the Central Government to do what is possible for the supply of seed.

श्री द्वा० ना० तिवारी : हम लोग कृषि मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने इसके बारे में प्रबन्ध किया है। लेकिन एक बात सन्देहात्मक है। आंध्र से और उड़ीसा इत्यादि से यह बीज रेल गाड़ियों से बिहार में जाएगा। जो बीज वहां उपलब्ध है वह ठीक समय पर वहां पहुंचे इसके लिए बहुत जरूरी है कि समय पर रेल गाड़ियां मिलें ताकि बीज की सप्लाई का तांता न टूटे और सीड को पहुंचने में देर न लगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस का भी प्रबन्ध माननीय मंत्री जी ने कुछ किया है ?

श्री जगजीवन राम : इस सम्बन्ध में रेलों से जितना सहयोग मिलना चाहिये, मिल रहा है। वहां जो बिहार सरकार के अधिकारी हैं और हमारे अधिकारी हैं और रेलवे के अधिकारी हैं वे सब मिल कर एक प्रोग्राम बना लेते हैं कि किस तरह से उसको भेजा जाए और कितनी वैगंज में भेजा जाए।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मंत्री महोदय स्वयं बिहार गए थे। वहां बीज जो आया भी है उसको खरीदने की शक्ति लोगों के पास नहीं है, क्रय शक्ति उनके पास नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं जानना चाहती हूं कि अभी बीज उनको कर्ज के रूप में दिया जाए, क्या सरकार इसके बारे में कोई कदम उठा रही है ? खास तौर पर जो क्षेत्र अकाल क्षेत्र घोषित हो चुके हैं और वहां लोग बीज खरीद नहीं सकते हैं, उनके पास साधन नहीं हैं, उनको कर्ज के रुप में बीज दिया जाए और पीछे वे उसका भुगतान कर सकें, क्या इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है ?

श्री जगजीवन राम : इस प्रकार की व्यवस्था है कि ऐसे किसानों को बीज के लिए या खाद के लिए शौर्ट टर्म लोन दिये जायें मैं नहीं समझता हूं कि इस में कोई कठिनाई है।

श्री भोगेन्द्र झा : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि बिहार सरकार के अधिकारियों ने उड़ीसा में जा कर बीज लेने से इन्कार कर दिया है। बिहार सरकार ने बीज की मांग की थी और बीज अलग अलग किस्म का होता है, धान की अलग अलग किस्में होती हैं। क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जो अधिकारी वहां गए थे उन्हें किसानों से इसको खरीदने को कहा गया ? साथ ही जो बेचने के लिए था उस में आठ दस किस्मों का धान मिला हुआ था। कोई एक महीना पहले पकने वाला था और कोई एक महीना बाद में पकने वाला था। क्या यही कारण नहीं है कि उनको बीज के वास्ते नहीं लिया गया ? चूंकि बीज की मांग हो रही है इसलिए क्या मंत्री महोदय भारत सरकार के खाद्य मंत्री की हैसियत से बीज का स्टाक रखते हैं या नहीं रखते ह, बीज के रूप में धान देने को तैयार हैं या नहीं हैं। कर्ज के रूप में बार बार इसको देने की बात यहां हो रही है। शायद मंत्री महोदय को मालूम होगा कि बिहार सरकार ने एलान कर दिया है कि एक भी पैसा देने की किसानों को जरूरत

नहीं है, कल बीज कर्ज के रूप में दिया जाएगा जो धान बीज के रूप में उनको आप दे रहे हैं उससे तो फसल बरबाद हो जाएगी । क्या आप बीज उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : मैं समझता हूं कि शायद इस सदन के सदस्यों को इतना ज्ञान है कि जब इतनी मिकदार में धान के बीज की आवश्यकता होगी, तो भिन्न भिन्न प्रान्तों के किसानों ने इतना बीज बना कर तो नहीं रखा । जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा है, जो धान हम इस समय ले रहे हैं, अधिकांश वह धान है, जो विभिन्न प्रान्तों के किसानों ने अपने खाने के लिए रखा है ।

श्री मधु लिमये : सरकार ने क्यों नहीं रखा ?

श्री जगजीवन राम : हम कहां से रखते ?

श्री मधु लिमये : वहां पर दो साल से अकाल की स्थिति है । सरकार को इस की व्यवस्था करनी चाहिए थी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि बीज का धान दो वर्ष तक नहीं रखा जा सकता ।

Shri P. Venkatasubbaiah: Instead of this confusion and duplication in the matter of supply of paddy seeds, may I know whether the hon. Minister can consider the possibility of entrusting this work to the National Seeds Corporation so that they may supply the seed and it will be then a uniform procedure? May I know whether he can make that arrangement?

Shri Jagjivan Ram: Even the Seeds Corporation cannot find the seeds in such large quantities. It is required in view of the emergency that has arisen there, and naturally, we had to arrange from different States whatever was available in the shape of paddy; this is not necessarily kept as seed but as paddy, and so certain defects will be noticeable in that.

Shri Chintamani Panigrahi: May I know whether the Minister is aware that after the rejection of the quantity of paddy seed, 25,000 tons of paddy seeds have again been negotiated with the Food Corporation of India to be purchased from the Orissa Government and, if so, whether the Orissa Government has agreed to this.

Shri Annasahib Shinde: I have already mentioned that Bihar Government has sent a senior official who is already there and I think arrangements would be made in the near future perhaps to transport that to Bihar.

Shri Chintamani Panigrahi: What about the quantity?

Shri Annasahib Shinde: 20,000 tons was indicated in the initial stage. That was to be supplied by the Orissa Government.

श्री तुलशी दास जाधव : बिहार में सीड की ग़र्ज बहुत ज्यादा है, लेकिन उस को जो क्वांटिटी एलोकेट की गई है, वह 60,846 टन है, जब कि डिसपैच किया गया है 31,798 टन । यह सीड एक ही टाइम पर बोया जाता है, लेकिन अभी तक केवल आधी मात्रा ही भेजी गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी सीड कब भेजा जायेगा ।

Mr. Speaker: It has been answered. Shri Madhu Limaye.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Taking up of Private employment by Retired I.C.S. Officers

*332. **Shri C. Janardhanan:**
Shri P. C. Adichan:
Shri Vasudevan Nair:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of former members of the Indian Civil Service who, on retirement, have taken service in foreign companies or companies having substantial foreign share-holding;

(b) the number of such ex-ICS officers normally residing in Delhi as representatives of these concerns; and

(c) whether any of these officers have been enlisted by Government as 'contactmen'?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The information is not available with the Government because retired officers are not required under the rules to furnish reports about their employment and employers or about their place of residence. Only when they wish to accept commercial employment within two years from the date of retirement are they required to obtain prior permission of Government.

(c) No. Sir.

Commission on Functions of Governors

*333. **Shri R. S. Vidyarthi:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up any Commission or Committee for the proper elucidation of the conventions implied in the Constitution relating to the functions of the Governors; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Tripartite Committee on Bonus

*338. **Shri K. Ramani:**
Shri Umanath:
Shri Mohammad Ismail:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the Tripartite Committee on Bonus has completed its work;

(b) if so, what has been its outcome; and

(c) if not, when the Committee is likely to submit its report to Government?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). A Bipartite Committee was constituted by the Standing Labour Committee on the 26th October, 1966 to consider various proposals and alternatives to meet the situation arising from the Supreme Court's judgement declaring certain sections of the Payment of Bonus Act, 1965, as constitutionally invalid. The Committee met twice, but could reach no agreement. The position was reported to the Standing Labour Committee on the 10th May, 1967.

Parliamentary Committee on Education

*339. **Shri Eswara Reddy:**
Shri N. R. Laskar:
Shri Shradhkar Supakar:
Shri Liladhar Kotoki:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Madhu Limaye:
Shri Mohan Swarup:
Shri Sharda Nand:
Shri J. B. Singh:
Shri Ranjit Singh:
Shri Shri Gopal Saboo:
Shrimati Jyotsna Chanda:
Shri C. K. Bhattacharyya:
Shri Vasudevan Nair:
Shri Indrajit Gupta:
Shri C. Janardhanan:
Shri S. C. Samanta:
Shri A. K. Kisku:
Shri S. N. Maiti:
Shri Tridib Kumar Chaudhuri:
Shri Yashpal Singh:

Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri R. Barua:
Shri Y. A. Prasad:
Shri N. K. Sanghi:
Shri D. N. Patodia:
Shri C. C. Desai:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the Committee of Members of Parliament on Education has submitted its report;

(b) if so, the main recommendations contained in the report;

(c) whether Government have examined these recommendations; and

(d) if so, the decisions taken thereon?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

Hindi-knowing Employees

***340. Shri Sharda Nand:**
Shri Bharat Singh Chauhan:
Shri Ranjit Singh:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to give special incentives to the Hindi-knowing Government employees for switching over their official work from English to Hindi;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government's policy is that non-Hindi-knowing staff working in the Central Government offices should not be placed at a disadvantageous position.

Mizo Hills Problem

***341. Shri Hem Barua:**
Shri Surendranath Dwivedy:
Shrimati Tarkeshwari Sinha:
Shri Madhu Limaye:
Shri S. M. Banerjee:
Shri George Fernandes:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Maharaj Singh Bharati:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the extent to which Government have succeeded so far in restoring civil administration after the revolt staged by the Mizo National Front for independence from India in the Mizo Hills District of Assam; and

(b) the measures adopted so far to implement this objective and the results, if any, these measures have yielded?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). According to information available with us, civil administration has been restored in the Mizo Hills district. In the interest of better administration, a scheme of limited regrouping of villages has recently been implemented, covering all villages within a ten mile belt of the road from Silchar to Lungleh *via* Aijal. The administration of the grouped centres has also been taken over by the Civil authorities. The problem of complete restoration of law and order in the district is being tackled with vigour by our Security Forces.

Payment of Bonus by Associated Cement Companies

***342. Shri P. Ramamurti:**
Shri A. K. Gopalan:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a National Tribunal under the Industrial Disputes Act has been set up to enquire and submit its report on the dispute of payment of bonus for the

workers employed in the Associated Cement Companies;

(b) if so, the progress made by the Tribunal so far; and

(c) when the report is likely to be ready?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) Yes.

(b) The parties have filed their statements.

(c) Efforts are being made by the Tribunal to fix an early date for the hearing of the case.

Dandakaranya Project Employees

*343. **Shri P. K. Deo:**
Shri K. P. Singh Deo:
Shri D. N. Deb:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the Class III and Class IV employees of the Dandakaranya Project have recently represented to Government against the retrenchments and reversions in the Project; and

(b) if so, the action taken on their representation?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) Certain employees who became surplus due to reorganisation and reduction in Establishment and who had been given the usual notice of termination of services had represented against the issue of such notices.

(b) Action is being taken to adjust the surplus employees in other equivalent or lower posts. It is hoped that by such adjustments, it will be possible to avoid retrenchment.

Wage Board

*344. **Shrimati Tarkeshwari Sinha:**
Shri D. C. Sharma:
Shri Sidheshwar Prasad:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to bring about any statutory provision for implementation of the recommendations of the Wage Boards; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) No decision in this regard has been taken so far.

(b) Does not arise.

Urdu as Second Language

*345. **Shri Abdul Ghani Dar:**
Shri Madhu Limaye:
Shri S. M. Banerjee:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri George Fernandes:
Shri Bairaj Madhok:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have taken a decision to declare Urdu as the second language in certain States;

(b) if so, the names of the States where Urdu has been declared as the second language; and

(c) the names of the States which are in favour of declaring Urdu as the second language?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) In the Governor's address to the Bihar State Legislature on 17th March, 1967, it was announced that recognition would be given to Urdu as the second official language in the State. The Andhra Pradesh Official Languages Act, 1966 provides for the use of Urdu, in addition to the Telugu language, in certain areas of the State for such official and other purposes as may be specified by notification.

Indian Hockey Team Fixtures

*346. **Shri George Fernandes:**
Shri J. H. Patel:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the decision of the British Hockey Association to cancel the fixtures of the Indian hockey team due to tour Europe in April, 1967;

(b) whether the Indian High Commissioner in the U.K. was asked to approach the British Sports authorities to prevail upon the British Hockey Association not to cancel the fixtures; and

(c) whether the prestige of Indian hockey is likely to suffer by the reasons for the cancellation of the British fixtures?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) No fixtures were arranged with the British Hockey Association.

(b) and (c). Do not arise.

Wage Board for Engineering Industry

*347. **Shri Indrajit Gupta:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether all public sector engineering units have implemented the recommendations of the Central Wage Board for Engineering Industries on interim relief;

(b) whether such relief has been paid in addition to normal dearness allowance revisions; and

(c) the names of units which have not made the normal D.A. revisions in addition to payment of interim relief?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Guidelines to Governors

*348. **Shri Madhu Limaye:**
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri S. M. Banerjee:
Shri George Fernandes:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 260 on the 5th April, 1967 and state:

(a) whether Government have since held consultation with the Leaders of Political parties and non-party constitutional lawyers;

(b) whether any proposals have been formulated;

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether Government intend to issue any guiding principles to the Governors of the various States?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) The views of the constitutional experts in the matter are being ascertained. Discussions with the leaders of the Opposition groups could be held after their advice has been received.

(b) to (d). Do not arise at this stage.

उपकुलपतियों की नियुक्ति

*349. श्री ओंकार सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री 29 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1967 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों की नियुक्त के बारे में कोई निर्णय किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) जी, नहीं। सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Reforms in Examination System

*350. **Shri Vasudevan Nair:**
Shri Ram Kishan Gupta:
Shri K. P. Singh Deo:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the question of reforming the present examination system has been considered by Government; and

(b) if so, the result thereof?

The Minister of Edcation (Dr. Triguna Sen): (a) and (b). The National Council of Educational Research and Training has initiated a programme of examination reform in cooperation with State Governments and their Boards of Secondary Education. Under the programme, improvements are being made in question papers, scoring procedures and internal evaluation. Paper-setters, examiners and others connected with examinations are being trained.

इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज

*351. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज में परीक्षा तथा अनुसंधान के माध्यम के सम्बन्द में क्या निर्णय किया गया है; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं को कोई आदेश दिया है कि वे संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन न करें ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) स्कूल के उपनियमों के अनुसार, परीक्षा तथा अनुसंधान का माध्यम अंग्रजी है। फिर भी स्कूल की अनुसंधान बोर्ड को यह विवेक (डिस्क्रीशन) दिया गया है कि वह अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा में विद्यार्थी को अपनी थीसिस लिखने की अनुमति दे दे बशर्तेकि उसे सम्बधित भाषा में थीसिस की जांच के लिए कुशल अधीक्षक तथा परीक्षक मिल जाए।

(ख) सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था यदि संविधान का उल्लंघन करती है, तो देश के कानून पर विश्वास किया जा सकता है कि उसके अनुसार स्वाभाविक कारवाई हो सकती है। इसलिए इस मामले में मंत्रालय द्वारा कोई आदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

Hindi Teleprinters

*352. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri Onkar Singh:
Shri Kameshwar Singh:
Shri J. H. Patel:
Shri Madhu Limaye:
Shri Sidheshwar Prasad:

Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 518 on the 5th April, 1967 and state:

(a) whether M/s. Hindustan Teleprinters Ltd. have completed negotiations with their collaborators, M/s. Olivetti of Italy, for the supply of tooling and technical know-how for manufacturing Hindi Teleprinters in India;

(b) if so, the result thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). Yes Sir. The Hindustan Teleprinters Ltd. have completed the negotiations with their collaborators, M/s. Olivetti of Italy. The draft agreement for the supply of

tooling and Technical know-how under the Italian Supplier's Credit has recently been approved by the Government. The formal agreement is expected to be signed by the two parties in about a month's time.

(c) Does not arise in view of the position stated in the reply to parts (a) and (b).

Kidnapping by Naga & Mizo Hostiles

***353. Shri S. M. Banrejee:**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Naga and Mizo hostiles kidnapped some civil/military Officers in April 1967;

(b) if so, the number of Officers so kidnapped; and

(c) whether they have been rescued?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). Only one incident of kidnapping in the month of April, 1967 has been reported, according to which a Sub-Inspector of Schools and his Peon were kidnapped by Mizo hostiles on 9th April, 1967. The kidnapped persons were traced on 13th April, 1967.

Pay Scales of Haryana College Teachers

***354. Shri Ram Kishan Gupta**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the position regarding the implementation of the University Grants Commission's recommendations regarding new salary scales for college teachers in Haryana;

(b) whether the recommendations have been fully implemented by the State Government; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) to (c). The matter is under consideration of the Government of Haryana.

Labourers under Private Contractors

***355. Shri P. P. Esthose**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to extend the benefits enjoyed by the Industrial labourers to the labourers employed under private contractors; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). Government propose to introduce the Contract Labour (Regulation and Abolition) Bill during the current session of the Parliament. The Bill provides for certain welfare and Health measures as also for hours of work, minimum wages, payment of wages etc.

Rickshaw Pulling

***356. Shri Deven Sen:**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government have made any inquiry into the ill-effects of rickshaw pulling (cycle and hand) on the rickshaw pullers;

(b) whether Government have formulated any programme for the guidance of the States for the replacement of rickshaws by auto-rickshaws;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the reaction of the State Governments thereto?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) Government have been advised that rickshaw pulling in itself has no harmful effect on health though it is possible that considerable physical labour

on the part of ill-nourished and ill-housed rickshaw pullers might precipitate lung diseases which are common amongst slum dwellers due to hard work and unhygienic environments.

(b) No, sir.

(c) and (d). Do not arise.

Ban on Fresh Recruitment

*357. **Shri S. R. Damani:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have recently issued a directive to ban or restrict the recruitment of fresh staff to effect economy; and

(b) if so, the nature of the directive?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). In order to arrange for the redeployment of surplus staff located as a result of introduction of administrative reforms or of the studies by the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance, a Central (Surplus Staff) Cell has been set up in the Ministry of Home Affairs. To facilitate absorption of such surplus staff, a total ban has been imposed on direct recruitment being made in all Government organisations to ministerial, non-gazetted posts like Assistants, Upper Division Clerks and Lower Division Clerks unless a certificate is obtained from the Central Cell to the effect that the Cell has no suitable candidates to offer. The ban, however, does not apply to recruitments made through annual competitive examinations conducted by the U.P.S.C. but it is intended that the actual number to be taken through such recruitment should be kept as low as possible.

East Pakistan Raid on Berubari

*358. **C. K. Bhattacharyya:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 126 on the 29th March, 1967 and state:

(a) whether the investigation in the crime committed by miscreants from East Pakistan raiding South Berubari, Jalpaiguri District, on the 9th March, 1967 has been completed;

(b) if so, the result thereof;

(c) whether any reply has been received from Pakistan to the protests lodged from our side; and

(d) if so, the nature thereof?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). Yes, Sir. A final report of the investigation was submitted by the local police on the 30th April, 1967, suspecting ten Pak. nationals of Dinajpur District, East Pakistan of having committed the offence.

(c) and (d). Sector Commander Border Security Force, Kadamtala, in response to a protest lodged by him to the East Pakistan Rifles Sector Commander, Dinajpur, received a reply stating that the matter had been investigated in East Pakistan and had not been found to be true. No reply has, however, been received either by the State Government or by the Deputy Commissioner, Jalpaiguri, from their counterparts in response to the protest notes lodged in this connection.

Working Hours of Government Servants

*359. **Shri Baburao Patel:**
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Jagannath Rao Joshi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to reduce the working hours for Government servants and close all Government offices on Saturdays and Sundays as is done in some foreign countries;

(b) if so, the number of public and restricted holidays which Government intend to reduce to compensate for these week-end holidays;

(c) whether Government will require more staff as a result of overall reduction in working hours;

(d) whether Government have worked out in terms of money and loss that will have to be suffered if less work and more holidays are given; and

(e) if so, the amount of loss that will be incurred?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) No such proposal is under consideration.

(b) to (e). Do not arise.

Funds for Delhi Municipal Corporation

***360. Shri Kanwar Lal Gupta:**
Shri R. S. Vidyarthi:
Shri Hardayal Devgun:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have rejected the Delhi Municipal Corporation's plea for funds;

(b) whether it is also a fact that there is a deficit of Rupees 6 crores in the Municipal Corporation;

(c) whether the Corporation is unable to make even the payment of salaries of its staff; and

(d) the action Government propose to take to remove the difficulties of the Corporation in compensating the aforesaid deficit of the past 9 years?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The Government of India extend financial assistance to the Delhi Municipal Corporation in accordance with a pre-determined pattern of assistance. Payments falling due periodically on the basis of this pattern are regularly being made to the Corporation.

(b) The Corporation has estimated the amount of deficit to be about Rs. 6 crores;

(c) The Corporation have been paying salaries to its staff regularly.

(d) The Government have appointed a Commission of Enquiry to inquire into the financial resources and requirements of local bodies in Delhi. Any change in the pattern of assistance to the Corporation will be decided in the light of the recommendations of the Commission. The report of the Commission is awaited.

Telephone Exchanges and Public Call Offices in Haryana State

1640. Shri Ram Kishan Gupta: Will the **Minister of Communications** be pleased to state the number of Public Call Offices and telephone exchanges to be opened in Haryana State during 1967-68?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): Ten Public Call Offices and six telephone exchanges are likely to be opened in Haryana State during 1967-68.

Direct Telephone Service

1641. Shri Ram Kishan Gupta: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to provide direct telephone service between, Charkhi Dadri-Rewari and Charkhi Dadri-Narnol in Haryana; and

(b) if so, when it is proposed to be implemented?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) There is no such proposal under consideration at present.

(b) A recent examination of the traffic on the circuits shows that the direct trunck telephone circuits between the stations is not fully justified at present. However, a watch will be kept on the traffic with a view to provide a direct trunk circuit from Charkhi Dadri to Rewari.

मिजो विद्रोहियों से हथियारों का पकड़ा जाना

1729. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री राम सिंह अयर गल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1967 के प्रारम्भिक चरण में सुरक्षा सेनाओं ने फैलांग के निकट मिजो विद्रोहियों से हथियारों का छिपाया हुआ एक बड़ा भण्डार पकड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन हथियारों पर किन देशों के चिन्ह अंकित हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

Delhi High Court Bench for Himachal Pradesh

1730. Shri K. N. Pandey: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Himachal Bench of the Delhi High Court has started functioning at Simla with effect from the 3rd May, 1967; and

(b) if so, how much expenditure will be incurred during the year on this Bench?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) Yes, Sir from 1st May, 1967.

(b) The basis on which the expenditure on this Bench is to be determined is under consideration.

महानगर परिषद् दिल्ली

1731. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री किस्कू :
श्री स० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में महानगर परिषद् के बनने के बाद केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्य सूची में सम्मिलित सभी शक्तियां उपराज्यपाल को सौंप दी गई हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि महानगर परिषद् के बनने के बाद भी कई मंत्रालयों ने विषय तथा शक्तियां दिल्ली प्रशासन को नहीं सौंपी हैं ; और

(ग) इस शिकायत को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) संविधान में दी गई राज्य सूची में, उन विषयों का उल्लेख है जिनके सम्बन्ध में राज्य विधान सभा कानून बनाने के लिए सक्षम है। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, इन विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति संसद् को प्राप्त है और यह शक्ति उपराज्यपाल को हस्तान्तरित नहीं की गई है।

(ख) और (ग). सरकार का ध्यान दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद के, 9 मई,

1967 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना तथा राजधानी के सभी अस्पतालों को दिल्ली प्रशासन के नियंत्रण के अधीन लाया जाना चाहिये।

इन मामलों तथा इस समय मंत्रालयों द्वारा प्रयुक्त शक्तियां उपराज्यपाल को प्रत्यायोजित किये जाने के प्रश्नों पर मुख्य कार्यकारी पार्षद द्वारा गृह मंत्री के साथ 27 मई, 1967 को चर्चा की गई। इसके दौरान यह बताया गया कि सफदरजंग अस्पताल तथा विलिंगडन अस्पताल का हस्तान्तरण व्यवहार्य नहीं था क्योंकि ये दोनों अस्पताल मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निमित हैं और शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा डिस्पैन्सरियों के शीर्ष संस्थान थे। दिल्ली दुग्ध योजना को दिल्ली प्रशासन को सौंपने के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपराज्यपाल को शक्तियां सौंपने के विषय में, यह सुझाव दिया गया क दिल्ली प्रशासन को विभिन्न संबंधित मंत्रालयों को उनके विचार के लिये, विस्तृत सुझाव भेजने चाहिए।

G.P.O., Bhubaneswar

1732. Shri Chintamani Panigrahi: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the area of the Capital at Bhubaneswar in Orissa is increasing rapidly;

(b) if so, the number of letters and other postal articles being handled daily in the G.P.O. at Bhubaneswar; and

(c) the steps taken to increase the delivery and sorting staff of the G.P.O. at Bhubaneswar for facilitating quick and timely delivery of letters?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement on the points raised has been laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

I. *No. of letters and other postal articles being handled daily in the GPO at Bhubaneswar on an average.*

(a) Unregd. articles received for delivery :

Through Postmen	6489
Through Post Boxes	6669

(b) Unregd. articles posted for despatch: 23,170
(The sorting work is done at the Bhubaneswar Head Office) Sorting Office (RMS)

(c) Accountable articles posted for despatch:

Registered letters	251
Insured Letters	5
VP letters	2
Registered Parcels	30
Money Orders	110

(d) Accountable articles received for delivery :

Registered letters	691
Insured Letters	2
VP letters	17
Registered Parcels	108
VP Parcels	4
Insured parcels	1
MOS paid	155
Unpaid letters	23

II. *Steps taken to increase the delivery and sorting staff of the GPO at Bhubaneswar for facilitating quick and timely delivery of letters:*

The establishment of the post office was reviewed last on 22nd February, 1967 and as a result eight postmen, one Reader postman and one Delivery clerk were sanctioned. In February, 1967, one more delivery office *viz.* Bhubaneswar-6 was opened. It has also been decided that the number of beats should be increased from 14 to 18 with effect from the 1st June, 1967.

Work-charged Staff at G.P.O., Bhubaneswar

1733. Shri Chintamani Panigrahi: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that out of 40 departmental

officials in the Bhubaneswar G.P.O., thirty are working on ten days work-charged basis;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether representations have been received that these thirty men are being appointed at the mercy of the appointing authorities and their services are also being utilised in performing personal work; and

(d) if so, the steps taken in the matter?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). It is not a fact that out of 40 departmental officials in Bhubaneswar G.P.O., 30 are working on work charge basis for 10 days. When the shortage of staff exceeds the permissible leave reserve in the cadre of postmen and Class IV staff in the Head Office, a few persons are occasionally appointed on a work charge basis.

(c) and (d). Such outsiders are employed on the personal responsibility of the Head of office or some other permanent official of the office. Allegations about 2 officials being utilised for personal work were received. On enquiry, these could not be substantiated.

Indian School of International Studies

1734. Shri Y. A. Prasad:
Shri N. K. Sanghi:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether a proposal to send a University Grants Commission team to enquire into the affairs of the Indian School of International Studies is under consideration of Government; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) and (b). No, Sir. The question was discussed with the Chairman, University Grants Commission. A Review Committee of the University Grants Commission which looked into the working of the School in 1965 found nothing exceptionable in its academic programmes and financial management. The Committee supported the School's continued recognition as a 'deemed' university. The Chairman of the University Grants Commission and I agree that in view of this, it is not necessary to appoint another team to inquire into the working of the School.

Assistance for Cultural Centres in U.P.

1735. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether any financial assistance was given to Uttar Pradesh for the construction of Cultural Centres in the State during 1965-66 and 1966-67; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Yes, Sir.

(b) The details are given below:

1965-66

Rs. 17,686 to Nari Seva Samiti, Lucknow for the construction of auditorium.

1966-67

Rs. 7,500 to Ghatkhande College of Hindustani Music, Lucknow for the construction of building. The amount was not drawn by the grantee during 1966-67.

Counselling Centres at Universities

1736. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission's Committee on Students Welfare and Allied Matters has suggested the setting up of Counselling Centres at Universities and Colleges in the country to deal

with the emotional problems of students; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) The Committee has suggested introduction of a properly organised counselling system in the Universities and Colleges The Committee has further recommended that if this cannot be undertaken on a large scale due to paucity of resources, the tutorial system should be improved and encouraged.

(b) The Government generally agree with these suggestions.

I.A.S. Training

1737. Dr. M. Santosham: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the length of the period of training given to young men and women selected to the Indian Administrative Service before they are assigned independent charge as Heads of Departments or District Administrators;

(b) whether there is a prescribed period of training and, if so, whether it is uniformly applicable to all States;

(c) how does their efficiency compare with those who are promoted from the ranks by virtue of their long period of service and experience;

(d) whether there is any age restriction for I.A.S. officials for eligibility to responsible Administrative posts involving independent charge; and

(e) whether Government propose to introduce either minimum age or minimum period of experience before I.A.S. officials are posted as Administrative Heads?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). There is no prescribed period of training for examination recruits before appointment to senior posts and as Heads of Departments or District Officers. Such recruits are put on probation for two years and thereafter they are also appointed to junior posts for on-the-job training and experience. The late Shri V. T. Krishnamachari in his report in "Indian and State Administrative Services and Problems of District Administration" recommended a pattern of training to be imparted to examination recruits before being put in charge of districts and had suggested that a district charge should be given towards the end of the sixth or in seventh year of service. The State Governments are following the recommendations to the extent possible depending on local conditions.

(c) The annual competitive examination for the IAS is of a very high standard and is made against 75 per cent of the senior posts in each State Cadre, State Civil Service officers who have completed eight years' service are eligible to be considered for appointment to the I.A.S. against the remaining 25 per cent of the senior posts by selection. No comparison of efficiency after dividing officers into two such groups is practicable.

(d) No. It depends on suitability for such appointment.

(e) No, since the fitness for holding such posts is already determined on considerations of length of service, maturity and experience.

Allotment of C.S.I.R. Accommodation in Jamshedpur

1738. Shri Bhogendra Jha: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently some quarters were allotted to some officers who joined only in March, 1967 disregarding the rules for allotment of accommodation in C.S.I.R. in Jamshedpur while many senior officers are waiting for years for accommodation;

(b) whether residential quarter within the Low Shaft Furnace premises is kept unallotted for years caus-

ing loss of revenue to the exchequer and inconvenience to officers waiting for accommodation;

(c) whether any unauthorised subletting of C.S.I.R. accommodation in Jamshedpur has come to the notice of Government; and

(d) whether Government have received any representation from staff in this regard and if so, the action taken thereon?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) No, Sir, not in disregard of the rules.

(b) No, Sir. Few quarters built in the premises of Low Shaft Furnace Plant are meant exclusively for essential staff, including security, attached to the plant and are not available for general allotment.

The quarter in question has since been occupied w.e.f. 1st April, 1967 and, being rent free, there is no question of any loss of revenue.

(c) No, Sir.

(d) No representation has been received from any staff member of the laboratory. However, representations from some Associations have been received. Since these are not recognised Associations, no reply has been sent.

खानों में दुर्घटनायें

1739. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में विभिन्न खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) उनके परिणाम स्वरूप कितने खनिक मारे गये; और

(ग) मृत व्यक्तियों के परिवारों को कितनी राशि प्रतिकर के रूप में दी गई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अप्रैल, 1966 से मार्च, 1967 तक 264 घातक दुर्घटनाएं ?

(ख) 311 ।

(ग) इस प्रकार का मुआवजा कर्मकार प्रतिकर आयुक्तों द्वारा दिया जाता है, जो कि राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । दुर्घटना द्वारा मृत्यु की सूरत में दिया जाने वाला अधिकतम मुआवजा 10,000/- रुपये है । प्रत्येक मामले में दिए गए मुआवजे का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

Employees in Laccadive, Minicoy and Amindive Islands

1740. **Shri P. M. Sayeed:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Class I, Class II, Class III and Class IV officers employed in the Administration of the Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindive Islands at present;

(b) the number of officers who are natives of the Islands in each category of posts;

(c) whether it is a fact that even for Class IV posts, recruitments have been made from persons belonging to the mainland, when sufficient number of eligible candidates for such posts is available in the Islands; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). A statement is attached.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

STATEMENT

Classfication of posts	Total number of posts	Number of posts held by natives of the islands
(1)	(2)	(3)
Class I . . .	2	Nil
Class II . .	24	1
Class III . .	649	146
Class IV . .	266	215

Tellicherry Head Post Office

1741. Shri P. Gopalan:
Shri A. K. Gopalan:
Shri P. Ramamurti:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government had acquired a site for the construction of a building for the Tellicherry Head Post Office;

(b) if so, when the site was acquired;

(c) whether the work on the building has started;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) when the work will start; and

(f) when it will be completed?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) 25th July, 1961.

(c) No.

(d) The work could not be taken up during 1966-67 for want of funds.

(e) Tenders for the work were opened on 22nd May, 1967. The rates being on the high side, tenders are being reinvited. If reasonable rates are received on recall, the work is likely to be started during August, 1967.

(f) 18 months after commencement.

Indian Service of Engineers

1742. Shri G. S. Mishra: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the reasons for the delay in constituting the Indian Service of Engineers;

(b) the number of engineers unemployed at present in the country;

(c) the measures taken to secure employment for them; and

(d) the turn-out of engineers at present and what will be the rate of increase of unemployment among the Engineers in the next five years?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Divergent views were held by the State Governments on certain basic issues such as, the need for and composition of a Central Cadre in the Service, the general pattern of encadrement of posts, the question of inclusion of teaching and research posts etc. Some decisions have since been taken. A Memorandum along with the draft Cadre Rules, Recruitment Rules and Initial Recruitment Regulations have been sent to all State Governments on 31-3-1967. Further steps to constitute the Service will be taken as soon as their comments are received.

(b) there were 4,335 Engineering Graduates (including post-graduates) on the live register of Emp'oyment Exchanges in the country as on 31st December, 1966. Not all unemployed engineers are registered in the Employment Exchange. Those registered also include some who are employed but are seeking better employment. Registration in the Employment Ex-

change, therefore, provides only a rough indication of the unemployment position.

(c) various development schemes under the Five Year Plan are directed towards creating employment opportunities for all categories of the unemployed including Engineers;

(d) the out-turn of engineering graduates in 1965 was 10,282. In 1966 it was approximately 12,000. It is not possible to estimate the degree of unemployment among the Engineers during the next five years. The expansion in the facilities for Engineering education which has taken place during the Third Plan was based on estimates of requirements of engineering personnel during the 4th Plan period. Employment prospects during the next five years would become clear only after the 4th Plan takes final shape.

Police Force, Andamans

1743. Shri D. N. Patodia:
Shri S. K. Tapuriah:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no free uniform was issued to the Police Force, Andamans and Nicobar Islands for about 3 years; and

(b) if so, the reasons therefor and how the money sanctioned for this purpose was utilised?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). Certain articles of uniform could not be issued, owing to non-receipt of supplies indented for. Although under the sub-head 'Clothing and Equipment' there were proportionate savings due to non-receipt of supplies indented for, there were practically no savings under the head 'Contingencies' in the overall budget allocation of the police Department of the Andaman and Nicobar Administration.

Complaints against Andaman Officers

1744. Shri D. N. Patodia:
Shri S. K. Tapuriah:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether complaints have been received against the Officers of Andaman Administration about the harassment of active workers in Political field and their sons in Andamans;

(b) the action taken in the matter; and

(c) whether there is a proposal to bring popular Government in the territory at an early date?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No such specific case has come to notice of Government.

(b) Does not arise.

(c) No such proposal is under the consideration of the Government.

Attack by Mizos in May, 1967

1745. Shrimati Jyotsna Chanda: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a gang of 15 Mizo hostiles entered Cachar district in the second week of May and fired on the villagers at Jalnachherra, injuring one, looted some shops and escaped with cash and grain;

(b) if so, the amount of loss as a result thereof; and

(c) the measures taken to extend more security on the border?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) The estimated loss is reported to be about Rs. 300/-.

(c) Security forces have been alerted and patrolling has been intensified

in order to prevent recurrence of such incidents.

Offer of Withdrawal by Nagas

1746. Shrimati Jyotsna Chanda: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Underground Nagas have offered to withdraw some of their armed men from the ceasefire areas in the Ukhrul and Tamenlong Sub-Divisions of Manipur, provided there is reciprocal response from the other side; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Betapur Pitcher Nalla Farm in Middle Andaman

1747. Shri K. K. Sinha: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Betapur Pitcher Nalla Paddy Farm in the Middle Andaman started by the Andaman Administration has been abandoned;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that a senior officer of the Ministry of Rehabilitation has described this farm as wasteful;

(d) if so, whether the report will be placed on the Table of the House; and

(e) the total expenditure incurred on the farm in 1966-67 and the total quantity of paddy produced and the cost per maund of paddy?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir, the Betapur Farm Project has not been abandoned.

(b) Does not arise.

(c) No.

(d) Does not arise.

(e) On part of the land reclamied up to the end of the 1965-66 season, trial varietal sowings of paddy and experimental farming operations were undertaken. The quantity of paddy produced was 1936 maunds. Figures of expenditure and cost per maund of paddy are being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Fees Charged from Visitors to Monuments

1748. Shri Sezhiyan: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fees are collected from visitors to the monuments of historical interest in India; and

(b) if so, the list of such monuments and the rates of fees collected?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) Yes, Sir, but only at a few monuments, and not all.

(b) A list of monuments where entrance fees are collected from visitors is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-554/67]. The rate of fee is twenty paise per person above the age of fifteen years, on all week days except Fridays when admission is free.

I.A.S., I.P.S. and Central Secretariat Officers

1749. Shrimati Savitri Shyam: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than 100 I.A.S., I.P.S. and the Central Secretariat Officers, who were not promoted on merit, are drawing the same emoluments as they would have received had they been promoted under the 'next below rule'; and

(b) the additional expenditure incurred on account of this rule during the years 1963-64, 1964-65 and 1965-66?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir, it is a fact that more than 100 I.A.S., I.P.S. and Central Service Officers (inclusive of Central Secretariat Officers) have been given benefit of higher pay under the 'next below rule' However, it is not correct to say that this benefit is given to officers who would not have been promoted on the basis of merit had they been available in the regular line. Officers not suitable for promotion on merit are not to be given the benefit of the next below rule'. The intention of the rule is that an officer out of his regular line should not suffer by forfeiting acting promotion which he would otherwise have received had he remained in his regular line.

(b) Attention is invited to the information laid on the Table of the House in reply to question No. 3853, to which an interim reply was given on 31-8-1966 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-555/67].

Coal Mines Provident Fund

1750. Shri Deven Sen: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many of the colliery employers, particularly in the Asansol belt, do not deposit their share of Provident Fund with the Provident Fund Commissioner;

(b) whether it is also a fact that even the workers contribution to the Provident Fund deposited with the employers is not deposited with the Provident Fund Commissioner;

(c) if so, the names of such defaulting employers; and

(d) the steps taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). Yes. Some colliery employers have defaulted in payment of their share of Provident Fund and of the contribution of workers deducted from their wages to the Coal Mines Provident Fund Commissioner

(c) and (d). A statement showing the names of the defaulting employers and the steps taken against them has been already laid on the Table of the Lok Sabha on the 7th April, 1967.

Miners' Camps and Hostels

1752. Shri P. C. Adichan: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of unauthorised Miners' Camps and Hostels in the Coal Mines;

(b) the names of coal mines where these camps and hostels are functioning; and

(c) the steps taken to abolish them?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) Twelve.

(b) I—Raniganj Coalfield.

(1) Samla Manderboni Colliery, P.O. Pandaveswar.

(2) Madhujore Colliery, P.O. Kajoragram.

(3) Ghusick Colliery, P. O. Kalipahari.

(4) Porascole Colliery, P. O. Kajoragram.

II—Jharia Coalfield.

(1) Kharkharee Colliery, P.O. Kharkharee.

(2) Ena Colliery, P.O. Dhansar.

(3) Bhatdee Colliery, P.O. Dhansar.

(4) Murlidih Colliery, P.O. Mahuda.

(5) Khas Dharmabad Colliery, P.O. Malkera.

(6) Loyabad (North) Colliery, P.O. Sijua.

III—Karanpura Coalfield.

Khas Karanpura Colliery P.O. Patratu (Hazaribagh).

IV—Pench Valley Coalfield.
Newton Chickli Colliery, P.O. Parasia,

District Chindwara.

(c) The issue really is whether and on what conditions, such unauthorised hostels for Gorakhpuri labour should be recognised.

The Central Hostels Committee under the Chairmanship of the Coal Mines Welfare Commissioner which grants recognition to miners hostels and lays down standards for recognition is already seized of the matter. A Central Evaluation Committee has also recently been set up under the Chairmanship of the Director General of Mines Safety and this Committee is also looking into this question.

Accident in Coal Mines

1753. Shri P. C. Adichan: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the names of Coal mines where fatal accidents took place in April, 1967;

(b) the number of workers killed in these accidents in each mine; and

(c) the findings of the departmental enquiry in each of these accidents?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). A statement is attached. Supplementary information will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

STATEMENT

S. No.	Name of Colliery	No. killed	Findings of the Departmental Enquiry
1	Samla Dalurband	1	Fault of Co-worker
2	North Laikdih	2	Report not received
3	New Majri	1	Misadventure
4	Duman Hill	1	Fault of management.
5	Jogidih	1	Report not received
6	Loyabad	1	Fault of subordinate supervisory staff
7	Mithrpur	1	Fault of deceased
8	Bhatdee	1	Misadventure
9	Lower Kenda	1	Report not yet finalised
10	Kamptee	1	Report not received
11	Ballarpur	1	Report not received
12	Pootkee	1	Report not yet finalised
13	Sitanala	1	Report not received
14	Khas Kusunda	1	Misadventure
15	Sri Amritnagar Selected	1	Report not yet finalised
16	Chalkari	1	Misadventure
17	Deulbera	1	Report not received
18	Samdi Sangramgarh	1	Fault of management and subordinate official.
19	Pure Nichitpur	1	Report not received
20	Dhori	1	Report not received
21	Kendwadih (5-pit Khoira)	1	Report not received

Profit Sharing Bonus in Coal Mines

1754. Shri P. C. Adichun: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number and names of coal mines which have not paid the profit sharing bonus for the year 1965; and

(b) the action taken to persuade the Coal Mines to pay the bonus without further delay?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) 343 coal mines have not so far paid the profit-sharing bonus to their workmen for the accounting year 1965. The names of these coal mines are not readily available.

(b) Following an increase in the price of coal, sanctioned by Government in December 1966 to enable employers to pay the arrears of bonus, the Joint Working Committee of employers was asked to advise their constituents to make payment without any further delay. The defaulting col'ieries have been served with show-cause notices to explain why action should not be taken against them for contravention of the Payment of Bonus Act, 1965. Several prosecution proposals are under the examination of the Government.

Mahajan Boundary Commission

1755. Shri E. K. Nayanar: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Kerala Government have boycotted the Mahajan Boundary Commission, when the Commission visited Kasargod (in Kerala) to take evidence from the people;

(b) whether Government are aware that only pro-merger section in Karnatka has given evidence before the Mahajan Commission; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). According to the information furnished by the Commission, the Chief Minister of Kerala in his letter of 17th April nad apprised the Commission of the stand taken by the State Government in regard to the Kasargod question and expressed the view that it would be better to allow the present borders between Mysore and Kerala to continue. In reply to a suggestion by the Commission that either the Chief Minister or one of his Ministers might meet the Commission at Kasargod or Mangalore to explain the stand taken by the State Government, the Chief Minister informed the Commission that as he had already explaind the reasons for the decision taken by the State Government, it wou'd not be necessary for him or any of his Ministers to meet the Commission. The Commission will, therefore, take into account the Chief Minister's letter of 17th April as representing the State Government's views in the matter. It is also understood that the evidence tendered and recorded by the Commission at Kasargod on 15th May was mainly from associations, parties and individuals who had favoured merger of Kasargod taluk in Mysore. There were one or two representations for the maintenance of *status quo* also.

Compulsory National Service Scheme

1756. Shri K. P. Singh Deo:
Shri P. K. Deo:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a scheme for Compulsory National Service for University Students is being introduced;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the estimated annual expenditure involved in the implementation of the scheme?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) to (c). The matter is under consideration.

Thefts in M.P's. Residence

1757. Shri Kameshwar Singh:
Shri Madhu Limaye:
Shri Shri Chand Goel:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Mrs. V. L. Pandit's house was burgled on the 23rd May, 1967;

(b) whether other M.Ps. have had similar experience in the past two-three years;

(c) the number of such thefts and burglaries;

(d) in how many cases the culprits were apprehended and convicted; and

(e) the steps proposed by the Delhi Administration and the Centre to prevent these burglaries and thefts?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) to (e). Two statements ('I' and 'II') are laid on the Table of the House.

Statements I and II

Below are given the number of theft and burglary cases reported to the police in which the property belonging to the M.Ps. was involved and also the details of the persons arrested during the years 1965, 1966 and 1967 (upto 26th May, 1967).

Period	Head of Crime	Cases reported	Persons Arrested	Persons Convicted so far
1965	Burglary	12	2	2
1966	Do.	10	..	..
1967 (upto 26-5-67)	Do.	6	..	..
1965	Theft	8	2	2
1966	Do.	7	2 (both the accused were acquitted)	..
1967 (upto 26-5-67)	Do.	1	..	..

Statement II in Reply to part (e) of the Question

(i) Adequate number of policemen are being posted round the clock to patrol in the areas where M.Ps. live.

(ii) Flats which are exposed are receiving special attention. The work of beat constables is supervised by the Division Officers, mobile patrol incharge, Station House Officer and occasionally by the Superintendent of Police himself.

(iii) The investigation of such cases is entrusted to senior and experienced Investigating Officers.

(iv) The Station House Officer concerned has been made responsible for keeping a close watch on the investigation of these cases and for developing sources of information.

(v) C.I.D. Inspection Team is sent to observe the scene of crime and lift finger prints, etc. left behind by the culprits at the scene of crime.

(vi) Every case of theft and burglary reported from these flats is being looked into promptly by the Superintendent of Police and the Illaqa Gazetted Officer together.

(vii) In July 1964, a circular letter was issued to all Members of Parliament residing in North and South Avenues seeking their co-operation on the following matters with a view to bringing down the incidence of thefts and burglaries in these areas:

(1) To intimate to the Superintendent of Police, Parliament Street, about their departure from Delhi and the duration of their stay outside Delhi approximately, so that special arrangements may be made to keep a guard on their residences;

(2) To intimate also to the Superintendent of Police whether in their absence any of their domestic servants, friends or relatives will be occupying the flat; and

(3) Whether they have hired any garage and if so, whether they have domestic servants or a driver or any one else occupying the garage.

Rehabilitation Settlements

1758. Shri K. P. Singh Deo:
Shri P. K. Deo:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there have been large desertions from the rehabilitation settlements;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the amount spent on the rehabilitation and relief programmes from 1948 to 1966?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) There have been some desertions of migrants form East Pakistan who came to India on or after 1st January, 1964 from agricultural rehabilitation settlements in various States, including Dandakarnya Project. Apart from these desertions, a very large number of families had left the relief camps in which they had been accommodated prior to their dispersal to the rehabilitation settlements.

(b) (i) Migrants' inability to adjust themselves to their new environment, particularly to the unfamiliar climatic and soil conditions, lower rainfall and a different cropping pattern.

(ii) The drought and scarcity conditions prevailing over large parts of the country which affected the rehabilitation settlements also for the last two successive years and consequential failure of crops.

(iii) Relations still living in West Bengal.

(iv) Natural inclination to settle down in West Bengal, strengthened by the hope that the newly constituted State Government would settle them in that State itself.

(v) Fear of prosecution for being spurious migrants.

(vi) False and misleading promises of rehabilitation in West Bengal made by unscrupulous elements who sometimes infiltrate into resettlements.

(c) From 1947-48 to 1965-66 a sum of Rs. 440.08 crores was spent on relief and rehabilitation programmes sanctioned for displaced persons from East Pakistan and West Pakistan. Of this amount a sum of Rs. 199.46 crores was expended on programmes for displaced persons from West Pakistan and the balance of Rs. 240.62 crores on programmes for displaced persons from East Pakistan.

Fair Price Shops in Industrial Establishments

1759. Shri Y. A. Prasad:
Shri N. K. Sanghi:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring in legislation to compel employers to set up fair prices shops in industrial establishments; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). The matter is under consideration.

Employment for Unskilled and Agricultural labour

1760. Shri P. K. Deo:
Shri K. P. Singh Deo:
Shri D. N. Deb:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a plan has been drawn up to provide employment to the unskilled and agricultural labour in the rural areas;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the expenditure incurred on the rural workers programme during the Third Plan period?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) and (b). The important schemes intended to provide employment to unskilled and agricultural labour in rural areas are:

(i) Rural Works Programme, and

(ii) Rural Industries Programme.

The details of these are contained in the Draft Outline of the Fourth Five Year Plan.

(c) The expenditure incurred on the Rural Works Programme during the Third Plan period was Rs. 19.33 crores.

Vishal Haryana

1761. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a memorandum has been presented to the Prime Minister by Members of Parliament from Rajasthan, Delhi, Uttar Pradesh and Haryana demanding the formation of Vishal Haryana; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Rehabilitation Ministers' Conference

1762. Dr. Ranen Sen: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at the Conference of State Rehabilitation Ministers held at New Delhi in May, 1967, the Union Minister for Rehabilitation did not agree to the suggestions regarding the so-called residuary problem with the Minister from West Bengal;

(b) whether the West Bengal Rehabilitation Minister has submitted some schemes for the rehabilitation of refugees; and

(c) if so, the reaction of the Central Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) During the Conference of the State Rehabilitation Ministers held on the 19th May, 1967, the West Bengal Minister for Rehabilitation in his speech invited attention to certain pending problems. However, an opportunity was taken before and after the Conference to exchange views and ideas with the West Bengal Minister on matters relating to the rehabilitaton of old and new migrants. Some of the points discussed related to items outside the "Residuary Problem".

As regards the "Residuary Problem", certain aspects relating to the implementation of individual schemes were discussed. In view of the slow progress of sanctioned schemes, the West Bengal Government were asked to take necessary measures to step up the pace of implementation.

The Union Minister did not reject any "suggestions" of the Minister for Rehabilitation, West Bengal, in regard to commitments accepted under the Residuary Problem, during the recent discussions.

(b) and (c). The State Government have approached the Government of India with certain proposals for providing additional educational, medical and training facilities to relieve pressures in these sectors caused by the influx of new migrants since 1964. The schemes briefly are:—

(i) Setting up of Special I.T. institutes for D.P. Boys;

(ii) Training of D.P. girls as nurses and the setting-up of as B.Sc. Nursing College; and

(iii) Rehabilitation of old migrants families squatting on defunct camp sites.

These proposals are being examined in consultation with the Ministry of Finance.

Post Offices in Kangra District

1763. Shri Prem Chand Verma: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Post Offices and Public Call Offices in Kangra and Bilaspur Districts of Himachal Pradesh; and

(b) the number of them which are functioning?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral):

	P.Os.	P.C.Os.
(a) Kangra District	676	32
Bilaspur Distt.	78	4

(b) All are functioning.

Pay Revision of Manipur Government Staff

1764. Shri M. Meghachandra: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are sanctioning the pay revision of the Manipur Police and Radio Staff on Central Government pattern of pay scales;

(b) whether their pay was revised when the pay of the employees of the Government of Manipur was revised with effect from 1st April, 1964; and

(c) whether the Government of Manipur are moving the Centre for a pay revision for their staff on Central pattern, if so, when and from which date effect is being given?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). The Government of India have recently received proposals for the revision of scales of pay of the Manipur Police and Radio Staff on the Assam pattern. These proposals are being examined.

Grants to Manipur Schools

1765. Shri M. Meghachandra: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Manipur Government have not paid the regularly payable grants to the Government aided elementary schools for the last few months;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether this has resulted in irregular receipt of pay and the non-receipt of arrears of pay by the teachers in these schools; and

(d) the steps taken to pay the grants in time?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (d). Yes, Sir. There have been delays in the payment of grants during the last few months, which has resulted in irregular payment of salaries to teachers. Grants for March, 1967 have already been paid in many cases. Grants for the period April to August, 1967 as well as for the arrears of pay have been sanctioned and payments will be made soon after clearance from the Accounts authorities. The delays are reported to be mainly due to observance of such procedural requirements as checking of accounts, obtaining utilization certificates, etc. The Administration of the Union Territory of Manipur are examining the ways and means of avoiding delays in future.

दिल्ली पुलिस का आन्दोलन

1766 **श्री ब्रह्मानन्दजी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व दिल्ली पुलिस के आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार की गई महिलाएं तथा बच्चे अब भी जेलों में बन्द हैं;

(ख) यदि हां, तो इन महिलाओं तथा बच्चों की संख्या कितनी है;

(ग) उन्हें जेलों में बन्द रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने बच्चों को खाद्य पदार्थ, दूध आदि देने की क्या व्यवस्था की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). दिल्ली पुलिस के आन्दोलन के दौरान 8 महिला कांस्टेबिल गिरफ्तार करके जेल भेज दी गई । न्यायालय द्वारा उन सब की जमानत मंजूर कर ली गई हैं । उनमें से चार का जमानत/जमानत बन्ध की पूर्ति पर जेल से पहले ही छोड़ा जा चुका है, शेष चारों को उनके द्वारा जमानत की औपचारिकता को पूरा करने के बाद तुरन्त ही छोड़ दिया जाएगा । बच्चे गिरफ्तार नहीं किए गये थे ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Retiring Age of Teachers

1767. Shri S. C. Jha: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the present retiring age limit for the school teachers; and

(b) whether it is a fact that the Kothari Education Commission Report has recommended that the retiring age limit of school teachers be fixed at 65?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-556/67].

Statehood for Manipur

1768. Shri M. Meghachandra: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Assembly of Manipur and all the political parties in Manipur are demanding for the grant of Statehood to Manipur; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) In September, 1966, the Manipur Legislative Assembly passed a resolution to the effect that full-fledged Statehood be granted to Manipur.

(b) Government do not propose any change in the status of this Union territory.

Centralisation of Services of L.D.C's./U.D.C's./Assistants

1769. Shri M. L. Sondhi: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of L.D.C's. Ministry-wise, who have completed 10 years' service in the grade but have not been promoted to the grade of U.D.C.;

(b) the number of L.D.C's. promoted as U.D.C's. during the period Ministry-wise;

(c) whether it is a fact that in some cases senior LDCs. could not be promoted as UDCs. for want of vacancies in that cadre in the Ministry and as such there is much discontentment among the employees;

(d) whether such disparity and the resultant discontentment are due to the decentralisation of these services;

(e) whether it is also a fact that such disparity and discontentment are in existence in the cases of UDCs.; Assistants, and Section Officers also;

(f) if so, whether Government propose to centralise these services as before; and

(g) if not, the reasons therefor?

मध्य प्रदेश में पुरावशेषों (ऐंटीक्विटीज) की चोरी

1686. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में 750 से अधिक प्राचीन पुरातत्वीय स्मारकों और पुरावशेषों की समुचित देखभाल न होने के कारण इन की चोरी की घटनायें बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्ति अपने आप को पुरातत्वीय विभाग के अधिकारी जता कर और यह कह कर कि वे पुरावशेषों आदि को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में ले जा रहे हैं, उन पुरावशेषों को ले जाते हैं और उन्हें विदेशियों को बेच देते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा संरक्षित केवल 316 स्मारक हैं जिनमें 1963 से मई 1967 तक 9 चोरियां हुईं, 1963 में 3, 1964 में 1, 1965 में 2, और 1967 में (मई तक) 3 ।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसे कोई मामले नहीं आये हैं ।

(ग) अपराधियों को पकड़ने के लिये पुलिस का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के अलावा, पुरातत्वीय महत्व की असंगठित मूर्तियों को जहां तक संभव हो मूर्ति शेडों में और संग्रहालयों में ले जाने तथा धन की मौजूदा सीमाओं के भीतर चौकीदारी और निगरानी को और अधिक कड़ा करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

Centre-States Relations

1687. **Shri S. M. Banerjee:**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the reported speech of the Chief Justice of India, as quoted in the 'Hindustan Times' of the 17th April, 1967 that the Supreme Court has powers to resolve conflicts between Centre and the State Governments; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) The Government are in complete agreement with the reported observation of the Chief Justice of India that there are elaborate provisions to resolve the disputes between the Centre and States relating to legislative powers or the existence or extent of any legal right.

भारत और भूटान के बीच डाक संबंधी करार

1688. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री वस्तात्रय कुंटे :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान और भारत के डाक विभागों के बीच डाक और तार के बारे में हाल में एक नया करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। 21 अप्रैल, 1967 को दो डाक व्यवस्थाओं पर (एक पत्र डाक के आदान-प्रदान के लिये और दूसरी मनीआर्डर के आदान-प्रदान के लिए) हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) पत्र-डाक व्यवस्था के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच रजिस्ट्री और बेरजिस्ट्री वस्तुओं का विनिमय किया जाएगा। भूटान की डाक दरें व शुल्क भारतीय डाक-दर और शुल्क के अनुरूप होंगी। एक देश की डाक को दूसरे देश से भेजने पर किसी भी प्रशासन द्वारा कोई भी पारगमन शुल्क नहीं दिया जाएगा।

मनीआर्डर व्यवस्था के द्वारा भारतीय रुपये में दोनों देशों के बीच मनीआर्डरों का विनिमय किया जा गा ; अधिक से अधिक रुपया भेजने की सीमा और कमीशन की दरें वही होंगी जो भारतीय देशीय मनीआर्डर सेवा में लागू हैं।

Profit Sharing Bonus in Coal Mines

1689. Shri Deven Sen: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the profit-sharing bonus for 1965 has not been paid to the various collieries in the Uktra-Kajora-Bombula belt of Asansol Sub-division, District Burdwan, though it has become due since long;

(b) whether all attempts for the settlement by the Conciliation Officer (Central) Asansol have failed; and

(c) if so, the steps taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) Out of 104 collieries in the Ukhra-Kajora-Bohula belt of Asansol Sub-division, 75 have already paid the profit-sharing bonus for the accounting year 1965.

(b) and (c). The defaulting collieries have been served with show-cause notices to explain why action should not be taken against them for contravention of the Payment of Bonus Act, 1965. Proposals to prosecute these collieries are under the examination of the Government.

जनगणना के आंकड़े

1690. **श्री ओ० प्र० त्यागी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है तथा हिन्दुओं, मुसलमानों तथा ईसाइयों की जनसंख्या पृथक पृथक कितनी है ; और

(ख) 1951 से 1961 तक के 10 वर्षों की अवधि में हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों की जनसंख्या में किस अनुपात से वृद्धि हुई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	1961 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	प्रतिशत वृद्धि—(1951—1961)
(1)	(2)	(3)
भारत	439,234,771	—
हिन्दु	366,502,878*	20.29
मुस्लिम	46,939,357*	25.61
ईसाई	10,726,350	27.38

इसमें उत्तर-पूर्वी सीमांत अभिकरण की जनसंख्या शामिल नहीं है ।

टिप्पणी :—उत्तर-पूर्वी सीमांत अभिकरण के विषय में 1961 और उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण, जम्मू व काश्मीर और पांडीचेरी के विषय में 151 के लिए पृथक्-पृथक् धर्मवार संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । इस प्रकार आंकड़ों के दो समूह निश्चित तुलना के योग्य नहीं हैं । अतः कालम तीन में दिखाई गई प्रतिशत वृद्धि तुलनात्मक क्षेत्रों के लिये है ।

असिस्टेन्ट और अपर डिविजन क्लर्क

1691. **श्री राम चरण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित असिस्टेंटों और अपर डिवीजन क्लर्कों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इन दोनों श्रेणियों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी प्रशासनिक शाखा में काम करते हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 20.

(ख) 2.

अराजपत्रित कर्मचारियों को विशेष भत्ते

1692. **श्री राम चरण** : क्या शिक्षा मंत्री 27 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4545 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अराजपत्रित कर्मचारियों के इन पांच पदों पर, जिन पर दैनिक अथवा रहे हैं, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन पदों पर लम्बी अवधि से काम कर रहे इन व्यक्तियों में से किसी के स्थान पर अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के किसी कर्मचारी को नियुक्त करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां । एक ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

जनता से प्राप्त हुए सुझाव

1693. **श्री राम चरण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में उनके मंत्रालय में जनता से कितने सुझाव प्राप्त हुए ;

(ख) उनमें हिन्दी और अंग्रेजी में पृथक्-पृथक् कितने सुझाव थे ;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) उनमें से कितने सुझावों को केवल उनकी प्राप्ति की सूचना भेजने के बाद फाइल कर दिया गया ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी करने में जो समय और मेहनत लगेगी, वह प्राप्त होने वाले नतीजों की समसामयिक न होगी ।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

1694. **श्री राम चरण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो उस मंत्रालय के

स्वायत्तशासी निकायों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं ; और

(ख) उन्हें प्रति मास कितना प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 91.

(ख) उनको सामान्य नियमों के अनुसार प्रत्येक मामले में जो भी प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जा सकता है, दिया जा रहा है ।

Mining Operations in Jharia

1695. Shri Beni Shanker Sharma:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the mining operations are going on underneath the Jharia town;

(b) if so, the names of the Companies engaged on these operations;

(c) whether they are acting strictly in accordance with the provisions of the law and whether sounds of blasts are heard in the night by the people sleeping in their homes causing anxiety to them about their safety;

(d) whether blasting operations endangering the life and property of the people are permissible legally; and

(e) if not, the steps Government are taking to stop such illegal activities?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) Yes.

(b) The companies are the South Jharia Colliery of M|s. J. K. Banerjee & others and the East Bhuggatdih Colliery of M|s. East Bhuggatdih Coal Company (P) Ltd., Jharia.

(c) The colliery companies are acting strictly in accordance with the provisions of the Mines Act and Regulations. Sounds of blasting in the underground workings are at times heard on the surface.

(d) Does not arise as blasting operations are not endangering life and property.

(e) Does not arise.

Partition Implementation Committee Report

1696. Shri Hem Raj: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Punjab Partition Implementation Committee has completed the various items pending between the two Governments; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). The Governments of Punjab and Haryana who were consulted have reported that there is no Committee called the Punjab Partition Implementation Committee. However, in January 1967, it was decided that the stores relating to Secretariat and offices of Heads of Departments which had jurisdiction over the composite State of Punjab should be divided by agreement and that the Chief Secretaries of Punjab, Haryana and Himahal Pradesh and the Chief Commissioner of Chandigarh should meet and settle these matters. It was also decided that un-issued stores of the composite State of Punjab should be divided by a committee consisting of Chief Secretaries of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and that in doing so, requirements of Chandigarh should be kept in view. It is reported that the division of stores of 24 departments has been effected by agreement and that the work of dividing the stores of other departments is in progress. Information is also being collected by the Government of Punjab regarding the un-issued stores. The Committee of Chief Secretaries will take up the question of division of these stores as

soon as the information has been collected. Schemes for division of various Inter-State Corporations are also being drawn up by the Government of Punjab. It is reported that the scheme relating to the Khadi and Village Industries Board has since been finalised in consultation with the other Governments concerned and some more schemes are expected to be finalised shortly.

Mortar Shell Explosion near Ranjitpura (Rajasthan)

1697. Dr. Karni Singh: Will the Miniter of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that nine children were killed and several others received serious injuries as a result of mortar shell explosion near Ranjitpura on the border of India and Pakistan in Rajasthan in February, 1967;

(b) if so, whether the cause of explosion have been ascertained and the compensation, if any, paid to the families of the children killed and those injured; and

(c) the steps taken to clear the entire area of five mortars which found their place there during the Indo-Pak. conflict?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) Yes, Sir. Nine children were killed and one woman and a child were injured as a result of a mortar explosion near Ranjitpura, District Bikaner, on 15-2-1967.

(b) While collecting fire-wood the children picked up a three-inch mortar bomb left over from the Indo-Pak. conflict of 1965. One of the boys hit the bomb with an axe, as a result of which it exploded. The question of payment of compensation if any to the families of the children killed and injured is under consideration of the State Government.

(c) Necessary steps were taken by the Army to locate and neutralise any un-exploded bombs and rocket-shells in these areas and constant watch is kept for any stray un-exploded shell or bomb.

South Africa's Apartheid policy

1698. Shri H. N. Mukerjee: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the move initiated by a number of African countries to ensure that South Africa gives up its Apartheid policy in sport or is compelled to keep out of the Olympic Games at Mexico in 1968; and

(b) whether Government are giving adequate direction to the Indian Olympic Association and other relevant bodies in this matter?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Yes, Sir.

(b) Necessary advice has been given to the Indian Olympic Association on the subject.

Iron Ore Mines Labour Welfare Fund

1699. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) how much money has been collected so far in the Iron-ore Mines Labour Welfare Fund;

(b) how much cess is levied on the production of one metric tonne of iron-ore; and

(c) how much money has been spent out of the said fund?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) Rs. 165.34 lakhs approximately.

(b) 25 paise per tonne.

(c) Rs. 21.79 lakhs approximately.

मिजो पहाड़ियों को संघ राज्यक्षेत्र का दर्जा देना

1700. श्री ... :
श्री हाराज सिंह भारती :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री भोलाह प्रसाद :
श्री रवि राय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिजो पहाड़ियों को संघ राज्यक्षेत्र का दर्जा देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लोक-कथाओं का संरक्षण

1701. श्री प० ला० बारूपाल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों में हमारी प्राचीन लोक-कथाओं का जल्दी ही लोप हो रहा है, क्या उनके संरक्षण के लिये सरकार किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). लोक संगीत, लोक नृत्य और और लोक नाटक के पुनरुत्थान और संरक्षण के लिए संगीत नाटक अकादमी का एक कार्यक्रम है । अकादमी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) इन कलाओं से सम्बन्धित टेप संगीत, फिल्म और फोटोग्राफी के रूप में बड़ी मात्रा में सामग्री एकत्र करना ;

(ii) सेमिनारों और समारोहों का आयोजन, जिनमें लोक कला के रूप सदैव एक अभिन्न अंग रहे हैं;

(iii) वित्तीय सहायता देकर इन कला रूपों से सम्बन्धित अनुसंधान—लेखों के प्रकाशन में सहायता;

(iv) अभिनय कला के क्षेत्र में लगी अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना;

(v) चौथी पंचवर्षीय आयोजना में लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाटक के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए तथा संगीत साजों, लोक वेशभूषा और मुखौटों आदि के अपने संग्रहालय के विस्तार की भी अकादमी की एक योजना है ।

ललित कला अकादेमी, साहित्य अकादेमी और आकाशवाणी के भी अपने अपने क्षेत्र में लोक संगीत और कला के संरक्षण के लिये कुछ कार्यक्रम हैं ।

शहीदों की समाधियां

1702. श्री प० ला० बारूपाल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमर शहीद सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु सुखदेव की समाधियां जीर्णावस्था में पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन महत्वपूर्ण समाधियों का नवीकरण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकार को इस की जानकारी नहीं है ।

(ख) क्योंकि समाधियां एक सौ वर्ष से कम पुरानी हैं, इसलिए ऐनसेंट मान्यूमेंट एण्ड आर्कियोलोजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1958" के अधीन उसका संरक्षण नहीं दिया जा सकता ।

गंगानगर जिले में पुरातत्व सम्बंधी खुदाई

1703. श्री ए० ला० बारूपाल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के गंगानगर जिले में कालीबंगा में पुरातत्व सम्बन्धी जो खुदाई की गई है, उससे क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ख) क्या प्राचीन वस्तुओं का पता लगाने के लिये यह खुदाई जारी रहेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य पर कितना धन खर्च करने का विचार है और इस सम्बंध में कितना समय लगने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :(क) कालीबंगा में की गई खुदाई से इस स्थल पर बस्तियों की दो कालों का पता चला है । इन में से ऊपर वाला (दूसरा काल) हड़प्पाकालीन (लगभग 2300—1800 ई०पू०) था ; निचली बस्ती (पहला काल) हड़प्पा पूर्व की थी और इसके किले की दीगल ईंटें मिट्टी की चिनाई की बनी थी । हड़प्पाकालीन बस्ती (दूसरा काल) में दो प्रमुख अंग थे ; (क) दुर्ग और (ख) नीचे का शहर । दुर्ग परित्यक्त हड़प्पा पूर्व बस्ती के स्थल पर मिला था, नीचे का शहर इससे करीब 40 मीटर पूर्व की ओर था, दुर्ग में दो—अलग अलग ढांचे वाले रास्ते और करीब—करीब समान आकार के हिस्से मिले हैं, जो प्रत्येक अलग अलग प्राचीर से घिरा हुआ है । दक्षिण वाले आधे हिस्से में चार से छः तक ईंट मिट्टी के चबूतरें ह, जिनमें से कुछ का इस्तेमाल धार्मिक या संस्कार कार्यों के लिये होता होगा । दुर्ग के उत्तर वाले आधे हिस्से में श्रेष्ठ जनों के रहने की इमारतें थीं । संभवतः निचले शहर के भी चारों ओर दीवाल थी । इसके भीतर उत्तर—दक्षिण और पूर्व—पश्चिम चलने वाले मार्ग मिले हैं, जिनपर विशिष्ट ग्रिड पद्धति के मकान थे ।

(ख) जी हां, लेकिन कुछ ब्यौरे का

(ख) जी हां । लेकिन कुछ ब्यौरों का पूरा करने के लिए छोटे से पैमाने पर ही ।

(ग) 50,000 रु० । काम के इस साल पूरे हो जाने की उम्मीद है ।

Privy Purses

1704. Shri S. R. Damani: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether there has been any variation in the quantum of payment of privy purses during 1966-67; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). There has been a reduction of Rs. 40,000 per annum on account of payment of a reduced amount in one case in accordance with the provisions of the Merger Agreement.

Taj Mahal

1705. Shri Baburao Patel: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to an article entitled "The Most Sensational Dis-

covery in 300 Years" by Shri P. N. Oak regarding the building of Taj Mahal, published in the February 1967 issue of *Mother India;*

(b) whether in view of the sensational revelations made by the writer, Government propose to appoint a Committee of historians and archaeologists to investigate the truth of the statements made in the said article; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) It is primarily for scholars and research institutions to establish their theories.

Missing File regarding Dr. Joshi Murder Case

1706. Shri Bal Raj Madhok: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the file regarding Dr. Joshi murder case including the judgment of the trying Sessions Judge is missing from the record room of the Delhi Courts;

(b) whether any inquiry has been instituted to find out the whereabouts of the said files; and

(c) if so, the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Sessions case under Section 302 I.P.C., State versus Abdul Ghani Quereshi, decided on 1-6-1948, is not in the record rooms of the Delhi Courts.

(b) and (c). An inquiry has been instituted by the District and Sessions Judge, and is in progress.

Ahmedabad Post Office

1707. Shri Manibhai J. Patel: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the volume of work and the strength of staff of a post office where Class-I Post Master is posted;

(b) the volume of work and the staff strength in Ahmedabad Post Office; and

(c) the reasons for not posting a Class-I Post Master in Ahmedabad Post Office?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Post offices are placed in charge of Class I Postmasters on the basis of the number of clerks working therein. Generally, only those post offices which have about 300 clerks are placed in charge of a Class I Postmaster.

(b) The number of clerks in Ahmedabad GPO is 166.

(c) A Class I Postmaster has not been posted to Ahmedabad post office as the clerical strength of the office falls much short of 300.

दिल्ली में हडसन लाइन्स तथा आउटरम लाइन्स के क्वार्टर

1708. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में हडसन लाइन्स तथा आउटरम लाइन्स स्थित क्वार्टरों की कीमत की वसूली में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि यह कीमत आठ वार्षिक किस्तों में वसूल की जानी थी लेकिन अब खरीदारों को ब्याज सहित कई किस्त एक मुश्त अदा करने के नोटिस दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन अनियमितताओं को दूर करने तथा इन कीमतों के आगे साधारण वार्षिक किस्तों में वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम के नियम 42 के अनुसार गैर-दावेदार विस्थापित व्यक्तियों को 1-10-59 तक मूल्य के 20 प्रतिशत का भुगतान करना था और बकाया ब्याज सहित सात बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना था। बाकी-दारों को बकाया के भुगतान के लिये नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shifting of Offices to Nagpur

1709. Shri D. S. Patil: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether consequent on the shifting of the office of the Post-Master General from Nagpur to Bhopal, Government have decided to shift other important Post and Telegraph Offices to Nagpur from other places; and

(b) if so, the progress so far made in this regard?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Cost of Living Index

1710. Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri K. Pradhani:
Shri Heerji Bhai:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the cost of living index in Delhi is rising; and

(b) if so, the nature of the rise during 1966-67?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). The following table of monthly Consumer Price Index Numbers for industrial workers in Delhi during 1966-67 indicates the extent of rise:—

Year/Month		Index Numbers base 1960 —100
1966	January	138
	February	138
	March	140
	April	142
	May	145
	June	150
	July	151
	August	151
	September	151
	October	152
	November	154
	December	155
1967	January	157
	February	159
	March	161
	April	162

Outstanding Telephone Revenue in Orissa

1711. Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri K. Pradhani:
Shri Heerji Bhai:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total amount of telephone revenue outstanding at present in Orissa; and

(b) the steps taken to recover the same?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Rs. 9:83 lakhs on 1-2-1967 for bills issued upto 31-10-66.

(b) Action has been taken to enforce the disconnection of telephones of defaulting subscribers. Other special steps, such as, pursuing the defaulting subscribers, recourse to legal action, where necessary, are also

being taken to secure early settlement. For a more effective pursuit, the telephone revenue work relating to Cuttack Division has been transferred from Calcutta to Cuttack with effect from 1-9-66.

Postal Services in Orissa

1712. **Shri Ramachandra Ulaka:**
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri K. Pradhani:
Shri Heerji Bhai:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of villages covered by postal service in Orissa till the end of April, 1967; and

(b) the number proposed to be covered by postal services during 1967-68?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). All the villages in Orissa are already covered by postal services.

Rehabilitation Industries Corporation

1713. **Shri Ramachandra Ulaka:**
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri K. Pradhani:
Shri Heerji Bhai:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the amount outstanding as on the 30th April, 1967 with various industrial concerns who were provided with loans by the Rehabilitation Industries Corporation?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): A statement showing arrears of loans and interest outstanding as on 30th April, 1967, is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-553/67].

C.I.A. help to Seamen's Unions

1714. **Shri Chintamani Panigrahi:**
Shri C. K. Bhattacharyya:
Shri P. Gopalan:
Shri K. Ramani:
Shri Umanath:
Shri Nambiar:
Shri Mohsin:
Shri Vasudevan Nair:
Shri C. Janardhanan:
Shri Shashi Ranjan:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Yashpal Singh:
Shri S. C. Samanta:
Shri S. N. Maiti:
Shri Tridib Kumar Chaudhuri:
Shri K. N. Pandey:
Shri D. N. Deb:
Shri P. K. Deo:
Shri K. P. Singh Deo:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Central Intelligence Agency of U.S.A. had helped to organise Seamen's Unions in India;

(b) whether Government have now found out which Seamen's Unions in India received C.I.A. funds; and

(c) if so, the particulars of those Unions and their office-bearers and affiliations?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Government have seen press reports to the effect that the Central Intelligence Agency of the U.S.A. had helped organize Seamen's Unions in India.

(b) and (c). An inquiry is being made.

Aligarh Muslim University Act

1715. **Shri Mohsin:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government intend to bring forward a new Bill to replace the present Aligarh Muslim University Act; and

(b) if so, when?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) and (b). Yes, Sir. A Bill to amend the present Aligarh Muslim University Act will be brought forward as soon as possible.

Panchayat Samiti Offices in Rajasthan

1716. Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri K. Pradhani:
Shri Heerji Bhai:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Panchayat Samiti Offices in Rajasthan provided with telephones as on the 30th April, 1967; and

(b) the number of Panchayat Samiti Offices in the State to be provided with telephones during 1967-68?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) 177 places having Panchayat Samiti Offices have been provided with Telephones facility as on 30th April, 1967; and

(b) 15 such places are likely to be provided with telephone facility during 1967-68.

At all such places, telephones can be provided to the Panchayat Samiti Offices on rental basis, as and when applied for.

Quarters for P&T Employees in Rajasthan

1717. Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Heerji Bhai:
Shri K. Pradhani:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Post and Telegraph employees in the Rajasthan Circle who have been provided with Government residential accommodation till the 30th April, 1967;

(b) whether there is any proposal to construct staff quarters for the Post and Telegraph staff in the Rajasthan Circle during 1967-68; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) 972.

(b) Yes, Sir.

(c) (i) *Quarters under construction:*
Pilani—4. Costing approximately Rs. 40,000.

Kekri—4. Costing opproximately Rs. 40,000.

(ii) *Quarters proposed for* 1967-68:
Bilara—4. Cost Rs. 66,000 approximately.

Beawar—1. Cost Rs. 25,000 approximately.

(iii) Construction of 56 quarters costing about Rs. 7 lakhs at Jaipur is also being processed.

Post Offices in Rajasthan

1718. Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Heerji Bhai:
Shri K. Pradhani:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Branch Post Offices, Sub-Post Offices and Public Call Offices in Rajasthan as on the 30th April, 1967; and

(b) the number of such offices proposed to be opened in that State during 1967-68?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Branch Post Offices—5,020.

Sub Post Offices—659.

Public Call Offices—226.

(b) Owing to the financial stringency restrictions have been imposed on the opening of new Extra Departmental

Branch Post Offices. In case these are removed, 124 EDBOs, 10 Departmental Sub Offices and 20 Public Call Offices are likely to be opened.

Telephone Connections in Rajasthan

1719. **Shri Dhuleshwar Meena:**
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri K. Pradhani:
Shri Heerji Bhai:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of applications for grant of telephone connections pending in various telephone exchanges in Rajasthan as on the 30th April, 1967; and

(b) the steps taken to expedite the matters?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) 5,314.

(b) Efforts are continuously being made to open new exchanges, expand the existing exchanges and lay underground cables to give more and more connections.

Retrenchment in C.S.I.R.

1720. **Shri D. C. Sharma:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the Council of Scientific and Industrial Research Workers' Union has urged to defer the proposed retrenchment of Class III and IV employees in C.S.I.R. and its Laboratories;

(b) whether they have also opposed the move for part payment of Dearness Allowance in the form of national securities or through the revival of the compulsory Deposit Scheme and demanded *inter alia* housing facilities, promotion on the basis of seniority and fixation of pay scales in conformity with the Second Pay Commission's recommendations; and

(c) if so, the decisions taken in the matter?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) and (b). No such representation or demand has been received from the C.S.I.R. Workers' Union.

Incidentally, there is no proposal for retrenchment under the consideration of the Council of Scientific and Industrial Research.

(c) Does not arise.

Cumulative Time Deposit Accounts

1721. **Shri D. N. Patodia:**
Shri Mohammed Imam:
Shri S. K. Tapuriah:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are huge arrears due to the public in the Cumulative Time Deposit Accounts with the P. & T. Deptt.; and

(b) if so, the details thereof and the reasons for not paying the amount to the persons concerned?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). There are three types of CTD Accounts viz. 5-year, 10-year and 15-year. The CTD Scheme having been introduced from 1st January, 1959, only the 5-year CTD Accounts have so far been maturing for payment from 1st January, 1964 onwards. Out of 6,20,314 5-year CTD Accounts opened upto 31st March 1962, 3,55,442 Accounts had been closed till 31st March 1967. Unless, the depositor calls at the post office for closing the account and receiving the payment, the Department is not in a position to make the payment.

Boundary Disputes between Orissa and Bihar

1722. **Shri Chintamani Panigrahi:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Eastern Zonal Council meeting recently held in Cal-

cutta discussed the boundary disputes between Orissa and Bihar;

(b) whether the Orissa Government raised this question in the Conference;

(c) if so, whether any decisions have been taken in this regard;

(d) whether the difficulties of the Oriya-speaking population in the District of Singhbhum in Bihar were brought to the notice of the Council; and

(e) if so, the decisions taken to safeguard their interests?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Yes, Sir.

(e) The proceedings of the meeting embodying *inter alia*, the decisions of the Council will be placed in the Parliament Library as usual as soon as the Proceedings are finalised.

Greetings by Telephone Operators

1723. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal that Telephone Operators in Delhi should wish 'Namaskar' instead of 'Good Morning'; and

(b) if so, when the Hindi expression will be introduced all over India?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The proposal has already been implemented from 17th May, 1967 in Delhi.

(b) There are no proposals at present to introduce the new expression all over India.

Images for National Museum

1724. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether some images belonging to ancient times have been acquired by the National Museum from foreign countries; and

(b) if so, the amount spent in foreign exchange for bringing them to India?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) Yes, Sir, by way of gifts presented to the National Museum.

(b) No Foreign exchange expenditure was incurred by the National Museum.

स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें

1625. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों के मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि दसवीं कक्षाओं तक के विद्यार्थियों के लिये पाठ्य पुस्तकें विधिवत विचार करने के बाद एक बार मंजूर की जानी चाहियें और वे कई वर्षों तक रहनी चाहियें तथा प्रति वर्ष पुस्तकें मंजूर करने की प्रथा समाप्त कर देना चाहिये और यदि हां, तो उस पर प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पाठ्य पुस्तकें राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित और निर्धारित की जाती हैं। इसलिए इस मंत्रालय के लिए यह बताना संभव नहीं है कि पाठ्य पुस्तकों के संबंध में स्कूलों में कोई भ्रष्टाचार विद्यमान है या नहीं।

(ख) और (ग). पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का संबंध राज्य सरकारों से है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है। तथापि, मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात को छोड़ कर बाकी सभी राज्य सरकारों ने विभिन्न स्तरों और भिन्न-भिन्न मात्राओं में पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन का राष्ट्रीयकरण कर दिया है।

गांवों में डाकघर

1726. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि में गांवों में डाकघर खोलने के लिये कितनी जनसंख्या की सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे गांवों में, जहां हाई स्कूल और कालेज हैं, उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखकर डाकघर खोलने का है ;

(ग) क्या गांवों के डाकघरों पर व्यय उनकी आय के अनुपात से किया जाता है अथवा यह समान होता है ; और

(घ) गांव के प्रत्येक डाकघर पर औसतन वार्षिक व्यय कितना होता है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) डाकघर उन गांवों या दो मील की अरीय दूरी के भीतर आने वाले गांव-समूहों में, जिनकी आबादी 2000 या उससे अधिक हो खोला जाता है, बशर्ते कि मौजूदा डाकघर से उसकी दूरी तीन मील से कम न हो और घाटा प्रतिवर्ष 750 रु० से अधिक न हो। डाकघर उन गांव-समूहों में भी खोले जा सकते हैं जिनकी आबादी 2,000 से कम हो बशर्ते कि किसी मौजूदा डाकघर की दूरी तीन मील से कम न हो और घाटा प्रतिवर्ष 500 रु० से अधिक न हो। उन स्थानों के लिए जो सामुदायिक प्रायोजनाओं के मुख्यालय हों, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड हों या जहां जिला परिषद् या स्थानीय बोर्डों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल हों या ऐसे स्कूल हों जो राज्य सरकारों से स्वीकृत हों या जिन्हें उनसे सहायता मिलती हो, मौजूदा डाकघर से दूरी की सीमा की शर्त घटाकर 2 मील कर दी जाती है। उन क्षेत्रों में जिन्हें अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र घोषित किया गया हो, न्यूनतम आबादी की कोई पाबन्दी नहीं है। फिर भी आबादी या दूरी पर विचार किये बिना भी डाकघर खोले जा सकते हैं, बशर्ते कि उसमें दिलचस्पी रखने वाली कोई पार्टी न लौटाये जाने वाला अनुदान देकर उसे चलाने पर होने वाला कुल खर्च वहन करने के लिए तैयार हो।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। दूसरी शर्तें पूरी होने पर डाकघर खोले जा सकते हैं बशर्ते कि वार्षिक व्यय और आय में इतना अन्तर हो जो उस विशेष मामले पर लागू होने वाले घाटे का अनुमत्य सीमा के भीतर हो।

(घ) लगभग 1,000 रु०

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को मेरठ में बसाना

1727. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान

से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को मेरठ में बसाने की योजना बनाई है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह पुनर्वास कार्य सरकार द्वारा न किया जा कर अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई संगठन की भारतीय शाखा से करवाया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उनकी रुचि और शिक्षा के अनुसार नहीं दिया जाता बल्कि मनमाने ढंग से काम दिया जाता है जिस कारण उनमें से अधिकांश व्यक्ति उस काम को स्वीकार करने से इन्कार कर देते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० न० मिश्र) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को मेरठ जिले में पुनर्वास देने के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं। इन योजनाओं की सूची तथा प्रत्येक योजना में पुनर्वासित किये जाने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सभी योजनायें उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी या पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा अमल में लाई जायेंगी। तथापि एक अन्य योजना, पूर्वी पाकिस्तान से आये 50 प्रव्रजक परिवारों को हस्तिनापुर के गंगाखादर क्षेत्र में कृषि पर बसाने के लिये, भारतीय ईसाई परिषद् द्वारा क्रियान्विति की स्थिति में है। वह एक आजमायशी योजना है जिसे भारतीय ईसाई परिषद् ने स्वेच्छा से लिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	योजना	पुनर्वास पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	हस्तिनापुर में एक असार्वजनिक कताई मिल के लिये इस शर्त पर आर्थिक सहायता दी जायेगी यदि विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया जाये ।	600
2	हस्तिनापुर में कताई मिल में रोजगार पाने वाले विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की योजना ।	
3	हस्तिनापुर में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा सहकारी रूप से 250 बिजली चालित करघे स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता ।	250

क्रम संख्या	योजना	पुनर्वास पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
4	मेरठ के निजी औद्योगिक खण्डों में प्रशिक्षण पाने वाले विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों को इस उद्देश्य से वित्तीय सहायता कि उन्हें अन्त में उन खण्डों में रोजगार मिल सके ।	200
5	हस्तिनापुर में एक बढ़ईगीरी खण्ड स्थापित करने के लिये एक निजी पार्टी को पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा वित्तीय सहायता ।	200
6	कृषि औजार निर्माण करने के लिये पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा एक खण्ड की स्थापना ।	100
7	हस्तिनापुर में उद्योग प्रशिक्षण संस्था	126
8	हस्तिनापुर में सीमेन्ट कंक्रीट से सामान बनाने का खण्ड ।	95
9	हस्तिनापुर के गंगाखादर क्षेत्र में मछुओं के कार्य में विस्थापित व्यक्तियों का बसाया जाना ।	25

हस्तिनापुर का विकास तथा प्रबन्ध

1728. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के हस्तिनापुर के प्रबन्ध तथा विकास के लिये राज्य के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्रीय सरकार के कितने प्रतिनिधि काम करते हैं तथा केन्द्र व्यय का कितने प्रतिशत वहन करता है ;

(ख) उक्त स्थान पर पुनर्वास कार्य में कितना समय लगने तथा खर्च होने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में राज्य सरकार ने संसाधनों के अपने भाग नहीं जुटाये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) हस्तिनापुर नगर विकास बोर्ड में दो केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हैं। प्रतिवर्ष 10,700 रुपये की अधिकतम सीमा तक, केन्द्रीय सरकार आय में कमी तथा बोर्ड के खर्च को वहन करती है।

(ख) मंजूरशुदा योजनायें या जो योजनाएं विचाराधीन हैं, उन्हें तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण करने की संभावना है और अनुमानतः इन पर 97 लाख रुपये खर्च होंगे।

(ग) जी नहीं।

मिजो विद्रोहियों से हथियारों का पकड़ा जाना

1729. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री राम सिंह अयर गल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1967 के प्रारम्भिक चरण में सुरक्षा सेनाओं ने फैलांग के निकट मिजो विद्रोहियों से हथियारों का छिपाया हुआ एक बड़ा भण्डार पकड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन हथियारों पर किन देशों के चिन्ह अंकित हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

Delhi High Court Bench for Himachal Pradesh

1730. Shri K. N. Pandey: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Himachal Bench of the Delhi High Court has started functioning at Simla with effect from the 3rd May, 1967; and

(b) if so, how much expenditure will be incurred during the year on this Bench?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) Yes, Sir from 1st May, 1967.

(b) The basis on which the expenditure on this Bench is to be determined is under consideration.

महानगर परिषद् दिल्ली

1731. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री किस्कू :
श्री स० ना० भाइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में महानगर परिषद् के बनने के बाद केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्य सूची में सम्मिलित सभी शक्तियां उपराज्यपाल को सौंप दी गई हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि महानगर परिषद् के बनने के बाद भी कई मंत्रालयों ने विषय तथा शक्तियां दिल्ली प्रशासन को नहीं सौंपी हैं ; और

(ग) इस शिकायत को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) संविधान में दी गई राज्य सूची में, उन विषयों का उल्लेख है जिनके सम्बन्ध में राज्य विधान सभा कानून बनाने के लिए सक्षम है। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, इन विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति संसद् को प्राप्त है और यह शक्ति उपराज्यपाल को हस्तान्तरित नहीं की गई है।

(ख) और (ग). सरकार का ध्यान दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद के, 9 मई,

1967 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना तथा राजधानी के सभी अस्पतालों को दिल्ली प्रशासन के नियंत्रण के अधीन लाया जाना चाहिये।

इन मामलों तथा इस समय मंत्रालयों द्वारा प्रयुक्त शक्तियां उपराज्यपाल को प्रत्यायोजित किये जाने के प्रश्नों पर मुख्य कार्यकारी पार्षद द्वारा गृह मंत्री के साथ 27 मई, 1967 को चर्चा की गई। इसके दौरान यह बताया गया कि सफदरजंग अस्पताल तथा विलिंगडन अस्पताल का हस्तान्तरण व्यवहार्य नहीं था क्योंकि ये दोनों अस्पताल मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हैं और शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा डिस्पैन्सरियों के शीर्ष संस्थान थे। दिल्ली दुग्ध योजना को दिल्ली प्रशासन को सौंपने के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपराज्यपाल को शक्तियां सौंपने के विषय में, यह सुझाव दिया गया कि दिल्ली प्रशासन को विभिन्न संबंधित मंत्रालयों, को उनके विचार के लिये, विस्तृत सुझाव भेजने चाहिए।

G.P.O., Bhubaneswar

1732. Shri Chintamani Panigrahi: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the area of the Capital at Bhubaneswar in Orissa is increasing rapidly;

(b) if so, the number of letters and other postal articles being handled daily in the G.P.O. at Bhubaneswar; and

(c) the steps taken to increase the delivery and sorting staff of the G.P.O. at Bhubaneswar for facilitating quick and timely delivery of letters?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement on the points raised has been laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

I. *No. of letters and other postal articles being handled daily in the GPO at Bhubaneswar on an average.*

(a) Unregd. articles received for delivery :

Through Postmen	6489
Through Post Boxes	6669

(b) Unregd. articles posted for despatch: 23,170
(The sorting work is done at the Bhubaneswar Head Office) Sorting Office (RMS)

(c) Accountable articles posted for despatch:

Registered letters	251
Insured Letters	5
VP letters	2
Registered Parcels	30
Money Orders	110

(d) Accountable articles received for delivery :

Registered letters	691
Insured Letters	2
VP letters	17
Registered Parcels	108
VP Parcels	4
Insured parcels	1
MOS paid	155
Unpaid letters	23

II. *Steps taken to increase the delivery and sorting staff of the GPO at Bhubaneswar for facilitating quick and timely delivery of letters:*

The establishment of the post office was reviewed last on 22nd February, 1967 and as a result eight postmen, one Reader postman and one Delivery clerk were sanctioned. In February, 1967, one more delivery office *viz.* Bhubaneswar-6 was opened. It has also been decided that the number of beats should be increased from 14 to 18 with effect from the 1st June, 1967.

Work-charged Staff at G.P.O., Bhubaneswar

1733. Shri Chintamani Panigrahi: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that out of 40 departmental

officials in the Bhubaneswar G.P.O., thirty are working on ten days work-charged basis;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether representations have been received that these thirty men are being appointed at the mercy of the appointing authorities and their services are also being utilised in performing personal work; and

(d) if so, the steps taken in the matter?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). It is not a fact that out of 40 departmental officials in Bhubaneswar G.P.O., 30 are working on work charge basis for 10 days. When the shortage of staff exceeds the permissible leave reserve in the cadre of postmen and Class IV staff in the Head Office, a few persons are occasionally appointed on a work charge basis.

(c) and (d). Such outsiders are employed on the personal responsibility of the Head of office or some other permanent official of the office. Allegations about 2 officials being utilised for personal work were received. On enquiry, these could not be substantiated.

Indian School of International Studies

1734. Shri Y. A. Prasad:
Shri N. K. Sanghi:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether a proposal to send a University Grants Commission team to enquire into the affairs of the Indian School of International Studies is under consideration of Government; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) and (b). No, Sir. The question was discussed with the Chairman, University Grants Commission. A Review Committee of the University Grants Commission which looked into the working of the School in 1965 found nothing exceptionable in its academic programmes and financial management. The Committee supported the School's continued recognition as a 'deemed' university. The Chairman of the University Grants Commission and I agree that in view of this, it is not necessary to appoint another team to inquire into the working of the School.

Assistance for Cultural Centres in U.P.

1735. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Education** be pleased to state?

(a) whether any financial assistance was given to Uttar Pradesh for the construction of Cultural Centres in the State during 1965-66 and 1966-67; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Yes, Sir.

(b) The details are given below:

1965-66

Rs. 17,686 to Nari Seva Samiti, Lucknow for the construction of auditorium.

1966-67

Rs. 7,500 to Ghatkhande College of Hindustani Music, Lucknow for the construction of building. The amount was not drawn by the grantee during 1966-67.

Counselling Centres at Universities

1736. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission's Committee on Students Welfare and Allied Matters has suggested the setting up of Counselling Centres at Universities and Colleges in the country to deal

with the emotional problems of students; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) The Committee has suggested introduction of a properly organised counselling system in the Universities and Colleges The Committee has further recommended that if this cannot be undertaken on a large scale due to paucity of resources, the tutorial system should be improved and encouraged.

(b) The Government generally agree with these suggestions.

I.A.S. Training

1737. Dr. M. Santosham: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the length of the period of training given to young men and women selected to the Indian Administrative Service before they are assigned independent charge as Heads of Departments or District Administrators;

(b) whether there is a prescribed period of training and, if so, whether it is uniformly applicable to all States;

(c) how does their efficiency compare with those who are promoted from the ranks by virtue of their long period of service and experience;

(d) whether there is any age restriction for I.A.S. officials for eligibility to responsible Administrative posts involving independent charge; and

(e) whether Government propose to introduce either minimum age or minimum period of experience before I.A.S. officials are posted as Administrative Heads?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). There is no prescribed period of training for examination recruits before appointment to senior posts and as Heads of Departments or District Officers. Such recruits are put on probation for two years and thereafter they are also appointed to junior posts for on-the-job training and experience. The late Shri V. T. Krishnamachari in his report in "Indian and State Administrative Services and Problems of District Administration" recommended a pattern of training to be imparted to examination recruits before being put in charge of districts and had suggested that a district charge should be given towards the end of the sixth or in seventh year of service. The State Governments are following the recommendations to the extent possible depending on local conditions.

(c) The annual competitive examination for the IAS is of a very high standard and is made against 75 per cent of the senior posts in each State Cadre, State Civil Service officers who have completed eight years' service are eligible to be considered for appointment to the I.A.S. against the remaining 25 per cent of the senior posts by selection. No comparison of efficiency after dividing officers into two such groups is practicable.

(d) No. It depends on suitability for such appointment.

(e) No, since the fitness for holding such posts is already determined on considerations of length of service, maturity and experience.

Allotment of C.S.I.R. Accommodation in Jamshedpur

1738. Shri Bhogendra Jha: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently some quarters were allotted to some officers who joined only in March, 1967 disregarding the rules for allotment of accommodation in C.S.I.R. in Jamshedpur while many senior officers are waiting for years for accommodation;

(b) whether residential quarter within the Low Shaft Furnace premises is kept unallotted for years caus-

ing loss of revenue to the exchequer and inconvenience to officers waiting for accommodation;

(c) whether any unauthorised subletting of C.S.I.R. accommodation in Jamshedpur has come to the notice of Government; and

(d) whether Government have received any representation from staff in this regard and if so, the action taken thereon?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) No, Sir, not in disregard of the rules.

(b) No, Sir. Few quarters built in the premises of Low Shaft Furnace Plant are meant exclusively for essential staff, including security, attached to the plant and are not available for general allotment.

The quarter in question has since been occupied w.e.f. 1st April, 1967 and, being rent free, there is no question of any loss of revenue.

(c) No, Sir.

(d) No representation has been received from any staff member of the laboratory. However, representations from some Associations have been received. Since these are not recognised Associations, no reply has been sent.

खानों में दुर्घटनायें

1739. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में विभिन्न खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) उनके परिणाम स्वरूप कितने खनिक मारे गये; और

(ग) मृत व्यक्तियों के परिवारों को कितनी राशि प्रतिकर के रूप में दी गई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अप्रैल, 1966 से मार्च, 1967 तक 264 घातक दुर्घटनाएं ?

(ख) 311 ।

(ग) इस प्रकार का मुआवजा कर्मकार प्रतिकर आयुक्तों द्वारा दिया जाता है, जो कि राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । दुर्घटना द्वारा मृत्यु की सूरत में दिया जाने वाला अधिकतम मुआवजा 10,000/- रुपये है । प्रत्येक मामले में दिए गए मुआवजे का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

Employees in Laccadive, Minicoy and Amindive Islands

1740. **Shri P. M. Sayeed:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Class I, Class II, Class III and Class IV officers employed in the Administration of the Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindive Islands at present;

(b) the number of officers who are natives of the Islands in each category of posts;

(c) whether it is a fact that even for Class IV posts, recruitments have been made from persons belonging to the mainland, when sufficient number of eligible candidates for such posts is available in the Islands; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). A statement is attached.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

STATEMENT

Classfication of posts	Total number of posts	Number of posts held by natives of the islands
(1)	(2)	(3)
Class I . . .	2	Nil
Class II . .	24	1
Class III . .	649	146
Class IV . .	266	215

Tellicherry Head Post Office

1741. Shri P. Gopalan:
Shri A. K. Gopalan:
Shri P. Ramamurti:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government had acquired a site for the construction of a building for the Tellicherry Head Post Office;

(b) if so, when the site was acquired;

(c) whether the work on the building has started;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) when the work will start; and

(f) when it will be completed?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) 25th July, 1961.

(c) No.

(d) The work could not be taken up during 1966-67 for want of funds.

(e) Tenders for the work were opened on 22nd May, 1967. The rates being on the high side, tenders are being reinvited. If reasonable rates are received on recall, the work is likely to be started during August, 1967.

(f) 18 months after commencement.

Indian Service of Engineers

1742. Shri G. S. Mishra: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the reasons for the delay in constituting the Indian Service of Engineers;

(b) the number of engineers unemployed at present in the country;

(c) the measures taken to secure employment for them; and

(d) the turn-out of engineers at present and what will be the rate of increase of unemployment among the Engineers in the next five years?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Divergent views were held by the State Governments on certain basic issues such as, the need for and composition of a Central Cadre in the Service, the general pattern of encadrement of posts, the question of inclusion of teaching and research posts etc. Some decisions have since been taken. A Memorandum along with the draft Cadre Rules, Recruitment Rules and Initial Recruitment Regulations have been sent to all State Governments on 31-3-1967. Further steps to constitute the Service will be taken as soon as their comments are received.

(b) there were 4,335 Engineering Graduates (including post-graduates) on the live register of Employment Exchanges in the country as on 31st December, 1966. Not all unemployed engineers are registered in the Employment Exchange. Those registered also include some who are employed but are seeking better employment. Registration in the Employment Ex-

change, therefore, provides only a rough indication of the unemployment position.

(c) various development schemes under the Five Year Plan are directed towards creating employment opportunities for all categories of the unemployed including Engineers;

(d) the out-turn of engineering graduates in 1965 was 10,282. In 1966 it was approximately 12,000. It is not possible to estimate the degree of unemployment among the Engineers during the next five years. The expansion in the facilities for Engineering education which has taken place during the Third Plan was based on estimates of requirements of engineering personnel during the 4th Plan period. Employment prospects during the next five years would become clear only after the 4th Plan takes final shape.

Police Force, Andamans

1743. Shri D. N. Patodia:
Shri S. K. Tapuriah:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no free uniform was issued to the Police Force, Andamans and Nicobar Islands for about 3 years; and

(b) if so, the reasons therefor and how the money sanctioned for this purpose was utilised?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). Certain articles of uniform could not be issued, owing to non-receipt of supplies indented for. Although under the sub-head 'Clothing and Equipment' there were proportionate savings due to non-receipt of supplies indented for, there were practically no savings under the head 'Contingencies' in the overall budget allocation of the police Department of the Andaman and Nicobar Administration.

Complaints against Andaman Officers

1744. Shri D. N. Patodia:
Shri S. K. Tapuriah:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether complaints have been received against the Officers of Andaman Administration about the harassment of active workers in Political field and their sons in Andamans;

(b) the action taken in the matter; and

(c) whether there is a proposal to bring popular Government in the territory at an early date?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No such specific case has come to notice of Government.

(b) Does not arise.

(c) No such proposal is under the consideration of the Government.

Attack by Mizos in May, 1967

1745. Shrimati Jyotsna Chanda: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a gang of 15 Mizo hostiles entered Cachar district in the second week of May and fired on the villagers at Jalnachherra, injuring one, looted some shops and escaped with cash and grain;

(b) if so, the amount of loss as a result thereof; and

(c) the measures taken to extend more security on the border?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) The estimated loss is reported to be about Rs. 300/-.

(c) Security forces have been alerted and patrolling has been intensified

in order to prevent recurrence of such incidents.

Offer of Withdrawal by Nagas

1746. Shrimati Jyotsna Chanda: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Underground Nagas have offered to withdraw some of their armed men from the ceasefire areas in the Ukhrul and Tamenlong Sub-Divisions of Manipur, provided there is reciprocal response from the other side; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Betapur Pitcher Nalla Farm in Middle Andaman

1747. Shri R. K. Sinha: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Betapur Pitcher Nalla Paddy Farm in the Middle Andaman started by the Andaman Administration has been abandoned;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that a senior officer of the Ministry of Rehabilitation has described this farm as wasteful;

(d) if so, whether the report will be placed on the Table of the House; and

(e) the total expenditure incurred on the farm in 1966-67 and the total quantity of paddy produced and the cost per maund of paddy?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir, the Betapur Farm Project has not been abandoned.

(b) Does not arise.

(c) No.

(d) Does not arise.

(e) On part of the land reclamied up to the end of the 1965-66 season, trial varietal sowings of paddy and experimental farming operations were undertaken. The quantity of paddy produced was 1936 maunds. Figures of expenditure and cost per maund of paddy are being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Fees Charged from Visitors to Monuments

1748. Shri Sezhiyan: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fees are collected from visitors to the monuments of historical interest in India; and

(b) if so, the list of such monuments and the rates of fees collected?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) Yes, Sir, but only at a few monuments, and not all.

(b) A list of monuments where entrance fees are collected from visitors is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-554/67]. The rate of fee is twenty paise per person above the age of fifteen years, on all week days except Fridays when admission is free.

I.A.S., I.P.S. and Central Secretariat Officers

1749. Shrimati Savitri Shyam: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than 100 I.A.S., I.P.S. and the Central Secretariat Officers, who were not promoted on merit, are drawing the same emoluments as they would have received had they been promoted under the 'next below rule'; and

(b) the additional expenditure incurred on account of this rule during the years 1963-64, 1964-65 and 1965-66?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir, it is a fact that more than 100 I.A.S., I.P.S. and Central Service Officers (inclusive of Central Secretariat Officers) have been given benefit of higher pay under the 'next below rule' However, it is not correct to say that this benefit is given to officers who would not have been promoted on the basis of merit had they been available in the regular line. Officers not suitable for promotion on merit are not to be given the benefit of the next below rule'. The intention of the rule is that an officer out of his regular line should not suffer by forfeiting acting promotion which he would otherwise have received had he remained in his regular line.

(b) Attention is invited to the information laid on the Table of the House in reply to question No. 3853, to which an interim reply was given on 31-8-1966 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-555/67].

Coal Mines Provident Fund

1750. Shri Deven Sen: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many of the colliery employers, particularly in the Asansol belt, do not deposit their share of Provident Fund with the Provident Fund Commissioner;

(b) whether it is also a fact that even the workers contribution to the Provident Fund deposited with the employers is not deposited with the Provident Fund Commissioner;

(c) if so, the names of such defaulting employers; and

(d) the steps taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). Yes. Some colliery employers have defaulted in payment of their share of Provident Fund and of the contribution of workers deducted from their wages to the Coal Mines Provident Fund Commissioner

(c) and (d). A statement showing the names of the defaulting employers and the steps taken against them has been already laid on the Table of the Lok Sabha on the 7th April, 1967.

Miners' Camps and Hostels

1752. Shri P. C. Adichan: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of unauthorised Miners' Camps and Hostels in the Coal Mines;

(b) the names of coal mines where these camps and hostels are functioning; and

(c) the steps taken to abolish them?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) Twelve.

(b) I—Raniganj Coalfield.

(1) Samla Manderboni Colliery, P.O. Pandaveswar.

(2) Madhujore Colliery, P.O. Kajoragram.

(3) Ghusick Colliery, P. O. Kalipahari.

(4) Porascole Colliery, P. O. Kajoragram.

II—Jharia Coalfield.

(1) Kharkharee Colliery, P.O. Kharkharee.

(2) Ena Colliery, P.O. Dhansar.

(3) Bhatdee Colliery, P.O. Dhansar.

(4) Murlidih Colliery, P.O. Mahuda.

(5) Khas Dharmabad Colliery, P.O. Malkera.

(6) Loyabad (North) Colliery, P.O. Sijua.

III—Karanpura Coalfield.

Khas Karanpura Colliery P.O. Patratu (Hazaribagh).

IV—Pench Valley Coalfield.
Newton Chickli Colliery, P.O. Parasia,

District Chindwara.

(c) The issue really is whether and on what conditions, such unauthorised hostels for Gorakhpuri labour should be recognised.

The Central Hostels Committee under the Chairmanship of the Coal Mines Welfare Commissioner which grants recognition to miners hostels and lays down standards for recognition is already seized of the matter. A Central Evaluation Committee has also recently been set up under the Chairmanship of the Director General of Mines Safety and this Committee is also looking into this question.

Accident in Coal Mines

1753. Shri P. C. Adichan: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the names of Coal mines where fatal accidents took place in April, 1967;

(b) the number of workers killed in these accidents in each mine; and

(c) the findings of the departmental enquiry in each of these accidents?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). A statement is attached. Supplementary information will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

STATEMENT

S. No.	Name of Colliery	No. killed	Findings of the Departmental Enquiry
1	Samla Dalurband	1	Fault of Co-worker
2	North Laikdih	2	Report not received
3	New Majri	1	Misadventure
4	Duman Hill	1	Fault of management.
5	Jogidih	1	Report not received
6	Loyabad	1	Fault of subordinate supervisory staff
7	Mithrpur	1	Fault of deceased
8	Bhatdee	1	Misadventure
9	Lower Kenda	1	Report not yet finalised
10	Kamptee	1	Report not received
11	Ballarpur	1	Report not received
12	Pootkee	1	Report not yet finalised
13	Sitanala	1	Report not received
14	Khas Kusunda	1	Misadventure
15	Sri Amritnagar Selected	1	Report not yet finalised
16	Chalkari	1	Misadventure
17	Deulbera	1	Report not received
18	Samdi Sangramgarh	1	Fault of management and subordinate official.
19	Pure Nichitpur	1	Report not received
20	Dhori	1	Report not received
21	Kendwadih (5-pit Khoira)	1	Report not received

Profit Sharing Bonus in Coal Mines

1754. Shri P. C. Adichan: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number and names of coal mines which have not paid the profit sharing bonus for the year 1965; and

(b) the action taken to persuade the Coal Mines to pay the bonus without further delay?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) 343 coal mines have not so far paid the profit-sharing bonus to their workmen for the accounting year 1965. The names of these coal mines are not readily available.

(b) Following an increase in the price of coal, sanctioned by Government in December 1966 to enable employers to pay the arrears of bonus, the Joint Working Committee of employers was asked to advise their constituents to make payment without any further delay. The defaulting collieries have been served with show-cause notices to explain why action should not be taken against them for contravention of the Payment of Bonus Act, 1965. Several prosecution proposals are under the examination of the Government.

Mahajan Boundary Commission

1755. Shri E. K. Nayanar: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Kerala Government have boycotted the Mahajan Boundary Commission, when the Commission visited Kasargod (in Kerala) to take evidence from the people;

(b) whether Government are aware that only pro-merger section in Karnatka has given evidence before the Mahajan Commission; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). According to the information furnished by the Commission, the Chief Minister of Kerala in his letter of 17th April had apprised the Commission of the stand taken by the State Government in regard to the Kasargod question and expressed the view that it would be better to allow the present borders between Mysore and Kerala to continue. In reply to a suggestion by the Commission that either the Chief Minister or one of his Ministers might meet the Commission at Kasargod or Mangalore to explain the stand taken by the State Government, the Chief Minister informed the Commission that as he had already explaind the reasons for the decision taken by the State Government, it would not be necessary for him or any of his Ministers to meet the Commission. The Commission will, therefore, take into account the Chief Minister's letter of 17th April as representing the State Government's views in the matter. It is also understood that the evidence tendered and recorded by the Commission at Kasargod on 15th May was mainly from associations, parties and individuals who had favoured merger of Kasargod taluk in Mysore. There were one or two representations for the maintenance of *status quo* also.

Compulsory National Service Scheme

1756. Shri K. P. Singh Deo:
Shri P. K. Deo:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a scheme for Compulsory National Service for University Students is being introduced;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the estimated annual expenditure involved in the implementation of the scheme?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) to (c). The matter is under consideration.

Thefts in M.P's. Residence

1757. Shri Kameshwar Singh:
Shri Madhu Limaye:
Shri Shri Chand Goel:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that **Mrs.** V. L. Pandit's house was burgled on the 23rd **May, 1967;**

(b) whether other M.Ps. have had similar experience in the past two-three **years;**

(c) the number of such thefts and **burglaries;**

(d) in how many cases the culprits were apprehended and convicted; and

(e) the steps proposed by the Delhi Administration and the Centre to prevent these burglaries and thefts?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) to (e). Two statements ('I' and 'II') are laid on the Table of the House.

Statements I and II

Below are given the number of theft and burglary cases reported to the police in which the property belonging to the M.Ps. was involved and also the details of the persons arrested during the years 1965, 1966 and 1967 (upto 26th May, 1967).

Period	Head of Crime	Cases reported	Persons Arrested	Persons Convicted so far
1965	Burglary	12	2	2
1966	Do.	10	..	..
1967 (upto 26-5-67)	Do.	6	..	..
1965	Theft	8	2	2
1966	Do.	7	2 (both the accused were acquitted)	..
1967 (upto 26-5-67)	Do.	1	..	..

Statement II in Reply to part (e) of the Question

(i) Adequate number of policemen are being posted round the clock to patrol in the areas where M.Ps. live.

(ii) Flats which are exposed are receiving special attention. The work of beat constables is supervised by the Division Officers, mobile patrol incharge, Station House Officer and occasionally by the Superintendent of Police himself.

(iii) The investigation of such cases is entrusted to senior and experienced Investigating Officers.

(iv) The Station House Officer concerned has been made responsible for keeping a close watch on the investigation of these cases and for developing sources of information.

(v) C.I.D. Inspection Team is sent to observe the scene of crime and lift finger prints, etc. left behind by the culprits at the scene of crime.

(vi) Every case of theft and burglary reported from these flats is being looked into promptly by the Superintendent of Police and the Illaqa Gazetted Officer together.

(vii) In July 1964, a circular letter was issued to all Members of Parliament residing in North and South Avenues seeking their co-operation on the following matters with a view to bringing down the incidence of thefts and burglaries in these areas:

(1) To intimate to the Superintendent of Police, Parliament Street, about their departure from Delhi and the duration of their stay outside Delhi approximately, so that special arrangements may be made to keep a guard on their residences;

(2) To intimate also to the Superintendent of Police whether in their absence any of their domestic servants, friends or relatives will be occupying the flat; and

(3) Whether they have hired any garage and if so, whether they have domestic servants or a driver or any one else occupying the garage.

Rehabilitation Settlements

1758. Shri K. P. Singh Deo:
Shri P. K. Deo:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there have been large desertions from the rehabilitation settlements;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the amount spent on the rehabilitation and relief programmes from 1948 to 1966?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) There have been some desertions of migrants form East Pakistan who came to India on or after 1st January, 1964 from agricultural rehabilitation settlements in varicus States, including Dandakarnya Project. Apart from these desertions, a very large number of families had left the relief camps in which they had been accommodated prior to their dispersal to the rehabilitation settlements.

(b) (i) Migrants' inability to adjust themselves to their new environment, particularly to the unfamiliar climatic and soil conditions, lower rainfall and a different cropping pattern.

(ii) The drought and scarcity conditions prevailing over large parts of the country which affected the rehabilitation settlements also for the last two successive years and consequential failure of crops.

(iii) Relations still living in West Bengal.

(iv) Natural inclination to settle down in West Bengal, strengthened by the hope that the newly constituted State Government would settle them in that State itself.

(v) Fear of prosecution for being spurious migrants.

(vi) False and misleading promises of rehabilitation in West Bengal made by unscrupulous elements who sometimes infiltrate into resettlements.

(c) From 1947-48 to 1965-66 a sum of Rs. 440.08 crores was spent on relief and rehabilitation programmes sanctioned for displaced persons from East Pakistan and West Pakistan. Of this amount a sum of Rs. 199.46 crores was expended on programmes for displaced persons from West Pakistan and the balance of Rs. 240.62 crores on programmes for displaced persons from East Pakistan.

Fair Price Shops in Industrial Establishments

1759. Shri Y. A. Prasad:
Shri N. K. Sanghi:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring in legislation to compel employers to set up fair prices shops in industrial establishments; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). The matter is under consideration.

Employment for Unskilled and Agricultural labour

1760. Shri P. K. Deo:
Shri K. P. Singh Deo:
Shri D. N. Deb:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a plan has been drawn up to provide employment to the unskilled and agricultural labour in the rural areas;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the expenditure incurred on the rural workers programme during the Third Plan period?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) and (b). The important schemes intended to provide employment to unskilled and agricultural labour in rural areas are:

(i) Rural Works Programme, and

(ii) Rural Industries Programme.

The details of these are contained in the Draft Outline of the Fourth Five Year Plan.

(c) The expenditure incurred on the Rural Works Programme during the Third Plan period was Rs. 19.33 crores.

Vishal Haryana

1761. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a memorandum has been presented to the Prime Minister by Members of Parliament from Rajasthan, Delhi, Uttar Pradesh and Haryana demanding the formation of Vishal Haryana; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Rehabilitation Ministers' Conference

1762. Dr. Ranen Sen: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at the Conference of State Rehabilitation Ministers held at New Delhi in May, 1967, the Union Minister for Rehabilitation did not agree to the suggestions regarding the so-called residuary problem with the Minister from West Bengal;

(b) whether the West Bengal Rehabilitation Minister has submitted some schemes for the rehabilitation of refugees; and

(c) if so, the reaction of the Central Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) During the Conference of the State Rehabilitation Ministers held on the 19th May, 1967, the West Bengal Minister for Rehabilitation in his speech invited attention to certain pending problems. However, an opportunity was taken before and after the Conference to exchange views and ideas with the West Bengal Minister on matters relating to the rehabilitaton of old and new migrants. Some of the points discussed related to items outside the "Residuary Problem".

As regards the "Residuary Problem", certain aspects relating to the implementation of individual schemes were discussed. In view of the slow progress of sanctioned schemes, the West Bengal Government were asked to take necessary measures to step up the pace of implementation.

The Union Minister did not reject any "suggestions" of the Minister for Rehabilitation, West Bengal, in regard to commitments accepted under the Residuary Problem, during the recent discussions.

(b) and (c). The State Government have approached the Government of India with certain proposals for providing additional educational, medical and training facilities to relieve pressures in these sectors caused by the influx of new migrants since 1964. The schemes briefly are:—

(i) Setting up of Special I.T. institutes for D.P. Boys;

(ii) Training of D.P. girls as nurses and the setting-up of as B.Sc. Nursing College; and

(iii) Rehabilitation of old migrants families squatting on defunct camp sites.

These proposals are being examined in consultation with the Ministry of Finance.

Post Offices in Kangra District

1763. Shri Prem Chand Verma: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Post Offices and Public Call Offices in Kangra and Bilaspur Districts of Himachal Pradesh; and

(b) the number of them which are functioning?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral):

	P.Os.	P.C.Os.
(a) Kangra District	676	32
Bilaspur Distt.	78	4

(b) All are functioning.

Pay Revision of Manipur Government Staff

1764. Shri M. Meghachandra: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are sanctioning the pay revision of the Manipur Police and Radio Staff on Central Government pattern of pay scales;

(b) whether their pay was revised when the pay of the employees of the Government of Manipur was revised with effect from 1st April, 1964; and

(c) whether the Government of Manipur are moving the Centre for a pay revision for their staff on Central pattern, if so, when and from which date effect is being given?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). The Government of India have recently received proposals for the revision of scales of pay of the Manipur Police and Radio Staff on the Assam pattern. These proposals are being examined.

Grants to Manipur Schools

1765. Shri M. Meghachandra: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Manipur Government have not paid the regularly payable grants to the Government aided elementary schools for the last few months;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether this has resulted in irregular receipt of pay and the non-receipt of arrears of pay by the teachers in these schools; and

(d) the steps taken to pay the grants in time?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (d). Yes, Sir. There have been delays in the payment of grants during the last few months, which has resulted in irregular payment of salaries to teachers. Grants for March, 1967 have already been paid in many cases. Grants for the period April to August, 1967 as well as for the arrears of pay have been sanctioned and payments will be made soon after clearance from the Accounts authorities. The delays are reported to be mainly due to observance of such procedural requirements as checking of accounts, obtaining utilization certificates, etc. The Administration of the Union Territory of Manipur are examining the ways and means of avoiding delays in future.

दिल्ली पुलिस का आन्दोलन

1766 **श्री ब्रह्मानन्दजी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व दिल्ली पुलिस के आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार की गई महिलाएं तथा बच्चे अब भी जेलों में बन्द हैं;

(ख) यदि हां, तो इन महिलाओं तथा बच्चों की संख्या कितनी है;

(ग) उन्हें जेलों में बन्द रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने बच्चों को खाद्य पदार्थ, दूध आदि देने की क्या व्यवस्था की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). दिल्ली पुलिस के आन्दोलन के दौरान 8 महिला कांस्टेबिल गिरफ्तार करके जेल भेज दी गई । न्यायालय द्वारा उन सब की जमानत मंजूर कर ली गई है । उनमें से चार को जमानत/जमानत बन्ध की पूर्ति पर जेल से पहले ही छोड़ा जा चुका है, शेष चारों को उनके द्वारा जमानत की औपचारिकता को पूरा करने के बाद तुरन्त ही छोड़ दिया जाएगा । बच्चे गिरफ्तार नहीं किए गये थे ।

(घ) प्रश्न हो नहीं उठता ।

Retiring Age of Teachers

1767. Shri S. C. Jha: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the present retiring age limit for the school teachers; and

(b) whether it is a fact that the Kothari Education Commission Report has recommended that the retiring age limit of school teachers be fixed at 65?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-556/67].

Statehood for Manipur

1768. Shri M. Meghachandra: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Assembly of Manipur and all the political parties in Manipur are demanding for the grant of Statehood to Manipur; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) In September, 1966, the Manipur Legislative Assembly passed a resolution to the effect that full-fledged Statehood be granted to Manipur.

(b) Government do not propose any change in the status of this Union territory.

Centralisation of Services of L.D.C's./U.D.C's./Assistants

1769. Shri M. L. Sondhi: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of L.D.C's. Ministry-wise, who have completed 10 years' service in the grade but have not been promoted to the grade of U.D.C.;

(b) the number of L.D.C's. promoted as U.D.C's. during the period Ministry-wise;

(c) whether it is a fact that in some cases senior LDCs. could not be promoted as UDCs. for want of vacancies in that cadre in the Ministry and as such there is much discontentment among the employees;

(d) whether such disparity and the resultant discontentment are due to the decentralisation of these services;

(e) whether it is also a fact that such disparity and discontentment are in existence in the cases of UDCs.; Assistants, and Section Officers also;

(f) if so, whether Government propose to centralise these services as before; and

(g) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The information is given in the Statement I placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-557|67].

(b) Prior to 1-11-62 when the Service was decentralised promotions to the U.D.C's Grade were being made on an all-Secretariat basis. Statement II gives the number of promotions made Ministry-wise after 1-11-62 which is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—557/67].

(c) to (g). The Central Secretariat Services were decentralised with a view to ensuring better personnel management and better utilisation of the training and experience received in each Ministry. After decentralisation, persons allotted to a cadre can look forward to promotion only against vacancies arising in that cadre and some disparity in the promotion prospects from cadre to cadre is, therefore, inevitable. Government have carefully considered the problems of decentralisation and have decided that although it has created some disparity in the opportunities for promotion in certain cadres, the balance of advantage would clearly lie in maintaining the decentralised set up in the large public interest. There is, therefore, no question of recentralising the Services.

Delhi Judicial Service

1770. Shri O. P. Tyagi: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the rules of the Delhi Judicial Service have been framed by the Lt. Governor in consultation with the Union Public Service Commission as required under Article 234 of the Constitution;

(b) how many Officers gave their option for Delhi Judicial Service and what will be or has been the method of selection;

(c) whether in absence of ' Cadre rules the options have been considered and if not, how many officers have been selected and by whom;

(d) the reasons why the selection was not done by U.P.S.C.; and

(e) whether there will be a joint judicial cadre of the subordinate judiciary of Delhi and Himachal Pradesh?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (e). It is proposed to constitute a Delhi and Himachal Pradesh Higher Judicial Service and a Delhi and Himachal Pradesh Civil Service (Judicial Branch). The former service will comprise posts of District and Sessions Judge and comparable posts. The latter service will comprise posts of Sub-Judges, Judicial Magistrates and comparable posts. The draft rules are under preparation in consultation with the Delhi High Court.

आयल इंडिया कम्पनी के तेल शोधक कारखानों में श्रमिक संघ

1771 श्री सूरजू पाण्डेय :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री आयल इण्डिया कम्पनी के तेल शोधक कारखानों के श्रमिक संघ के बारे में 27 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4496 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया कम्पनी के तेल शोधक कारखानों के श्रमिक संघों को मानता देने से सम्बन्धित जांच पड़ताल, जो पहले स्थगित कर दी गई थी, पुनः आरम्भ कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। इस सम्बन्ध में कुछ और जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर का मुख्य डाकघर

1772. श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इसहाक सामली :

क्या संचार मन्त्री 16 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1518 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर के मुख्य डाकघर के लिये इमारत का निर्माण, जो धन की कमी के कारण रोक दिया गया था, अब फिर आरम्भ किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस इमारत का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इमारत का निर्माण-कार्य पूरा करने के लिये 22 मई, 1967 को एक ठेकेदार को सौंप दिया गया है। ठेकेदार सामान आदि की व्यवस्था कर रहा है और स्थान पर काम शीघ्र ही चालू हो जाने की सम्भावना है।

(ख) ठेके अनुसार इमारत का निर्माण-कार्य जून, 1968 तक पूरा हो जाना चाहिए। यदि कोई अप्रत्याशित कठिनाइयां पैदा न हुई तो आशा है कि इमारत जून, 1968 तक पूरी हो जाएगी।

Christian Missionaries in India

1773. **Shrimati Suseela Gopalan:**
Shri P. Gopalan:
Shri C. K. Chakrapani:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have imposed certain restrictions upon the foreign Christian missionaries in India;

(b) if so, the nature of restrictions imposed;

(c) the total number of missionaries working in India, State- wise; and

(d) the nature and character of their activities in India?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The rules relating to entry into, stay and movement in India of foreigners are also applicable to foreign missionaries. These rules have recently been extended to missionaries from Commonwealth countries who were hitherto exempt from them.

(c) Statements showing the number of foreign and Commonwealth missionaries is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—558/67].

(d) The main activities on which they are engaged are medical, educational, social, evangelical, etc.

Central Schools in Assam

1774. **Shri Dhireshwar Kalita:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of Central Schools opened in Assam so far;

(b) whether it is a fact that the Central School Organisation has refused to open one school at Maligaon *i.e.* North East Frontier Railway Headquarters at Pandu;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether Government have any proposal to open some more central schools in Assam in the near future?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Three.

(b) No, Sir. The Central Schools Organisation has already communicated its willingness to the Railway

authorities to open a school at Maligaon subject to availability of suitable accommodation and requisite funds.

(c) Does not arise.

(d) Yes, Sir. The schools will be opened according to availablity of funds and other requisite facilities.

मैसूर के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान

1775. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैसूर राज्य के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर राज्य के प्राथमिक स्कूलों को कितना धन देने का निश्चय किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) मैसूर राज्य के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाने के प्रश्न का संबंध मुख्य रूप से राज्य सरकार का है । चौथी आयोजना के ढांचे के अनुसार, इस प्रयोजन से राज्य को केन्द्रीय सहायता की कोई व्यवथा नहीं है ।

Small Scale Industries in Madhya Pradesh

1776. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh have forwarded any proposal for the establishment of small scale industries for the rehabilitation of new migrants from East Pakistan;

(b) if so, when these proposals were received and the decision taken by Government thereon;

(c) whether Government have since issued orders sanctioning establishment of such industries; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). In November, 1965, the Government of Madhya Pradesh sent proposals for the setting up of an Industrial Estate at Itarsi, with 57 small scale industrial units, for providing employment to 2,480 new migrants from East Pakistan, at an estimated cost of Rs. 56.48 lakhs. The proposal was examined from the point of view of marketing, profitability, availability of raw materials, foreign exchange requirements and ratio of capital investment to employment potential. Schemes for 15 industrial units were considered unsuitable. Certain comments for modification of 13 schemes were forwarded to the State Government. The State Government were also requested to consider location of some of the units near Betul Project where new migrants were being settled in sizeable numbers and to ascertain the market prospects of the products with reference to the experience of the existing units in the State manufacturing similar items.

2. Following further discussions in December, 1966, a revised proposal was received in January, 1967, from the State Government for setting up of 13 industrial units near Betul for the employment of 451 new migrants at an estimated cost of about Rs. 36.39 lakhs and of 21 industrial units at Itarsi for the employment of 841 new migrants at an estimated cost of Rs. 40.72 lakhs.

While forwarding the revised proposal, the State Government had indicated that the economics and marketing facilities will have to be considered carefully. The State Government have been requested to indicate whether these aspects have been examined and, if so, which of the 34 schemes they would recommend in the light of such examination. In view

of the shortage of funds, the State Government are also being requested to indicate an order of priorities for the schemes, for phasing the expenditure, keeping in view the ratio of capital investment to employment potential.

Girls' Education in Orissa

1777. **Shri Dhuleshwar Meena:**
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri K. Pradhani:
Shri Heerji Bhai:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred by the Central Government on girls' education in Orissa State during the first year of the Fourth Five Year Plan; and

(b) the amount allocated to Orissa for the same purpose for 1967-68?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Particulars have been called for from the State Government. They will be placed before the House, as soon as they are received.

(b) As the Orissa Government finalised plan proposals for 1967-68 have not so far been received it is not possible to give the figures of allocation for 1967-68.

Primary School Buildings in Orissa

1778. **Shri Dhuleshwar Meena:**
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Heerji Bhai:
Shri K. Pradhani:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the amount proposed to be given to the Orissa Government for the construction of primary school buildings during 1967-68; and

(b) the details thereof?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) The final Annual Plan proposals of Orisa Government for 1967-68 have not been received so far. The scheme is, however, entitled to 40 per cent Central assistance during 1967-68.

(b) Does not arise.

Education Schemes in Orissa

1779. **Shri Heerji Bhai:**
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri K. Pradhani:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the amount proposed to be given by the Centre to Orissa State for expansion of the education schemes in the State during 1967-68; and

(b) the details thereof?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) and (b). The State Education plan for 1967-68 has not yet been finalised. The amount of Central assistance payable to State Government for 1967-68 can be worked out only after the details of the finalised plan are available.

Books Presented to Foreign Countries

1780. **Shri K. Pradhani:**
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Heerji Bhai:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the titles and value of each book presented to foreign countries by his Ministry during the last three months; and

(b) the names of countries and the institutions to which these were presented?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) and (b). The required information is being compiled and will be laid on the Table of the House shortly.

Officers on Deputation in Himachal Pradesh

1781. Shri Hem Raj: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Officers sent to Himachal Pradesh on deputation during the last five years in the different Departments with a break-up of their number in each Department; and

(b) the total extra emoluments to which they are entitled during their term of deputation?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The number of officers on deputation between 1962 and 1967 Department-wise is as follows:—

P.W.D. & Multipurpose project department	145
I.A.S.	10
I.P.S	3
Forest	3
Finance Secretary	1
Judicial Secretary	1
Transport & Works Manager	1
TOTAL	164

(b) Officers brought on deputation upto August, 1966, used to get the normal deputation terms which usually enabled them to get a deputation allowance equal to 20 per cent of the basic pay subject to certain conditions. After August, 1966, only those who are sent on deputation to higher posts are eligible for deputation allowance. The total extra emoluments would depend on the salary of each individual officer and his annual rate of increment.

Delhi-Madras Telephone Line

1782. Shri P. K. Deo:
Shri S. K. Tapuriah:
Shri P. K. Singh Deo:
Shri D. N. Patodia:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether trunk telephone lines between Delhi and Madras were frequently out of order during April-May, 1967; and

(b) if so, the number of hours during the last two months the telephone lines were out of order and the loss sustained by the Department as a result thereof?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) There have been some interruptions.

(b) 573 hours during the two months for the four circuits. Loss sustained by the Department cannot be ascertained since accounts are not maintained on this basis.

Registration in Post Offices

1783. Shri Shiva Chandra Jha: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that to get an article registered in a Post Office, a person has to go to three counters, one for getting the mail weighed, another for due postage and the third for getting registration done; and

(b) if so, the steps taken for getting all these done at one counter to avoid wastage of time?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes, Sir. In some of the larger post offices this is the case.

(b) The following steps have been taken to expedite booking and to avoid the need for customers having to move from one counter to another:

(i) Instructions have been issued that in big post offices the stamp vendor should be seated

between the registration and parcel clerks.

(ii) It has also been enjoined that in smaller post offices the registration and parcel clerks should themselves keep a stock of stamps and sell them to the customers.

(iii) Franking machines have been installed in selected post offices, where a large number of registered articles is booked, so that the need to purchase postage stamps is dispensed with.

पुरानी मूर्तियों की चोरी

1784. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुराने मन्दिरों से मूर्तियों की चोरी के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों के बारे में कोई जांच की है;

(ग) क्या यह सच है कि चोरी की गई ये मूर्तियां जनपथ, नई दिल्ली की दुकानों में खुले आम बिक रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से हुई चोरियों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच की गई थी अथवा की जा रही है।

(ग) ऐसी कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निःशुल्क उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

1785. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर माध्यमिक अथवा मैट्रिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने के गत वर्ष के सरकार के निर्णय को इस बीच क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में उन स्कूलों तथा कालेजों की संख्या कितनी है; जिन में उच्चतर माध्यमिक अथवा मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था। किन्तु मन्त्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, हाई स्कूल अथवा हायर सेकेण्डरी स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की स्थिति इस प्रकार है:—

आन्ध्र प्रदेश (केवल लड़कियों के लिए)
जम्मू तथा काश्मीर
मध्य प्रदेश (केवल लड़कियों के लिए)
मद्रास
मैसूर (दसवीं कक्षा तक)

उड़ीसा (लडकियों, प्राथमिक स्कूल अध्यापकों तथा राज्य के चतुर्थ श्रणी कर्मचारियों के बच्चों और अनसूचित जातियों/अनसूचित कबीलों के लिए)

पंजाब (कुछ वर्गों के लिए अर्थात् लड़कियों के लिए और पिछड़े तथा हरिजनों के

बच्चों के लिए, आय की निर्धारित शर्तों के अनुसार) ।

उत्तर प्रदेश (दसवीं कक्षा तक केवल लड़कियों के लिए) ।

पश्चिम बंगाल (साक्षरता की कम प्रतिशतता वाले कबीलों और अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए दसवीं कक्षा तक)

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

दादरा और नागर हवली ।

लकादीव, मिनीकाय और अमीनदीव द्वीप समूह ।

उपर्युक्त ।

पांडिचेरी (केवल लड़कियों के लिए) ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य चिन्ह

1786. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि मद्रास सरकार ने राज्य चिन्ह से देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' शब्द हटा दिये हैं और उनके स्थान पर प्रादेशिक भाषा के शब्द रख दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) यह बात भारत सरकार के ध्यान में आई है । मामला विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में निःशुल्क शिक्षा

1787. **श्री राम स्वरूप :**
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अभावग्रस्त पूर्वी जिलों के प्राइमरी स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध किया है, और

(ख) यदि हां, तो कब से और उन जिलों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्राथमिक शिक्षा सारे राज्य में पहले से निःशुल्क है । कालेजों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Ancient City at NEFA Foothills

1788. **Shrimati Jyotsna Chanda:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ruins of an ancient city have recently been discovered in the foothills of NEFA; and

(b) if so, the date ascribed to this ancient city?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) Government have not received and official information in the matter. It is understood that the Historical Research Officers of the NEFA Administration were working on the site. Necessary enquiries are being made.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Theft of articles from Nehru Museum

1790. Shri George Fernandes:
Shri S. M. Joshi:
Shri Madhu Limaye:
Shri Virendrakumar Shah:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether there is any truth in the rumours that several official and personal papers of the late Shri Jawaharlal Nehru have disappeared from the almirahs of the late Prime Minister's house at Teen Murti, New Delhi;

(b) if so, when the discovery of the loss of these papers was made; and

(c) whether any steps have been taken to recover the lost papers?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) No disappearance of Prime Minister Nehru's papers has been reported or came to notice.

(b) and (c). The questions do not arise.

Telephone Exchange, Bombay

1791. Shri George Fernandes:
Shri S. M. Joshi:
Shri J. H. Patel:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of telephone exchanges operating in Greater Bombay and the total lines installed;

(b) the number of applicants for telephones in Greater Bombay who are still on the waiting list and the period for which these applications are pending at the various exchanges; and

(c) when the Bombay's telephone requirements will be fully met?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). The statement showing number of exchanges in Greater Bombay, total number of lines installed, number of applicants on the waiting list and the time since when they are waiting is laid on the Table of the Lok Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-559/67].

(c) It is difficult to indicte any time limit. However, subject to availability of resources, continuous efforts are being made to open new telephone exchanges, increase the capacity of the existing ones and lay underground cables to give more and more connections.

Strike in Deulbera Colliery

1792. Shri K. P. Singh Deo:
Shri P. K. Deo:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the workers of Deulbera Colliery, Talcher in Dhenkanal District, Orissa have gone on strike since 4th May, 1967;

(b) whethre an appeal has been made by the President of Deulbera Colliery Labour Union for conciliation; and

(c) if so, the action taken by Govment in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) No. But some sand-loading workers of the colliery who were transferred temporarily to Talcher Colliery under the same management continued to work on their own at Deulbera Colliery and demanded wages for such work.

(b) yes, by a group of the union not recognised.

(c) No conciliation was held but enquiries were made. A bipartite settlement was reached between the management and the recognised group of the union whereby most workers have resumed duty.

———

12.22 hrs.

RE. MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES (*Query*)

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं ने एक स्थगन-प्रस्ताव दिया था । कल यहां बताया गया था कि गाजा पट्टी में हमारे पांच आदमी मारे गए । आज पेपर्ज में आया है कि आठ आदमी मारे गए हैं ।

Mr. Speaker: Order, order. Please resume your seat.

श्री एस० एम० जोशी : उस के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो दूसरे भारतीय नागरिक हैं, ...

Mr. Speaker: Well, I have no objection. I am prepared to allow it for 10 minutes even, if it is the desire of the House.

श्री एस० एम० जोशी : आप मुझे कहने दीजिए । मैं बताना चाहता हूं कि जो दूसरे भारतीय नागरिक हैं, . . .

Mr. Speaker: Order, order. What the hon. Member says will not be recorded.

श्री एस० एम० जोशी : *

Mr. Speaker: Order, order. Will you now sit down, please? Nothing has been taken down anyway. Every day, I have been noticing one thing. Call Attention notices are given in large numbers. I am not mentioning any one Member, but about the whole House generally, whether it is this side or that side. Notices are given; they are considered. It is not just one or two Members, but I get notices from 40 Members. I get 20, 30, 40 notices. Now, whichever notice is not accepted, if the Members begin to make speeches like this, well, I have on objection. If that is what is wanted, I have absolutely no objection. If you change the rules and make rules saying that anybody can begin speaking and raise any point, I have no objection.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : माननीय सदस्य ने यह मांग की है कि मंत्री महोदय बयान दें । बयान तो आना चाहिए ।

Shri Nath Pai (Rajapur): What about our notice? We have not been informed anything.

Mr. Speaker: It is under consideration, if he is not informed.

12.26 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST *THE HINDUSTAN TIMES*

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, परसों मैं ने बिड़ला समूह के एक हिन्दी दैनिक, **हिन्दुस्तान**, के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और चूंकि सदन ने या सदन के किसी भी सदस्य ने, उस का विरोध नहीं किया, इस लिए वह सीधा विशेषाधिकार समिति के पास पहुंच गया । आज मैं जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं, वह उसी बिड़ला समूह के अंग्रेजी दैनिक, हिन्दुस्तान टाइम्स, के खिलाफ है मेरी राय है कि एक मानी में यह मामला हिन्दी दैनिक, **हिन्दुस्तान**, के मामले से भी ज्यादा गम्भीर है और इस का कारण मैं अभी बताता हूं ।

रविवार के **हिन्दुस्तान टाइम्स** में जो लेख प्रकाशित हुआ था, उस का नाम है, "शेड्ज आफ दि स्टार चैम्बर" । शायद हमारे कुछ मित्र यह नहीं जानते होंगे कि यह स्टार चैम्बर क्या बला है । इस लिए मैं एक ही वाक्य में बताना चाहता हूं कि जब

*Not recorded.

[श्री मधु लिमये]

सत्रहवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में राजाशाही और संसदीय लोकशाही के बीच संघर्ष चल रहा था, तो स्टार चैम्बर की अदालत का इस्तेमाल राजाशाही करती थी लोकतन्त्र को दबाने के लिए। कई इतिहासकारों ने स्टार चैम्बर की अदालत का वर्णन इस प्रकार किया है :

"A convenient and secondary instrument of repression."

हाई कमीशन की अदालत एक नम्बर पर थी और यह दूसरे नम्बर पर।

इस संबंध में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में निम्न वाक्य आता है :

"Under James I and Charles I, star chamber continued as an important court largely respected and liked. As puritan and parliamentary opposition developed, however, it incurred odium from severe penalties and the reputation then affixed by the enemies has since persisted."

इस का मतलब यह है कि स वक्त स्टार चैम्बर का अर्थ है दमन का हथियार। यह उस लेख का नाम है। तो जब पार्लियामेंट के बारे में, वह राज्य सभा हो या लोक सभा, "शैड्ज आफ दि स्टार चैम्बर" शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस का साफ मतलब है कि लेखक हमारे ऊपर यह लांछन लगा रहा है कि हमारी कार्यवाही और प्रक्रिया ऐसी है कि वह दमन चलाने का एक साधन है—यह संपद दमन चलाने का एक हथियार बन गई है।

इस लेख में यह कहा गया है कि राज्य सभा के सदस्यों ने शायद हजारी रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। इस तरह की आलोचना के खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है। हम लोगों को इस प्रकार की टीका-टिप्पणी पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन आगे चल कर लेखक ने कहा है कि जो आरोप प्रत्यारोप किये गए, वे ऐबसर्ड हैं। इस पृष्ठभूमि में मैं इस लेख मे दो वाक्य पढ़ता हूं :

"If the Birlas have foreclosed industrial licensing, if the Birlas have evaded income-tax, if the Birlas have salted away foreign exchange by fraud, there is a case for letting them take their deserts under the law of the land. But the stronger case is against a government which permitted all these things to happen because it was, as we are told, beholden to the Birlas."

आगे लेखक यह कहते हैं कि यह बात सही नहीं है :

"The proposition has only to be put in this manner to recognise the absurdity of it."

लेकिन आज के **स्टेट्समैन** में यह खबर आई है कि हिन्दुस्तान मोटर्ज के पांच बड़े अधिकारियों को चीफ़ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने उन के ऊपर फुछ इल्जामात लगा कर बुलाया है। वे आरोप इस प्रकार हैं :

"On a charge under section 120(b) IPC criminal conspiracy, read with section 5 of the Imports and Exports Control Act."

इस में बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के नाम हैं, वाइस प्रैसीडेंट हैं, कार्मशियल मैनेजर हैं, सप्लाई मैनेजर हैं, आज के कार्मशियल मैनेजर हैं, आफिस इन्चार्ज आफ दि कलोअरिंग डिपार्टमेंट आफ दि फर्म और फिर आज के आफिस इन्चार्ज यह सब अधिकारी हैं।

"The last two accused have been further summoned on charges of forgery and using forged documents as genuine. The other three have also been further summoned...."

Mr. Speaker: You may ask for leave of the House.

श्री मधु लिमये : मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, कोई गलत बात मेरे मुंह से नहीं आयेगी। उस की पृष्ठभूमि में मैं ने यह कहा।

"The other three have also been further summoned on charges of abetment of the alleged forgery and using forged documents as genuine."

अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो आरोप लगाए गए हैं वह साबित हो गए हैं। यह मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। इतना ही कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान मोटर्स आदि मामलों की चर्चा हम लोग यहां करते हैं और मांग करते हैं कि जांच हो, अदालत के सामने मामले लिए जांय तो उस के बारे में हमारे ऊपर आरोप किया जाता है कि हम यहां पर "स्टार चैम्बर" चलाना चाहते हैं, इसलिए मैं ने यह कहा : अध्यक्ष महोदय, इस में सबसे दो तीन जो खतरनाक वाक्य हैं जिन को लेकर यह विशेषाधिकार का मामला उठता है वह निम्न प्रकार है। पहले तो कहा गया कि जब हम और आप हिन्दुस्तान मोटर्स के खिलाफ कुछ कहेंगे, रुबी कम्पनी और न्यु एशियाटिक कम्पनी के खिलाफ कहेंगे, तो इस के संबंध में मुलगावकर साहब क्या लिखते हैं :

"Wild charges which have been flung in Parliament against the Birlas...."

हम अपने कर्त्तव्य को, फर्ज को निभाते हैं, उस के बारे में दलीलें देते हैं, उदाहरण देते हैं, हम यहां कोई न्याय करने नहीं जा रहे हैं, हम जेल में उन को नहीं भेजते, हम सरकार से केवल मांग करते हैं.....

Mr. Speaker: This can be argued before the Privileges Committee.

श्री मधु लिमये : तो अध्यक्ष महोदय, वाइल्ड चार्जेज हम करते हैं इस तरह का हमारे ऊपर लांछन लगाया गया है। अब सब से ज्यादा खतरनाक चीज की तरफ अब मैं आ रहा हूं।

"The question that now arises is how far can we go in allowing Parliament to behave like some kind of a Star Chamber sitting in judgment on individuals and institutions who have no means of defending themselves without undermining democracy itself."

अध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि "हाउ फार कैन वी गो इन एलाविंग पार्लियामेंट," मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन टिको जी राव या तीसमार खां हैं? हम को इजाजत देने वाले? पार्लियामेंट को इजाजत देने वाले यह तीसमार खां कौन हैं जो कहते हैं?

"how far can we go in allowing Parliament to behave like some kind of a Star Chamber."

यह मैं समझता हूं इस में सब से खतरनाक चीज है। आगे चलकर कहते हैं कि संसद सदस्यों को जो स्वतन्त्रता दी जाती है और बिरला वालों की चर्चा में उस का जो इस्तेमाल किया गया उस वाक स्वातन्त्र्य का इस्तेमाल लोकतन्त्र को खत्म करने के लिए हम लोग कर रहे थे : यह वाक्य है :

"who use the freedom of an open democratic society for the express purpose of subverting it."

बिरला समूह के मामलों को लेकर जो चर्चायें दोनों सदनों में हुई उस में जो वाक स्वतन्त्रता के अधिकर का इस्तेमाल किया गया उस के बारे में कहते हैं कि हम लोग लोक तन्त्र को उखाड़कर फेंकना चाहते हैं... (**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म करने जा रहा हूं मुझे पता चला कि कुछ लोग विरोध करना चाहते हैं, इसलिए मैं जरा लम्बा भाषण कर रहा हूं ताकि वह अपना विरोध वापस

[श्री मधु लिमये]

ले लें और सदन का समय बचे। अध्यक्ष, महोदय, अगर यह अखबार वालों की स्वतन्त्रता के लिए लड़ते तो कुछ बात समझ में आती, लेकिन वह बात नहीं है। यहां जो कार्यवाही होती है वह सुरक्षित है, जैसे कि दो दिन पहले मैं ने बताया, यह अदालत में नहीं जा सकती इसी तरह यहां की कार्यावाही जो प्रकाशित होती है, अखबारों में छपती है वह भी सुरक्षित है। अब यह महोदय चाहते हैं कि यह अखबार वाला संरक्षण उठा लिया जाय, मतलब हम यहां पर जो बातें करते हैं वह अखबारों में छपे नहीं, जो उन के हक में हों वह छपें, जो उन के खिलाफ हों वह नहीं छपे। तो इस तरह अध्यक्ष महोदय यह मामला है। अब मैं आप को और उद्धरण नहीं देना चाहता। एक ही वाक्य में देना चाहता हूं कि यह कैसे विशेषाधिकार भंग होता है, मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस से तो मैं ने दिया लेकिन हाउस आफ कामन्स के एक बहुत विद्वान सचिव थे कैम्पियन साहब, उन की किताब से मैं एक वाक्य पढ़ कर सुना देना चाहता हूं :

"Disrespect to the House collectively, whether committed by a Member or any other.

This is the original and fundamental form of breach of privilege and almost all breaches can be reduced to it. Special instances of it are libels on the House at large, upon the Speaker and upon Select Committees."

तो यह पूरे सदन का मामला है। उस के बारे में मैं ने यह कैम्पियन से उद्धरण दिया है। अब अन्त में मैं अपना प्रस्ताव औपचारिक रूप में रखता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि **हिन्दुस्तान टाइम्स** के स्तम्भ लेखक, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक तथा मालिक के खिलाफ.....

Mr. Speaker: You must first take the leave of the House.

श्री मधु लिमये : विरोध किसी ने नहीं किया तो लीव की क्या जरूरत है ?

Mr. Speaker: After the leave of the House is granted, he can move the motion. Now he should ask for leave. Is it being objected to?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): We have no objection.

अध्यक्ष महोदय : कोई विरोध नहीं कर रहा है।

श्री मधु लिमये : तो मैं प्रस्ताव रख रहा हूं।

Shri Himatsingka (Godda): I feel that the article that has been published is a fair comment and does not come within the mischief of privilege.

Mr. Speaker: That is all right. He can oppose it. But speaking can be done only after the motion is moved. Now, let the hon. Member move the motion.

श्री मधु लिमये : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दुस्तान टाइम्स के स्तम्भ लेखक, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक तथा मालिक के खिलाफ विशेषाधिकार भंग का उपरोक्त मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाय।

Mr. Speaker: Day before yesterday some thing on the same lines was moved in the Rajya Sabha and they took a decision two days before it was moved in this House. They have referred it to their Privileges Committee. Now the motion is before the House. If anybody wants to support or oppose it, he can do so, though I do not think it is necessary to make any speeches. I would now put the motion to the vote of the House.

Shri Himatsingka: The reference suggested is with respect to the writer, the editor, the printer and proprietors. I do not think that there are any proprietors in a company. There may be directors . . . (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Now it is the chance of the members of the opposition to hear. Even if they do not agree, they may please hear him.

Shri Himatsingka: I believe the motion is in a much wider form. It should be restricted to the person who wrote it and the editor.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I rise to support the motion of my friend, Shri Madhu Limaye, and I must congratulate him for bringing the Birla house on the mat of this House.

Mr. Speaker: What is all this? The motion is against the paper.

Shri S. M. Banerjee: About the article which has been referred to under the heading "Shades of the Star Chamber" in the *Hindustan Times*, the cartoon on that is that every Minister has failed in getting a cheap car or a small car and that now it is the turn of Shri Fakhruddin Ali Ahmed . . . (*Interruption*).

Mr. Speaker: Why all this?

Shri S. M. Banerjee: Please see the cartoon. What does it show? (*Interruption*).

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Why do you discuss the cartoon now?

Shri S. M. Banerjee: Sir, the question now arises as to how far he can go. 'He' stands for whom? 'He' does not stand for Mr. 'Mulgaokar'.... (*Interruption*).

Mr. Speaker: You finish now.

Shri S. M. Banerjee: I want to bring to your attention another sentence. The objection has been raised by Mr. Himatsingka that it is against the editor and not against the proprietor. The motion of my friend, Shri Madhu Limaye, is मालिक को भी बुलाया जाय।

श्री मधु लिमये : "बुलाया जाय" मैंने नहीं कहा है।

Mr. Speaker: That is enough now.

Shri S. M. Banerjee: There is another sentence which has not been quoted. I quote:

> "The country is very near to the point where the public is losing all confidence in the instruments of democratic organisation."

We have raised questions on nefarious activities of the Birlas either in this House or in the other House. You need not give any weightage to the objections raised on the other side.

Mr. Speaker: It has nothing to do with the Birlas.

Shri Shashi Ranjan (Pupri): The remarks made by the author in the column of the *Hindustan Times* have caused reflection on the entire parliamentary democratic system. It further goes to say:

> "The century-old libel law is completely obsolete in today's conditions. It has become an instrument in the hands of blackmailers and subverters."

This is a very serious charge and I feel that this matter must be referred to the Privileges Committee.

Shri N. Dandekar (Jamnagar): Sir, I am not concerned at all with the merits or the demerits of the allegations that were made against the Birla house either in this House or in the other House. I am merely concerned with the propriety of our attacking newspaper comments in an article, to the point at which it is

[Shri N. Dandeker]

suggested that they have gone beyond the bounds of propriety and, therefore, the writer of that article is being hauled up before the Privileges Committee.

Before we decide upon this, I think, we ought to consider very carefully the principles involved in this kind of situation. I am quite clear in my mind that in regard to the freedom of speech of Members of the House, it ought to be unlimited,—it is unlimited,—and consequently anything that encroaches upon the freedom of expression of the Members of the two Houses must be taken exception to. But I hope it is also understood that freedom to say things in this House or in the other House is not a licence and that there must be restraint and that there must be reasonable material on the basis of which comments are made. If a journalist takes it upon himself to argue or takes the view that the comments made were unrestrained amounting to licence, that the comments were made without foundation, that the particular report supposed to constitute the foundation for those comments does not in fact furnish any foundation,—we may not agree with the view he takes,—but I submit, it would be a dreadful curtailment of the right of the freedom of the press for us to object to the comments of that kind. I think you ought to be very very careful in that.

Mr. Speaker: The Privileges Committee may take all this into consideration.

Shri N. Dandeker: Sir, various accusations have been made. So, I am entitled to make my observations. I am not speaking against the motion. But I am entitled to make observations concerning the merits of the motion.

I would like to add a few more comments about the right of freedom of the Press. A free Press is probably the most important institution, next only to the two Houses of Parliament for the protection of freedom and for the preservation of democracy. We ought to be exceedingly careful before we attack it even to some extent. I do not think that in this case the press comment was not sober or that the comment was not reasonable, but I am prepared to agree that some Members who are exceedingly touchy about comments concerning themselves may find the comment somewhat vigorous or excessively and highly critical. Nevertheless, in so far as the comments are concerned, I would respectfully suggest that we should be prepared to give nearly as much freedom,—though not quite,—nearly as much freedom, to the Press to comment upon us as we have freedom to comment on affairs and men, so that neither the one nor the other is allowed to become a licence. I think, that is a right of the Press to which we are entitled in a democracy—(*Interruptions*).

Shri N. Sreekantan Nair (Quilon): Is it the opinion of the Swatantra Party or his own opinion?

Mr. Speaker: The hon. Member has expressed his opinion.

Shri N. Dandeker: I have not finished, Sir.

Two other points have been made. One is about calling the two Houses "shades of the Star Chamber". The difference between the shade of the tree and the tree itself is well recognised and I do not think somebody calling the House "shades of the Star Chamber" is in fact calling the House the Star Chamber.

Finally, as a journalist, the writer gives speculative consideration to whether something should not be done about this. That was perhaps wrong; he should not have done that. But being a responsible journalist, after having speculated as to whether the hon. Members of Parliament might

not be restrained from saying things of this kind, he goes on to say—that obviously, that is an exceedingly undesirable and impossible task. Perhaps this remedy, he feels, will raise other complications. There is certainly a danger that this will place a limitation on free expression in this House and so on. In other words, I submit that this is a fair comment; it is well within the ambit of not only the right, but also the duty, of sound journalism to make such a remarks.

Mr. Speaker: So many hon. Members are standing. Do they want to have a debate on this?

श्री मधु लिमये: एक मिनट मैं भी उनका जवाब देना चाहूंगा । अभी अभी अखबारों की स्वतंत्रता की बात कही गई है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने सारे अखबारों को खरीद लिया है, कहां है अब समाचार स्वतंत्रता ।

Mr. Speaker: No, no. Now I put the motion to the vote of the House. The question is:

"That this question of breach of privilege against the columnist, Editor, Publisher, Printer and Proprietor of the *Hindustan Times* be referred to the Committee of Privileges."

The motion was adopted.

12.49 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Industrial Disputes Act, 1947

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): On behalf of Shri Hathi, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O. 1776 published in Gazette of India, dated the 20th May, 1967, under sub-section (3) of section 40 of the Industrial Disputes Act, 1957, adding 'Service in any oil-field' to First Schedule to the said Act. [*Placed in Library, See* No. LT-542/67].

Annual Report of Indian Institute of Science, Bangalore

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the year 1964-65. [*Placed in Library, See* No. LT-543/67].

12.50 hrs.

RE: CALLING ATTENTION NOTICE

Mr. Speaker: Before I go to the other items of papers to be laid on the Table, I would like to say this. Mr. Nath Pai referred to some call attention or something and since I had not seen it, I was surprised where it had gone. Now I find that this came after 10.30. Normally according to rules, all the motions which are given till 10.30 are placed before me, and before I come to the House, I see them. But unfortunately Mr. Nath Pai's motion was given after 10.30. I was really wondering where it had gone. This is the reason why it was not seen by me. A decision on that has to be taken separately, independently. It was given later, after 10.30. That is what I understand from the office.

Shri Nath Pai (Rajapur): It has not been my habit to blame the Secretariat; they serve on the whole very loyally and at times very efficiently. I would not insist that they have made a representation to you which is not in harmony with the reality. So far as I can recall, when I was in the Notice Office—I had checked up the time—it was just 10.30. But the new rule which we have amended has not yet been accepted. Anyway, I would not be technical. May I make a request to you, if you are, on this technical ground, disallowing....

Mr. Speaker: No question of disallowing. It is a physical fact. I have not seen it.

Shri Nath Pai: May I request you to direct the Minister of External Affairs to make a comprehensive statement on the Resolution adopted by the Security Council. There have been three more deaths of Indian soldiers....

Mr. Speaker: No, no...

Shri Nath Pai: Since you have not seen it, I wanted to tell you.

Mr. Speaker: The Minister of Parliamentary Affairs may convey the feelings of the House to the Minister of External Affairs.

Shri Nath Pai: I have not finished my submission.

Mr. Speaker: I think he has understood the point.

Shri Nath Pai: I am speaking absolutely to the point. Three more Indian soldiers have lost their lives in doing a duty with which we agreed completely; I think the Government of India are responsible for not having brought them back home in time, and this was done, according to the information in the newspapers....

Mr. Speaker: The Foreign Minister will be asked to make a statement.

Shri Nath Pai: Because Government wanted to save some money, precious lives have been lost.

Mr. Speaker: Now, the hon. Member is straying away from the main point.

Shri Nath Pai: Not at all, this was the subject of my notice. May I know whether you are directing Government to make a statement on these points?

I want also to bring to your notice that the anxiety and agony expressed by Shri S. M. Joshi deserved your attention. You exercised your authority. I do not like anybody to defy it. But you ought to have heard him and listened to what he was saying. There are Indian citizens there and we are responsible for their safety and security. Is it not legitimate to ask the Government of India what steps they are taking for their safety and security? We have Indian citizens in Israel who have gone there on legitimate passports given to them and we had permitted them to go there....

Mr. Speaker: This will be communicated to the Minister concerned, and if he makes a statement I shall be very happy.

Shri Nath Pai: What steps are being taken to ensure the safety of our citizens in Cairo and Tel Aviv? I hope you will direct Government to make a comprehensive statement on all the three matters that I have raised.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (बलरामपुर) जो वक्तव्य होने वाला है उसमें एक बात और जोड़नी चाहिये। कल प्रधान मंत्री ने कहा था कि सैनिकों को हम लाना चाहते थे मगर युनाइटेड नेशंस ने वह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आज यू० एन० आई० की रिपोर्ट है कि रक्षा मंत्रालय के किसी उच्च अधिकारी ने उन सैनिकों को हवाई जहाज से लाने से रोक दिया क्योंकि खर्चा ज्यादा होगा। यह कहा गया कि वह पानी के जहाज से लाये जायें। अगर यह बात है तो यह प्रधान मंत्री के वक्तव्य के विपरीत है। हम जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है? क्या हम उन्हें हवाई जहाज से लाने को तैयार थे? जो वह वक्तव्य देने वाले हैं उसमें यह भी वह शामिल कर लें।

Shri Nath Pai: It was the Finance Ministry official who had stood in the way.

Mr. Speaker: How can he answer it? Some notice must be given and somebody must come and then make a statement.

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): On this issue which the hon. Member Shri A. B. Vajpayee has raised, I can give the details....

Mr. Speaker: Shri Ranga wants to make some point. Shri Ranga.

Shri Ranga (Srikakulam): It is within your right to advise Government to make a comprehensive report with regard to all these points.

Mr. Speaker: If, on the spur of the moment, the Defence Minister is prepared to make a statement, I have no objection.

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस आने वाले वक्तव्य के सम्बन्ध में मैं एक सवाल करना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर, श्री स्वर्ण सिंह ।

Shri Swaran Singh: The point that has been raised by Shri A. B. Vajpayee is not correct. The correct position is that the responsibility of repatriating, fixing the date of departure and making arrangements is squarely that of the UN. It is true that at one time it was suggested that they might be repatriated by air. This was not a question of any officer in the Defence Ministry or any officer in the Finance Ministry of the Government of India rejecting that, but this being the Secretary-General's responsibility, he insisted and he desired that the repatriation should take place according to a phased programme. He had actually fixed the date also and said that 19th June would be the date on which the Indian contingent should withdraw.

Shri Nath Pai: The Canadians and others had gone already.

Shri Swaran Singh: I am giving the facts, and he can argue on the basis of those facts.

Shri Nath Pai: These are selective facts. Is it not a fact that the Canadians had gone back earlier?

Shri Swaran Singh: This date was fixed as the 19th June; not only our contingent, but the Brazilian soldiers, the Swedish soldiers, and I presume, Yugoslavian soldiers also, were there. It is true that the contingent of one country, namely Canada was withdrawn, but that was under special circumstances, because the UAR Government had suggested to Canada that in view of the Canadian attitude in the Security Council and in the UN generally there was a strong feeling against the Canadians in UAR, and therefore, they advised that the Canadians should be immediately withdrawn. So, in this respect, the news item that has appeared that any officer in the Defence Ministry or in the Army Headquarters or in the Finance Ministry had turned down the proposal on financial considerations is not correct. It was the Secretary-General's responsibility, and our contingent having served the UN for a long time, we could not very well say 'no' if he said that the withdrawal should be according to a phased programme. He actually fixed the date, 19th June, and also fixed the mode of repatriating them, by sea. This is the actual position.

12·56 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—*contd.*

DISPLACED PERSONS (COMPENSATION AND REHABILITATION) AMENDMENT RULES

Shri L. N. Mishra: I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Amendment Rules, 1967, published in Notification No. G.S.R. 435 in Gazette of India dated the 1st April, 1967, under sub-section (3) of section 40 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act,

[Shri L. N. Mishra]

1954. [*Placed in Library, see* No. LT-554/67].

(2) A copy of the Revised Estimates for the year 1966-67 and Budget Estimates for the year 1967-68 of the Employees' State Insurance Corporation, under section 36 of the Employees' State Insurance Act, 1948. [*Placed in Library, See* No. LT-545/67.]

(3) A copy of Government Resolution No. WB-2(3)|67 dated the 3rd June, 1967, publishing Government's decisions on the recommendations made by the Central Wage Board for Iron Ore Mining Industry. [*Placed in Library, See* No. LT-546/67].

(4) A copy of Government Resolution No. WB-2(4)|67 dated the 3rd June, 1967, publishing Government's decisions on the recommendations made by the Central Wage Board for Limestone and Dolomite Mining industries. [*Placed in Library, See* No. LT-547/67].

AMENDMENT TO INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE (PAY) RULES; ETC.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): On behalf of Shri Vidya Charan Shukla,

I beg to lay on the Table:

(1) A copy of Notification No. G.S.R. 696 published in Gazette of India dated the 13th May, 1967, making certain amendment to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951. [*Placed in Library, See* No. LT-548/67].

(2) A copy of the Defence of India (Amendment) Rules, 1967, published in Notification No. G.S.R. 781 in Gazette of India dated the 26th May, 1967 under section 41 of the Defence of India Act, 1962 [*Placed in Library, See* No. LT-549/67].

12.57 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRD REPORT

Shri Khadilkar (Khed): I beg to present the Third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): I beg to move:

"That in pursuance of paragraph 3(2) (d) of the late Department of Education, Health and Lands Resolution No. F. 122-3|35-E dated the 8th August, 1935, as amended from time to time, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, four members from among themselves to serve as members of the Central Advisory Board of Education, subject to the other provisions of the said Resolution."

Mr. Speaker: The question is:

"That in pursuance of paragraph 3(2) (d) of the late Department of Education, Health and Lands Resolution No. F. 122-3|35-E dated the 8th August, 1935, as amended from time to time, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, four members from among themselves to serve as members of

the Central Advisory Board of Education, subject to the other provisions of the said Resolution."

The motion was adopted.

(ii) COUNCIL OF THE INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE, BANGALORE

Dr. Triguna Sen: I beg to move:

"That in pursuance of sub-clause (e) of clause 9 (1) of the Scheme for the Administration and Management of the properties and funds of the Indian Institute of Science, Bangalore, read with regulations 3.1 and 3.1.1. of the Regulations of the Institute the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Council of the Institute for the term ending on the 31st December, 1969".

Mr. Speaker: The question is:

"That in pursuance of sub-clause (e) of clause 9(1) of the Scheme for the Administration and Management of the properties and funds of the Indian Institute of Science, Bangalore, read with regulations 3.1 and 3.1.1. of the Regulations of the Institute the members of Lok Sabha do procced to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Council of the Institute for the term ending on the 31st December, 1969."

The motion was adopted.

12.57 hrs.

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

Mr. Speaker: General discussion on the General Budget to continue. Out of the 20 hours allotted, we have already taken 4 hours 50 minutes, leaving 15 hours 10 minutes. It is 12.57 now. We adjourn for lunch and meet again at 2 P.M.

12.59 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Shri Hanumanthaiya (Bangalore): Yesterday I was discussing the question of food subsidy which is of the order of Rs. 118 crores this year, and was of the order of Rs. 830 crores last year. I made the point that this food subsidy system is giving room for blackmarketing and corruption.

The second point I want to make on this subject is that according to available figures, fair price shops cater approxmately to a population of 230 million, of which 30 million are in statutorily rationed areas. That is to say, this big chunk of Rs. 118 crores is being given exclusively to a portion of the population, between 3 crores and 23 crores; it goes on petering out at the upper level. Why should, I ask in the name of social justice, 50 crores of people pay out of their pocket, by the compulsion of Government, to a small number of the population? You will agree, a nation must share both the benefits and difficulties equally, may be quitably, but merely because whe have political power in our hands, and governmental machinery in our hands, to compel the majority, overwhelming majority of the population to pay in this manner to a minority, is not social justice.

Thirdly, if you deal with this question of payment of food subsidy on a rational basis as I have been suggesting, the demand by the States will automatically go down, food imports will go down, foreign exchange will be saved.

[Shri Hanumanthaiya]

If perchance the Finance Minister reduces food subsidy or even abolishes it, we can straightway do away with the many taxes that he proposes to impose. This question of bringing down prices is a challenging task. It is not just a Government order that is to be passed, and not anyone and everyone, however earnest he may be, will be able to achieve it. It can be done only by a superman. Among, the ranks of our leaders, I see that the present Deputy Prime Minister partakes of that nature. If it was a lesser personality I would not have made this appeal. This problem of bringing down the prices is being discussed for the last twenty years, ever since we brought democratic Governments into existence here and in the States. Every Leaders became Finance Minister or Prime Ministers but no one has been able to fulfil the promise made viz. bringing down prices. Here is the last chance of your life. If in the course of this year, you are going to bring down the prices, not only we, some of your admirers, but even Members of Opposition parties will hail you as one of the great benefactors of India who gave new direction to the Indian economy. But if you fail you will be forfeiting even the confidence that you have earned so far during a public life which covers almost half a century.

As I was saying, food subsidy is one of the items. I have hardly the time now. The Government have given me an opportunity to scrutinise the administrative expenditure and make suggestions and I propose to do so in all earnestness so as to command acceptance from the Opposition Benches and from my own colleagues. It is with this approach that I am proposing to discharge the work entrusted to me by my Party and my Government. I am happy that the Administrative Reforms Commission's work has received the approbation of my enlightened friend Mr. Masani. May be, merely because Mr. Masani approves, some of my friends here may dub me as the spokesman of the Swatantra; some of their papers do say so. I can reveal to you a secret about the Congress success. We are a responsive organisation and when good ideas come, whether from the Swatantra party or Jan Sangh or the Communist Party, we accept them in all humility. Even in foreign policy, one party may not be able to agree with us, while another party is able to agree with us. Therefore, if Mr. Masani, the leader of the Swatantra Party approved the recommendations that the Commission has made, it is not because we want to toe the line of this or that party but we think it is the correct stand to take. We want more than anything else the progress of the country, and the progress of the country depends on administration. I am much beholden to Members of the Swatantra Party and I am sure the other parties will follow suit and give encouragement and appreciation and much more, coopertion and help to this Commission which is their true servant.

The Gajendragadkar Commission report has been published and I understand that the extra expenditure is likely to be of the order of Rs. 28 crores for the few months, and if it is implemented on a long-term basis it is going to cost about 40 crores a year. This makes for the upward movement of the price spiral. The Deputy Prime Minister and the Finance Minister has to show a cooperative spirit towards States whether Congress or Non-Congress Governments. He is not merely the Finance Minister and the Deputy Prime Minister representing the Government of India. He, I suppose, is a national leader, A national leader is a leader not only for the Government of India but also

for the States. It is in that full sense of patriotism, stature of all-India level that we have to judge our financial problems and not from the point of view of the Indian Government alone, because in the Constitution, in our anxiety to make the Centre strong, we have given many more sources of revenue than should have been given to the Centre. It is therefore that the Chief Ministers and the Finance Minister at the Centre have to sit together, as has been suggested by the Gajendragadkar Commission itself and evolve a formula for the payment of dearness allowance. This approach to the problem of dearness allowance is the first of its kind, it is now being done on the basis of consultation and not on the basis of a unilateral stand that has all the time been taken by the Government of India. We have to see that the difference in the pay structure, in emoluments and promotion prospects is bridged between the Central Government employees and the State Government employees. All the time, all of us talk of bridging the gulf between the poor and the rich. Why don't you apply that formula at least in this governmental field where you have got the opportunity and the power to do it? If you do not bridge the wide gulf that separates the State Government employees and the Central Government employees, all our talk will be bogus to the extent that we do not practise what we preach in our own homes.

I will deal only with one very unpopular subject and close my speech. Kindly bear with me. Members in their anxiety to bring down prices, ask the Government to reduce governmental expenditure. As you know reduction in governmental expenditure necessarily means getting rid of superfluous personnel, and when that is done, my hon. friends—some of them and not of all of them—come and say, "You cannot retrench; you have to give them the same employment." I will tell you, so far as social justice and employment are concerned, I have my own views. What is required in India is a proper distribution of our manpower in various sectors of production. Now, there is maldistribution. Every educated and intelligent man wants to work in an office, whether it is in the State Government or the Central Government. Much of the unemployment that we discuss pertains to that factor. Suppose certain people in the government service, whether it is the community project or the civilian employment in defence establishment, are retrenched, they can be employed in, the fields and the factories. We can open more factories. We can can open more factories and more State farms and things like that and give employment to them. But to ask them to be employed in the same offices and do the same work and be paid the same emoluments is a proposition which stultifies itself. I am for employment. But the State which takes the responsibility for employment must also be empowered to make proper distribution of our manpower in any field of productivity open to us. It is illogical for us to adopt the attitude that a Deputy Collector, if he is retrenched, must be found occupation somewhere also in an equal category of post. If a Deputy Collector or even a Collector is retrenched, let him go and be the principal of a college or school. Our educational system, according to our Triguna Sen and many of our friends, is very badly managed by poorly trained teachers. Let these people get their own pay of Collector, but let them be transferred to the field of education or any other field of development, factory or agriculture. In order to ensure production, reduction in expenditure and the bringing down of prices, this distribution of manpower should be looked at from this new angle rather than insisting, as Shri S. M. Banerjee does

[Shri Hanumanthaiya]

many times, in a very routine, mechanical manner, that the same people should be employed in the same office and on the same grade and in the same work.

Sir, I thank you for giving me the time.

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : उपाध्यक्ष महोदय, नीयत तो होती है कि जहां श्री हनुमन्तय्या ने विषय छोड़ा है वहां से शुरू करूं क्योंकि देश में इसमें कोई शक नहीं है कि आज सब से बड़ा संकट श्रम का संकट है। चरित्र का संकट, विश्वास का संकट, इन सब संकटों से बड़ा संकट श्रम का संकट है। लेकिन उसको कैसे दूर करना है, इसका जब पता लगाने की कोशिश की जाती है तो मालूम पड़ता है कि हनुमन्तय्या जी कहीं ऐसी जगह पाए जाते हैं, जहां श्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिये सबसे पहले मैं आप से कहूंगा कि मुझे तो आप से बोलना है विपक्ष से बोलना है और उस लंगोटी के फकीर के उन लोगों से बोलना है जो गद्दी पर बैठने के लिये उसके पीछे नहीं लगे थे, लेकिन जो उसके आदर्श के कारण लगे थे।

सुना था कि अब की बार बड़ा बढ़िया कोई बजट आने वाला है जिससे देश में नई जान आयेगी, उन्नति होगी, नया जमाना आएगा, तरक्की होगी, आत्म सम्मान जागृत होगा। लेकिन जब काटा तो खून का एक कतरा भी नहीं निकला और प्राण घातिनी रक्त की एक भी बूंद नहीं निकली। निकली जरूर। लेकिन क्या? शराब की बोतलें। शराब की बोतलें राज्यों के लिए, जितनी चाहो, पी लो। लेकिन रक्त की बूंदें नहीं।

अब ऐसी स्थिति हो तो शराब बन्दी या सोना बन्दी के बारे में मुझे एक बात कहना है। ये चीजें बड़ी अच्छी थीं कोशिश करते वक्त। लेकिन क्यों असफल हुए? क्योंकि बीस बरस में जो हमारा राजा वर्ग रहा है, वह या उसके नजदीक के लोगों ने इन बन्दियों से आर्थिक लाभ उठाया और प्रजा में भी ऐसा संकल्प और स्वयं सेवक नहीं रहे। चीन को मैं राक्षस समझता हूं। लेकिन उस संकल्प के मामले में उसका उदाहरण देना चाहता हूं।

अब सवाल विपक्ष का रहता है। उधर से मुझको कई बार गारंटी मिली है कि हम तीस आदमी तुम्हारी तरफ आने को तैयार हैं लेकिन एक शर्त पर कि इधर का कोई उधर न चला जाए और ये सब मिल कर सरकार बना लें। अब यह गारन्टी देना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि प्रधान मंत्री जी आजकल बड़ी उदास रहती हैं। लेकिन उनका चेहरा जरूर खिल उठता है जब वह विपक्ष को आपस में लड़ता देखती हैं। कल भी यही हुआ है। और भी मौकों पर हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि कल जब मैं अटल बिहारी बाजपेयी जी को सुन रहा था तो ऐसा लगा कि अटल बिहारी बाजपेयी जी और डांगे जी और गोपालन जी ये तीनों चाहें तो आसानी से एक सरकार में रह कर अपना कामकाज चला सकते हैं। हां थोड़ी अतिवादियों में झंझट होगी—अतिवादी जैसे श्री बलराज मधोक, श्री कंठन नायर। उनके आपस में आने में थोड़ी देर लग सकती है लेकिन आखिर को जो इन्होंने कहा था, बाजपेयी जी ने, डांगे जी ने और मैं अंदाजा लगाता हूं राम मूर्ति जी के द्वारा गोपालन जी ने बात एक ही थी। बात तो वैसे प्रधान मंत्री की भी वही थी। गर्म सांसें बहुत थीं उनकी भी और दूसरों की भी। लेकिन बात क्या थी? एक सिपाही नहीं भेजना, एक कुमुक नहीं भेजनी, एक रसद नहीं भेजनी, कुछ नहीं भेजना लेकिन—

Shri Randhir Singh (Rohtak): Speak on the budget.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह पैसे का मामला है, यह इन को आप ही बता दें।

सांस की गर्मी थी लेकिन कहती थीं कि रसद आदमी यहां तक की दवा दारू करने के लिए एम्बुलेंस तक भेजने की बात किसी ने नहीं कही। जहां तक कि कर्म था उस मामले में सब बिल्कुल ही निरपेक्ष थे या किसी की तरफ नहीं थे।

क्या बात है ? क्यों न हम सब लोग एक आधार के ऊपर विपक्ष के लोग विदेश नीति में भी इकट्ठा हो जाएं? पारथासार्थी जी सुरक्षा परिषद् में जो कुछ प्रस्ताव रख पाए मैं तो दंग रह गया यह देख कर कि रूस और अमरीका उससे भी और कम में एक हो गए। यह हम सब के लिए सोचने वाली बात है। रूस और अमरीका तो कई दफा हो जाते हैं लेकिन हिमायती लोग आपस में ज्यादा लड़ा करते हैं। जो मुख्य लोग होते हैं वे कम पर भी राजी हो जाया करते हैं। वे तो इस बात पर राजी हो गए हैं कि युद्धबन्दी कर डालें।

असल में हमारा जो यह सारा मामला बिगड़ा हुआ है, उस का कारण है विदेशी सहायता, विदेशी नीति और यह विदेशी अंश, जो हमारी राजनीति, बजट, रुपये-पैसे, खेती-कारखाने मे आ गया है। मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूं कि किस तरह से भारत तन और मन दोनों से अपना नहीं रह गया है पराया बन गया है।

अक्तूबर, 1949 में प्रधान मंत्री जी अमरीका गये थे। तब उन्होंने बीस लाख टन गेहूं और पूंजी चाही थी, लेकिन वह उन्होंने भीख की तरह नहीं मांगी थी। तब तक आत्म-सम्मान था, अहंकार था। अमरीका वालो ने स्वीकार नहीं किया। कब तक वह अहंकार चला। दिसम्बर, 1950 तक—अक्टूबर 1949 से ले कर दिसम्बर, 1950 तक। और तब वहां के राजदूत ने लिख कर अमरीका वालों ने बीस लाख टन गेहूं और पूंजी की मदद मांगी। इस बारे में अमरीका वालों ने जो अपने प्रस्ताव पास किये, उन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि हम भारत को गेहूं वगैरह तो देंगे, लेकिन हम उस से ऐसा सामान लेंगे, जो अमरीका को चाहिए, चाहे अपने साधनों में कमी के कारण और चाहे लड़ाई वगैरह के लिए जरूरी होने के कारण।

मैं खाली वाक्यांश पढ़े देता हूं।

"Administrator for Economic Cooperation."

वह क्या ले लेगा।

"Materials required by the United States as a result of deficiencies, actual or potential, in its own resources."

और वे क्या चीजें हैं ?

"Immediate and continuing transfer of such materials particularly those found to be strategic and critical".

1951 में यह बात कही गई और हिन्दुस्तान ने अमरीका को मैंगानीज और मौनाजाइट अयस्क जिस को लोग और कहते हैं जो अणु उद्योग में बहुत जरूरी हैं देना शुरू कर दिया। 1951 के बाद से हिन्दुस्तान का खान बिल्कुल अमरीका के हाथों में चला गया।

इतना मैं आप को बता दूं कि एक दफा अमरीका की सेनेट के प्रस्ताव में "मैंगानीज और "मोनाजाइट" शब्द भी आ गए थे। लेकिन बाद में जब दोनों सदनों की बैठक हुई तो जरा सम्मान को रखने के लिये उस में से ये शब्द हटा दिये गए थे। यह बात भी सही है कि इस समय भी भारत का व्यापार और जो कुछ भी तन का रिश्ता होता है करीब करीब अस्सी सैकड़ा, और अगर मान लें कि वह कुछ बदला भी हो, तो भी सत्तर सैकड़ा उस तरफ है। उसी कानून की धारा 7 के अनुसार इस ऋण के सूद से विद्यार्थियों, प्रोफेसरों, तकनीकियों वगैरह को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हुई यह मामला अमरीका से शुरू हो जाता है।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

जब अमरीका से यह मामला शुरू हुआ, तो रूस की थोड़ी सी बात जान लेनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से अमरीका चीन से खतरा खा चुका था और उस को जरूरत थी हिन्दुस्तान जैसे देश की, उसी तरह से स्टालिन की मृत्यु के बाद रूस को भी जरूरत पड़ गई ऐसे देश की जो चीन के बगल में, या तराजू के बटखर में मुकाबले पर रखा जा सके। पहली दफ़ा ख्रुश्चेव और मिकोयान वग़ैरह 1954 में पीकिंग में जा कर कम्युनिस्ट नेताओं से मिले। मामला वहां से सरकना शुरू हो गया और तब जून, 1955 में आवागमन हो गया और बड़े जोरों की दोस्ती चल पड़ी। अमरीका और रूस दोनों को इस बात की जरूरत थी कि चीन के मुकाबले में एक शक्ति खड़ी की जाये।

अमरीका ने तन लिया रूस ने मन लिया— वैसे मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्राणी का तन अलग हो जाता है उस का तन ही महत्वपूर्ण हुआ करता है मन नहीं—, लेकिन मन भी कहना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि असल में रूस को मतलब बोली से था कि बोली किस के साथ हो। बोली का प्रेम। रूस को अपनी जनता को बताना था कि अगर सत्तर करोड़ चीनियों से हमारा वैमनस्य हो रहा है तो कम से कम पचास करोड़ हिन्दुस्तानी तो हमारे हाथ लग रहे हैं। इस के अलावा उन को जरूरत थी कि हिन्दुस्तान में सरकारी धन्धे वग़ैरह निजी धन्धों के मुकाबले में बढ़ें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि साधारण तौर से यह समझा जाता है कि शीत-युद्ध तब शुरू हुआ, लेकिन शीत-युद्ध तो 1950 में खत्म हो गया था। जब इस बारे में अच्छी तरह से अध्ययन होगा, तो इस बात का पता चलेगा कि अमरीका और रूस दोनों ने जो कुछ करना था, वह उन्होंने 1949 तक कर लिया। अमरीका वाले ग्रीस, ईरान और तुर्की वग़ैरह में जीत गए और रूस वाले पौलैंड वग़ैरह में जीत गए। 1950 के बाद जो शीत युद्ध शुरू हुआ, वह असलियत से ज्यादा नाटक था। फिर रूस और अमरीका में एक तरह का समझौता हो गया कि ऐसी बीन बजाते रहो, जिससे दुनियां भर के सांप सोते रह जायें। उन में यह समझौता हो गया कि हिन्दुस्तान जैसे देश को सुला कर रखा जाये, इस में ताकत न आ पाए। चीन एक जंगली जानवर की तरह इस जाल में फंस गया। जब वह मात्सू और किमाय पर अपने दांत गड़ाने गया, तो उसके दांत टूट गए। तब उसने हिमालय जैसे मुलायम मांस में अपने दांत गड़ा कर अपना पागलपन दिखाया। लेकिन इस में कोई शक नहीं हैं कि तब से भारत सरकार यहां पर गुलामी, दरिद्रता और विघटन की एजेन्ट बन गई। जो भारत की कांग्रेस अंग्रेजों के जमाने में आजादी की एजेन्ट थी, वह रूस और अमरीका के इस चक्कर में चलते हुए और चीन की इस पागल नासमझी के कारण ग़रीबी और गुलामी की एजेन्ट बन गई।

अगर आप इस विदेशी सहायता के कुछ मोटे मोटे अंक देखें, तो एक बड़ी विचित्र बात मालूम होगी। पहली योजना में कुल विदेशी मदद 5.8 सैकड़ा, दूसरी योजना में लगभग 21 सैकड़ा, तीसरी योजना में लगभग 25 सैकड़ा थी और चौथी योजना में लगभग 25 सैकड़ा का प्रस्ताव रखा गया है। विदेशी सहायता का अंश बढ़ता चला जाता है। और आमदनी का क्या हाल होता है ? पहली योजना में राष्ट्रीय आमदनी 18 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी, यानी करीब करीब 4 सैकड़ा बढ़ी और तीसरी योजना में राष्ट्रीय आमदनी में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था 5 सैकड़ा का, लेकिन वास्तव में, 2, 2.5 सैकड़ा की वृद्धि हुई। जैसे जैसे विदेशी सहायता बढ़ती है, वैसे वैसे राष्ट्रीय आमदनी घटती है, यह बात मैं आंकड़ों से बिल्कुल साबित किये दे रहा हूं। विदेशी सहायता बढ़ी और आमदनी घटी, इस के क्या कारण हैं ? इस सदन को इस पर ग़ौर करते वक्त यह भी फैसला करना चाहिए

कि अब यह जरूरी हो गया है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो कर इस ढंग की विदेशी सहायता को खत्म करके अपनी आमदनी को बढ़ायें ।

इसके साथ ही भुगतान का संतुलन बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ गया है कि पहली योजना में तो खाली 3 अरब रुपये की कमी रही और इस वक्त 63 अरब तक मामला चला जाता है ।

कहते हैं कि इन योजनाओं का नतीजा है आत्म-निर्भरता, लेकिन है आत्म-प्रवंचना । एक तो मैं मसानी साहब को बताना चाहूंगा कि अमरीकी लोग अपने देश में योजना पसन्द नहीं करते, लेकिन देश के बाहर पसन्द करते हैं । यूरोप में मार्शल प्लान था । हिन्दुस्तान में कोई न कोई प्लान है, क्योंकि बिना योजना के उनको ऋण देना और सहायता देना बड़ा मुश्किल हो जाया करता है । यहां पर भी जब तक योजना न बनायें, तब तक तर्क बड़ा मुश्किल हो जाता है ।

भारत की जनता को बतायेंगे क्या कि हम क्या कर रहे हैं । तो तर्क के कारण और ऋण लेने के कारण यह लोग योजना बनाते हैं, योजना में और कोई आत्म-निर्भरता वगैरह का उद्देश्य है नहीं । योजना का नतीजा अलबत्ता यह हुआ है कि विदेशी सहायता में अगर सब अब कर्जा जोड़ा जाय और मैं वह 20 करोड़ रुपया जो अंग्रेजों के यहां बाकी था उस को भी जोड़े लेता हूं और अवमूल्यन से जो रुपया बढ़ा है उस को भी जोड़ लेता हूं तो आज 80 अरब हो गया है और 1950 में कुल 32 करोड़ था । 32 करोड़ से 80 अरब । 200 गुना बढ़ा है । अगर उसके साथ साथ आय बढ़ी होती, पूंजी बढ़ी होती, व्यापार खेती बढ़ी होती तो बात समझ में आती लेकिन ऐसा मालूम होता है कि यह सरकार उस बाप की तरह है जो अपने बेटे के ऊपर अपने चालू खर्चे का बोझ डालता रहता है और उस को शर्म भी नहीं लगती कि क्या वह कर रहा है ? इसी तरह से इस योजना का नतीजा यह हुआ है कि कहीं किसी तरह का विचार दर्शन नहीं रहा और अगर आप याद करें तो सिलसिलेवार इस सरकार ने क्या कहा ? क्या विचार अपने सामने रखा ? एक दफे कहा सब वाद खत्म करो, सब इज्म खत्म करो, खाली हिन्दुस्तान बनाओ । फिर वह, जब काफी नहीं लगा तो दूसरा इन्होंने नारा लगाया जिस का कामनवेल्थ नाम रखा, पता नहीं क्या अर्थ निकलता है उस का ? फिर वह खत्म हुआ । तब कहा कि हम कल्याणकारी राज बनायेंगे । फिर वह खत्म हुआ तब कहा कि अब हम समाजवादी ढांचा बनायेंगे । अब समाजवाद है । वास्तव में केवल एक वाद है कि कोई भी वाद मत रखो क्योंकि जो विदेशी सहायता देने वाले लोग हैं वह चाहते हैं कि इस देश में वाद नहीं रहना चाहिए । इस देश में योजना पदार्थ के ऊपर बने । मुझसे न जाने कितने लोगों से बात हुई है विदेशियों से । वह झट से कह देते हैं कि तुम्हारे देश को जानते हो क्या चाहिए ? ट्रैक्टर चाहिए, तुम्हारे देश को उर्वरक चाहिए । हमेशा पदार्थ के बारे में बात करते हैं । यह खाली अमेरिका नहीं रूस भी कहता है । वह भी कहते हैं, तुम्हारे देश को जानते हो क्या चाहिए ? बोकारो चाहिए, तुम्हारे देश को फौलाद चाहिए । हमेशा पदार्थ की बात करते हैं । कभी भी वह मनुष्य की, मनुष्य के दर्शन की, सम्पत्ति के रिश्तों की, किस तरह से व्यापार खेती कारखानों के संगठन को बनाया जाय इस की चर्चा नहीं करते । इस मामले में रूसी और अमरीकी एक जैसे हो गए हैं और क्यों न हो जायं ? रूसी अब अपना अतीत भूल चुके हैं । अब वह आज के रूस को जानते हैं । वह देखते हैं कि आज का रूस खुश हो रहा है, सुखी हो रहा है । तो जो उनका वर्तमान अनुभव है वही अनुभव वह हिन्दुस्तान के ऊपर भी लाद देना चाहते हैं । अमरीका और रूस दोनों चाहते हैं कि यहां पर एक खर्चीला और आधुनिक वर्ग पैदा हो जाय जो उन की नीतियों

[डा० राम मनोहर लोहिया]

को समझौता हुआ आगे बढ़ा सके । उनकी नीतियों में संघर्ष बहुत कम होता है । मैंने बताया जहां होता है वहां थोड़ा सा तन और मन वाला वरना स्थिरता दोनों चाहते हैं । स्वतंत्र आर्थिक विकास, अथवा स्वतंत्र आर्थिक चिन्तन इस योजना के कारण अपने देश में बिल्कुल खत्म हो चुका है क्योंकि हर एक के मन में अब यही हो गया है कि बाहर से पैसा लेते रहो, दोनों तरफ के आय व्यय को मिलाते रहो । किसी तरह से एकाध नये कारखाने बनाते रहो और अकाल को स्थित में हमेशा पड़े रहो । इस के लिए उदाहरण भी दिए देता हूं कि पहली योजना कोलम्बो प्लान में शामिल थी । दूसरी योजना की तैयारी में मैसाचूसेट्स इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी और हार्वड विश्वविद्यालय ने मदद दी थी । कितना ज्यादा यह मामला बढ़ता चलात आ रहा है और भुगतान संतुलन की बात तो मैंने आप से कही ।

अब इतनी स्थिति जब खतरनाक हो जाय तब मसानी साहब का कहना—बोकारो काटो—हो सकता है किसी हालत में सही हो और डांगे साहब का कहना कि त्रिवी पर्म काटो यह भी सही है । बिलकुल सही है हालांकि जो तर्क उन्होंने दिया वह अधूरा था । उन्होंने केवल तर्क दिया कि खाली पांच करोड़ रुपये का मामला नहीं है । उसके साथ साथ अधिकारों वगैरह का मामला है । यह मामला तो बहुत ही खतरनाक है । कुल कुटुम्ब और जाति की राजनीति का मामला है । जब तक हम अपने देश में ऐसा वर्ग बनाए रखेंगे जो केवल अपने जन्म और पैदाइश के कारण किसी विशेष अवसर को पाता रहेगा तब तक देश सुधर नहीं पायेगा । लेकिन मैं दोनों से कहूंगा कि यहीं क्यों रुकते हो ? इन्हीं को क्यों काटते हो ? और जरा आगे बढ़ो और काटो । मंत्रियों की सुविधाओं को काटो और करोड़पतियों की सुविधाओं को और नफे को काटो । देश में और जो फिजूलखर्ची होती है उसको काटो । मुझे आश्चर्य होता है जब इस सभा में, इस सदन में छोटी मोटर गाड़ियों के ऊपर बहस होती है । मेरी बात को गलत छापा जाता है । मैं छोटी गाड़ियों के खिलाफ नहीं हूं । मैं सब तरह की निजी गाड़ियों के खिलाफ हूं । जितना भी मोटर गाड़ियां बनाने का हिन्दुस्तान में इन्तजाम है वह अगले पन्द्रह बीस वर्ष तक सिर्फ ट्रैक्टर, बस, टैक्सी अथवा सिंचाई की मशीनों के लिए इस्तेमाल किया जाय । निजी मोटर गाड़ियां छोटी या बड़ी बनाई ही न जायें वहां पर रोक होनी चाहिए । उसी तरह से मकान और महल क्यों बनाए जायं । अगले पन्द्रह बीस वर्ष तक उन पर खर्चा रोक दिया जाय । अब स्कूल वाली बात तो धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगी है । सरकार के भी कागजों में वह बात आ रही है कि चाहे बड़े आदमी हों, चाहे छोटे आदमी हों सब के बच्चे कम से कम पांच से दस वर्ष की उम्र तक एक साथ पढ़ें । अगर इन सब खर्चों को जोड़े आप को कई अरब रुपये की बचत हो जायगी ।

वित्त मंत्री साहब प्रदेशों को कहते हैं कि जैसे मन में आये करो लेकिन अपने साधनों से । अगर मैं किसी प्रदेश का होता तो मैं कहता वित्त मंत्री जी, आप भी अपने ही साधनों से खाली करो । विदेशी कर्जे से नहीं । नोट छाप कर नहीं क्योंकि जो नोट छापते हो उस में जितना आप का है उतना ही हमारा भी है । अपने साधनों में काम करने की जो चुनौती यह देते हैं बार बार इन को चुनौती अगर प्रदेशों ने देना शुरू कर दिया और मैं चाहता हूं कि वह देना शुरू करें तो तब इनको पता चल जायगा कि यह कहां तक स्वयं आगे बढ़ सकते हैं ।

मैं समझता हूं कि भारत का बजट बहुत अच्छा साधनों के हिसाब से और आज की गिरावट की हालत में बनाया जा सकता है बशर्ते कि खाली आय-व्यय के हिसाब से न

देखा जाय। साधन श्रम है, साधन खर्चे में कमी है। मैंने अभी खर्चे की कमी की बात कही, स्रोत के ऊपर, उस के अलावा और तरीकों से। मुझे इससे मतलब नहीं किन चीजों का राष्ट्रीयकरण करते हो, जरूरत पड़े सब चीजों का राष्ट्रीयकरण करो। मुझे इस से मतलब नहीं कि खर्चे के ऊपर केवल सीमा कानून से लगाते हो या आयकर से लगाते हो या किस तरह से लगाते हो, लेकिन सीमा बांधो खर्चा करने के लिए चाहे जैसे भी हो। आज के हिन्दुस्तान में मैं पन्द्रह सौ रुपये से ज्यादा किसी को नहीं खर्च करने देना चाहता हूं। जिसमें वित्त मंत्री का तो पन्द्रह सौ भी नहीं पड़ेगा, बारह तेरह सौ शायद पड़ जाय तो पड़ जाय और उसमें सुविधाएं वगैरह शामिल हों। तो खर्चे की अगर सीमा बांध दी जाय तो मेरे हिसाब से करीब हजार से पन्द्रह सौ करोड़ यानी 15 अरब रुपया साल बच सकता है। लोग इस हिसाब को सुनकर दंग रह जाते हैं लेकिन वास्तविक स्थिति यही है। यह बात सही है जो हनुमंतैया साहब ने कही कि अब इस तरह का खर्चा कम करोगे तो सही बात है कि जो आजकल सरकारी नौकरों की तादाद बढ़कर सवा करोड़ डेढ़ करोड़ हो गई है जिस में कि एक लाख सरकारी नौकर तो आप जैसे बड़े लोगों की शान शौकत, ठाट बाट के लिए हैं, सलामी देने के लिए हैं और कुछ लंगूर लोग जाकर के सलामी ले भी लिया करते हैं, यह एक लाख आदमी जो हैं, इन के ऊपर खर्चा कम करना है तो मैं यह नहीं कहता कि इनको काम से बाहर निकाल दो। लेकिन यह सही है कि आपकी सरकार में दम नहीं है, शायद हमारी सरकार में भी दम नहीं है लेकिन वह सरकार जो दम रखेगी इन लोगों से खेती का खाने में काम कराने का या उन को बरखास्त करने का वही हिन्दुस्तान के मसले को हल कर सकेगी और कोई सरकार वहां के मसले को हल नहीं कर सकेगी। हजार से पन्द्रह सौ करो।

बोनस वगैरह के मामले में भी कह देना चाहता हूं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता है—साफ बात है—एक तरह का चक्कर चलता है, लेकिन चक्कर चलाता कौन है? केन्द्रीय नौकरों का बोनस बढ़ाते हो अपनी गद्दी को बरकरार रखने के लिये, तो प्रान्त के नौकर अपना बोनस क्यों नहीं बढ़वाना चाहेंगे। आपका जितना काम होता है, गद्दी पर बैठे रहने के लिये होता है, तो मेरे जैसा आदमी इस बात को जरूर कहना चाहता है कि आज ऐसा हिन्दुस्तान होना चाहिये, कि जिसमें जितनी चिन्ता नीचे के नौकरों का बोनस बढ़ाने की होनी चाहिये, उस से ज्यादा चिन्ता ऊपर वालों के खर्चे और सुविधायें घटाने की होनी चाहियें। जब बड़े बड़े मंत्रियों के घरों में नमक, दाल, हल्दी के दामों की फिक्र होने लग जायगी, तब जाकर चीजों के दाम गिरेंगे, उस से पहले गिरने वाले नहीं हैं। तो पहले बड़े लोगों के खर्चे गिराओ। यह श्रम का संकट है। चरित्र का संकट है—लोग ऐसा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो बड़े लोग हैं, वे बड़े लोग ईमानदार नहीं रह गये हैं। क्योंकि पिछले 20 वर्षों से लूट-खसोट मची हुई है, जो पाया उड़ाया। यहां की अर्थ-व्यवस्था विकासोन्मुख नहीं है, फैलाव इसमें नहीं रह गया है, विश्वास खत्म हो गया है, आज भारत की जनता को विश्वास नहीं रह गया है कि हमारी खेती और कारखानों में तरक्की हो सकती है या फैलाव हो सकता है और जब यह विश्वास खत्म हो जाता है तो हर समूह अपने टुकड़े को बढ़ाना चाहता है, हर व्यक्ति अपने हिस्से को बढ़ाना चाहता है—चाहे भाषा के नाम पर, चाहे प्रदेश के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, हर तरफ लूट मची हुई है कि अपना अपना हिस्सा बढ़ाओ क्योंकि कुल हिस्सा बढ़ाया नहीं जा सकता। यह श्रम का संकट बड़ा जबरदस्त है।

मैं एक चीज कह दूं—जो कुछ आंकड़े मैंने बतलाये हैं, उस के लिये मुझे बहुत ज्यादा मदद मिली है एक नौजवान अध्यापक से—काशी विद्यापीठ के श्री कृष्ण नाथ शर्मा से। दूसरे नौजवान लोग भी जरा स्वतंत्र चिन्तन इस ढंग से किया करें, तो ज्यादा

[डा० राम मनोहर लोहिया]

अच्छा है । तो केन्द्रीय योजना के लिए इस बजट में 1176 करोड़ रुपये कि व्यवस्था की गई है यानी 11 अरब रुपये की, जबकि चौथी योजना के मसविदे के मुताबिक औसत 2516 करोड़ रुपये का था यानी 25 अरब रुपये का । 25 अरब से 11 अरब पर उतरे हैं, 14 अरब काटे हैं मोरारजी भाई ने. . . .

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): That is not true. He must include the outlay on the States' plans also. It would be about Rs. 2000 crores.

डा० राम मनोहर लोहिया : वह भी गिन लीजिए, उस में कोई सुधार हो तो बता दीजिये, चलो इस को भी ले लो । अब मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा सहारा दिये देता हूं, आप 2000 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन राज्यों का 3420 करोड़ रुपया इस के अलावा है, वह भी आप जोड़ लें । सवाल यह है कि 1000 हजार करोड़ रूपया हर हालत में मोरारजी भाई ने काटा है, साहब ने काटा है, मैं साहब कहना भूल रहा था । अगर यह कट सकता है, तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मुझ से मत पूछना कि कैसे काटा है, आपने काटा है, अशोक मेहता के गले पर छुरी चलाई है एक हजार करोड़ रूपये की । मैं चाहता हूं कि उस रुपये का और किसी काम में नहीं, केवल सिंचाई के हर एक काम में प्रयोग होना चाहिये, चाहे वह जमुना जैसी गन्दी नदी से पानी उलीच कर फेंक देने में, जैसे आसमान पानी फेंकता है, चाहे नहर से पानी फेंको, जमीन के नीचे से पानी निकालो, चाहे कच्चे कुंए से, चाहे मशीन के कुंए से, जिस तरह से भी हो, पानी निकालो । अगर मैं जरा भी इस सरकार के ऊपर ताकत रखता तो इस सारे बजट को ऐसा बनाता और ये सारे साधन मौजूद हैं, इनके द्वारा ऐसी व्यवस्था करता कि यह जो तीन-चार अरब रुपया हम परदेसियों को खाने के लिये देते हैं, पहले ही साल में उस में आधे या तीन चौथाई की कमी हो जाती, और दूसरे वर्ष तक वह बिलकुल साफ हो जाता । पांच साल के अन्दर अन्दर पूरी जमीन को पानी मिल जाता, लेकिन इस काम के लिए एकाग्र मन चाहिये, आज एकाग्र चिन्ता नहीं है और हो कहां से ?

मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी इजाजत देंगे, क्योंकि मेरे बारे में कुछ बातें कही गई हैं . . . . . .

Mr. Deputy-Speaker: He should conclude now.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : हमारी ओर से एक ही वक्ता हैं, और कोई नहीं बोलेगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह कहा गया —कि यह आदमी बातें तो इस ढंग की करता है, लेकिन क्या यह कोई पूंजीपति है? एक साहू-जैन हैं, उस से एक लाख रुपया लेकर उसकी एक पैटीशन (याचिका) लोक सभा में दिलवादी है । "साहू-जैन से—उनकी याचिका"—मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, हालांकि मैं इसमें अपनी इज्जत की कमी समझता हूं कि मैं कहूं कि यह बात बिलकुल झूठ है, लेकिन फिर भी मैं कहे देता हूं । एक भले आदमी को इस बात के कहने की जरूरत पड़ी और आपकी इतिला के लिये बता दूं कि मुझे इस याचिका का तब पता चला, जब यह लोक सभा में दी जा चुकी थी और अखबारों में यह बात छपी थी, खैर मैं उसको छोड़े देता हूं । अब मैं इस पूंजीपति और अपने संबंध के बारे में कहे देता हूं, यह जो साहू-जैन महाशय हैं, इन के एक आदमी हैं, श्री राम कृष्ण डालमिया—मैं एक बात और कह दूं, मुझ को अमीर न समझ लेना, मेरे पास एक इंच भी जमीन नहीं है, पैसा नहीं है । मेरे किसी रिश्तेदार ने श्री राम कृष्ण डालमिया का जब दिवाला निकल रहा था,

उन को कर्जे के तौर पर रुपया दिया था। उन्होंने बताया कि अगर आज के हिसाब से सूद समेत लिया जाय तो पांच से दस लाख रुपया हमारे हिस्से पड़ेगा, मैं अभी तक उसका इन्तजार कर रहा हूं, वह अभी तक नहीं आया है। इसी साहू-जैन ने मुझे को बताया कि तुम तो अजीब आदमी हो, कांग्रेसवाले तो कोहनी पकड़ने देते हैं, कम्यूनिस्ट पहुंचा पकड़ने देते हैं, तुम तो अंगुली भी नहीं पकड़ने देते। क्योंकि मैं तो 1500 रुपये पर रोक लगाना चाहता हूं।

टाटा साहब ने एक बार मुझे खुद लिखा था, मुझे बड़ा अफसोस है कि उस वक्त मैंने उस का जवाब नहीं दिया, उस वक्त जवानी की कम उम्र थी। मैंने जमशेदपुर में एक भाषण दिया था कि टाटा साहब की रोज की 10—15 हजार रुपये की आमदनी है। उन्होंने लिखा था कि यह गलत है। तब मैंने उस पर बहस करने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन आज मैं उनसे माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं कि अगर उनकी सुविधाओं को जोड़ा जाय, जिसको वे लोग एमेनिटीज कहते हैं, तो यह आमदनी उस से भी कहीं ज्यादा है। एक बात मैं यहां पर यह भी कह दूं कि भारत में आज का जीवन न सिर्फ निर्लज्ज है, गन्दा है, खराब है, क्योंकि इस में एक्सपैन्डिचर एकाउन्ट को इन्कमटैक्स में नहीं जोड़ा जाता है। इन्कमटैक्स के जो तरीके इन्होंने बना रखे हैं, उस के हिसाब से जितना मन में आये खर्च करो, खूब खर्च करो, क्योंकि अगर बच जायगा तो आय कर में चला जायगा, इस लिये खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है।

आज कल बिरला की बात चल रही है। एक बार एक बिरला ने मुझ से कहा था, जब गांधी जी जिंदा थे, कि कांग्रेसियों से तो तुम ही अच्छे हो। मैंने कहा कि क्या सरदार पटेल ने कोई नया टैक्स लगा दिया है आपके ऊपर ? बोले, तुम तो हमेशा मजाक करते हो। कांग्रेस वाले कहते हैं कि पहले मोटे हो जाओ, 10 साल बाद काटेंगे। तुम कहते हो कि अभी काटेंगे। मैंने कहा याद रखना हम तुम्हारी जिन्दगी बचाने की हमेशा कोशिश करेंगे, आपका पैसा जरूर छीनना चाहते हैं, लेकिन सिर नहीं कटने देंगे। अगर मेरे हाथ में ताकत रही तो मैं चाहता हूं कि पूंजीपतियों का व्यापार का जो हुनर है, अकल है वह हिन्दुस्तान की खेती और कारखाने में इस्तेमाल की जाय। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपके ऊपर कोई कुत्ता छोड़ा जाय तो उस कुत्ते से तो कतरा जाओगे लेकिन उसके मालिक की गरदन पकड़ोगे न। मैंने सोचा था कि मैं शायद अब इस काम को न करूं लेकिन मुझे मजबूर होकर फिर से इस सरकार के मुखिया प्रधान मंत्री के व्यवहार के बारे में विचार करना पड़ता है क्योंकि जो कुछ बातें मैं कहता हूं वह आधार सहित कहता हूं और जो आरोप लगाता हूं उस के पीछे तथ्य है। अगर उस का नतीजा यह निकलता है कि मन में आया जहां जिस को मेरे ऊपर छोड़ दिया जाय तो मैं यह बताना चाहता हूं कि वह बिड़ला हैं न, इन्होंने प्रधान मंत्री का मार्ग प्रशस्त करने के लिये अमरीका में 10 लाख से ज्यादा खर्च किया। न्यूयार्क टाइम्स का एक विशेषांक निकाला था। यह दोस्ती कोई बहुत नई नहीं है। जब उन की शादी हुई थी तब भी बिड़ला लोगों ने 50,000 रुपये का हार दिया था। हार से कोई शोक है इन को। अच्छा है कोई बुरी बात नहीं है। मैंने सुना है कि औरतों का सब से अच्छा दोस्त आखिर हीरा ही हुआ करता है और उसके साथ साथ मुझे यह भी याद है...

Shri Hanumanthaiya: May I rise on a point of order? We have all got much respect for Dr. Lohia. Let us deal at the political level instead of going into all kinds of personal matters. That is my appeal to him.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप समझते हो कि यह पर्सनल है लेकिन यह पर्सनल बिलकुल नहीं है .....

Mr. Deputy-Speaker: I entirely endorse what he said just now, because it will bring down the dignity of this House ultimately if we indulge in personal recriminations.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह पर्सनल बिलकुल नहीं है । मैं कोई निजी बात नहीं कहता । उस का संबंध जब सार्वजनिक रूपये से होता है तब मैं कहता हूं वरना कुछ नहीं कहता । निजी बात मैं बिलकुल नहीं कहा करता, अपनी जिंदगी में कही नहीं है वरना न जाने यहां क्या क्या बातें कही जा सकती हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा सार्वजनिक बात को ही यहां चर्चा करता हूं । नेपाल के राणा पदम शमशेर की हीरों की डलिया का क्या हुआ ? और वह सऊदी अरेबिया के हार का मैंने सुना कि रिजर्व बैंक ने उसे 10,000 या 40,000 में नीलाम किया । क्या वह तेलका (?) का महाराणा इतना कंजूस था कि 10,000 का हार देकर चला गया ? यह अजीब हालत हो रही है । लोगों को बोलते वक्त याद रखना चाहिए कि वह किस के बारे में बोल रहें हैं ? मैं चाहता हूं कि इस सदन की एक जांच बिठायी जाय जो मेरी भी हर एक सम्पत्ति की पूरे तरीके से जांच कर ले अगर कहीं निकले और इस तरीके से प्रधान मंत्री की भी सब सम्पत्ति की जांच की जाय तब पता चलेगा कि यह पिछले बीस वर्ष समाजवाद के वर्ष रहे हैं या यह पिछले 20 वर्ष लूटो, खाओ और यह अर्थ-व्यवस्था को विकासोन्मुख न बना कर बिलकुल पतनोन्मुख ले चले । इस के पीछे है यह सारा मामला । आप जान रहे हैं कि किस हद तक इस कांग्रेस संगठन ने जो किसी समय आजादी और एकता का संगठन था किस हद तक इस ने विघटन से खेलना शुरू कर दिया है ?

मीजो और नागा आप सुन चुके हो अब मैं आप से खासी उस इलाके की बात कहता हूं जो असम के बिलकुल हृदय में है, खासी जयन्तिया, वहां पर भी पूर्ण स्वतंत्रता का आन्दोलन छिड़ चुका है और एक बड़ा लड़का, लड़का कहूं या 27–28 वर्ष का युवक जिसका नाम बड़ा विचित्र है । उस का नाम स्टालिन कैसे पड़ा ? वह स्टालिन राजी अगस्त सन 1966 से जेल में है । वह आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा है । मैं नहीं बतलाऊंगा कि उस के रिश्तेदार कौन हैं ? ऐसे भी रिश्तेदार हैं जो इस सरकार के इर्दगिर्द रहते हैं और वह पाकिस्तान में लालडेंगा से बातचीत कर चुके हैं । उस तरीके से गारो पहाड़ियों में कप्तान संगमा अपने डेढ़ सौ आदमियों को पाकिस्तान भेज चुका था । मामला बहुत ज्यादा बढ़ रहा था लेकिन अभी मालूम होता है कि अन्दर अन्दर कुछ उस को वचन दे दिया गया है इस लिए कुछ स्थिर है तो यह गारो, मीजो, खासी जयन्तिया नागा हिल्स, यह जितने इलाके हैं यह टूट रहे हैं । यह क्यों टूट रहे हैं ? ऐसा इस लिए है क्योंकि यह सरकार असम में अपने वोट को सुरक्षित रखना चाहती है । असम की गद्दी पर बैठे रहने के लिए और अपने वोट को सुरक्षित रखने के लिए यह हर तरीके का काम करने के लिए तैयार है । जरूरत जहां होती है सख्ती की वहां नरमी बर्तती है और जहां जरूरत होती नरमी की वहां सख्ती बर्तती है । इस का सारा मामला उलटा पड़ा हुआ है और न सिर्फ असम में बल्कि देश के और हिस्सों में आप ने देखा होगा कि किस तरीके से यह शिव सेना गैरह बनाते हैं चुनाव जीतने के लिए । लड़ाओ, वोट लेना है ।

Shri Chintamani Panigrahi: What about the RSS?

डा० राम मनोहर लोहिया : अरे आर० एस० एस० का नाम क्यों लेते हो मेरी पार्टी का नाम ले लेते तो मैं मान जाता । यही तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सारे देश की सड़ांध, सारे देश का विघटन उस की बुनियादी और केन्द्र आप कांग्रेस वाले हो और वह छूत हम पर भी लगती है और हम भी आप की नकल करने लग जाते हैं । इसलिये जरा इस

तरीके से आप बात मत करो, कुछ देखने की कोशिश करो . . . (व्यवधान)

Shri Randhir Singh: Why do you say baseless things? It is unbecoming of a leader like you. You should not go down so low.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सब देखा है। आप ने एलैक्शन में क्या किया ? आप गोली चलवा कर आये हैं . (व्यवधान)

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, वोट लेने के लिए ये लोग कहां तक जा सकते हैं ? अभी उन्होंने गरीब उड़िया और तेलगू का झगड़ा मचा डाला था। तेलगू के एक कांग्रेसी ने उड़िया लोगों के बारे में कुछ गंदी बातें लिखीं और फिर उड़िया के कांग्रेसियों ने उस का इस ढंग से जवाब देना शुरू किया कि जिसमें झगड़ा खड़ा हो जाये। केन्द्र की जो कांग्रेसी सरकार है वह इस तरह की अनुचित हरकतें वोट हासिल करने और पावर में रहने के लिए करने से नहीं चूकती। हमारी राजनीति इस तरीके की हो गयी है कि उस में सड़ांध मौजूद है . . . (व्यवधान)

Shri Chintamani Panigrahi (Bhubaneswar): It is completely wrong. The Swatantra people are doing it.

डा० राम मनोहर लोहिया : ठीक है सब कर रहे हैं। स्वतंत्र वाले कर रहे हैं, ठीक है आप ने जो यह कहा लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि स्वतंत्र वाले कर रहे हैं मैं तो कहता हूं कि हिन्दुस्तान की राजनीति सड़ गई है। वोट लेने के लिए हर पार्टी गंदी बन गयी है लेकिन क्या इस गंदगी में केन्द्र की कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी पीछे है ? मेरा कहना है कि जब तक यह गन्दगी केन्द्र से खत्म नहीं होगी तब तक स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ या संसोपा कोई भी पार्टी अच्छी नहीं हो पायेगी। इसलिए उस केन्द्र को खत्म करने की जरूरत पड़ गयी है।

उसी तरीके से मैंने आपको केन्द्रीय नौकरों और प्रदेशीय नौकरों के झगड़े को बताया है। इस के अन्दर कैसे चलता है। जहां मौका पाते हैं उभारते है। मालूम होता है कि अंग्रेजों से इन्होंने और कोई चीज सीखी हो या न सीखी हो लेकिन एक चीज अवश्य सीखी है कि लोगों को आपस में लड़ाओ और अपना उल्लू सीधा करो। आजकल के जमाने में उल्लू सीधा करने का मतलब है वोट पाओ और राज्य चलाओ। ऐसी चीज चल पड़ी है। आजकल आंख में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है।

एकाधिपत्य की समाप्ति की चर्चा बड़ी चल पड़ी है। मुझे अफसोस होता है कि कैसे लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं ? अमरीका में जितना ऐंटी ट्रस्ट आन्दोलन हो चुका है क्या दुनिया में कहीं और हुआ है ? वह लगातार 20 वर्ष तक हुआ था। आप जानते हैं कि वह किस बात पर हुआ था ? रौकफिलर नाम की एक बड़ी कम्पनी वाले हैं। एकाधिपत्य के खिलाफ कानून पास कर दिया गया तो देखा गया कि उधर स्टैन्डर्ड आयल कम्पनी आफ न्यु जर्सी और कालटैक्स आदि बन जाती हैं और भी न जाने कौन कौन सी कम्पनियां बन जाती हैं। इस तरह से पांच, पांच और 6, 6 कम्पनियां में बंट जाते हैं। रौकफिलर पहले जितने अमीर थे उससे ज्यादा अमीर बने रहते हैं। इन अमीरों से आप ऐसे पार नहीं पाओगे कि एक कानून उन के लिए बना दिया गया है और आप का मकसद पूरा हो गया। वह अपने को कई कम्पनियों में तोड़ देगें और इस तरह से अपनी मोनोपली बढ़ाते चले जायेंगे। बिड़ला साहबों में से अगर कोई साहब मुझ को सुनता होता तो उन से जरूर मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं ने सुना है कि उन्होंने वर्तमान प्रधान मंत्री को जिताने में मदद पहुंचायी थी। अब जरा उन को सोचना चाहिये कि हिन्दुस्तान के पूंजीपति पैसा कमाने में बड़े चतुर मालूम होते हैं लेकिन उन की राजकीय सूझबूझ बड़ी नादान है। नहीं तो

[डा राम मनोहर लोहिया]

यह समझ पाते कि यह छल की रानी किस तरह से बड़े पूंजीपतियों को आपस में लड़ा कर अपना उल्लू सीधा कर सकती है। अगर कोई बिड़ला इस बात को समझ जाये तो जरा मामला आगे बढ़े। रौकफेलर की बात मैंने आप से कही।

एक चीज मैं आप से कहना भूला जा रहा था, जब मैंने आप से अमरीका और अमरीकी सहायता की चर्चा की थी, कि यह अमरीका वाले कभी कभी कितने गन्दे हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक अतिथि आया। उस का नाम है प्रो० सडनी हिलमैन। वह कैनेडो साहब के जमाने में दक्षिण एशिया का और एसि-याई मामलों का सचिव था और जिस वक्त चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया वह यहां पर शायद ऐवेरेल हैरिमेन या किसी मिशन में आया था। तब उस ने उस वक्त के प्रधान मंत्री से कहा था कि देखो तुम पाकिस्तान से समझौता कर लो, तब जा कर चीन से अच्छी तरह मुकाबला कर पाओगे। तब, उस प्रोफेसर ने मुझे बताया कि हैरिमेन साहब ने कहा था कि मालूम होता है तुम लोग कुछ बूढ़े हो गये हो, कुछ थक गये हो, एक नई बात करते हुए डरते हो, इसलिये यह चीज कर नहीं पाये। मैंने कहा : देखो प्रोफेसर, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बात यदि रखना कि अमरीका वालों के पास धन बहुत है। और बम बहुत है। जिन के पास धन और बम ज्यादा होते हैं, बुद्धि उन की कुछ स्थूल हो जाया करती है। नतीजा यह हुआ कि जब वह मिशन यहां आया था तब उस ने भारत सरकार से क्या कहा कि काश्मीर के ऊपर समझौता करलो। अगर कहीं अमरीका को यह अक्ल आई होती और कहते कि भारत और पाकिस्तान का जो बटवारा 1947-48 में हुआ था उसको खत्म करते हुए कोई ऐसा समझौता कर लो जिस में काश्मीर का समझौता अपने आप हो जाये, तो बड़ा मजा आया होता। प्रोफेसर कहने लगा कि शायद तुम सही कह रहे हो? शायद मुझे खश करने के लिये कहा हो या उसके दिमाग में यह बात आई हो।

यह लोग कैसे होते हैं इसके संबंध में मेरे पास प्रवाशचन्द्र लहड़ी की लिखी हुई एक किताब है पूर्वी पाकिस्तान के संबंध में, उसके एक दो वाक्य पढ़कर सुनाता हूं। पूर्वी पाकिस्तान में 1954 के साधारण चुनाव में मुस्लिम लीग खत्म हो गई। शायद संसार में यह सब से अद्भुत चुनाव था क्योंकि सरकारी पार्टी जिसके पुराने सदन में 310 आदमी थे, उसके केवल नौ रह गये। 310 से 9। यह याद रखना कि कब हुआ है। 1954 में। कहां? पूर्वी पाकिस्तान में।—तो डांडेकर साहब यहां कब हो रहा है?—खैर यह हुआ वहां कि 310 से 9 रह गये। जब यह हुआ तब तमाम चीजें बदल गई। एक तो यह कि पूरा पाकिस्तान का आधार टूटने लगा, हिन्दू मुसलमान के बीच में जो घृणा थी वह खत्म होने लग गई, और लोगों को डर लगने लग गया कि पूर्वी पाकिस्तान शायद पाश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो जाये उसके बाद—मुझे कहते हुये बुरा लगता है—उपाध्यक्ष जो पूर्वी पाकिस्तान असेम्बली के थे उन को मार डाला। उस से मौका मिल गया अय्यूब खां साहब को, जो उस वक्त पलटन के अफसर थे और बाद में प्रजिडेंट अथवा राष्ट्रपति बने। उस में कहा गया है पेन्टागान को, यानी अमरीका के रक्षा विभाग को—मुझे लगता है कि शायद सी० आई० ए० वगैरहा की जो बात चलती है वह भी उसमें रही हो—उनकी बुद्धि बडी स्थूल है। यह लोग उस मां की तरह हैं, रूसी और अमरीकी दोनों,—मैं सिर्फ अमरीका के लिये नहीं कह रहा हूं—जो अपने घर का काम काज करती रहती है, लेकिन जिसके कान खड़े रहते हैं कि कब कहां कौन बच्चा किसी चीज को गिरा

कर तोड़ रहा है, और आवाज होते ही वह दौड़ पड़ता है। इसी तरह से रूसी और अमरीकी आम तौर से अमरीका का जो पेन्टागान है या जो सी० आइ० ए० है उसको, जहां कोई खटका होता है, वह दौड़ पड़ते हैं। जब पाकिस्तान में बढ़िया सी चीजें हो रहीं थीं, वहां जितनी घृणा हिन्दू से हो रही थी, उतनी ही मुसलमान से हो रही थी, बटवारे का पाप शायद खत्म होने वाला था, लेकिन वैसे मौके पर इन लोगों को खटका हो गया, उन अमरीकियों को जो कि विदेशी सहायता देते हैं और क्या सहायता देते हैं--शौकीनी की--क्यों कि अमरीका की सुरक्षा एक तरफ तो है उसके बम में और दूसरी तरफ है ऐसे लोगों में अफ्रीका और एशिया के जिनका महीने का खर्च एक हजार रुपये से ज्यादा है--और मैं यहां रूस के लिये भी कहना चाहता हूं, रूस और अमरीका दोनों--जिसमें हिन्दुस्तान की जनता गरीबी का दलदल बना रह जाये, 49 करोड़ आदमी गरीब बने रहें लेकिन 50 लाख या 1 करोड़ लोग, एक हजार रुपया महीना खर्च करने वाले, उनकी सुरक्षा के लिये यहां तैयार हो जायें। इस बारे में रूस और अमरीका में कोई मत भेद और कोई अन्तर नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिये उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में क्या काम कर दिखलाया?

अगर इस बजट में कोई दम है तो विदेशी सहायता को एक दम ठुकराया जाये। अब इस में कुछ नहीं रह गया है। उसने हमारे पूरे दिमाग को बिगाड़ दिया है। कितना दिमाग बिगाड़ा है इसका दिन रात परिचय मुझे यहां विरोधी पक्ष में मिलता रहता है। कोई फर्क नहीं बुनियादी बातों में। अभी कल की बात मैं कहूं। नीति बिल्कुल एक थी श्री अटल विहारी वाजपेयी की, श्री डांगे की और श्री राममूर्ति की। कोई नहीं कह रहा था कि सिपाही भेजो अरबिस्तान में जाकर लड़ाई लड़ने के लिये। लेकिन सांसें इतनी गरम हो रही थी। उसका कारण यह है कि हम लोग विदेशी सहायता पाते पाते अपने दिमागों को भी खराब कर बैठे हैं। अगर दिमाग ठीक तरह से सोचना शुरू करे तो मुमकिन है कि हम समझें कि भारत में आज जरूरत है उस श्रम की जिसकी चर्चा हनुमन्तैया साहब ने की। वह चले गये। वह कह रहे थे कि श्रम चाहिये हम को।

मैं कोई बढ़ा कर नहीं कह रहा हूं। अगर सरकार मेरे कहने पर चले तो जो आज 350 रु० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की आय है वह पांच वर्ष के अन्दर 1,000 रु० हो सकती है। बहुत से लोग सुनकर घबरा जायेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। सोचेंगे कि यह पागलपन की बात कह रहा है। बिल्कुल पागलपन की बात है क्योंकि वहां बैठकर गिरजा शंकर वाजपेयी की औलादों से मैं भी अपना बजट नहीं बनवाता। नौकरशाही के पंजे में हम आज इतने फंस गये हैं। नौकरशाही के भी दो अंग हैं। जो जवान नौकरशाह हैं, मैं उन से एक अपील करूंगा कि घबराओ मत। अपने कर्त्तव्य को करते रहो। कल वक्त आ रहा जब इन पुराने नौकरशाहों से इस देश को छुटकारा दिलाया जायेगा, जबकि पुरानी लकीरों से, जिस में लोग फंस चुके हैं, हट कर हम अपने देश का पुनर्निर्माण कर सकेंगे।

आज हमको ताना मारा जाता है कि तुम्हारी गैर-कांग्रेसी सरकारें क्या कर रही हैं? मुझ से ज्यादा गैर-कांग्रेसी सरकारों की टीका कौन करता है जब वह बुरे रास्ते पर जाती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई कोई काम गैर-कांग्रेसी सरकारें ऐसे कर रहीं हैं जिनका यह कांग्रेसी सरकारें ख्वाब भी नहीं देख सकती थीं। उड़ीसा सरकार ने मालगुजारी खत्म कर दी है। बिहार सरकार ने न सिर्फ अंग्रेजी फेल विद्यार्थियों को पास कर दिया है बल्कि दफा 109 जिसमें कि हिन्दुस्तान के कैदियों में से

[डा० राम मनोहर लोहिया]

पांचवां हिस्सा जेलों में रखा जाता है और साहूकार लोगों को चोर बनाने का जो साधन है, उसको भी मुल्तवी रखा है। और भी छोटे छोट तफसील के काम प्रशासन के हुये हैं, जैसे ससराम में 17,000 रु० टैक्स पर जो बाजार नगरपालिका ने ठकेदार को दिया हुआ था उसको 1 लाख रु० में बदल दिया है। अगर एक ऐसा काम आप रोज करते रहें, जैसे कि ब्वाय स्काउट्स के लिये कहा गया है: **वन गुड टर्न ऐ डे** तो काफी काम हो सकता है। मैं इन गैर-कांग्रेसी मंत्रियों से कहूंगा कि एक अच्छा काम रोज करो। बड़ा काम न सही तो कम से कम प्रशासन की जो तफसीलें हैं, जिन में रुपया बरबाद होता है, या जिस में अन्याय होता है, उसको देखें। जैसे कि बिड़ला के मिर्जापुर के कारखाने में 70–80 आदमी बिल्कुल अन्यायपूर्ण ढंग से निकाले गये। उन में से 45 को वापस ले लिया है, लेकिन मैं इतने से ही खुश नहीं हूं। बाकी 25 को भी काम पर वापस जाना चाहिये। एक अच्छा काम रोज करो लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं, कोई खुश नहीं होगा। देश भी खुश नहीं हो सकता है। एक जो अंधेरा बीस बरस का रहा हो, आप क्या यह समझते हैं कि उजाला ऐसे ही आ जाएगा? उजाले में देर लगेगी। अंधेरे और उजाले में बड़ी देर तक अभी आंख मिचौनी चलेगी। मैंने चाहा था कि वह आंख मिचौनी जल्दी खत्म हो जाए लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। हो सकता है कि जल्दी कोई ऐसा वक्त आ जाए कि मेरे जैसे आदमी के भाषण का विपक्षी दलों पर कोई असर पड़े और यह एक गारंटी आप दें कि अगर उधर से तीस आदमी आ गए तो हम लोग मिल कर एक सरकार बनाने को तैयार हैं तो यह आंख मिचौनी जल्दी खत्म हो सकती है—(इंटरप्शंज) अभी तो वे आए नहीं हैं और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया है और अगर आ जायेंगे तो फिर पता नहीं बेचारों को क्या हो जाएगा तीस की गारंटी मुझे मिल चुकी है। लेकिन आप लोग गारंटी नहीं दे रहे हैं

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member is supposed to address the Chair. This is not a public platform.

डा० राम मनोहर लोहिया: मैं तो उस तरफ देखता ही नहीं। मोरारजी भाई को नहीं देखता हूं तो इनको क्या देखूंगा। मैं तो सिर्फ आपको देख कर बोल रहा हूं। उधर हाथ चला जाता होगा तो बात अलग है।

मैं जरूर चाहता हूं कि एक कोई बड़ा काम गैर कांग्रेसी सरकार जरूर रोज करें। छोटे मोटे काम तो करती रहें लेकिन एक अच्छा काम रोज किया करें ताकि लोगों की भूख जो लोगों में बदलाव की भूख जगे। बीस बरस में लकीर के फकीर हम लोग बन गए है। एक गड्ढे में सड़ते चले जा रहे हैं। आप जानते ही हैं वह कहावत वाला कबीर दास का किस्सा। फंस गए हैं बिल्कुल लकीर में। उससे हट कर एक रास्ते से हट कर कोई एक बड़ा काम करें और बड़ा काम करने की भूख को इतना ज्यादा जगा दें ताकि देश में भारतीय जनता की भूख इतनी जबरदस्त हो जाए कि अगर मान लो यह सदन अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते तो जनता उस कर्तव्य को पूरा जल्दी से जल्दी कर दे। बस इसी कामना को ले कर मैं अपनी बात खतम करता हूं

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़): मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि बराबर आप मुझे बोलने का तब मौका देते हैं जब मेरे बुजुर्ग डा० लोहिया साहब बोल लेते हैं.

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी): यह आप अन्याय कर रही हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं न्याय कर रही।

श्री राम सेवक यादव: बुजुर्ग कह कर।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: वह बुजुर्ग इसका मैं उनको एहसास करा रही हूं।

वह कभी-कभी इस बात को भूल जाते हैं।

यों डा० सहाब के जीवन से हम परिचित हैं, अन्दर से भी और बाहर से भी। हम लोग बच्चे थे जब वह कांग्रेस में थे और एक बड़े नेता के रूप में हम लोगों ने बचपन से ही उनके बारे में एक धारणा बनाई थी। परिस्थितिवश वह हम से अलग हो गए। उसके बाद से हमने उनको दूर से ही देखा। दिल्ली में वह रहते हैं, लेकिन बहुत नजदीक से हम फिर भी उनको देख नहीं पाते हैं चूंकि अन्दर जाना जरा मुश्किल है। बाहर से ही देखते हैं। उनकी बात को हम अकसर सुनते हैं यहां भी और बाहर भी। उन में बड़े गुण हैं। अच्छे सिद्धान्तों को ले कर वह चले हैं और सिद्धान्तों को ले कर चलने के वह आदी रहे हैं। इस में कोई शक की बात नहीं और इस में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं हैं। जब कभी कोई सैद्धान्तिक प्रश्न उत्पन्न होता है तो डाक्टर साहब की ही यह हिम्मत है कि अकेले भी रहें तो भी सिद्धान्तों को ही ले कर चलते हैं......... (इंटरप्शंज) डा० साहब का बजट बनाने का मुझे मौका मिले तो मैं तो बहुत अच्छा बना सकती हूं। मौका मिलना भी तो चाहिये। हम लोगों को जरा अपने नजदीक आने का मौका दें तो गलतफहमी भी कम हो सकती है।

जहां तक सिद्धान्तों का प्रश्न है, उसूलों का प्रश्न है, वह उन पर अडिग रहते हैं, इस में कोई सन्देह नहीं है। इस बारे में किसी को कोई शिकायत भी नहीं हो सकती है। आज इस भाषण में उन्होंने कुछ सिद्धान्तों की चर्चा की है। मैं नहीं समझती कि हाउस में कोई भी सदस्य उन सिद्धान्तों के प्रति कोई मतभेद रख सकता है। इसके लिए डा० साहब बधाई के पात्र हैं। वह एक सुधारक हैं लेकिन गांधी की तरह के सुधारक नहीं। गांधी जी अपने आसपास सब तरह के लोगों को रखा करते थे। अच्छे लोगों को भी और बुरे लोगों को भी रखा करते थे। उन्होंने बुरे लोगों को भी देखा और उनको अपनाया, उनमें कुछ अच्छाइयां भरने की कोशिश की। डा० साहब भी सुधारक हैं। पर अगर कहीं झाड़ू देने की जरूरत होती है, कूड़ा साफ करने की जरूरत होती है तो झाड़ू ले कर वह सारा कूड़ा अपने घर से निकाल कर पड़ोसी के घर में डाल देते हैं। मैं समझती हूं कि वह इस देश का बहुत बड़ा कल्याण कर सकते अगर अपने घर का कूड़ा और दूसरों के घर का कूड़ा उठा कर डस्टबिन में डाल दिया करें न कि दूसरों के घर के सामने . . . .

श्री अब्दुल ग़नी दार (गुड़गांव) : आप बेइंसाफी कर रही हैं उनके साथ....

(شری عبدل غنی ڈار- آپ بے انصافی کر رہی ہیں اِن کے ساتھ)

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : डा० साहब को मेरी बात पसन्द आ रही है आप क्यों ख्वामख्वाह कबाब में हड्डी बन जाते हैं ?

डा० साहब जब भाषण कर रहे थे तो मैं उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उनका भाषण आज बहुत ऊंचे स्तर का था। हम सब बड़े ध्यान से उनकी बात को सुनते हैं, सारा मुल्क उनकी बात को ध्यान से सुनता है। उनकी बहुत बड़ी देन है इस मुल्क के प्रति और हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अपना सब कुछ मुल्क को दिया है और आज भी दे रहे हैं। परन्तु डा० साहब को यह शोभा नहीं देता है कि व्यक्तिगत बातों की तरफ वह इतना ज्यादा इशारा करें। उनके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के लिये यह शोभा की बात नहीं है, इसको ले कर उनके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की कुछ आलोचना होती है और यह मैं उनको एक साथी की हैसीयत से, एक बहन की हैसीयत से कह रही हूं। इससे हम को

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

भी तकलीफ होती है । वह शायद इस बात को नहीं जानते हैं कि मुंह पर तो शायद बहुत से लोग उनकी प्रशंसा करते होंगे लेकिन उनके अलावा और भी लोग हैं, हम जैसे भी लोग हैं जोकि उनके गुणों को एक तराजू पर तोलते हैं । इसलिए मैं उन से अपील करूंगी कि अगर ऐसी बातों की चर्चा वह कम किया करें और जिन सिद्धान्तों को ले कर, जिन उसूलों को ले कर, वह आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की चर्चा ज्यादा किया करें, उन्हीं उसूलों को ले कर आगे बढ़ा करें तो हमारा और उनका, दोनों का कल्याण होगा । इससे देश का भी बहुत बड़ा कल्याण वह करेंगे ।

एक बात के ऊपर मैं उनके नेतृत्व को मानती हूं । हिन्दी के बारे में, प्रान्तीय भाषाओं के बारे में, रिजनल भाषाओं के बारे में, जो उसूल उन्होंने रखे हैं, रिजनल भाषाओं को आगे ला कर, अंग्रेजी को जो वह हटाना चाहते हैं, उसका हम दिल से समर्थन करते हैं । इसके लिये हम उनकी प्रशंसा करते हैं । यहां भी करते हैं और बाहर भी करते हैं । इसलिये मैं डा० साहब से अपील करना चाहती हूं कि उनके जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं । मैं एक शेर भी उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहती हूं । प्रजातंत्र में हम लोग रह रहे हैं । राजनीति में हम लोग भी आए हैं और आप लोग भी आए हैं । किसी का कुछ किसी दूसरे से छिपा हुआ नहीं है । जो उधर होता है उसकी जानकारी हमें होती है और जो हमारी तरफ होता है उसकी जानकारी उनको होती है । अगर हम इस तरह से खुल कर इलजाम लगाना शुरू कर देंगे, छिछालेदर करना शुरू कर देंगे तो यह एक विराट रूप हो जायगा । इस वास्ते ऐसी बातों के बारे में जबान और आंख बन्द रखें तभी अच्छा होगा, अगर हम लोग एक दूसरे के बारे में कहना शुरू कर देंगे तो इसका कोई अन्त नहीं होगा । इसी बात को मैं एक शेर के रूप में डा० साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहती हूं :

गो शेफ्ता की धूम थी जाहिद के जो हद की,
अब क्या कहूं कि वे मुझे किस के घर मिले ।

मेरा ऐसा खयाल है कि हम लोगों की बात का भी डा० साहब पर कभी-कभी असर होता है । अपने आज के भाषण में उन्होंने बड़ा सन्तुलन रखा है । लेकिन न जाने हीरे के नैकलेस, औरतों की गर्दन, औरतों की चाह और न चाह, ये बीच में कहां से ले आए अगर इनको वह न लाते तो आज वाकई उनका भाषण एक बड़े ऊंचे स्तर का होता । मैं उन से अपील करती हूं, प्रार्थना करती हूं, कि इन बातों की तरफ कम तवज्जह दें और जो बुनियादी चीजें हैं, जो इस वक्त इस मुल्क में हो रही हैं, उनकी तरफ ज्यादा तवज्जह दें तो अच्छा होगा । इन्हीं बातों पर ध्यान हमें इस बजट की बहस में भी देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, उसके बारे में जो कुछ लिखा या सुना गया है, उस में टैक्स की तरफ़ ही ज्यादा ध्यान दिया गया है, परन्तु जो बुनियाद है इस बजट की, जिस के कारण यह बजट इस रूप में आया है, उसकी तरफ़ लोगों की तवज्जह नहीं गई है । आज का बजट सिर्फ टैक्स लगाने का एक माध्यम नहीं है । आज बजट कुछ ऐतिहासिक तत्वों से प्रभावित होता है, कुछ वर्तमान से गठित होता है और कुछ भविष्य की तरफ़ निदेश करता है । जब सरकार और उस का शासन सिर्फ प्रशासन चलाने के लिये हुआ करता था, तब बजट एक प्रशासन के बजट के रूप में आया करता था । परन्तु अब कोई भी बजट देश को सम्पन्न बनाने में मदद करने वाला बजट होना चाहिये, देश की बुनियादी दिक्कतों को दूर करने वाला बजट होना चाहिये और इसलिये बजट का दायरा और बजट पेश करने का दायरा

भी बहुत बढ़ गया है । हमें देखना चाहिये कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट को इस आकार में रखा है या नहीं जिससे कि हमारी इन समस्याओं का समाधान मिलता हो ।

मैं पहले भूत की—भूत-प्रेत की नहीं—पिछले दिनों की—बात करना चाहती हूं । हमारे देश में दो साल सुखाड़ हुआ और डीवैल्यूएशन हुआ । विरोधी दल के सदस्यों को मालूम है कि हम लोगों ने भी डीवैल्यूएशन का विरोध किया । और अब वह बात साबित भी हो गई है । इस में कोई शक नहीं है कि उस से आर्थिक जगत में जो प्रवंचना, असंतोष और विघटन पैदा हुआ, वे सब आर्थिक विषमता को बढ़ाने का कारण रहा । परन्तु सुखाड़ किसी के हाथ की बात नहीं है । दो सालों में बहुत बड़े पैमाने पर सुखाड़ हुआ । यह भी नहीं चाहती हूं कि हम सारा दोष सुखाड़ या डीवैल्यूएशन पर मढ़ दें । मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि जो समस्या कुछ सुधरी हुई या कुछ हल्की जान पड़ती, वह सुखाड़ और डीवैल्यूएशन की वजह से बड़ी जटिल हो गई है ।

सच पूछिए तो डीवैल्यूएशन कोई कारण नहीं है, बल्कि एक अभिशाप है, नतीजा है चन्द आर्थिक कारणों का । क्या हुआ है हमारे इस देश में ? उपाध्यक्ष महोदय, आप तो आंकड़ों की बड़ी जानकारी रखते हैं । आप को याद होगा कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ने लगा था और औद्योगिक विकास करीब करीब 161 प्रतिशत हो गया था । उस समय इसी पार्लियामेंट में इस की बड़ी सराहना की गई थी और बहुत कम ऐसे लोग थे, जो इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करते थे कि अगर औद्योगिक विकास को इसी प्रकार बढ़ने दिया गया और अगर उस के अनुपात से पावर, आवागमन के साधन, खेती की उपज और खेती के प्रसाधन नहीं बढ़ते हैं, तो जो योजना एक शृंखला के समान है, अगर उसकी एक भी कड़ी भंग हो जाती है, तो सारी शृंखला शिथिल और कमजोर हो जायेगी । इस में कोई शक नहीं है—मैं इस आलोचना को मानती हूं—कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना में हमें इस बात को देखना चाहिये था कि हमारे आर्थिक विकास के क्षेत्र में जो एक तरह का इम्बैलेंस पैदा हो गया है, उस को हम कैसे दूर करें ।

परन्तु आज मसानी साहब के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है । जो उन के साथी हैं, जिन के बारे में वह यहां बातें रखते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या उस जमाने में उन्होंने उन लोगों का, उन उद्योग-पतियों और उत्पादनकर्ताओं का जिनके उद्योगों का वह हवाला देते हैं, ध्यान इस बात की तरफ दिलाया था कि यह जो विषमता पैदा हो रही है, जिस को इकनामिक इम्बैलन्स कहा जाता है, उस को कैसे दूर किया जाये या औद्योगिक विकास की रोक-थाम की जाये, जिस से वह विकास भी बाकी विकास के क्रम में चल सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप आर्थिक विषयों के बड़े पंडित हैं, विशेषज्ञ हैं । आप जानते हैं कि हमारे देश में जो आर्थिक विषमता पैदा हुई है, उस का सब से बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां कोई अनुशासित अर्थ-व्यवस्था नहीं है, हमारी अर्थ-व्यवस्था में अनुशासन, कानोमिक डिसिप्लन बहुत कम है और इकानोमिक सैक्टर्ज बहुत डिस-आर्गनाइज्ड हैं । हमारी आर्थिक स्थिति इतनी पिछड़ी हुई है कि यह स्थिति उत्पन्न होना अनिवार्य सा ही है ।

मैं आप को एक उदाहरण देना चाहती हूं । हम औद्योगिक विकास करना चाहते हैं, लेकिन इस के बावजूद हम किसी फ़ैक्टरी या इंडस्ट्री या उद्योग को एक खास जगह पर नहीं रख सकते, क्योंकि आर्थिक विकास के साथ साथ हमें इस देश के हर एक तबके के विकास का भी, जिसे रिजनल डैवेलपमेंट कहा जाता है, उसका भी ख़याल रखना है ।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

मैं कहना चाहती हूं कि इस देश की व्यवस्था में शुरू से ही कुछ ऐसी बातें रही हैं कि जिन के कारण यहां की आर्थिक विषमतायें बढ़ती चली गई हैं। दुनियां की तरक्की जिस रफ़्तार से हो रही है, अगर हम उस रफ़्तार से अपने देश को मिलायें तो हम देखेंगे कि हमें अपने देश की समस्यायें अपने तराजू पर नहीं, बल्कि दुनियां के तराजू पर तोलनी हैं।

हमारा आयात और निर्यात का सामंजस्य करीब-करीब टूटने लगा है। पहली पंच-वर्षीय योजना में हमारे पास इतना बड़ा स्टर्लिंग बैलेंस था कि हम चाहे जो कुछ कर सकते थे और इसी लिए कोई आर्थिक विषमता पैदा नहीं हुई। परन्तु उस के बाद जैसे हमारा निर्यात एक ही स्तर पर रहा और आयात बढ़ता गया, तो ये विषमता बढ़ती गई। हम यह जानने की कोशिश करें कि आखिर हमारा निर्यात वहीं पर क्यों रह गया या क्यों घटा। डीवैल्यूएशन के बाद 130 मिलियन टन निर्यात घटा है। हम यह मानने से भी इन्कार नहीं कर सकते कि जिस पैमाने पर और देशों का निर्यात बढ़ा है, हमारा निर्यात उस पैमाने पर कभी नहीं बढ़ा। इस का कारण क्या है? माननीय सदस्य दुनियां के हर कोने में गए होंगे। हम देखते हैं कि दुनियां के और देशों में जो चीजें बनती हैं, उन के दामों से हमारी चीजों के दाम बहुत अधिक हैं, क्योंकि या तो उनके खर्च से हमारा खर्च बहुत अधिक है, या हमारा पर कैपिटा प्राडक्शन कम है, या हमारे पास पर्याप्त टैक्निकल नो-हाऊ नहीं है, या हमारे पास वे चीजें नहीं हैं, जिन की हमें जरूरत है। दुनियां की चीजों के मुकाबले में हमारी चीजें हल्की-फुल्की मालूम होती हैं। कारण जो भी हो, तथ्य यह है कि हम अपने निर्यात को एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से बढ़ाने में सफल नहीं हो पाए हैं।

पहले हमारा मुल्क जूते, कपड़ा, चाय, काफ़ी आदि सब चीजें बेचता था और दुनियां में हमारा कोई काम्पीटीटर नहीं था। हम वायर्ज मार्केट में काम करते थे, लेकिन विरासत में हमें इन्टरनेशनल सेलर्स मार्केट मिली, ऐसी मार्केट मिली, जहां बिक्री करने वालों की तादाद ज्यादा है और ख़रीदने वालों की तादाद कम है। इस लिए ख़रीदने वाले लोगों का नख़रा ज्यादा है और उस नख़रे और नाज़ो-अंदाज़ को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। परन्तु उस तरफ़ हमारी तवज्जह नहीं है।

हम राजनीतिक भाषण दिया करते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते कि जो बजट हमारे सामने रखा गया है, वह इस तरह से क्यों लाया गया है। इस की वजह यह है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था इन सभी विषमताओं और समस्याओं का शिकार हो गये है। अगर माननीय सदस्य इस के लिए किसी पार्टी को ख्वाह-म-ख्वाह दोष देने लगें, तो उस से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आखिर इस पार्टी को, कांग्रेस को, विरासत में क्या मिला?

कोई जर्मनी तो हम नहीं थे, जो हिटलर द्वारा छेड़ी गई लड़ाई में तबाह तो हो गया, लेकिन अपनी बुनियादी ताकत के कारण एक बार फिर नया देश बन गया और जो आज दुनिया का सबसे धनी देश है। हम जापान भी नहीं थे। हमारी आर्थिक व्यवस्था उतनी संगठित नहीं थी कि हम उस तरह से उन्नति कर सकते। हम को विरासत में मिली एक्सपोर्ट मार्केट दिन-प्रति-दिन कठिन होती गई और हमारी चीजों की बिक्री बहुत मुश्किल से होने लगी। इस लिए हमारी आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारा निर्यात या तो वहीं का वहीं रह गया है या गिरने लगा है।

इस बजट में एक और समस्या की तरफ भी ध्यान दिलाया गया है। हम इस बात

को कैसे भूल जायें कि हमारे देश की जमीन का रकबा दुनियां की जमीन के रकबे का 2.6 प्रतिशत है, जब कि हम को दुनिया की आबादी का 14.8 प्रतिशत हिस्सा मिल गया है ? चीन को छोड़ कर दुनिया में कोई ऐसा बदकिस्मत देश नहीं है और चीन से हमारा मुकाबला नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर अगर लाखों आदमी भी मर जायें, तो किसी को कोई परवाह नहीं है, जब कि हमारे यहां एक जान की भी बड़ी कीमत होती है ।

श्री राम सेवक यादव : अगर होती, तो अच्छा होता ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : फर्क इतना ही है कि माननीय सदस्य के कहने के लिए होती है और हमारे करने में होती है, लेकिन होती है । मुझे माननीय सदस्य को इस बात का अहसास कराने की जरूरत नहीं है कि जब हम यहां प्रजातंत्र में रहते हैं, तो हम सभी जान की कीमत समझते हैं । जब दुनिया की केवल दो या ढाई प्रतिशत जमीन हमारे पास है और दुनिया की करीब बत्तीस प्रतिशत आबादी यहां रहती है, तो आबादी और जो कुछ पूंजी हमारे पास है, उस में हमेशा कशमकश होती रहेगी । या तो हम आबादी को कम कर के अपने देश में इस विषमता में एक सामंजस्य पैदा करें । वर्ना इन विषमताओं का कोई अन्त नहीं होगा । इसलिए जरूरत तो इस बात की थी कि हमारे पास जो भी रीसोर्सिज हैं, जो भी हमारे पास पूंजी है, हम उस का आठ या दस गुना ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग करें । लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि ऐसा नहीं किया गया है ।

इंडियन कौंसिल आफ अप्लाइड एकोनामिक रिसर्च के कुछ आंकड़े मैंने पढ़े हैं । उसमें मुझे मालूम हुआ कि यहां पर इतना ज्यादा अंडर यूटिलाइजेशन आफ रिसोर्सेज होता है जिस का कोई हद हिसाब नहीं । इस देश में एक बड़ी विडम्बना है । एक तरफ हम गरीब हैं, दूसरी तरफ जो हमारे यहां पूंजी तैयार हो रही है, धरोहर तैयार हो रही है उस का या तो पूरा इस्तेमाल नहीं करते या जो इस्तेमाल करते हैं उस इस्तेमाल करने में जरूरत से ज्यादा पूंजी लगाते हैं। इस प्रकार जो आर्थिक विषमता जो आज है उस के लिए मैं इतना जरूर कहूंगी कि वित्त मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दें । मुझे बजट में इस बात का संकेत मिला है कि उन्होंने इस की तरफ इशारा किया है । मैंने इसीलिए एक वाक्य बजट के बारे में कहा था कि यह बजट सिर्फ कोरामिन की खुराक है । कोरामिन उस समय दी जाती है कि जब रोगी की घिग्घी बंध जाती है, या वह मरने को हो जाता है तो कोरामिन की खुराक देकर कुछ दिनों के लिए रोकथाम कर जिन्दा रखा जाता है उस का इलाज करने के लिए । इस बजट से लोग अगर यह समझते हैं कि इससे सभी इलाज हो सकता था तो मैं नहीं समझती कि वह सही तरीके से सोचते हैं । इलाज कैसे होगा ? जिस वित्त मंत्री को इतनी सारी समस्याओं का समाधान करना हो, उस के प्रति गुस्सा नहीं तरस आना चाहिए । यों तो श्री मोरारजी देसाई तरस के बहुत हकदार नहीं हैं और शायद उन को पसन्द भी नहीं आयेगा कि कोई उन पर तरस खाये लेकिन मैं मोरारजी देसाई के प्रति व्यक्तिगत तरीके से नहीं, उनके व्यक्तित्व पर तरस नहीं खा रही हूं, वित्त मंत्री महोदय के लिए कहती हूं कि वाकई गुस्सा आने के बजाये हमें उन पर तरस खाना चाहिए क्योंकि इतनी समस्याओं का समाधान करनेका काम आज उन के ऊपर आ पड़ा है. . .

श्री मधु लिमये : बड़ा बोझ ले लिया है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हां, सचमुच बड़ा बोझ ले लिया है, इस में कोई भी शक नहीं परन्तु अफसोस तो यही होता है कि बोझ का एहसास करने वाले लोग भी और ऊपर से

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

उस बोझ को बढ़ाने के लिए रुई के बारे मे पानी डाल दिया करते हैं . . . (व्यवधान) असल में एक का बोझ रहे तो लिया भी जा सकता है, कई लोगों का बोझ हो जाता है तो नहीं लिया जा सकता है । अकबर बीरबल की कहानी है, इसके बारें में मैं उस की चर्चा नहीं कर सकती अभी आप के सामने ।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं नान-यूटिलाइजेशन आफ रिसोर्सिज की बात कर रही हूं । अभी भी 60–62 प्रतिशत से ज्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होता । समाजवाद मे विश्वास करने वाली पार्टी के लिए यह कटाक्ष जब सुनना पड़ता है कि पब्लिक सेक्टर में कुछ नहीं किया है, तो हमें आखें नीची कर लेनी पड़ती हैं । क्यों ? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि आपके आंकड़ों के अनुसार पब्लिक सेक्टर का जो टोटल रिटर्न है वह 5 परसेंट है । यह ठीक है कि आप के कई पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स मुनाफा कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सबको लें क्योंकि आखिर घर और बजट एक से तो नहीं चलता है, सब को लेकर देखना पड़ता है तो टोटल रिटर्न जब पब्लिक सेक्टर का देखते हैं तो उसमें .5 परसेंट आता है । इस में कोई शक नहीं कि समाजवाद के ऊपर जब यह आघात होता है तो हम उस बहादुरी से इस आघात का मुकाबिला नहीं कर सकते जिस बहादुरी से उस का मुकाबिला करना चाहिए । वित्त मंत्री महोदय से मेरा यह कहना है कि आप इस की तरफ पूरी तवज्जह दें । अध्यक्ष महोदय, आप भी पार्लियामेंट मे इतने दिनों से हैं, आप को तजुर्बा शासन का भी है . . . (व्यवधान) . . इतना ज्यादा व्यय होता है, इतनी बरबादी होती है आप आदमियों को कम नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर आदमियों को . . . . (व्यवधान) . . . . दादा आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, जरा मुझे बोलने दें, मैं क्षमा चाहती हूं ।

आचार्य जे० भा० कृपालानी (गुना) : मैंने यह कहा कि यह मिनिस्टर तो रहे नहीं, शासन का तजुर्बा इन को कहां से हो गया?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: यह मैं मानती हूं ।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती थी कि यहां पर हर स्कीम लेबर इन्सेन्टिव स्कीम रहेगी । इस से हम इन्कार नहीं कर सकते । हमारे इस देश में आबादी की समस्या है । पन्द्रह परसेंट दुनिया की आबादी यहां इस देश में है । तो हम उस को अपने से हटाकार काम नहीं कर सकते । इसलिए हमेशा यह जो बात होती है कि आफिसर को या कर्मचारियों को हटाया जाय, इस से इस का निपटान हो जायगा, मैं समझती हूं इस से निपटान होने वाला नहीं है ।

इसलिए जहां हमें अपनी उंगली डालनी चाहिए, वह है हमारा इतना बड़ा परचेज सेक्शन है । मैं नहीं जानती अध्यक्ष महोदय, वित्त महोदय से मैं अपील करूंगी कि सरकारी खर्चा सिर्फ सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात मैं नहीं करती, पब्लिक सेक्टर, सिविल एक्सपेंडीचर, डिफेंस एक्सपेंडीचर इन सब के जरा आंकड़े बतायें कि कितना सरकार खरीद फरोख्त करती है । किसी ने कहा कि 40–45 प्रतिशत तक सरकार खरीद करती है । अगर 45 प्रतिशत या 50 प्रतिशत सामान की खरीद आप करते हैं तो मैं समझती हूं कि उस में एक सौ, डेढ़ सौ या दो सौ करोड़ रुपये की बचत करना आप के लिए जरा भी मुश्किल नहीं है, अगर आप तवज्जह दें उन चीजों की तरफ जहां कि खर्चे में बचत होनी चाहिए । मैं उदाहरण देती हूं । आप का इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट है । सारे अखबार वहां जाते हैं । परन्तु एक उदाहरण मैं देना चाहती हूं । अगर किसी मंत्री के यहां जा कर देखिए, मैं भी मंत्री थी, मेरे यहां भी आते थे, जितने दुनिया के अखबार हैं

सब वहां आते हैं। इतने पर भी इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट की कटिंग उनके यहां आती है। न जाने कितनी फुर्सत उन को रहती है अखबार पढ़ने की। अगर पढ़ना है तो बेशक मंगायें लेकिन इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट की कटिंग उनके पास भेजने की फिर क्या जरूरत है? यह मैं ने एक उदाहरण दिया। अगर इस तरह के हजारों उदाहरण देख एक एक विभाग के तह में जाने पर मिलेंगे। इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि तह में जाकर देखने की कोशिश करें कि कहां खर्चे में कटौती कर सकते हैं।

अब मैं पांडे रिपोर्ट की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहती हूं। अभी हाल ही में वह रिपोर्ट निकली है दुर्गापुर के बारे में। दुर्गापुर का जो हवाला पांडे रिपोर्ट में मिलता है जो कि हमारे सामने आया है, इस तरह हम पब्लिक सेक्टर को हमेशा ही से प्राणदान नहीं दे सकते। पब्लिक सेक्टर को बढ़ाना है तो हमें ऐसी चीजों को नहीं होने देना पड़ेगा। 50 करोड़ जनता को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि पब्लिक सेक्टर में न सिर्फ समाजवाद की पुष्टि होगी पर चूंकि यहां पर अधिकांश चीजें पब्लिक सेक्टर में ही महत्वपूर्ण ढंग से पैदा की जायेंगी, पब्लिक सेक्टर को हमें इस लायक बनाना होगा जिससे कि हम जो उस से उत्पादन करना चाहते हैं उस को हम अच्छी तरह से और सुघड़ तरीके से कर सकें।

इस के अलावा मैं यह कहना चाहती हूं कि यह एक मजाक कहने के लिये हो गया है कि मिनिस्टर साहब तो बाहर बोलते हैं अन्दर बोलते हैं, पालियामेंट के सदस्य अन्दर बोलते हैं, बाहर बोलते हैं। लेकिन अफसर भी बोलते हैं और वह सब से ज्यादा बोलते हैं, परन्तु वह फाइलों में बोलते हैं। अगर फाइल में वह बोलना कम कर दें तो बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो जाय। यह लालफीताशाही जो बढ़ गई है उस की वजह से हर बात में इतनी देर हो जाती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता यह एक परम्परा सी हो गई है, इसमें मैं किसी खास व्यक्ति को दोष नहीं दे सकती। हर बात में आज इतनी देर होती है, खुदा न ख्वास्ता, मुझे तो कोई बिजनेस करना ही नहीं पड़ा परन्तु आप की सारी मुसीबतों की जड़ जो है पैदा हो गई है वह इसीलिए पैदा हो गई कि हर काम में देर होती है, हर काम में पैरवी कोशिश की जरूरत पड़ती है बिना पैरवी के कोई काम होता ही नहीं। आम जिन्दगी का अन्जाम, जिन्दगी अहसास ही पैरवी हो गया है। पैदा होने के साथ ही पैरवी शुरू हो जाती है और सारी जिन्दगी ही पैरवी के ताने बाने में बुनकर ऐसी गड़ जाती है कि हम सांस नहीं ले सकते। देश की गाड़ी आगे तभी चल सकती है जबकि यह पैरवियां कम होंगी, देरी कम होगी।

अब मैं एक बात और कहना चाहती हूं। वह है ब्लैक मनी। उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हम जानते हैं कि काला रुपया पैरेलल करंसी हो गया है। एक रिजर्व बैंक ऊपर से है एक अन्दर से न जाने कितना इस प्रकार का रुपया है? कोई कहता है चार हजार करोड़ है, कोई कहता है पांच हजार करोड़ है, कोई दो जहजार करोड़, कोई तीन हजार करोड़ इस तरह करोड़ों का भाव चुटकियों में होता है। अध्यक्ष महोदय, किसी मुल्क में तीन हजार फी करोड़ पैरलल करंसी चलती हैं वहां क्या कभी आर्थिक विषमता दूर हो सकती है? कभी नहीं दूर हो सकती है? वित्त मंत्री महोदय ख्वाब देखेंगे अगर वह यह सोचेंगे कि तीन चार हजार करोड़ काला रुपया पैरलल करंसी के रूप में चलता रहेगा और चीजों की कीमतें कम हो जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, मुझ दो तीन मिनट और दे दें। तो पैरेलल करेंसी के बारे में मैं चाहती हूं कि प[illegible]मेंट में इतने लोग बैठे हैं। चाहे विर[illegible] के लोग हों चा इस तरफ के हों, मैं वित्त मंत्री महोदय से अपील करूंगी कि वह सबको बुलायें, विरोधी

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

दल के लोगों को बुलायें, सभी से बात करें कि क्या साल्यूशन है इसका, इसके लिये वह क्या करना चाहते हैं, सब लोगों की राय लेकर ब्लैक करेंसी के बारे में कार्यवाही करें। बेल्जियम ने अध्यक्ष महोदय, एक तरीका निकाला। मैं नहीं कह सकती कि हम उसको कर सकते हैं या नहीं। परन्तु बेल्जियम वालों ने एक नुस्खा निकाला। वह नुस्खा यह है कि फैक्ट्री और मकान जो इम्मोबाइल आबजक्टस हैं किसी कट्टी में, उन लोगों ने यह किया कि उन के इनकम टैक्स का रिटर्न उस तरह से नहीं लेंग जिस तरह से कि किसी और बारे में देखभाल या जांच पड़ताल के बुनियादी तरीके से करते हैं। जो इस तरह के इम्मोबाइल आबजेक्ट्स के माकि हैं, जैसे मकानात या और ऐसी चीजें हैं वह जो रिटर्न देंगे तो उसकी मान्यता को मानकर वित्त विभाग चलेगा। पता नहीं इस चीज को वह करेंगे, या नहीं पर मैं एक सुझाव रखना चाहती हूं, मैं नहीं जानती कि कहां तक यह हो सकता है पर मुझे यह तरीका देखने में काफी इन्टरेस्टिंग लगा कि उन्होंने यह किया कि इम्मोबाइल आबजेक्ट्स में ब्लैक मनी लग जाती है तो फिर सर्कुलेशन में वह रुपया नहीं आता है। इसलिये उस अनुपात में या उस परसेंटज में वह ब्लैक मनी कम हो जाती है और वह फिर बाजार में घूमती नहीं जो कि आज सारी मुसीबतों की जड़ है।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : वह तो रेकरिंग हो जाता है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : रेकरिंग हो जाता है, परन्तु व्हाइट-मनी के रूप में, फिर वह ब्लैक मनी के रूप में सर्कुलेट नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ आप इस से एक बहुत बड़ा काम कर लेंगे, हिन्दुस्तान में आज हाउसिंग की बहुत बड़ी प्राबलम है, इस तरह की बात डा० लोहिया को पसन्द नहीं आयेगी, लेकिन पिछवाड़े के दरवाजे से वित्त मंत्री हाउसिंग की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैंने यह एक सुझाव रखा है, मैं नहीं जानती कि कैसे इस को कर सकेंगे, यह सफल भी हो सकेगा या नहीं। परन्तु बेल्जियम की ब्लैक मनी की प्राबलम के बारे में मैंने एक किताब पढ़ी थी, जहां मुझे यह सुझाव दिया मिला और इस वजह से मेरी दिलचस्पी इस सुझाव की तरफ बढ़ी, जिसे मैंने इस समय वित्त मंत्री जी के सामने रख दिया है।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं—जहां तक टैक्स कलैक्शन का सवाल है, उस के बारे में भूथलिंगम कमेटी अपने कुछ सुझाव दे रही है। मैं भी इस के बारे में एक-दो सुझाव देना चाहती हूं। एक तो ट्रक आपरेटर्स और दूसरे जो कांट्रैक्ट लेते हैं, वे अच्छी तरह से टैक्स नहीं देते हैं और आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा शस्त्र या अस्त्र नहीं है जो इन कांट्रैक्टर्स या ट्रक आपरेटर्स से टैक्स वसूल कर सके, क्योंकि उन का रजिस्ट्रेशन कहीं होता है, और बिजनेस वे कहीं करते हैं। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि इन के टैक्स का डिडक्शन एट-सोर्स करना चाहिये। जिस तरह से कि सैलरिज से डिडक्शन, एट-सोर्स होता है, उसी तरह से उन का डिडक्शन भी एट-सोर्स होना चाहिये। ट्रक्स के बारे में आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है—इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट अथोरिटीज हैं, जो कि टैक्स-टोकन दिया करती है, उन के कानून में परिवर्तन किया जाय और वे अथोरिटी तब तक उन को टोकन न दें, जब तक कि वे अपना इन्कम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट न पेश करें। इस के लिए आपको कानून में परिवर्तन करना होगा। इन्कम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट देने के बाद ही उन को टैक्स टोकन मिले, यदि आपने ऐसा किया तो इस से आप को बहुत लाभ होगा।

आल इंडिया रेडियो का इस्तेमाल हम हर चीज के लिये करते हैं, परन्तु हमारे टैक्स

का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से टैक्स देना चाहिये, कैसे टैक्स का भुगतान किया जा सकता है, इन सब चीजों की जानकारी हर एक के लिये मुश्किल है। मैं वित्त मंत्रालय में वर्षों तक रही, लेकिन अपना टैक्स भरवाने के लिये मुझे वकील की शरण लेनी पड़ती थी। जैसे जैसे कानूनों की बाढ़ आती जाती है, वैसे वैसे वकीलों की भी बाढ़ आती जाती है। इस लिये मैं यह कहना चाहती हूं कि इस काम के लिए आल इंडिया रेडियो का इस्तेमाल होना चाहिये ताकि लोगों को बताया जा सके कि किस तरह से टैक्स अदा किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : डाक्टर साहब को तो सवा घन्टा मिला है.....

श्री मधु लिमये : वह तो हमारा समय था।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आपका समय थोड़ा हमें भी दे दीजिये, दो मिनट हम भी आपका समय ले लें।

श्री मधु लिमये : अगर कुछ बचा है तो इन्हें जरूर दिया जाय।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं चाहती हूं कि आल इंडिया रेडियो की तरफ से इस के बारे में पूरी जानकारी लोगों को कराई जाय। एक शेडयूल रख दिया जाय कि आधा घन्टा या 10 मिनट या 5 मिनट टैक्स के बारे में लोगों को जानकारी कराई जायगी कि कैसे टैक्स दिया जाता है।

पार्टनरशिप फर्म में आपने एलाऊ किया है कि अलग अलग पार्टनर्स को अपना अलग अलग टैक्स देना पड़ता है। पूरे पर अगर ज्यादा टैक्स पड़ता है, तो अलग अलग पार्टनर्स से अलग अलग टैक्स लेने में बहुत कम टैक्स मिल पाता है क्योंकि इस तरह से टैक्स डिवाइडेड हो जाता है। प्रपोर्शनेटली टैक्स का रेशियो कम हो जाता है, इस लिये यह फर्म की आमदनी के रेशियो के हिसाब से मिलना चाहिये।

Shri Piloo Mody (Godhra): What absolute nonsense!

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस तरह से यदि आप व्यवस्था करेंगे तो अधिक टैक्स मिल पायेगा।

एक सुझाव यह है कि टैक्स-इवेडर्स को डेटेरेन्ट पनिशमेन्ट मिलना चाहिये।

Shri Piloo Mody: Hang them, as you promised ten years ago.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अमरीका में डेटेरेन्ट पनिशमेंट देने की व्यवस्था है। परन्तु आपके यहां टैक्स इवेड करने वाला वर्षों मुकदमा लड़ता रहता है और उस का कुछ नहीं होता।

एक बात और कह देना चाहती हूं कि जहां तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है उस में आप डबल आडिटिंग सिस्टम शुरू कीजिये। आडिटर जेनरल तो जेनरल आडिटिंग करते ही हैं, लेकिन यदि आप उस में कामर्शल आडिट, और कास्ट-एकाउन्टिंग की व्यवस्था करायें तो बहुत बड़ी मात्रा में जो पब्लिक सेक्टर के दोष हैं, वे खत्म हो जायेंगे।

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Mr. Deputy-Speaker, Sir, some of the friends who have participated in this discussion have characterised this budget as anti-people budget and anti-socialist budget. I think those friends who ever thought that the Congress party or this Government would ever be able to give this country a budget which will in

[Shri Surendranth Dwivedy]

any way further the cause of socialism or the egalitarain society are even now roaming in a dreamland of their own. At the present moment, the country is passing through a great crisis and we are almost at the brink of economic disaster. Everything is stagnating; in whatever sphere you take, there is no progress at all. Therefore, even Mr. Masani who represents a particular school of opinion had to say that this was a status quo budget. He also feels that there should have been more dynamism and it should have been a revolutionary budget. He is only disappointed; he does not disagree with the assessment of the situation by the Finance Minister. He is only disappointed that he has not been able to produce a budget to which Mr. Masani would give whole hearted support. In the name of socialism this Government has created confusion in the minds of the people and has brought this country to disaster. You cannot expect anything better from this Government. There is no question of personality involved in this. I do not know whether Mr. Morarji-bhai claims himself to be a socialist or not, but he represents this Government.

15.48 hrs.

[SHRI G. S. DHILLON *in the Chair*]

If we take his statement which he made when he was out of office for about two years, he said that there was room for a cut of ten per cent in the expenditure on administration. I do not think he can, practise it. When he had the first opportunity to do so and when he became the Finance Minister and gave us a budget all that he now says is: am trying to persuade my own Ministry to have some cut in expenditure in my own Ministry; will try to influence others to do so. The entire economic policy of the Government is not for the people's benefit nor is it given a socialist reorientation but is only in order to stick to power somehow or other to produce a budget which will not create or tension in their own party. After fifteen years of planning and a Government policy for twenty years which they say they are sincerely following, what is the state of the economy in the country today?

What is the position today? In 1948-49, the per capita income was Rs. 249.6. In 1965-66, it is Rs. 298.3, that is, an increase of only of 19 per cent if 1948-49 is taken as 100. What are the changes after these three Plans? During the first Plan, it was 8.2 per cent. In the second Plan it was 9.5 per cent. In the third Plan it was 1.7 per cent. This is in regard to *per capita* income, the changes that have come into being after this planning.

Look at the agricultural production. I do not want to quote figures of previous years. In the year 1965-66, agricultural production has fallen to the tune of 17 per cent over the previous year. Then we find that there is a proportionate decline in rice, jute, tobacco, oilseeds, which are essential and on which very much depends our foreign exchange earning; the decline is from 15 to 20 per cent. About industrial production, it is better I do not quote figures; not only it is stagnating, but it is falling very sharply. In 1966-67, it is only 3.5 per cent. Therefore, the economy has been put in the neutral gear. Mr. Masani would like to take this economy towards the reverse gear, and there is a critical period—and he has his own remedies. He has suggested that the Government should do away with the Bokaro plant and cut defence expenditure. I found that the Swatantra and the left Communists are agreeing on one point at least: that is, cut down the defence expenditure, because Mr. Masani feels that by cutting down defence expenditure, we

will be depending on some other foreign country for all that we need, even for the growth of the economy of our country; and the other friends feel that if our defence is weakened, then it is possible for some other country who is always nibbling at our borders to occupy this country.

Mr. Masani at the same time spoke about planning. He has a right to criticise the way the planning has been implemented in this country. But he does not want planning at all, and we have really reached a stage when there is really no planning where is that planning? We are discussing the budget in the second year of the fourth Five Year Plan. But where is the Plan? Have they been able to produce a Plan at all? There is no Plan at all. Even as Dr. Lohia pointed out, Mr. Mehta may be thinking of a big Plan, a bigger-sized Plan, but this budget indicates that the plan estimates have been reduced to the tune, of Rs. 2,000 crores, without the Plan being finalised. So, it is a planless economy altogether. There is no Plan, nothing of the kind.

If they have any desire to cut down civil expenditure, well, I understand the Administrative Reforms Commission have given a report about the Planning Commission. Everybody knows, that this Planning Commission is a white elephant. There is a big paraphernalia of administration and the desire is, which has been expressed in this country, time and again, that we must have an expert body. I do not mean experts who do not believe in socialism or this sort of economy that we have decided in this country, but those who believe in the basic principles; let us have such an expert body. Why do they take time to take a decision in this matter? Therefore, what I feel is that this confusion created in the economic field has its reactions in the political side also. In the society, in the country today, there is unrest. There is dissatisfaction. In no sphere of the society does anybody feel that he can ever see a better future. Dr. Lohia has hinted that this sort of a situation cannot continue for long; we want to break the Government at the Centre. He says, let 30 or 40 members from the Congress Party come and join the opposition; the opposition parties together can form a government. But I would ask: for the healthy growth of democracy, it is necessary and there is no doubt that the Centre should go. But what I would prefer is, if they want to have any effective government in this country, let the Congress accept the standing offer of Prof. Ranga. Morarjibhai, the Deputy Prime Minister and leader of the Congress Party, would establish a greater reputation for himself if honestly he accepts it. There is a standing offer for the Swatantra Party and the Congress Party to come together and form a coalition, which will give stability. Actually the real picture today is we are at the mercy of the capitalists and the private sector and foreign interests for the growth of our economy and even for carrying on our administration. In such a situation, there will be probably some stability, and some realignment of political forces will come into being in this country if they choose their real ally. That is what Mr. Masani indicates.

Shri J. B. Kripalani: Mr. Masani wants to become Prime Minister.

Shri Surendranath Dwivedy: Whether he becomes Prime Minister or Morarjibhai becomes Prime Minister, it will not make much difference.

Shri P. N. Solanki (Kaira): That can be adjusted.

Shri Surendranath Dwivedy: As he says, they will adjust among themselves. At the rate at which we are going, I am sure we can never make

[Shri Surendranath Dwivedy]

any progress, unless there is a radical break from the present policies. As mentioned in the ECAFE report, our rate of growth is the lowest in Asia. It will take 137 years for us to catch up with Japan and 207 years to attain the present New Zealand *per capita* income. I would have thought that these things would have some effect on the Deputy Prime Minister. After the general elections, the Congress Working Committe thought that the situation was going from bad to worse and it must be arrested. As they have been doing all these years. to deceive the people, again they came out with some resolutions worded as vaguely as they have been all these years. They had proposed social control of banks, nationalisation of general insurance, progressive takeover of export-import trade, etc. Do you find any indication of any such thing in the budget proposals presented to this House? Would the Congressmen who support these proposals tell me "Here is a budget proposal which indicates that the Government is going to implement the directive given by the Congress Working Committee"? It is not so. He has only showed to the public that he has given us a balanced budget. It is a misnomer. It will be a healthy growth and a welcome change if balanced budget are placed not only at the Centre but also in the States. But this is not a balanced budget, as he has himself admitted in his speech.

16 hrs.

He has made up the deficit by taxing more. It is not a balanced budget in the sense that he has reduced the expenditure. The expenditure has increased as usual and in order to meet that expenditure some more taxes are levied on the people. This is not a balanced budget at all because he himself has said here:

> "During the current year, therefore, the additional revenue accruing to the Centre will be of the order of Rs. 68 crores. Changes in posts and telegraph rates will bring in Rs. 1 crore. The additional revenues of about Rs. 69 crores will more than cover the initial deficit of Rs. 68 crores."

He has also said:

> "...the total additional revenue in the full year will be of the order of Rs. 103.84 crores of which Rs. 22.98 crores will go to the States."

Therefore, in order to make up the deficit he has levied more on the common man and he says that this is a balanced budget. I do not know how the people will take it and how in the economic terms anybody would accept it as a balanced budget.

He has expressed grave concern about the rise in prices and he promised that he will try to stabilise the prices. Of course, we have reached such a stage that not only stabilisation is needed but what is needed is real reduction in prices. We should bring about a downward trend in the rising prices. It should be halted somewhere. He has said: "I am giving a budget which will stabilise the prices". He recognises the evil all right because it has come to a breaking point now. But has he taken measures to arrest this?

Let us examine what would be the ultimate outcome of the levies that he has imposed on tea, coffee, footwear and every little thing which the common man would use in this country. Will not the prices go up. He says the levy on aluminium, rayon etc., will not be passed on to the consumer, they will sit with the producers, talk to them and see that the consumer is not affected. Sir, we are sick of these promises. When devaluation was undertaken the same promise was given. But what happened? Fifteen days after devaluation there was six per cent increase in the wholesale prices all over the country.

Since 1959 there is an upward trend in prices. Even Morarjibhai himself in his budget speech has stated that during the last three years the wholesale prices have increased by 46 per cent. Let us see what happened in the devaluation year, from March 1966 to March 1967. The wholesale price index in March 1966 was 174 and in March 1967 it went up to 202.7 registering an increase of 16.5 per cent. In the case of food articles the price index was 175.3 in March 1966 and in March 1967 it went up to 217.6, an increase of 24.1 per cent. These are the achievements of last year. They are saying that they have not been able to arrest this rise because two wars intervened and there was devaluation.

Let us examine what happened during this period in other countries. Take Pakistan, for instance. Pakistan was as much affected by the war as we were. There is no question. But what has happened. If you take the period 1960—66, the rise in prices in our country has been the highest. In India in 1960 the wholesale price index was 111; today it is 165. In Pakistan in 1960 it was 105; they had also to face the recent conflct; but today in Pakistan it is 131. In USA it was 100; now it is 105. In UK it was 102; now it is 120. In Japan it was 102; today it is 108. I am quoting these comparisons with other countries to impress upon those people who are often telling,us that if we also compare our taxation proposals with those of other countries ours is the lowest. We can compare in other respects also our achievements. So, we want to express our deep concern at these developments. Whether we talk of socialism or capitalism, we have now seriously to think of arresting this growth.

If you are really anxious, can you evolve a policy which will arrest the abnormal growth of prices? I think the time has come when a high-power commission should be appointed to formulate an integrated price and income policy, because the way we are going, in the prevailing circumstances where the prices and income are chasing each other, there is no other way out. I know that it is a difficult task but I think there is no other alternative left for us. Otherwise, after a few months, again, however much they may now say no, we will be faced with a second devaluation because the market rate of our rupee would certainly fall both internally and externally. It is going to happen and no amount of assurance will help us unless we formulate and adopt an integrated price and income policy.

Now, what is this integrated prices and income policy which I am suggesting? If you want to have this policy then you have to change your own attitude. If we have to accept an integrated policy of prices and incomes then you have to revert to more stringent control, instead of your talking more and more of de-control, of cement, steel and other things. When goods are scarce and needs are more, control and regulation can hardly be dispensed with. Any type of decontrol at this stage would help only the profiteers and hoarders. Therefore, in such a policy the first condition is that there should be a general restraint on price rise; secondly, there should be price reduction, wherever possible, particularly in essential consumer goods; thirdly, wherever there is pressure for price increase, attempts should be made to adjust rise in one element by reducing the cost of another element so that there will be only a slight rise in prices. If we accept this, then we can base our economy on a solid rock of stability of prices. I think this policy will be of success if, with the guaranteed price stability, there is a standstill in incomes of various communities for some period, as has been suggested by Dr. Lohia. Let us decide once for all what would be the highest income, whether the ratio between the lowest and highest income would be 1 : 10 or something else. Then, we should have moratorium, restraint and control that everybody would have only

[Shri Surendranath Dwivedy]

such an amount and nothing more. Increase in income will mean higher productivity and with higher national income, the surplus will be diverted in a planned way to the lower-income groups, the depressed sections of the society, so that they enjoy a higher standard of living. The lower-income groups, the depressed sections of the society, are suffering as a result of this policy and if there is any talk of wage freeze or any such thing, it will be stoutly resisted. I think, it comes even within the framework of the present economic thinking of the Government, and I would like to know from this Government whether they are prepared, if they are really anxious, to stabilise prices, to accept such an integrated policy on prices and income.

They have talked too much about agriculture, that on agriculture depends the entire development of this country. This is nothing new. They always say so. Excepting in the First Plan, in the Second and Third Plans we had never given any attention whatsoever to agriculture. We have neglected agriculture and we are now reaping the consequences. The whole country is suffering today. He has given us a long lecture, as if there is lack of lectures, in his Budget speech, as to what they are going to do about increasing agricultural production, although, whenever any question will arise about agricultural production, the Food Minister will come forward and say, "I am not responsible for this; it is the States' responsibility; it is for the States to implement the policy; I am concerned only with supplying food". This is the position.

Now, we are talking of doing away with foreign food aid. As to how long we will take to do that, I do not know. Here, I want to put this question to him. In the last Presidential Address to both Houses of Parliament, for the first time, a firm promise was made. The President, while stating the policies of the Government said:

> "They have resolved to end our dependence on food assistance from abroad by the end of 1971."

I want to put it to the Minister whether there is any provision anywhere to see that there is a phased programme. By how much are you going to reduce this year, in 1967-68, foreign imports so far as agricultural goods are concerned? Is there any such plan? Is there any indication like that? Are you going to do that? The only reply will be, "What can we do? How can we do it? We can only do it if monsoons do not fail; we are in the hands of God".

Mr. Chairman: The hon. Member may try to finish now.

Shri Surendranath Dwivedy: How many minutes have I taken?

Mr. Chairman: You have taken 25 minutes.

Shri Surendranath Dwivedy: I will take 40 minutes; that is my due.

They are taking shelter, for the failure of their policies, under drought, famine, cyclones and floods, as if we would have planned in such a way that these things would never have happened. These things happen in a cyclic order. Take, for example, Pakistan. I am taking Pakistan because that is a small country and their problems are almost the same. What happens there? Its economy is periodically affected, dislocated, on account of cyclones, on account of floods and all that. At one time, it was discovered that in order to have a sustained agricultural improvement, they must change their priority. They were also importing agricultural goods and spending hundreds of crores of rupees. In one year, their import bill came to Rs. 100 crores. Immediately, they changed their priority. They spent as much as 41 per

cent of their entire budget on agriculture giving emphasis on agricultural production and industry that would help agriculture. They have changed their entire policy as a result of which they are not so much dependent on foreign imports as we are. Here, it is surprising that not only in foodgrains—in rice and in wheat—but also in jute, oilseeds, tobacco and tea, the agricultural products which were giving us sufficient foreign exchange earnings, we are lagging behind. Agriculture contributes about 50 per cent to our national income. When this is the state of affairs, how can we have any hope? He has repeated the same old thing. However much the Food Minister may try to satisfy the people, I do not think that he is going, in any way, to better or improve the conditions of this country. You have not implemented the land reforms, you have not implemented co-operatives, you have not done anything. I am not going into those factors. But the test is there; I want to put it to that test. Agricultural production, no matter whether you have a ceiling or not, whether you have big farms or not, agricultural production in this country can increase only if you provide the peasant with water, seed and fertiliser. These are the three minimum needs. It is not proper to accuse our agriculturists by saying that they are traditionally conservative, they do not take to production. Mr. Jagjiwan Ram is here and he will bear me out. He has visited some parts of Orissa.

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): Our agriculturists are not conservative.

Shri Surendranath Dwivedy: They are not conservative. The only thing is that they must get the wherewithals; they must get the necessary requirements. I find no indication of this here. At the time of crisis—we have become slaves because of failure in agricultural production—we are giving no attention at all. What I want to know is this. In terms of figures, as a result of the policies and programmes which you have chalked out for the year, how much water are you going to give to agriculturists; how are you going to give them fertilisers. This does not indicate anything. I would have understood if it was stated that we have a three-year programme and we shall make all-out efforts in this country to see that within three years at least 50 per cent of our agricultural land would be irrigated. Let us have a programme. Do not talk of Congress or non-Congress Governments. I do not think that any non-Congress Government would refuse to co-operate with you if you have such a policy and if you provide some money to carry out such policies.

Then, about technological development also, the time has come. We talk of tractors. Who is going to use tractors unless like Punjab you have big farms or unless you have an idea to bring the Joint Stock Companies and capitalists. You are in search of money. All the black money is with the capitalists today; it is put into the lands; they are purchasing hundreds of acres of land. Who needs tractors? What we want is power tiller; let some technological knowledge and research be put to practical application . . . (*Interruptions*).

An hon. Member: What we need is water.

Shri Surendranath Dwivedy: That, I have already stated. You take it from him. He is not giving you.

Our standard of living, industrial growth, everything depends on agriculture and I do not find any indication in the budget proposals that Shri Morarji Desai is going to make any revolutionary change to step up agricultural production.

Now, I come to the vexed question of taxation. Always, we are confronted with this question. 'If we do not tax, how will Government run?' But whom should we tax? That is the question. And what is it that

[Shri Surendranath Dwivedy]

Government have done during all these years? It is accepted and admitted by all economists that indirect tax is a burden on the common man. This is the accepted principle. But we find that in 1950-51 income-tax and corporation tax was to the tune of Rs. 173 crores; as against that, indirect tax, that is, customs duty, excise duty etc. was only Rs. 224 crores. In 1965-66 as against Rs. 576 crores of direct tax, that is, income-tax and corporation tax, the excise and customs tax went up to Rs. 1,436 crores. In 1967-68, as against Rs. 640 crores of direct tax, the indirect tax is going to be Rs. 1,857 crores. This is the order of indirect taxation that we are having. It is passed on easily to the consumer. When there is such a disparity in income and the standard of living is going down and down, how can we hope that the economy would ever grow? There is an imbalance as a result of which it is going to collapse.

Shri R. Barua (Jorhat): Is he objecting to the indirect taxes including corporate taxes?

Shri Surendranath Dwivedy: I have compared the incidence of the direct and indirect taxes. It is not a question of opposing this or that. But my point is that Government should tax in such a way that they would get some yield and at the same time they would not put greater burden on the poor sections of the community. But, unfortunately, what is happening is that the burden is being put on the poorer sections of the community.

Let us leave alone this question of corporate tax etc. Will my hon. friend say what is going to happen to the sum of about Rs. 3,000 crores which is current in the market, and which is in circulation in the market and what attempt has been made to get that money back?

So, the present taxation system has to be changed altogether. It is not as if I am opposing just any one single levy that the hon. Minister has imposed, but I am opposed to every levy that he has imposed in this budget. He has given some concession to small capitalists. I do not mind that. But the increase in the indirect taxes should be done away with.

Take the case of yarn, for instance. Of course, the hon. Minister may say that the tax on superfine yarn is not going to hit the common man. But I may tell you that today if anybody goes to any village, he will find that the taste of the people has changed; if you put khadi cloth, handloom cloth and powerloom cloth or mill cloth, before an ordinary villager, he will not look at the khadi or the coarse cloth at all. The taste of the people has changed and this has become a habit with them now, and it is good. It is in such a situation that the hon. Minister is imposing a levy on yarn. Who is going to be hit by it? It is the poor powerloom section which is going to be hit by it. I am told that about five lakhs of people are going to be affected as a result of it, in Maharashtra especially, because they cannot stand competition with the mills; that is their case. So, every single levy that has been proposed is going to hit the common man and the poorer sections of the society. I am, therefore, opposed to every single levy that he has proposed, because I feel that there is sufficient room to tap other sources; if he had a mind to do it, he could have taken recourse to other methods. For instance, he can get money by taxing urban property. If you go to any big city today, you will find that there are palatial buildings, big buildings and *mohullas* coming up. In the country banking and insurance companies generally put up big buildings. But in our country, go to Calcutta or Bombay or any big city. You will find big buildings coming up. Built by whom? By the industrialists. They have created another bank. By the time you nationalise banks—about which you talk but do not put into practice—they,

would have minted their money in other spheres. These buildings are tied to industries. They are not independent buildings. The loss shown in the industries is made up by these buildings. Why not tax them? Why not tax this urban property? Why not impose a tax on plantations?

What has been proposed is a joke. You tell the people: do not drink tea, do not smoke. These puerile things do not work. They do not appeal to the people. I would have supported him if he had imposed a licence fee for electric illuminations, use of loudspeakers etc. for weddings and other celebrations.

An hon. Member: For elections.

Shri Surendranath Dwivedy: Of course, but, for elections, we are to pay.

He could have imposed a licence fee on big hotels, restaurants and night clubs. There are lots of them in Bombay and other cities. If he had imposed levies on them, I would have supported him. I would have supported a levy even on refrigerators and coolers. I am surprised how these things escaped the notice of our Finance Minister who talks of austerity!

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Nobody taxes liquor.

Shri Surendranath Dwivedy: But he imposes these levies on the common man all right. I would like him to impose a tax on the personal assets and incomes of the princes. There is a demand for the abolition of the privy purses. Because some of the ex-princes have been able to defeat them in the elections, in the Congress Party some people are now raising this cry.

Mr. Chairman: The PSP's quota was 36 minutes. He has exceeded that already.

Shri Surendranath Dwivedy: I have taken 45 minutes? Anyway, I have given him good advice.

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): I must consider it good.

Shri Surendranath Dwivedy: I would support him if he becomes a little more....

Shri D. N. Tiwary: Do not include 'ifs'.

Shri Surendranath Dwivedy: Let him withdraw all these levies and impose the taxes I have suggested. We will support him.

Since you want me to conclude, I will not repeat what other friends have stated. But it is necessary in order to give health to our economy that we must introduce a system for changing the entire pattern of our economic development; if we really want to usher in an egalitarian society, then as a result of the policy, the disparity between the sections of our society in income and in wealth should be removed as quickly as possible.

In this connection, I will add my voice to what other friends have urged that Government must take steps to break the monopoly of capital and wealth in the hands of a few. They must take steps to abolish the managing agency system and also implement the recommendations of the Mahalanobis Committee and the Monopolies Inquiry Commission.

श्री राम किशन (होशियारपुर) : जनाब चेयरमैन साहब, श्री मोरार जी देसाई ने एक मुश्किल वक्त के अन्दर जो बजट पेश किया है, एक बैलैंस्ड बजट और इन्फ्लेशन को रोकने वाला और चैक करने वाला बजट है, उस के लिए मैं उन को धन्यवाद देता हूं । इस बजट में खामियों के बावजूद इस बात की कोशिश की गई है कि इस बजट

[श्री रामकिशन]

को प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ओरियंटिड बनाया जाय। मैंने आज डा० राम मनोहर लोहिया और श्री द्विवेदी की तकरीरों को सुना। उन की कुछ बातों को सुन कर मुझे अफसोस हुआ है कि आज के इस जमाने में जब कि हमारे सामने एक बड़ी गम्भीर स्थिति है तब भी हम कुछ गैलरिज से खेलते हैं। हमें इस सारी चीज को देखते हुए कि किस स्थिति का सामना करना है, किन हालात के अन्दर यह बजट हमारे सामने आया है, गम्भीरता के साथ इस के ऊपर विचार करना है।

लगातार पिछले 15 साल से हम ने देखा है कि नौन-डेवेलपमेंट स्कीमों के ऊपर जो कुछ खर्चे हमारे हुए हैं उससे पाच, छः गुना हमारा खर्चा पड़ा है। यह बात नहीं है जैसा कि द्विवेदी साहब ने कहा कि एग्रीकल्चर के साथ आप ने अन्याय किया है और इस बात को हर एक आदमी जानता है कि अगर हम पिछले 15 साल के सारे देश का एग्रीकल्चर का नक्शा देखें तो इस से पता चलता है कि कम से कम 100 परसेंट एग्रीकलचर पैदावार बढ़ी है। सवाल यह है कि जिन हालात का हमें इस वक्त सामना है, हमें अपनी इस शैटर्ड एकोनामी को ठीक करना है, हम ने यह इंटरनल और एक्सटरनल समस्याओं के ऊपर और अनाज की समस्या के ऊपर काबू पाना है उस के लिए हमारे सामने क्या पोजीशन है ? मेरी राय यह है कि तीन, चार चीजे ऐसी हैं जिनके कि ऊपर हमें फौरन तवज्जह देनी होगी। सब से बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारे देश की जो बेसिक चीज है फूड, अगर हम उस फूड के सवाल को हल नहीं कर पाते हैं तो इस मुल्क की इंटैग्रेटी खतरे में पड़ सकती है। इस मुल्क की सौवरैनिटी खतरे में पड़ सकती है। इस मुल्क को पूरे तरीके से फौरेन कंट्रीज पर डिपेंड करना होगा। अब जहां तक इस फूड का ताल्लुक है बातों से यह हल होने वाला नहीं है। यह बात ठीक है कि इस फूड के सवाल को हल करने के लिए हमारे एग्रीकलचरिस्ट्स के लिए पानी की, सीड की और फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 20 साल के अन्दर खाद वगैरह के लिए इतना रूपया मुहय्या नहीं किया गया है जितना कि इस बार श्री मोरार जी देसाई ने रक्खा है। उन्होंने कोई 225 करोड़ रूपया अपने बजट में इन सारी चीजों के लिए रक्खा है। मैं जानता हूं कि आज दुनिया के एग्रीकलचरल वर्ल्ड में जहां तक अपने देश का ताल्लुक है वह सब से बड़ा ऐग्रीकलचरिस्ट है लेकिन उस के मुताबिक वह फर्टिलाइजर्स औरों की तुलना में बहुत कम यूज करता है लेकिन वक्त आ गया है कि हम खेती के लिए आवश्यक सुविधाओं की तरफ़ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दें। मैं आप के जरिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब और उसी के साथ ऐग्रीकलचर मिनिस्टर की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि मेरा यह निश्चित मत है कि जितने इस वक्त आप के पास फंडस हैं जो कि आप के पास इस वक्त रिसोर्सेज हैं उस से आप अगले तीन, चार साल के अन्दर एग्रीकलचर के मामले में सैल्फ-सफिशिएंट हो सकते हैं लेकिन इस के लिए कुछ चीजों की तरफ तवज्जह देने की जरूरत है।

थर्ड प्लान के आखिर हमारे सामने यह कहा गया था कि हम थर्ड प्लान के आखिर कोई 12 लाख टन के करीब यह फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करेंगे लेकिन उस के मुकाबले जितने फर्टिलाइजर्स प्लांटस् चले हैं उस में 5 लाख 86 हजार टन की फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। जहां तक उस के प्रोडक्शन का ताल्लुक है वह भी उस से कम है। अगर हम ने 1970-71 तक इस देश को सैल्फ-सफिशिएंट बनाना है तो उस के मुताबिक कहा जाता है कि हमें कोई 24 लाख टन नाइट्रोजन की उस के फर्टिलाइजर्स की जरूरत होगी। जितनी इस वक्त हमारी लाइसैंसिंग कैपेसिटी है जितनी हमारी दूसरे प्लान्स के लिए

निगोशिएशंस चल रही है उन सब को मिला कर अगर वह पूरे तरीके से वर्किंग के अन्दर आये तब वह 17–18 लाख टन से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इस तरह से 1970–71 में कोई 6 लाख टन की उस में कमी रहती है। मेरी अर्ज यह है कि इस बात की तरफ तवज्जह देने की जरूरत है कि आप इस को किस हद तक पूरा कर सकते हैं। यह हमारे लिये एक चैलेंज है और मैं समझता हूं कि उस की तरफ हमें पूरी तवज्जह देनी चाहिए।

दूसरी चीज जिसकी कि तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह पानी की समस्या है। अभी पानी का यहां पर जिक्र हुआ। उस में यह कहा गया कि अगले साल के अन्दर हम दो मिलियन किलोवाट बिजली ऐडीशनल पैदा करेंगे लेकिन उस के मुताबिक पैदा की 12 लाख किलोवाट। यह 8 लाख किलोवाट बिजली क्यों पैदा नहीं हुई? किस का कसूर हुआ है किस जगह पर? इसलिए कुछ चीजों की तरफ तवज्जह देने की जरूरत है।

अभी थोड़े दिन हुए सारे इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस हुई थी। उस के अन्दर सारा जायजा लिया गया कि यह पिछले 20 साल के अंदर कितने हमने यह सारे जो वाटर रिसोर्सिज हैं देश के अन्दर उन सारों को टैप करके किस हद तक हम ने उनको युटिलाइज किया है? वह सारा नतीजा देखने के बाद पता चला कि स मुल्क के अन्दर जितने हम ने इरीगेशन के छोटे और बड़े डैम बनाये हुए हैं पानी हमारे पास एवेलेबल है लेकिन 38 लाख एकड़ जमीन की और पानी मिल सकता था लेकिन वह पानी नहीं दिया गया। मेरा यह सुझाव है कि इस वक्त जितना आपके पास पानी है, इरीगेशन के जो आपके डैम हैं उनको आप पूरे तरीके से युटिलाइज करें, आप बिजली को पूरे तरीके से युटिलाइज करें। खाद की मैं ने बात कही और उस के मुताबिक जहां तक उस से पैदावार करने का ताल्लुक है क्या यह हमारे लिए हर्ष की बात नहीं है कि आज सारे हिन्दुस्तान की बात नहीं है सारी दुनिया के अन्दर नीदर लैंड है जहां एक एकड़ के अन्दर ज्यादा से ज्यादा 4000 पाउंड की ईल्ड होती है लेकिन आप के सामने पंजाब के अन्दर एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी, लुधियाना के अठवाल ने एक नया तजुर्बा किया है उस के मुताबिक चेअरमैन साहब मैं आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि 80 फारमर्स ने 80 किसानों ने पंजाब के अन्दर ढाई टन से लेकर तीन टन तक अनाज अपने खेत के अन्दर एक एकड़ में पैदा किया है। यह मैक्सिकन व्हीट नहीं है। मैक्सिकन व्हीट के मुकाबले पर पी० बी० 18 कल्याण व्हीट होता है। उससे उसका मुकाबला होता है। डा० अठवाल का कहना है कि वह उस के चैलेंज को मंजूर करेगा और उन्होंने कहा है कि मैं 1968 के अन्दर अपने इस व्हीट के जरिए पंजाब के खेतों के अन्दर एक एकड में 10,000 पाउंड पैदा करके दिखलाऊंगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि दो साल के अन्दर हम पंजाब के अन्दर ऐसी हालत पैदा कर सकते हैं कि उस बीज के जरिए हम अपनी जरूरत के अलावा ऐडीशनल 10 लाख टन गेहूं पैदा करके देश को दे सकते हैं। उस के लिए शर्त यह है कि फर्टिलाइजर भी आ जाय, पानी भी आ जाय। हम बड़े बड़े डैमों की बात नहीं करते हैं। हमारा यह कहना है कि जितनी इस वक्त बिजली आप के पास ऐवेलेबल है अगर आप उसको ले कर और ट्यूब वैल सारे हमें दे दें तो उनका कहना है कि दो साल के अन्दर अर्थात सन् 1968 या 1969 के अन्दर 10 लाख टन हम एडीशनल गेहूं पैदा करके देश को दे सकते हैं।

इतना ही नहीं जिस बीज का मैंने जिक्र किया है और जिस इम्प्रूव्ड सीड की आपको जरूरत है, उनका यह कहना है कि नार्थन इंडिया के अन्दर जितनी भी आप की व्हीट बैल्ट हैं उस के लिए आप 1971 के लिए जितनी भी इम्प्रूव्ड सीड की जरूरत है वह सारा का सारा

[श्री राम किशन]

बीज डा० अठवाल उस एग्रीकल्चर युनिवरसिटी से आपको दे सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम उस तरफ तवज्जह देने को तैयार हैं ? एग्रीकल्चरल साइंटिस्टस पूरे तरीके से वही यूनिवरसिटी आप को मुहैय्या कर रही है। सारे देश के अन्दर स वक्त आप की जितनी एग्रीकल्चरल युनिवरसिटीज हैं, ख्वाह वह लुधियाना की हो, ख्वाह उदयपुर की हो, ख्वाह यहां आप के दिल्ली के अन्दर जो कि आपका एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन के अन्दर जितनी यह सारी चीजें हैं उन का किस हद तक सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है मेरी यह आप से अर्ज है कि इस की तरफ तवज्जह देने की जरूरत है।

स साल के अन्दर आप ने यह एलान किया है कि 1 लाख 68 हजार एकड़ जमीन के अन्दर यह जो हाई ब्रैड वैराइटी सीड है उस को आप बोयेंगे और 1970–71 तक आप 3 करोड़ 68 लाख एकड़ के अन्दर इस सारी चीज को करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि उस वक्त किसान को जिन जिन चीजों की जरूरत है आप उस को देने को तैयार हैं या नहीं ? अगर तैयार हैं तो यकीनन हम अगले तीन, चार साल के अन्दर इस सारी चीज को पूरा कर देंगे।

मैंने अभी बिजली का जिक्र किया है। पानी और बीज का जिक्र किया है और मेरा यह निश्चित मत है कि अगर हम पूरे तरीके से इन सारी चीजों की तरफ तवज्जह दें तो जहां तक यह हमारा खुराक का मसला है उसको हम पूरे तरीके से हल कर पायेंगे।

दूसरी चीज जिसकी कि देश को बड़ी सख्त जरूरत है वह हमारा इम्पोर्ट-ऐक्सपोर्ट का मसला है। हालत यह है कि इम्पोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है और जहां तक ऐक्सपोर्ट का ताल्लुक है उस के अन्दर कमी हो रही है। डीवैल्यूएशन के बाद यह कहा जाता था कि जहां तक हमारे ऐक्सपोर्ट का ताल्लुक है यह बढ़ेगा और इम्पोर्ट में कमी होगी। लेकिन जहां तक इम्पोर्ट का ताल्लुक है वह कोई हमारा 1400 करोड़ के करीब है लेकिन जब तक हमें फूड की जरूरत है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, डिफेंस की जरूरत है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये जो मशीनरी और कल पुर्जे आदि की जरूरत है तो उस के लिये हमें वह सारी वस्तुएं इम्पोर्ट करनी होंगी, मंगानी पड़ेंगी लेकिन जहां तक ऐक्सपोर्ट का ताल्लुक है चेअरमैन साहब अगर आप देखें तो सारा ऐक्सपोर्ट पिछले एक साल के अन्दर, अगर उस का सारा अंदाजा लगायें तो 169 मिलियन डालर की हमारे ऐक्सपोर्ट में एक साल में कमी हुई है। इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है, और आज जो वेस्टर्न एशिया की सिचुएशन है उस के अन्दर हमारा फ्रेटचार्जस और बढ़ गया है। अगर वह रुपये में देना होता तब भी कुछ और बात होती लेकिन वह हमें डालर और हार्ड करेन्सी में पे करना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है जब कि यह मुल्क इस चेलैन्ज को मंजूर करे, और जो आज सब से ज्यादा जरूरी है, यानी सेल्फ रिलायेंस, उस की तरफ जायें।

मैंने अभी जिक्र किया कि जहां इम्पोर्ट और ऐक्सपोर्ट का ताल्लुक है, उस के अन्दर हमारी बुरी हालत है, लेकिन इस के बारे में मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। जहां तक ऐक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का सवाल है मेरी अपनी राय यह है, और मैं आपके जरिये अपने फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि जो हमारी ऐक्सपोर्ट पहले 800 करोड़ रु० की थी वह अब 600 करोड़ रु० की रह गई है। यह जितनी अपनी सारी नैशनल इनकम है उस का 5 परसेंट बैठता है। आज जितनी डेवेलपिंग या डेवेलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने इसके लिये बड़े बड़े ऐक्सपोर्ट इन्सेन्टिव्ज दिये हैं। इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम इस सारी चीज को रेवेन्यू के प्वाइंट आफ व्यू से न देखें। अगर

हिन्दुस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती है तो हमें मालूम नहीं कि आप किस चीज के ऊपर अमल कर पायेंगे । जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी डेवेलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे आस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमरीका है, इंगलैंड है, उन्होंने चार-पांच तरह की फेसिलिटीज दे रक्खी है : फिस्कल इन्सेटिव्ज, फाइनेन्शल इन्सेटिव्ज, स्पेशल एक्सपोर्ट इन्सेंटिव्ज, ऐंड अदर फार्म्स आफ एक्सपोर्ट ऐसिस्टेंस । मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है जब हम भी इस चीज की ओर देखें कि जहां तक 5 परसेंट नेशनल इनकम एक्सपोर्ट से होने का ताल्लुक है, उस को रेवेन्यू इल्डिंग चीजों की तौर पर न देखें । अगर आप को एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो सारी चीज को रिव्यू करना होगा । इस रिव्यू के सिलसिले में मैं पाकिस्तान का जिक्र करना चाहता हूं । आज से कोई 15 साल पहले पाकिस्तान की क्या हालत थी ? उस की कोई एक्सपोर्ट नहीं थी लेकिन आज हमारे साथ उसका बड़ा सीरियस कम्पिटीशन पैदा हो गया है । उन्होंने 40 परसेन्ट बोनस वाउचर एक्सपोर्ट स्कीम जारी कर रक्खी है । आयरलैंड और आस्ट्रेलिया जैसे जो बड़े बड़े डेवेलप्ड देश हैं उन्होंने कहा है कि जब पहले एक पाउंड एक्सपोर्ट के पीछे पाउंड के ऊपर टैक्सेशन की छूट दी है ।

मैं नहीं कहता कि हम किसी से ट्रेड न करें । जरूर करें लेकिन अपना फायदा भी देखें । हम ने काफी और टी और अन्य चीजों पर लेवी लगाने की बात की है, लेकिन इस से काम बनने वाला नहीं है । आज तो टी और काफी नैशनल ड्रिंक हो चुके हैं उसकी अपने देश में खपत घट नहीं सकती । और इस पर लेवी का ग़रीब पर असर पड़ेगा । हम को लोगों के साइकालोजिकल एफेक्ट को इसके लिए देखना पड़ेगा । जो ट्रेडर और बिजिनेसमैन हैं वह इस प्वायंट आफ व्यू से देखते हैं कि किस से उन को प्राफिट होता और किस से लास होता है । मेरी अपने फाइनेन्स मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त है कि वह सारी चीज को देखें कि जितना हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड है उसको इस वक्त तक हम ने कितने इन्सेन्टिव दिये हैं और आया उस से कोई नतीजा निकला । अगर नहीं निकला तो किस चीज को खत्म करने की जरूरत और किस चीज को मॉडिफाई करने की जरूरत है । हमारे सारे देश के अन्दर कोई 4500 आर्गनाईज प्रोडक्शन यूनिटस हैं, और इन में से 125 यूनिटस हैं जो एक्सपोर्ट वगैरह करती हैं । एक्सपोर्ट के अन्दर करीब 3,000 आइटम्स हैं, जिन में से कई ऐसे आइटम्स हैं जो बिल्कुल निकम्मे हैं । मेरी अर्ज यह है कि अगर आप को इंडस्ट्री और ट्रेड की तरफ सारे देश का अटेनशन ड्रा करना है, अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो इंडस्ट्री और ट्रेड के जितने एक्सपोर्ट सेक्टर हैं उन के प्रतिनिधियों को बुला कर देखें कि हम को किस हद तक और किस तरह के वेज ऐंड मीन्स इस्तेमाल करने होंगे जिस में हम ज्यादा से ज्यादा उन की तवज्जह दिला सकें । जो भी हमारे मेजर आइटम्स हैं, फिस्कल, नान-फिस्कल, फाइनेन्शल, रेगुलेटरी, प्रोसीजरल और कंसेशनल मेजर्स, जहां तक उन का ताल्लुक है, उन को रिव्यू कर के हम देखें कि किस तरह से इस चीज की उन्नति दी जा सकती है । जितनी हमारी एक्सपोर्ट की जीजें हैं, उन के जो ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं जो उन के दूसरे लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं गवर्नमेंट के, वह सारी चीज को देखें कि जो डवैलप्ड और डिवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने क्या क्या इन्सेन्टिव्ज दिये हैं, और उस के मुताबिक सारी चीज को आगे करने की कोशिश करें ।

पिछले दिनों यहां पर एक यूनाटेड नेशन्स टीम आन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन आई थी । उन के लीडर बी० एफ० कोगाई थे । मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी थी और इस सम्बन्ध में कुछ रिकमेंडेशन्स

[श्री राम किशन]

की थीं। इस सारी चीज की तरफ तवज्जह देने की जरूरत है, और सरकार को देनी चाहिये।

इस सिलसिले में मैं एक बात और आप के जरिये से कहना चाहता हूं। अपने देश का जितना भी रुपया हम ने थर्ड प्लैन में लगाया है उस के सिलसिले म जिस सब से बड़ी चीज की तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह है हमारी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स। जो हमारी पब्लिक इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राईज है वह हमारी एकानमी के लिये जरूरी है। लेकिन पब्लिक सेक्टर की जो पोजीशन है उस की तरफ हम को तवज्जह देने की जरूरत है। अभी थोड़े दिन हुए यहां दुर्गापुर प्लान्ट का जिक्र आया था। उसी तरह हिन्दुस्तान स्टील प्लांट लिमिटड है। इन पर 885.10 करोड़ रुपया लग चुका है, लेकिन उन में से हमारी ईल्ड कितनी है, आउटपुट कितना है? जितनी भी हमारी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं, जिन में करीब 68 कंपनियां हैं, उन पर 2225 करोड़ रुपया लगाया गया है। अगर आप एवरेज रिटर्न देखें तो उन से कोई 2.9 परसेन्ट इयरल रिटर्न होता है। उस के मुकाबले में प्राइवट सेक्टर से करीब 19 परसेन्ट वार्षिक का रिटर्न होता है। इस लिये मैं आप के जरिये से अपने फाइनैन्स मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से अर्ज करना चाहता हूं कि वक्त आ गया है जब कि हम इन सारी चीजों को देखें

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को देखने के लिये एक पर्मानैण्ट एफिशियन्ट कमीशन बनाया जाना चाहिये। जिस कमीशन की बात मैं कर रहा हूं उस में एक्सपर्ट भी हों, वह लोग देखें कि खामी कहां है और मैनेजर वगैरह किस तरह से रखे जाते हैं इस नैशनल कमिशन के चेअरमैन खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हों। आज हालत यह है कि प्राइवेट सेक्टर के अन्दर अगर कोई 100 रु० का इन्वेस्टमेंट करता है तो 21 रु० का रिटर्न होता है लेकिन पब्लिक सेक्टर में उस के मुकाबले में 8 और 9 रु० होता है। इस को देखने की जरूरत है ताकि हम जितना रुपया बचा सकें बचायें।

इसके बाद मैं आपके जरिये से अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि जहां तक टैक्सेशन का ताल्लुक है, 25 मई को उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि 31 मार्च तक 552 करोड़ रु० के इनकम टैक्स के एरियर्स हैं। मालूम नहीं महावीर त्यागी की रिपोर्ट कहां गई? मेरा खयाल है कि आप उसके मुताबिक इस पर पूरी तवज्जह नहीं दे रहे हैं। आप इन सारे एरियर्स की तरफ भी तवज्जह दें ताकि इन सारी चीजों से जितना पैसा बचाया जा सके हम बचायें और हमारे एक्स्पेन्डिचर में जितनी कमी हो सके उस को करें। हमारा फूड आउटपुट बढ़ा है, हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा है पिछले तीन चार महीनों में, लेकिन जो प्लैन का टार्गेट था 11 परसेन्ट का लेकिन हमारे नार्मल ट्रण्ड 7 प्रतिशत है पर हुआ उसके मुकाबले में कम। किस लिये यह कमी रही है, इसको देखने की भी जरूरत है। जब तक आपका आउटपुट नहीं बढ़ेगा, देश की इकानमी जिस तरह से आगे जा रही है उसके मुताबिक हम तरक्की करने वाले नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब इन सारी चीजों की तरफ तवज्जह देंगे।

आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं। जहां तक फूड का ताल्लुक है उसके बारे में जितना भी सिलसिला सारे देश के अन्दर चल रहा है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बजट में कुछ और भी पैसा इस काम के लिए देने का फैसला किया है स्टेट्स को लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं कि कहां तक और किस हद तक उस पैसे से देश का फूड का

आउटपुट बढ़ेगा । लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सभी चीजों के मुताल्लिक एक नेशनल कमिशन आन फूड सफिशैन्सी मुकर्रर किया जाए जो सारी चीज, को देखे। आज कोई फैसला किसी चीज के मुताल्लिक होता है तो उस पर अमल दरामद होता है या नहीं यह देखने वाली बात है । सब से बड़ी बात जोंज की है । जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें हालत क्या है । मैं एक ही मिसाल देना चाहता हूं । कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और ऊना जो हिमाचल को गए हैं ये ऐसे इलाके हैं जो सारे हिन्दुस्तान के अन्दर मिलिटरी के लिए सब से ज्यादा बहादुर जवान देते हैं और यह वह इलाका है जहां के सिपाहियों ने भारत-पाकिस्तान लड़ाई के अन्दर सब से ज्यादा कुर्बानी की । लेकिन आज वहां हलात क्या है ? अगर पंजाब के एक इलाके में 70–80 रुपये क्विंटल के भाव पर गन्दम मिलती है तो उसके एक मील के फासले पर 130 और 135 रुपये क्विंटल के भाव पर मिलती है । जब इस तरह की बात हो तो क्या मिलिटरी फैमिलीज की ओर भी आपका ध्यान आता है या नहीं आता है । मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि सारी की सारी चीज पर हम विचार करें और देखें कि किस तरह से यह सम्भव हो सकता है कि सारे का सारा देश एक तरह से चले और देश के सभी भागों में उचित मूल्य पर खूराक मुहैया हो ।

एक अपील मैं अपोजीशन के लीडर साहिबान से करना चाहता हूं । अगर हम इस बात के अन्दर सब मुत्तफिक हैं कि देश में आउटपुट होना चाहिये, खूराक का प्राबलैम साल्व होना चाहिये, देश की इकोनोमी मजबूत होनी चाहिये, इंटरनली और एक्सटर्नली देश मैफूज होना चाहिये तो हमारे और आपके सामने एक परीक्षा की घड़ी आ खड़ी हुई है । क्या इस नैशनल एमरजेंसी के अन्दर हम सबके लिए इसके बारे में सोचने का वक्त नहीं आ गया है ? जो घेराव हैं वे हिन्दुस्तान को तबाह और बरबाद कर रहे हैं, जो स्ट्राइक्स हैं व हिन्दुस्तान की इकोनोमी को नुकसान कर रही हैं । आउटपुट बढ़ाने के रास्ते में ये बाधक सिद्ध हो रही हैं। क्या हमारा सब का फर्ज नहीं है कि नेशनल प्वाइंट आफ व्यू से हम सारी चीज को देखें । 1942 के अन्दर जब देश अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता प्राप्त करने की आखिरी लड़ाई लड़ रहा था तब तो हमारे ये अपोजीशन के दोस्त कम्यूनिस्ट और दूसरे कहा करते थे कि हर कारखाने के अन्दर पैदावार ज्यादा होनी चाहिये, किसानों से कहते थे कि हल ज्यादा वे चलायें, मजदूरों को कहते थे कि वे ज्यादा पैदावार करें लेकिन आज जब कि हिन्दुस्तान के अन्दर अपना राज्य है, एक नेशनल एमरजेंसी हमारे सामने है, देश के सामने है, बिहार और उत्तर प्रदेश आदि में सूखा पड़ा हुआ है तो क्या आज वक्त नहीं है कि कम से कम हम सब दो तीन साल के लिये इन घेराओं और इन स्ट्राइक्स को स्थगित रखें और इस बीच में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने पर ध्यान दें । अभी पीछे नम्बूदरीपाद साहब ने बिड़ला साहब को जो कंसेशन दिये थे उसमें उन्होंने कहा था पांच साल तक मजदूरों से आपका किसी तरह का कोई झ गड़ा नहीं होगा, कोई स्ट्राइक नहीं होगी और हर एक चीज की आपको पूरी तरह से इजाजत होगी । देश के एक छोटे से इलाके के लिए आप ऐसा कर सकते हैं तो आज जब कि हिन्दुस्तान की एग्जिस्टेंस का सवाल हमारे सामने है, उसकी सरवाइवल का सवाल हमारे सामने है तो क्या उचित नहीं कि आज हम ऐसा एटमासफीयर पैदा करें, ऐसी क्लाइमेट तैयार करें कि जिसमें इनवैस्टमेंट हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके ताकि देश को हम आगे ले जा सकें । मैं आशा करता हूं कि मेरी इस बात की तरफ तवज्जह दी जाएगी ताकि जिस चीज के ऊपर हमारे देश की इकानोमी ने बेस करना है, जिस चीज के ऊपर हमारा भविष्य निर्भर करता है, उन चीजों की तरफ हम पूरा ध्यान दे सकें । अगर ऐसा होगा तो

[श्री राम किशन]

तो देश नेशनल तौरपर मजबूत होगा। तब हम देश का भविष्य बना सकेंगे और तभी देश फख्र से, मान से खड़ा हो सकेगा और दुनिया का मुकाबला कर सकेगा।

Mr. Chairman: Now, before I call on the next hon. Member to speak, I would like to make one observation. I have noticed one hon. Member reading a newspaper in the House. I think it is not in the best healthy traditions of parliamentary system to read a newspaper openly in the House. I would request him not to do it. It is not in keeping with the decorum of the House.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या हाउस में सोने की इजाजत है ? एक माननीय सदस्य सो रहे हैं। श्री शिव नारायण जो कि एक लीडर हैं ....

श्री शिव नारायण (बस्ती) : इनको दिखाई नहीं देता है।

श्री कंवर लाल गुप्त : बहुत से काम होते हैं लेकिन सोने का काम आज ही हुआ है।

Shri Amiyanath Bose (Arambagh): Mr. Chairman, Sir, in an hour of great danger for England, in the year 1939, I heard Mr. Winston Churchil speaking in British Parliament, telling the British Prime Minister "f you want to look forward you must first look at the past and learn from history." I regret that our Deputy Prime Minister has not learnt the lessons of history, lessons of recent history, history of Chinese aggression on India, history of Indo-Pakistan conflict and history of the effects of devaluation on our economy in preparing this budget. I remember, and remember rather well, the interview Shri Morarji Desai gave to the press on the eve of the last general election on devaluation. I remember it because I used it with some effect in the election I was contesting with the then Finance Minister. Then he said that devaluation had raised the price level of our country. He said further that it had not in any way increased the exports, so far as our exportable goods were concerned. Now he should have been told by his Ministry why the exports did not improve as a result of devaluation.

It is a very common economic principle, a very simple economic principle that when devaluation takes place the general export position of any country improves, by and large. The main reason, the fundamental reason why the exports from our country did not improve, is that demand for our goods, to use an economic expression is inelastic. Therefore, even devaluation of the rupee and diminution of prices did not appreciably affect our export trade.

One of the essential features of the budget that the hon. Deputy Prime Minister has placed before the House is the imposition of excise duties. To quote just one sentence of his own:

> "My main justification for the selective but sizable increase in excise duties is that these are necessary in the interest of exports."

The hon. the Finance Minister ought to have known better, he ought to

have known that the effect of imposition of excise duties on articles of common use would be to raise the price level and that it will not in any way assist our export trade. In taxation there is an English liberal saying, not a socialist jargon, 'soak the rich and feed the poor.' The hon. the Finance Minister has reversed that proposition for India. By imposing excise duties on articles of common use, he will be inflating the price level of these things and will thus be putting unbearable burden on the common people.

It is known that when the price level rises, wages never rise in proportion. Therefore, the only economic effect of this imposition of excise duties will be to increase the profit margin that will be given to the capitalist classes of India.

The Finance Minister has referred the English saying and he wants to says, "Soak the poor and feed the rich."

17 hrs.

The next point that I want to take up is this. There are two main problems with which we are faced today, that is, the problem of food and the problem of India's security. Before I deal with this problem, one thing must be made clear in the House that we must never forget that China today has the third largest air-force in the world; China possesses nuclear weapons and China has almost completed the development of the delivery system. If you look at the map, there are airstrips all along our northern border and there are road communications which connect those airstrips to bases inside China and Tibet. This is the position. I know our country suffered reverses in NEFA—it is not because of those reverses that we lost the battle—but the day China exploded a nuclear bomb and we, in our country, declared that we shall not manufacture nuclear weapons, we lost the battle. We must proceed on the assumption that today China's hostility to India is a settled fact. Another danger with which we are faced today is the continued hostility on the part of Pakistan towards India. This is the problem of defence which the Budget must provide.

There is, of course, the problem of food. I have made some calculations. If we follow four principles which are applicable to a war economy—there is no difference in principles between a scarcity economy with which we are faced today and a war economy—we can effect considerable saving. Firstly, we should follow the principle of postponing, for the time being, all construction works in respect of all the Ministries. It was done in England on the eve of the last World War. All construction work in respect of all the Ministries should be postponed and stopped for a fixed period of time unless that construction is necessary in the interest of national security. Considerable amount of saving can be effected if that is done. Secondly, there is a considerable scope of economy in respect of all the estimates and if 10 per cent cut is made under all heads, there will be considerable saving. Then, I should like the hon. Finance Minister to increase direct taxation. I shall not give an Utopian idea, as given by my esteemed friend, Dr. Lohia, to reduce the income to Rs. 1500 or Rs. 1000 per month. We do not have that socialistic society. We have a Government, though it no doubt gives lip service to socialism, which is really a capitalist Government. Accepting that it is a capitalist Government, accepting the position that the Congress Party does not, in fact, believe in socialist society, I would say that there should be additional direct taxation to reduce at least 10 per cent. the income of all persons apart from the direct taxation which has already been imposed. There should be a 10 per cent. voluntary cut—I use the expression 'voluntary cut'—in the salaries of all government servants earning above a certain

[Shri Amiyanath Bose]

level. One has to exclude from these four principles the effects of direct taxation in assessing the expenditure. If these three principles are adopted in the Defence budget itself, there can be a saving of at least Rs. 70 crores. If that is applied to the rest of the Budget, there should be a saving of Rs. 150 crores. I say—even if I am the only person standing in this House and saying this—that out of these Rs. 150 crores, the Government of India, in the interest of national security, should immediately spend Rs. 100 crores for the manufacture of nuclear weapons. If you look at the Defence estimates, you will find that we are spending 75 per cent on Army, 20 per cent. on Air Force and only 5 per cent. on Navy. With a large coast line, with the growing Chinese submarine force, I think, this is a preposterous budget. The entire Defence economy of our country needs a through reorganisation. I understand that a British scientist, as early as 1949, made some suggestions. I believe that the scientific talent, the technological talent, and the military talent that are available in our country have not been properly utilised. There is so much of discrepancy between what we spend on Navy, Army and Air Force. I believe, there is no other modern country in the world today which spends only 20 per cent of its Defence estimates on Air Force excepting India. There is no other modern country in the world which does this.

17.05 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

It is important to develop nuclear weapons because the only argument that the world of today understands is the argument of force. It is easy to make speeches on peace, but the only argument that the world of today understands is the argument of force. It is necessary that our country, our Armed Forces, must be equipped with the most modern arms; it is necessary to give them the most modern weapons. No army can fight if they feel that against them is an army with nuclear weapons and they have none. I know that we have made many declarations. I know that our Foreign Minister has told us that they do not intend signing the non-proliferation treaty in its present form. I congratulate him on his stand, but I should ask the Government to go a step further; I shall ask the Government to stand firm and tell the people of India that it is in the interest of our country that nuclear weapons should be developed. I am sure that, even within the four corners of the present budget, it is possible to develop nuclear weapons.

I have examined with some care the estimates of our External Affairs Ministry. We contribute a large sum of money to international agencies which bring us no benefits, nor does it help us to promote peace. On this question, I say that a considerable amount of money should be set apart, so that we are able to assist a cause to which we are committed as a nation.

May I with your leave read before this august assembly a letter that I have just received from Khan Abdul Ghaffar Khan? He writes from Jalalabad on the 21st May, 1967 as follows:

> "Our Pakhtoonistan is very easy. We want an autonomous State. If India helps us in the right sense, I think that we will achieve our goal very quickly. I think that if they only influence Russia and America, even then, this matter can be solved. But I do not know..."

I would beseech you to mark these words, words of a very great man, words of one of the greatest fighters for India's freedom, words of, I believe, one of the greatest believers in non-violance—

> "But I do not know..."

There is some pain in his words when he writes this. He writes:

> "But I do not know why India is not taking much interest in this, although we the Pathans have given many sacrifices for the freedom of India."

And now comes something very important.

> "In our freedom we will gain a lot, but India will gain much more.".

Here is a man of peace giving us a lesson on strategy. He says:

> "I have started a Khudai Khidmatgar movement in the tribal areas and it has had a very good effect on the people. I have also published an appeal to the people of Afghanistan and asked them to help us in the Pakhtoonistan issue and the response was very good. Nowadays I am very busy and whenever I finish this work I shall come to India.
>
> I am a man of non-violance and will try to solve the matter in this way. If I do not succeed, then, as Gandhiji said, 'The Government of India will solve it."

I call upon the Government of India to honour the pledge that Gandhiji gave to the Pathans. It is a debt, we owe and it is a pledge that we all owe to the people of Pakhtoonistan. Gandhiji spoke for India, and it is for this Parliament to honour the pledge that Gandhiji gave to the people of Pakhtoonistan.

I hope to have another opportunity to speak on other aspects of the budget, to show that this budget is in essence an anti-socialist budget; it is in essence a budget which buttresses capitalism in India; it is a budget which is contrary to the declared policies of the Indian National Congress; it is a budget which is contrary to the declarations of Pandit Jawaharlal Nehru and it is a budget which is contrary to the teachings that I personally had from the Planning Minister. The Planning Minister has planned for capitalism; as the Planning Minister, he has buried socialism; as the Planning Minister, he has not created any enthusiasm among the common people of India. As for the Finance Minister, if I may put it in just a few words, the budget does not and cannot inspire the common people of India for greater effort, nor can it create enthusiasm among the Armed Forces of our country for national defence.

श्री रणधीर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बजट की पुरजोर हिमायत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह बजट एक मुसल्लिमा काबलियत के कांग्रेस पार्टी के लीडर का नहीं बल्कि देश के एक माने हुए बुलन्द शख्सियत के दिमाग की पैदावार है । मैं समझता हूं कि जिन हालात से देश गुजर रहा है इन हालात में जितने बड़े आदमी के हाथ में देश की इक्सादियात है और जिस ढंग से बजट पेश किया गया है किसी दूसरे शख्सियत या लीडर द्वारा इस काबिल तरीके से बजट पेश नहीं किया जा सकता था । मेरे दोस्त बातें बहुत करते हैं । बातें की भी जा सकती हैं । लेकिन अकेले बात करने से बात नहीं होती । ढोल बजाया जा सकता है पर पता तब लगेगा जब सिर पर कभी हुकूमत का बोझ पड़ेगा । अभी थोड़ा सा सीखो । सीखने के बाद पता लगेगा ।

मैं तारीफ करता हूं नायब प्रधान मंत्री की कि उन्होंने इस बजट में 590 करोड़ रुपया यानी छः अरब रुपये के करीब पहली बार किसानों के लिये रखा जो कि हिन्दुस्तान के 5 लाख गांवों में रहने वाला यहां का 80 प्रतिशत तबका है । उसके लिए पहली बार 6 अरब रुपया मखसूस किया है । मैं धन्यवाद करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि यह रुपया दुगुना और तिगुना होता जायगा ।

[श्री रणधीर सिंह]

अगले साल जो बजट आये उसमें इन देहात के, पांच लाख गांवों के किसानों के लिये, जिसमें कि 80 फी सदी आबादी तमाम देश की रहती है उन का काया कल्प करने के लिए और ज्यादा गुंजाइश रुपये की होनी चाहिए। मैं इस सिलसिले में इशारा करना चाहता हूं कि शहर तो आगे डेवलप हो सकते हैं लेकिन हिन्दुस्तान को डेवलप करने के लिए, इस गरीब देश को तरक्की देने के लिए देहात को आप को झिंझोड़ना होगा पड़ेगा और जिस गफलत की हालत में देहात को रखा जा रहा है उसको आपको चकाचौंध करना पड़ेगा डेवलप मेंट करके। देहात आज गन्दगी के ढेर हैं। वह कच्चे मकानात, छोटे छोटे मकानात की बदनुमा बस्तियां बनी हुई हैं। वहां कोई लैट्रिन वगैरह या पक्की सड़कें नहीं, और जो इस तरीके की सुविधाएं सैनिटेशन वगैरह की होती हैं वह भी वहां नहीं हैं। इसलिए हर एक गांव को सड़क से मिलाना है। उसमें बिजली ले जानी है। हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोलना है और पांच पांच सात सात मील की दूरी पर मिडिल स्कूल कायम करना है। हर दस मील पर हाई स्कूल ले जाना है और अगर कोशिश हो सके तो पांच सात साल के अन्दर ही पन्द्रह या बीस मील पर एक कालेज साइंस का या आर्टस का या ऐग्रीकल्चर अथवा इंजीनियरिंग का कायम करना है। यह तभी होगा जब साधन सुलभ होंगे। लेकिन जो कुछ हुआ है अब तक, मेरे भाई कुछ कहते रहें मगर अपने दिल पर हाथ रख कर पूछें क्या हमारा वही हाल है जो बीस साल पहले था ?

एक माननीय सदस्य : उस से ज्यादा खराब है ।

श्री रणधीर सिंह : गलत बात कहते हैं। हर स्फेयर में हमने तरक्की की है। चाहे किसान की साइड में देखें, मैं किसान होते हुए यह बात कहता हूं, चाहे मजदूर की साइड में देखें, हरिजन की साइड में देखें, बैकवर्ड भाइयों की साइड में देखें या जोगी बैरागी तेली नाई धोबी कोई भी हो, हर साइड में देहात के अन्दर अंग्रेजों के वक्त से दुगुनी और तिगुनी तरक्की हुई है और यह कांग्रेस सरकार की बदौलत है। मेरे भाई ठेका उठाये फिरते हैं सारे देश के आगे सिंडिज्म का, सारे देश के सोशलिज्म का और यह समझते हैं कि इनका जैसे ख्याल वाले देश में और कोई नहीं है। पिछली एक सदी में चार करोड़ आदमी लुकमाए-अजल हो गये थे, मौत के मुंह में चले गये थे, सन 1801 से लेकर 1901 तक 31 कहत पड़े थे, जिसमें हिन्दुस्तान के चार करोड़ आदमी मर गये थे। इसी तरह से सन 1945-46 में बंगाल में एक ही कहत पड़ा, उसमें डेढ़ मिलियन आदमी मर गये थे। यह सब मैं अंग्रेजों के वक्त की बात कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत ने सन 1947 के बाद एक-एक मन गेहूं अमरीका या दूसरे देशों से 100-100 रु० मन खरीदा, लेकिन एक भी आदमी को लुकमाये-अजल नहीं होने दिया। इस हुकूमत के सरबराह वे लोग हैं जिसने गांधी को पैदा किया, जिसने जवाहरलाल को पैदा किया, जिसकी रहबरी आज श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी भाई कर रहे हैं। इस में अशोक मेहता जैसे दिमाग बैठे हुए हैं। आपकी पार्टी में तो खिंचाव है, लेकिन अगर कोई समाजवादी दिमाग हमने अपने प्लैनिंग का इन्चार्ज किया है, तो अशोक मेहता जैसे शख्स को किया है जो अब्बू रखते हैं, काबलियत रखते हैं समाजवाद पर। जहां ऐसे आला दिमाग हैं, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर और जहां जगजीवन राम जैसे गरीब घर में पैदा हो कर आज सारे देश के फूड मिनिस्टर हैं, ऐसे आला दिमाग मिलेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई फिक्र करने की बात है।

एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, डिप्टी स्पीकर साहब, वह यह है जहां सरकार ने एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में कुछ कन्सेशन

दिया है, डाइरेक्ट टैक्सेज में कुछ कन्सेशन दिया है, कारपोरेट टैक्सेज में कुछ कन्सेशन दिया है, मैं यह समझता हूं कि बजाय इन चीजों में कन्सेशन दिया जाता, यह कन्सेशन देहात की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिये था, उनको लगान में माफी देने की तरफ डाइवर्ट किया जाता । आज जरूरत इस बात की है कि देश में एक नारा लगे, पूरे जोर से नारा लगे कि गरीब किसान को, जिसके पास पांच या दस एकड़ जमीन है, उस से कोई मालगुजारी नहीं ली जायगी । यूनियन टैरिटरीज में भी, सारे देश में एक यूनीफार्म ला पास किया जाय । मैं अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और फूड मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारी तरफ से इनीशियेटिव हो, पहल हो कि यह तरक्की पसन्द कदम सेन्टर की तरफ से उठा है, इसमें पार्टी की भी वाहवाही होगी और जो समस्या है, वह हल होगी और गरीब किसान को राहत मिलेगी ।

एक दूसरा नारा हमारी तरफ से "क्राप-इन्शोरेन्स" का होना चाहिये । मैं यह बात क्यों कहता हूं ? इसलिये कहता हूं कि हम किसान को झंझोड़ें, उस के अन्दर एंटीचूड लायें, उस को ऐसा अहसास करायें कि उसी ने इस देश को बचाना है वही एक ऐसा आदमी है कि जिस तरह एक सिपाही जिम्मेदार होता है, उसी तरह से भूखमरी को दूर करने के लिये वह जिम्मेदार है और देश का जो अपमान बाहर से अनाज लाने में होता है, उस अपमान से किसान ने देश को बचाना है और वह तब ही बचेगी जब कि आप किसान को हर बात में सहूलियत दें, उसकी मालगुजारी माफ करें । किसान की फसलों की इन्शोरेन्स स्कीम बनाई जाय, इसमें ज्यादा लम्बी चौड़ी रकम की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसान को बताने की बात है कि यह हुकूमत ऊपर से लेकर नीचे तक किसान के हित में है तथा किसान को ज्यादा से ज्यादा एन्केज करना चाहती है ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह मैंने पहले भी कही थी और आज फिर उसी को दोहराना चाहता हूं । श्री जगजीवन राम जी यहां पर बैठे हुए हैं—एक ऐग्रीकल्चर की फाइनेन्शल कारपोरेशन होनी चाहिये । जब आपकी इण्डस्ट्रियल फाइनान्स कारपोरेशन है और थोड़ी शरह सूद पर आप रुपया देते हैं, उसी तरह का इन्तजाम किसान के लिये भी होना चाहिये । मोरारजी भाई ने कहा है कि हम पांच करोड़ रुपया लोन मार्टगेज बैंक को दे रहे हैं, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि यह रकम काफी नहीं है, किसान को आज क्रैडिट फैसिलिटी की जरूरत है । उसे पांच-सौ, सात सौ या हजार रुपया नहीं चाहिये उसे पांच हजार या सात हजार रुपया चाहिये और वह भी लम्बी टर्म के लिये चाहिये, साल दो साल के लिये नहीं । हम देखते हैं कि सरकार तकावी देती है, लेकिन अगले साल ही उसकी वसूली के लिये कुड़की करना शुरू कर देती है, किसान ऐसा ऋण नहीं लेना चाहता, जिससे उसकी बेइज्जती हो, वह तकावी का रुपया नहीं लेना चाहता, वह कोआपरेटिव सोसाइटी से रुपया नहीं लेना चाहता, वह प्राइवेट मनी-लेन्डर से रुपया नहीं लेना चाहता, जिससे उसकी परेशानी में इजाफा हो । मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप हुकूमत की तरफ से इस किस्म का एक कारपोरेशन कायम करें और उसमें एक अरब रुपया कहीं से प्रोवाइड करें । अगर किसान मर गया, तो उससे देश कमजोर होगा, इस लिये उसको छूट दें और एक-एक गांव में दो-तीन ट्यूब-वेल का इन्तजाम करें । अगर ट्यूब वेल्ज का इन्तजाम हो सका तो सारी जमीन सरसब्ज हो जायगी, सैराब हो जायेगी और आप देखेंगे कि खाली हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि वह और देशों को भी खिला सकेगा । मेरे हिन्दुस्तान की एक तिहाई जमीन इस वक्त ऐसी है, जहां पानी नहीं पहुंचता । ट्यूब-वेल बनाइये, सरकारी ट्यूब-वेल बनाइये । अगर ज्यादा इस्टेब्लिशमेन्ट की वजह से नहीं बना सकते हैं तो किसानों

[श्री रणधीर सिंह]

को पया दें, पांच हजार रुपया दें—जो कि ट्यूब-वेल बनाने में लगता है ।

यह एक ऐसी बात है, जिसकी वजह से मेरे दिल में दर्द होता है । जब वह पांच हजार रुपया ट्यूब-वेल के लिये मांगता है, और हुकूमत की तरफ़ से इन्स्ट्रक्शन्ज़ हैं कि तीन महीने में ट्यूब वेल का रुपया दिया जाय, तीन तीन साल तक उसको ट्यूब-वेल का रुपया नहीं दिया जाता । उस पांच हजार रुपये में से दो हजार रुपये किसान को रिश्वत के देने पड़ते हैं– नीचे से लेकर ऊपर तक । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि मैं अभी एक महीने तक अपने सारे हल्के में घूम कर आया हूं, 100 गांवों के किसानों ने रोते हुए कहा कि हम देश को निर्भर बनायेंगे, देश की पैदावार को बढ़ायेंगे, लेकिन जो चीज चाहिये वह तो दो । हर किसान बिजली और रुपया चाहता है, अगर ट्यूब-वेल के लिये उसको रुपया दे दें, उस के लिये पानी का बन्दोबस्त कर दें, तब आप देखना कि इसका कितना शानदार नतीजा निकलता है ।

एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान अब इन मण्डियों की लूट-खसोट को बरदाश्त नहीं करेगा । आपने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन बनाई है, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाइये । जो अनाज किसान पैदा करता है, उसका सही रिटर्न उसको मिलना चाहिये । मैंने अन्दाजा लगाया है कि अगर एक मन गेहूं पैदा करने में किसान का 45 या 46 रुपया लगता है, तो वह चाहेगा कि जो रुपया उसका लगा है, उस का ठीक रिटर्न उसको मिले । स्टेट ट्रेडिंग की मारफत आप किसानों की जिन्स को लें, उसको कुछ रुपया फस्ल के मौके पर दें, उसके लिए रियूमनरेटिव प्राइस मुकर्रर कर दें, जितना पैसा उसका लगता है, उससे ज्यादा पैसा उसको दें, ताकि उसकी मेहनत का उसको सही रिटर्न मिल सके और अपनी पैदावार को बढ़ाने में उसका हौसला आफजाई हो सके ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें एक मियाद मुकर्रिर करनी चाहिये । डा० लोहिया ने भी आज इस बात का जिक्र किया है कि हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, जैसे हमारे पांच साला प्लान हैं, उसी तरह से इर्रिगेशन देने के लिये हमें एक पांच साला या सात साला प्लान बनाना होगा । जिसके मुताबिक पांच साल के अन्दर एक एक चप्पा जमीन को पानी देना होगा, अगर हम जमीन को पानी दे सके तो आप देखेंगे कि हमारी उपज किस तेजी से बढ़ती है ।

एक बात खास तौर से मैं फर्टीलाइजर के बारे में कहना चाहता हूं । फर्टीलाइजर, बीज और बिजली– ये किसान के मीडियम आफ़ प्रोडक्शन हैं ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may continue his speach tomorrow.

17.28 hrs.

NATIONAL FOOD BUDGET*

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय खाद्य बजट के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा गया था और जो उस का उत्तर आया है, उस को लेकर मैं यह बहस उठाना चाहता हूं । आपको याद है कि 30 मई को इस सदन में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में कुछ सवाल पूछे गये थे, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य बजट का सवाल भी पूछा गया था तथा सरकार की ओर से निम्न उत्तर दिया गया था—

*Half-An-Hour Discussion.

"It was recognised that the tentative national food budget placed before the Conference had some limitations on account of the imperfect data available relating to production, consumption etc. It was, therefore, felt that in order to meet the difficult situation during the year it would be necessary to proceed on an *ad hoc* basis."

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह मांग की गई थी कि राष्ट्रीय खाद्य बजट का जो मस्विदा उन्होंने मुख्य मंत्री सम्मेलन के सामने रक्खा था वह सदन की टेबुल पर भी रक्खा जाय लेकिन जान बूझ कर खाद्य मंत्री ने यह सदन की टेबुल पर नहीं रक्खा। किसी भी मंत्री का यह फर्ज होना चाहिए कि सदन जो जानकारी मांगता है वह जानकारी उन को तत्काल दें। वैसे तो स्वयं ही देनी चाहिये और मांगने पर तो बिलकुल इंकार नहीं करना चाहिये। लेकिन यहां अजीब हाल है? इसमें कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है फिर क्या वजह है कि मंत्री महोदय अपने आंकड़े और अपना मस्विदा सदन के सामने रखने के लिये तैयार नहीं हैं? मेरा अपना अंदाज है अनुमान है कि वह इसलिये नहीं रखना चाहते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य बजट का उन्होंने जो आधार बनाया था उसमें इतनी विषमता, असमानता और अमानुषता थी कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है सदन के सामने आने की। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास वह कागज नहीं है मैं कोशिश कर रहा हूं प्राप्त करने की अगर मुझको मिल जाएगा तो मैं स्वयं रख दूंगा। लेकिन मुझे खबर मिली है कि उस में इन लोगों ने कहा है कि कुछ राज्यों के आदमी जो हैं वह साल में 108 किलो या 112 किलो अनाज खाकर जिंदा रह सकते हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं कि जिनको 120 मिलना चाहिए, 130 मिलना चाहिए और कुछ राज्य शायद ऐसे भी हैं कि जहां 140 किलो देने की बात कही गई है। जैसा कि हमेशा होता है माननीय खाद्य मंत्री जिस इलाके से आते हैं वह क्या अभागा इलाका है, फी व्यक्ति राज्यवार आमदनी का जहां तक सवाल है हिन्दुस्तान में सब से गरीब इलाका बिहार का इलाका है। सरकार के पास मैं ने कई दफे कहा कि तीन योजनाएं खत्म हो चुकीं चौथी योजना आप बना रहे हो लेकिन अभी तक राज्यवार फी व्यक्ति आमदनी क्या है उसका अभी तक पता नहीं। कई सवाल मैंने पूछे मगर कह दिया गया कि योजना मंत्रालय अध्ययन कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इसका कब और कैसे पता चलेगा? अगर आप ठीक योजना बनाना चाहेंगे तो किस राज्य की क्या आवश्यकता है, कहां गरीबी ज्यादा है, स्वास्थ्य का इंतजाम सबसे खराब कहां है, शिक्षा की कमी कहां है इन चीजों का पता लगाना चाहिए। जब तक सरकार स्वयं इसके बारे में आंकड़े इकट्ठे कर के सदन के सामने नहीं रखती है और अपनी आर्थिक योजना भी उसी के आधार पर नहीं बनाती है। देश में संतुलित विकास नहीं हो पायेगा।

इसी तरह फी व्यक्ति अनाज की उपलब्धि पिछले पांच वर्षों में क्या रही उस के बारे में भी हमने कई सवाल पूछे थे लेकिन अखिल भारतीय औसत तो ये हर साल बतलाते हैं कि इस साल इतनी उपलब्धि रही, पिछले साल इतनी थी और कितनी कम हो गयी है। अखिल भारतीय औसत आंकड़े तो आ रहे हैं। लेकिन राज्यवार आंकड़े नहीं आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या हिन्दुस्तान के जो दूसरे पिछड़े हुए इलाके हैं उन में अनाज की फी व्यक्ति उपलब्धि अखिल भारतीय औसत है उस से दो या डेढ़ या ढाई आउंस कम है। उस के बारे में तथ्य और आंकड़े सदन के सामने नहीं रक्खे गये हैं। फी व्यक्ति आमदनी के औसत के आंकड़े शायद इनके पास उपलब्ध नहीं है लेकिन लोकनायक की जो संस्था

[श्री मधु लिमये]

है उस ने दो दफे इसके बारे में आंकड़े प्रकाशित किये हैं और इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 15 वर्षों में राज्यवार फी व्यक्ति जो आमदनी है, पर कैप्टा इनकम स्टेटवाइज उसमें जो अन्तर है, विषमता है वह कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। फिर मैं जिक्र करना चाहता हूं कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है, इन राज्यों की आमदनी और आंध्र, महाराष्ट्र के भी कुछ ऐसे जिले हैं और दूसरे इलाकों के भी जिले हैं जिनकी कि आमदनी बहुत कम है। पश्चिमी बंगाल चूंकि उसमें कलकत्ता है, उसी तरह पंजाब है जहां अंग्रेजों के जमाने से विकास पर पूंजी लग रही है, नहर आदि को लेकर महाराष्ट्र चूंकि उसमें बम्बई है, मैं देहाती इलाकों की बात नहीं कर रहा हूं फी व्यक्ति औसत आमदनी बिहार से दुगुनी है। इनके बारे में कोई आंकड़े नहीं दिये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और दुःख की बात है। मैं कभी कभी अपने को भी दोष देता हूं कि दो साल हो गये मेरे ध्यान में यह बात कैसे नहीं आई कि आप ने खेती के दाम निश्चित करने के लिए एक कमीशन बनाया। उस की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह मेरे पास है। यह करीब करीब दो साल पहले की रपट है। उस के बाद मेरा खयाल है कि 10–11 रपट आ चुकी हैं। इन में से एक भी आप ने प्रकाशित नहीं की है। अभी गेंहूं के बारे में, जूट के बारे में रपट आई है। यह रपट भी आप ने प्रकाशित नहीं की है। मैं आज खाद्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि पहली रपट प्रकाशित करने के बाद आज तक इन्होंने बाकी रपटों को क्यों नहीं प्रकाशित किया? सारांश तक नहीं है। मैं समझता हूं कि उस का कारण यह है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन ने अपनी विभिन्न रपटों में सरकार की खाद्य नीति की घोर आलोचना की है। वह डरते हैं कि उन्होंने ही जो कमिशन बनाया जो रपट है, जो सिफारिशें हैं उनके प्रकाशित होने से सरकार को नुक्सान पहुंचेगा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय खाद्य बजट इसलिए नहीं बन रहा है कि खाद्य के बारे में इनकी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। कल ही एक सवाल यहां पर पूछा गया कि इनकी जो देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देने की नीति है, जिसके कारण इधर का अनाज उधर नहीं जाता, उसका क्या नतीजा हो रहा है? ऐसा सवाल पूछा गया था। मेरा खयाल है कि देसाई साहब का यह सवाल है। उस में उन्होंने पूछा है कि विभिन्न राज्यों में जो अगल बगल में हैं, उनमें उसी अनाज के दाम क्या हैं? एक बड़ी विचित्र चीज मिलती है और खुद सरकार ने जवाब में स्वीकार किया है कि यह जो मोटे अनाज का मई महीने में थोक दाम 170 रुपये क्विंटल था और उसी का दाम महाराष्ट्र में साढ़े 68 रुपये था। इसी तरह मैं पंजाब और दिल्ली का भी जिक्र करूं। अनाज के दाम पंजाब में 77 रुपये है दिल्ली में 57 रुपये है। यह ज्यादा आंकड़े मैं देना नहीं चाहता लेकिन बात बिल्कुल साफ है कि इन्होंने देश में जो कई पाकिस्तान पैदा किये हैं उस का यह नतीजा हुआ है कि आज हिन्दुस्तान के कई इलाके चूसे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि खाद्य के बारे में वह बुनियादी बातों पर सोचें। उन से एक दफा पूछा गया कि खाद्य के बारे में हिन्दुस्तान में व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है, तो उन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया है। जब उन से आवश्यकता के बारे में पूछा गया तो वह यह जवाब देते हैं :

"There is no uniform daily requirement of foodgrains per person even in India. The requirement of foodgrains by a person depends on his income."

यानी खाद्य की आवश्यकता आमदनी पर निर्भर करती है। उपलब्धि या खरीदने की शक्ति आप कहेंगे उस पर निर्भर करती होती तो मैं मानता। लेकिन हमारा एक साधारण औसत तो निकालना चाहिये कि कम से कम जिन्दा रहने के लिये, ठीक तरह से, हिन्दुस्तान में गल्ले की इतनी आवश्यकता है। हर एक रोज किसी भी व्यक्ति को इतना अनाज देने की जिम्मेदारी, मैं समझता हूं, सरकार की और शासन की है। शासन से मेरा हर्गिज यह मतलब नहीं है कि केवल केन्द्रीय सरकार की। उस में मैं राज्य सरकारों को भी समाविष्ट करता हूं। लेकिन जब इस किस्म के ऊट पटांग जवाब आते हैं तो उस का मतलब होता है कि खाद्य मंत्री की राय में जो गरीब लोग हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ज्यादा मर रहे है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में—यही लोग मर रहे हैं पिछड़े हुए क्षेत्रों और वर्गों के जिन की आमदनी कम है--उन को अधिक खाद्य की आवश्यकता नहीं है। अगर यह कहते कि जितनी आवश्यकता है उतना नहीं मिल रहा है और उसे दिलाने के लिये हम राष्ट्रीय नीति बना रहे हैं, एक राष्ट्रीय बजट बना रहे हैं तो उन की बात मानता।

आप की मार्फत जो जानकारी मैंने मांगी है वह मंत्री महोदय देने की कृपा करें और अपनी राष्ट्रीय खाद्य नीति क्या है, उस की मोटी मोटी बातें क्या हैं, यह सदन के सामने रखने का कष्ट करें।

Shri R. K. Amin (Dhandhuka): Sir, I would like to ask one question.

Mr. Deputy-Speaker: According to rules only those who have intimated to me their desire to put a question will get a chance to do so. Only one question is allowed to be put by a Member. I will be very strict about the rules. It is a half-hour-discussion. He wants further clarification and information regarding a question where he was not satisfied with the reply.

Shri S. S. Kothari (Mandsaur): Sir, I have to build up the background.

Mr. Deputy-Speaker: If everybody starts building up the background this discussion will not be over in half-an-hour.

Shri S. S. Kothari: Sir, it is not even second-class-citizenship, my name is there on the motion.

Mr. Deputy-Speaker: Because your name is there, you have no right.

Shri S. S. Kothari: Then these rules should be changed.

Mr. Deputy-Speaker: That is another matter.

श्री मधु लिमये: इसीलिए मैंने कम समय लिया है। उन्हें दो चार मिनट तो दीजिये। वह हस्ताक्षर करने वालों में हैं।

Mr. Deputy-Speaker: There are several other people who have intimated their names to me.

Shri Srichand Goel (Chandigarh): Sir, it has been the practice in this House....

Mr. Deputy-Speaker: I have been here for the last ten years. I am following the rules. He may put his question.

Shri Srichand Goel: I only want to remind you of the practice that we have been following in this House.

Mr. Deputy-Speaker: I know the practice in this House. Let not the hon. Member take the time of the House over that.

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : सवाल यह है कि जिन्होंने इस तरह का क्वेश्चन दिया है, जिन्होंने इस तरह का नोटिस दिया है, कम से कम उन को समय मिलना चाहिये ।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Shri Kothari may put his question.

Shri S. S. Kothari: In view of the recent Hare-up in the West Asian situation, the whole national food budget which, as Shri Limaye said, has not been brought before the House, would have to be amended. The Food Minister has to amend it and present it before the House. Because the ships will have to be diverted along the Cape of Good Hope, it would mean a delay of about 15 days. What is your assessment of your being able to fulfil the demands of the various States and the amount of foodgrains that you are going to supply to them?

Mr. Deputy-Speaker: It does not arise out of this.

Shri S. S. Kothari: If it does not arise, what else will arise? The whole national food budget has to be abandoned. This budget is affected; that is a basic and fundamental point. If we ignore that, what is the use of discussing the national food budget?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): The situation which the hon. Member is referring to was not in existence when he sent his notice.

Shri S. S. Kothari: But the current situation has to be taken into account.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से विशेष वर्गों के लोगों के लिये खाने की मात्रा अधिक है तो क्या उसी तरह से खाद्य का वितरण हो रहा है ? सैनिक, असैनिक और अर्धसैनिक कर्मचारियों, खासकर पुलिस को जो भोजन दिया जाता है अथवा संसद् सदस्यों को, इस की मात्रा क्या अधिक है औरों की अपेक्षा ? यदि हां, तो इस में कितना अन्तर है ?

श्री जगजीवन राम : इस का बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है

Shri E. K. Nayanar (Palghat): The Government of India has not chalked out a national plan for the nearest future. Some ten years back the Food grains Inquiry Committee made some suggestions. One of the suggestions was that until there is social control over the wholesale trade we shall not be in a position to bring about stabilisation of the wholesale prices in foodgrains. That has not been taken into account. Following this recommendation by the Foodgrains Inquiry Committee in 1957, the National Development Council decided in November 1958 that the State should take over the wholesale trade in foodgrains.

Mr. Deputy-Speaker: Please come to your question.

Shri E. K. Nayanar: Even with the import Government have a national food plan. If Government procures all the surplus food in India, Government can give at least 15 ounces *per capita* per day. That has been explained by the well-known economist Dr. Raj in January last year. 15 ounces *per capita* per day is the production needed to supply every Indian reasonable food. In no year in the last decade has the *per capita* availability of foodgrains fallen below this level and except in two years, 1951-52 and 1952-53 it would have been possible to ensure this from domestic production. That is why I am asking if Government is prepared to take over all the surplus and the responsibility of the wholesale trade, as recommended by the National Development Council in 1958.

श्री रबी राय (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि दो फसलों के बीच में जो खाद्यान्न का भाव बढ़ता रहता है क्या वह 16 प्रतिशत के अन्दर ही रहेगा, उस से अधिक तो नहीं बढ़ेगा ? क्या इस की सूचना मंत्री महोदय हाउस में देंगे ?

Shri Sequeira (Goa, Daman and Diu): The hon. Minister stated in his reply that the food budget would be finalised after the Chief Ministers' Conference. I would like to ask of him when is it likely now to be finalised. He also said that it was difficult to finalise the budget because the the estimate of consumption and the movement on private account were not adequate. What arrangements have been made to improve the collection of this data? What progress has been made since this question was answered? I also wish to ask him whether any steps have been taken to mobilise public opinion in favour of a national food budget? Has the radio been used, has any other mass media of communication been used? If not, are they proposed to be used and when?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome this opportunity to discuss the problem raised in connection with the National Food Budget. Mr. Madhu Limaye is a very enthusiastic parliamentarian and all of us have great respect for him. But the way in which he raisd today's discussion, I do not think, there is much relevance in the point made out by him.

. . . . .

First of all, I shall be thankful to him if he brings to my notice that when Q. 20 was being discussed he made a demand that some documents which were circulated to Chief Ministers be placed on the Table of the House.

श्री मधु लिमये : मांग की गई थी । उस वक्त नहीं की गई थी बाद में की गई थी । मैं निकाल कर दे सकता हूं । उसका जवाब आपने दिया था कि ये टैंटेटिव है नहीं रखेंगे । अगर रखने के लिए तैयार हैं तो झगड़ा खत्म हो जाएगा । लेकिन उस वक्त आपने इन्कार किया था ।

Shri Annasahib Shinde: I am speaking with reference to Q. 20.

श्री मधु लिमये : मैं यह नहीं कहता हूं कि तब यह मांग की गई थी । लेकिन सदन में इस सम्बन्ध में मांग की गई थी । आपने "न" कहा था । इसलिए मुझ को कहना पड़ा ।

Shri Annasahib Shinde: This discussion is strictly confined to Q. 20.

श्री मधु लिमये : क्या सदन में इसी के सम्बन्ध में जो कहा गया है उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है ? इसके सम्बन्ध में एक बार जब मांग की गई थी तो उसके बारे में नहीं कहा गया था ? इस सदन में, इस सम्बन्ध में जो हुआ है, उसका उल्लेख करने का क्या मुझे अधिकार नहीं है ?

Shri Annasahib Shinde: The notice that had been given....

श्री मधु लिमये : आप तो मेरे भाषण को ही काट रहे हैं इरेलेवेंट कह कर । जो इस सदन में घटित हुआ है, उसके बारे में मैं कह रहा हूं ।

Shri Annasahib Shinde: I am not yielding. When he expressed views with which I disagree, I did not interrupt him at all.

श्री मधु लिमये : श्री जगजीवन राम जी ने कहा था कि हम नहीं रखेंगे ।

Shri Annasahib Shinde: The hon. Member need not interrupt me. I did not interrupt him when he was speaking.

Shri Sonavane (Pendherpur): Sir, is it a quarrel or a debate? There should be some control....

श्री मधु लिमये : पहले अपने मंत्रियों को आप कंट्रोल करें । हम को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं ? उनको पहले कंट्रोल करें ।

Shri Annasahib Shinde: Let us take it in a sportsmanlike manner. There is nothing unparliamentary ; we should give and take.

Sir, this National Food Budget was to be discussed in the Chief Ministers' Conference. Of course, some tentative documents were circulated to Chief Ministers for the discussion. We have never expressed the view that the facts mentioned in the documents which were circulated or the figures mentioned there in were final figures. They were only suggestions for discussions. In fact, the hon. Minister of Food and Agriculture who conducted the proceedings of the Conference pointed out in the Conference that there were certain limitations because of imperfect data in regard to availability of foodgrains in the country. For instance, it has already been mentioned that reliable estimate of actual levels of consumption on Statewise basis are not available in the absence of scientific and comprehensive surveys on food consumption. Moreover, all relevant data regarding inter-State inflow or outflow of foodgrains, particularly movement by road on private account are not available. Also, data on changes in stocks with producers and traders are not available. The usual allowance made for feed, seed and wastage is 12½ per cent of the total production in every State and such an allowance differs from grain to grain. Consumption patterns are influenced by the levels of income and changes therein over time obtaining in different States. The *per capita* consumption of cereals also depends on the extent to which subsidiary foods like, potatoes, sweet potato and tapioca supplement cereals intake.

Taking all these facts into consideration, the hon. Minister of Food and Agriculture suggested that it may not be possible to proceed on the basis of tentative suggestions that were mentioned in the documents circulated to the Chief Ministers. Perhaps, the Chief Ministers also had some difficulty about it and the National Food Budget was not finalised. I do not understand why the hon. Member should be so much concerned about it. Had we taken some decision on the basis of it or had we committed some mistake, perhaps, the hon. Member would have been right in making a complaint or raising a discussion here.

May I draw the attention of the hon. House to the fact that consumption pattern and *per capita* availability of food is a very complex matter all over the world? I have got the figures of F.A.O. for various countries. Considerable studies have been made. They also indicate considerable variations. In the case of some countries, the figures is 65 kgs. per year while in respect of some other countries, the figure shown is 223 kgs. per year. The variations is so wide, from country to country, and, similarly, it must be the case in respect of our country. The per-head availability of food must be different not only from State to State, but even within a State; for instance, take the case of North Bihar where the population pressure is too much, the land-man ratio is very high; even there, the consumption pattern must be different from the consumption pattern round about Jamshedpur or Calcutta.

I know something of Maharashtra. There, some studies were conducted in regard to consumption pattern of food, comparing the per-head availability of food, the consumption pat-

tern, in Bombay city with that in the drought affected areas, the areas which are subject to recurrent famines. I myself come from an area which is subject to recurrent famine. The studies conducted indicated that the disparity between the consumption pattern round about Bombay and Poona and the consumption pattern in rural areas which are subject to recurrent famine was very wide. One fails to believe that there could be so much of disparity. As is well known, a large section of the population is poor; they have no purchasing power and that is perhaps the reason for this disparity. I have a document here, the Third World Food Survey, an authoritative publication on behalf of F.A.O. It also says that the pattern of consumption of cereals is different from region to region and within a region also. This is an expert study. May I submit for the information of the hon. House that our endeavour should be to remove this disparity, but that is not so easy; it will take quite some years and it could be brought about perhaps only by increasing agricultural production, by raising the standard of living, but even then I do not know whether it can be done. I do not know of any country in the world where consumption patterns are on par, are on level. It is very difficult to find any region in the world where consumption patterns are similar.

Another point which has been raised by the hon. members is zonal restrictions. I know many hon. members of this House are agitated over this issue. But may I submit that this issue was examined by the Foodgrains Policy Committee? The members who were associated with the Foodgrains Policy Committee were not politicians, they were economists, they were not persons belonging to any party. They themselves have indicated in their document, which is available to the House, that in the present situation in which India is placed today, it would be in the interest of the country if we continue to have these restrictions on movement from State to State. They have suggested that whenever any movement of foodgrains is to take place from one State to another, it should be only on State account and no private trade should be allowed to operate in the present circumstances; otherwise, the people will have to undergo more distress, there will be more suffering. This is the conclusion of the Foodgrains Policy Committee. This document was placed before the Conference of Chief Ministers. Ours is a federal structure; the Centre can formulate the policy in regard to such matters which are in the concurrent list only in consultation with the States because we have the joint responsibility. This document was placed before the Chief Ministers in November, 1966. The general consensus in that Conference was that the present arrangement should continue. After the General Elections, the political complexion in some States has changed. Naturally, we thought that it would be advantageous if we consulted the Chief Ministers again on this issue. This came up for discussion in the Conference of Chief Ministers in the month of April.

श्री मधु लिमये : किन राज्यों ने विरोध किया था, बता सकते हैं ?

Shri Annasahib Shinde: Yes; I can say. Bihar, U.P., Gujarat and West Bengal. They expressed the view that it would be better if State restrictions are removed, but even then, at the end, some of them expressed the view that if the Centre would allocate more food, then perhaps there would be no further complaint; they made a demand that the State restriction should be removed. But, by and large, all the other Chief Ministers expressed the view that, as far as trade between one States is concerned, it should be on State account and the present State restrictions should continue. So, we were guided by the general consensus, and we had to announce on that basis that the present arrangement would continue.

[Shri Annasahib Shinde]

18 hrs.

I think that we shou'd not try to make political capital out of it. As is well known, even in our ruling party, some Members hold the view that the present arrangement is not satisfactory. So, it is a matter which cuts across party lines. There are some Members who have honestly felt that it is not satisfactory. But I would submit that we should not try to make political capital out of it because we are passing through a very difficult situation and the only way, as I see it, out of the situation is to increase production.

श्री मधु लिमये : खेती दाम कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं की गई ?

Shri Annasahib Shinde: We shall definitely consider the suggestion of the hon. Member whether they can be published.

श्री मधु लिमये : यह ताज्जुब की बात है कि हमको यह कहने की जरूरत पड़ती है।

Shri S. S. Kothari: What about the commitment to the States?

Shri Annasahib Shinde: It would depend upon the availability of foodgrains. After all, food grains do not fall from the sky.

Shri S. S. Kothari: Has he assessed the situation? What is his reading of it? Has he made any tentative reading of it?

Shri Annasahib Shinde: We have such a large-scale public distribution system in our country. We have a network of fair price shops. In fact, the Centre is trying to see that as far as possible, within the availability, the needs of the various States are looked into and met, and this position has been explained by the hon. Minister in this House several times.

Shri S. S. Kothari: Now, there will be a detour of the ships round the Cape of Good Hope.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को कह दें कि वह खेती दाम कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित करें या सदन के टेबल पर रखें ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister has already said that he would consider the suggestion.

Shri Annasahib Shinde: There was a reference to wholesale trade. Our policy in regard to this is well known, namely that we want that in the days to come, the food trade comes more and more in the public sector, and we have established . . .

Shri Jagjiwan Ram: Let the State Governments procure more and more of the surplus. We would have no objection.

Shri Annasahib Shinde: The Food Corporation has been established for that very purpose. We only wish that the State Governments would take adequate steps to procure more and to see that private trade is banned, and if they do so we shall support them. This position has been repeatedly explained in this House as well as outside. We shall give all co-operation to the State Governments if they really go in a big way to have the maximum procurement, to adopt anti-hoarding measures and to have food in the public sector.

श्री मधु लिमये : दामों का फर्क भी घटाया जाये । इस समय बहुत फर्क है ।

18.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, June 8, 1967/Jyaistha 18, 1889 (Saka).